राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या: 05

गुरुवार,

02 फरवरी 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

जैतारण में आपराधिक मामलों के दर्ज प्रकरण

89. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली) (श्री अविनाश (जैतारण) के स्थान पर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक चोरी, डकैती, लूट व हत्या के कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए? उक्त दर्ज कितने प्रकरणों में चालान पेश हुए? उक्त अवधि में उक्त विधान सभा क्षेत्र में वाहन चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हुए तथा कितने वाहन बरामद हुए व कितने शेष हैं? शेष रहने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में उक्त विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में चोरियों में बरामदगी का प्रतिशत कम रहा है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त दर्ज मुक़दमों में पकड़े गये अपराधियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा कितनों में जांच लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक चोरी के कुल 142, डकैती के 04, लूट के 62, हत्या के 35 प्रकरण दर्ज हुए। चोरी के 53, डकैती के 03, लूट के 36 एवं हत्या के 21 प्रकरणों में चालान पेश किया गया।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र में वाहन चोरी के 249 प्रकरण दर्ज हुए, वह चोरी अलग है, यह चोरी अलग है, जिनमें 99 वाहन बरामद हुए एवं 150 वाहनों की बरामदगी होना शेष है, जिनका पता नहीं चलने से बरामदगी नहीं हो सकी।

(2) उक्त अवधि में जैतारण विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में विगत 04 वर्षों में चोरी के सामान की बरामदगी का प्रतिशत क्रमश: वर्ष 2019 में 34 प्रतिशत, वर्ष 2020 में 42 प्रतिशत, वर्ष 2021 में 34 प्रतिशत एवं वर्ष 2022 में 35 प्रतिशत रहा है।

(3) जी हां। उक्त दर्ज प्रकरणों में पकड़े गये अपराधियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उक्त प्रकरणों में क्रमश: चोरी में 0.70 प्रतिशत, डकैती में शून्य प्रतिशत, लूट में 4.84 प्रतिशत, हत्या में 5.71 प्रतिशत तथा वाहन चोरी में 0.40 प्रतिशत प्रकरण जांच हेतु पेंडिंग हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने पैरा 4 में उत्तर दिया है, जिसमें आपके नाममात्र के प्रकरण जांच हेतु पेंडिंग हैं। माननीय मंत्री महोदय, पैरा (1) में आपने जो उत्तर दिया है कि कितने प्रकरणों में चालान हो गया, उस संख्या को आप देखोगे तो अभी भी 40 परसेंट प्रकरणों में चालान होना शेष है। आपकी लगभग जांच सारी पूरी हो गई है तो फिर चालान में यह विलम्ब क्यों?

दूसरा, जो वाहन चोरी का है, उसमें 249 प्रकरणों में से मात्र 99 वाहन ही आपने बरामद किये हैं, 150 वाहन अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, ये वाहन पकड़ने के लिये पुलिस कोई विशेष अभियान चलायेगी या और कोई अतिरिक्त प्रयास करेगी, ताकि ये वाहन भी पकड़ में आ जाएं?

पैरा (3) में आपने सामान बरामदगी का जो उत्तर दिया है, माननीय मंत्री महोदय, अगर चोर मिल जाता है और उसके बाद सामान नहीं मिलता तो कहीं न कहीं जांच में कमी रही है, जो प्रयास होने थे, उसमें कमी रही है। चोर मिल गया और बरामदगी किसी में 34 है, किसी में 42 है। अगर किसी का 10 तोला सोना गया और आपने 4 तोला बरामद कर लिया, कौनसा तीर मार लिया आपने? इसलिए मेहरबानी करके आप आदेश दो कि अगर चोर पकड़ा गया है तो बरामदगी भी लगभग पूरी हो जाये, इस बात के लिये वह प्रयास करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। इसका उत्तर दे दो आप।

श्री अध्यक्ष: उत्तर तो आपने खुद ने ही दे दिया।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक बरामदगी का सवाल है, चोर पकड़ा गया और बरामदगी नहीं हुई, अगर माल ही खुर्द-बुर्द कर दिया गया हो या माल को इस तरह से तितर-बितर कर दिया गया हो तो बरामदगी करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हाथों हाथ गिरफ्तारी हो जाती है, तब तो बात समझ में आती है, लेकिन कहीं भी थोड़ा-सा भी डिले हो जाता है या मुलजिम नहीं पकड़ में आता है तो इतना टाइम उसको मिल जाता है कि वह माल को खुर्द-बुर्द कर दे। इसलिए यह आपका जो शक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन यह सब कुछ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन वहां पर लगातार बढ़ाया गया है और बढ़ाने के कुछ रिजल्ट भी अच्छे आये हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहला प्रश्न पूछा था....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। आप सीनियर आदमी हैं, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, यह क्या तरीका है? वे बैठ गये क्या?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): बैठ गये थे वे।

श्री अध्यक्ष: आप खड़े हुए उसके बाद वे बैठे हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, पहले वे बैठे, फिर मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, ऐसा नहीं है। आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो बात अलग है। प्लीज, माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने परिशिष्ट अ, ब, स में सारी फिगर दी हैं। आप देखें कि कितने वाहन चोरी हुए हैं, वाहन तो एक ऐसी चीज है कि प्रदेश के बाहर निकल जाता है। राजस्थान का वाहन तमिलनाडु में घूम रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि किस स्टेट में है। वाहन बरामद करना बड़ा मुश्किल काम होता है, फिर भी 99 की फिगर तो पहुंच गई, बाकी में तफ्तीश चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि मुलजिम भी कितने गिरफ्तार हो गये, 141 गिरफ्तार हो गये हैं। चालान पेश

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हुए हैं, कई जगह एफ आर भी लगी है। कई असत्य शिकायत भी आती हैं, 162 की शिकायत भी है। 162 एफ आर लगी हैं। ये सब बातें आपके सामने हैं, आपको विवरण दे रखा है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहला प्रश्न पूछा कि जब आपकी जांच किसी में 0.70, किसी में 4.84, किसी में 5.71 है, जब इतनी जांच पेंडिंग हैं तो फिर चालान पेश नहीं होने के इतने प्रकरण किस कारण से पेंडिंग हैं?

श्री अध्यक्ष: अब यहीं रुको। चार प्रश्न पूछ लिये तो पहला छूट जाता है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मैंने पहला यही पूछा है।

श्री अध्यक्ष: तीन पूछ लिये आपने, पहला भी यही पूछा है। दो का जवाब दे दिया, एक का छोड़ दिया। माननीय मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि बरामदगी नहीं होने के कई कारण होते हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, ये चालान का पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो केसेज और चालान के प्रतिशत के बीच में गैप है। ये वाहन का नहीं पूछ रहे हैं, ये हत्या और सबके संबंध में पूछ रहे हैं कि जिसमें इस तरह का इन्वेस्टिगेशन है, चालान पेश होने में और इसमें गैप क्यों है, यह पूछ रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 86 चालान पेश हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक बरामदगी का सवाल है, जैतारण और रास, यह दोनों के दोनों नेशनल हाईवे पर हैं और वहां पर सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। वहां चोरी करके आदमी पता नहीं कहां से कहां निकल जाता है, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी गांव से, किसी छोटे कस्बे से या किसी छोटे नगर से चोरी होती है तब तो समझ में आ जाती है कि फटाफट पकड़ लो, चारों तरफ घेरा डाल लो, ट्रेफिक को रोक लो, लेकिन नेशनल हाईवे पर बड़ा मुश्किल होता है और अभियुक्त शातिर चोर होते हैं, ये मामूली चोर नहीं होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं। आपको ध्यान होगा कि यहां पर भी आदरणीय कमला जी की एक गाड़ी चोरी हुई थी। उसका धीरे-धीरे पता लगा तो वह आदमी जेल

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

में था, जेल में जो मुलजिम था, उसके पास पुलिस पहुंची और उससे टेलीफोन करवाया कि यह बरामदगी करवा दे, तब जाकर वह बरामदगी हो पाई थी। आपको वह सारा का सारा किस्सा याद होगा। चुराई हुई सम्पत्ति भी खुर्दबुर्द कर दी जाती है, कहां से बरामदगी होगी? प्रयत्न जारी हैं, निश्चित तौर पर इसके रिजल्ट अच्छे आयेंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, इस विषय को देखने की जरूरत पड़ेगी। आपके चोरी के 142 प्रकरण दर्ज हुए, उसमें से केवल 53 का चालान हुआ है और आप पेंडेंसी बता रहे हो 0.70, इसका मतलब एक केस पेंडिंग होगा। बाकी 90 केस अगर बिलकुल ही छूट जाते हैं तो लोगों के मन में विश्वास खतम होता है। इसको मॉनिटरिंग करने के लिये किसी अधिकारी को देकर दुबारा देखना पड़ेगा। चोरी का प्रकरण कई बार पांच साल बाद भी खुलता है, लेकिन आप उसको बिलकुल रफा-दफा में डाल दोगे तो फिर उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं करेगा। इसको सीरियसली डिपार्टमेंट को दिखायें कि कम से कम एफ आर नहीं लगायें, उसको पैंडिंग छोड़ दें। इससे कभी पता लगेगा तो जिस आदमी का चोरी का सामान गया है, उसको सामान मिल सकेगा, नहीं तो वह खतम हो जायेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि एफ.आर. कब लगती है? आपने तो यह महकमा बहुत साल संभाला है। एफ आर तब लगती है, जब पुलिस चारों तरफ से हतोत्साहित हो जाती कि, साहब, इसमें कुछ नहीं हो सकता, यह बिलकुल फर्जी केस है, तब जाकर एफ आर लगायी जाती है। एफ आर आसानी से नहीं लगती। एफ आर लगती है तो तफ्तीशकर्ता वहां से रिकमंड करता है, उसके बाद सी ओ के पास जाती है, फिर एडिशनल एस पी के पास जाती है, फिर एस पी के पास जाती है, तब जाकर एफ आर मंजूर होती है। आपका जो सजेशन था कि इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। मैं भी विभाग को लिखूंगा कि चोरी के मामले में खास तौर पर मॉनिटरिंग की जाये। साहब, कई बार क्या होता है, चालान तैयार है, चालान पेश करने के लिए बाकायदा पी एस आई और इन्चार्ज या थानेदार कोर्ट में जाकर खड़ा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

होता है और कोर्ट तारीख दे देती है। चालान पेश करने के लिए अदालतों के द्वारा कई बार दो-दो, पांच-पांच तारीखें दे दी जाती हैं, महीने-दो महीने की, तो उसमें भी दिक्कत आती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कहता हूं कि जिसके यहां भी चोरी होती है, उसके मन की पीड़ा वही समझता है। आप जो पेंडेंसी बता रहे हैं, इन 182 केस में से 0.7 परसेंट पेंडेंसी, मतलब एक केस की पेंडेंसी है। आपने 53 का चालान पेश किया है। इसका मतलब 90 केस ऐसे हैं, 90 होंगे, 89 होंगे, परसेंटेज के हिसाब से। 89 केसों को आपने बिलकुल खतम करके डाल दिया। मेरा कहना यह है कि इन केसों को, विशेषकर चोरी के प्रकरण में इसको रफा-दफा नहीं करना चाहिए। इसको पेंडिंग छोड़ना चाहिए। मान लो इससे कभी भी चोरी खुल जाये, कहीं भी सात साल बाद भी खुल जाये तो कम से कम जिसका सामान गया है, उसको सामान लेने में सुविधा रहती है, नहीं तो ऐसे खतम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी में पदस्थापित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

90. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित अनेक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्तियों पर लगा रखा है? यदि हां, तो संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्तियों पर लगे कर्मचारियों के आदेश निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर अन्य स्थानों पर नहीं लगा रखा है।

(2) प्रश्नोत्तर भाग 1 के अनुसार।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि खैरावाद पंचायत समिति के श्री रमीश रजा, अहमद रजा,

(श्री मदन दिलावर)

शाहिद खान, सीमा स्वामी, अब्दुल सलाम मिर्जा, राजकुमार मालव, मनोज कुमार, आशा मोदी, कुलदीप चौधरी, मधु सहगल, ये शिक्षक गैर-शैक्षिक एवं शैक्षिक कार्यों में किस-किस शिक्षा सत्र में कहां-कहां कार्यरत रहे, इसकी सूची सदन के पटल पर रखकर सदन को बतायें।

श्री अध्यक्ष: ये कह रहे हैं कि जी नहीं, तो कहां से लायेंगे?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरे पास है। मेरे पास जानकारी के अनुसार है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि रमीश रजा, शाहिद खान, अब्दुल सलाम मिर्जा और आशा मोदी, ये जिला कलेक्ट्रेट, कोटा के आदेश से चुनाव निर्वाचन के लिए मतदान की नामावली के लिए लगा रखे थे, लेकिन इनको वहां से कलेक्टर ने 31 तारीख को हटा दिया। पहली बात तो यह है कि प्रतिनियुक्ति पर नहीं थे, वे कार्य-व्यवस्थार्थ लगाये गये थे और लगाये जा सकते हैं। चुनाव आयोग को हम मना नहीं कर सकते हैं। आपके यहां 2335 स्वीकृत पद हैं, उनमें भी एक भी व्यक्ति नहीं लगा हुआ है। आपने जो चार के अलावा नाम पढ़े हैं, वे आपकी रामगंज मण्डी के नहीं हैं। उनको भी रिलीव करके सम्बन्धित स्थानों पर लगा दिया है। मेरे पास आदेश की प्रति है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि ये प्रतिनियुक्ति पर कहां-कहां, कब-कब कार्यरत रहे? सदन को इतना बता दें, जिनके नाम मैंने बोले हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): रमीश रजा जिला कलेक्ट्रेट में 12.09.2022 से कार्यरत है। शाहिद खान 20.07.2022 से, अब्दुल सलाम मिर्जा 22.09.2022 और आशा जी 24.01.2022 से कार्यरत थीं, लेकिन आज की तारीख में वे कार्यरत नहीं हैं। उनको कार्य-व्यवस्थार्थ लगाया गया था और कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, आपका भी अनुभव है और मेरा भी अनुभव है। आप केवल जांच करा लें, कई शिक्षक इसी तरह से, उनका आर्डर निकलता है कि वह कहां काम करेगा। अगर आपके किसी अधिकारी के आदेश से वे वहां पर काम करते हैं, कर रहे हैं तो प्रतिनियुक्ति है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

या नहीं है? अगर है और आपका जवाब ठीक नहीं हुआ तो इसके लिए वह अधिकारी, जिसने यह उत्तर बनाकर भेजा है, वह इसके लिए दोषी है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिनियुक्ति वह कहलाती है, जिस विभाग में अपन लगाते हैं तो उस विभाग के द्वारा उसकी तनख्वाह दी जाती है और चुनाव वगैरह की ड्यूटी में जिसको हम लगाते हैं, वह कार्य-व्यवस्थार्थ लगाते हैं, उनके पैसे का भुगतान सम्बन्धित मूल विभाग ही करता है, इसलिए उसको कार्य-व्यवस्थार्थ कहते हैं। प्रतिनियुक्ति में, मान लीजिये कि आज मंत्रियों के पास कोई प्रतिनियुक्ति पर है तो उसका भुगतान सचिवालय करेगा। किसी भी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो सम्बन्धित विभाग के द्वारा उसकी तनख्वाह दी जाती है। कार्य-व्यवस्थार्थ और प्रतिनियुक्ति में यही फर्क है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं कि आपने ये जो नाम पढ़े हैं, आप केवल इनके बारे में जांच करवा लें कि ये वहां पर किसी आदेश से गये हैं या कलेक्टर ने मांगे हैं, इसलिए बिना आदेश के ही वहां रवाना कर दिये?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): मैंने आपको बताया था कि आदेश दिये गये थे। जिला कलेक्ट्रेट, कोटा ने 04.11.2022 को, शाहिद खान का 19.07.2022 को, अब्दुल सलाम मिर्जा का आदेश 21.09.2022 को दिया था। आशा जी का आदेश डायरेक्टर ने 18.01.2022 को दिया था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रश्न के लगने के बाद इनको वहां से रवाना किया तो क्या काम खतम हो गया था?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन नामावलियों का कार्य जनवरी में होता है, वह खतम हो गया था। हमने 30 जनवरी को चिट्ठी लिखी, 31 को उनको वापस भेज दिया गया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि चुनाव व्यवस्थार्थ लगाये थे, यह गलत है। मेरे पास एक मनोज कुमार हैं, ये बस्सी में लगाये हुए हैं। आशा मोदी बीकानेर में लगायी हुई हैं। कुलदीप चौधरी प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कोटा में लगाये हुए हैं। ये चुनाव के लिये नहीं लगाये गये हैं। मैं और भी नाम बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने-कितने समय रहे? इन्होंने जो तारीख बतायी, वह लास्ट की बतायी। सब टुकड़ों-टुकड़ों में तीन-तीन, चार-चार साल से प्रतिनियुक्तियों पर हैं। हमारी शिक्षा सफर कर रही है, बच्चे सफर कर रहे हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि इनके यहां टोटल 2335 व्यक्ति कार्यरत हैं, उनमें से मात्र 4 व्यक्ति कार्य-व्यवस्थार्थ लगाये थे। आशा जी हैं, उनको शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग में ही लगाया हुआ था। निदेशक ने अपने काम से लगाया हुआ था। शिक्षा विभाग तो अपने काम से किसी को लगा ही सकता है। केवल मात्र चार व्यक्ति लगे हुए थे। जैसे ही निर्वाचन का काम खतम हुआ, हमने चिट्ठी लिखी और उनको कलेक्टर ने रिलीव कर दिया। जो नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 है, इसकी धारा 27 में जो भी दस वर्षीय जनगणना, आपदा प्रबन्धन, चुनाव कार्यों, पल्स पोलियो अभियान के लिए इनको लगाने की छूट है। इसके साथ-साथ इसमें समय-समय पर 21.06.2019, 06.09.2019, 14.11.2019, 05.08.2020 को मुख्य सचिव ने और उसके बाद 09.12.2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) ने बार-बार परिपत्र जारी कर कलेक्टर्स और सभी को कहा है कि जैसे ही काम खतम हो, इनको तत्काल रिलीव करके भेज दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. प्लीज आप बैठें, I will not allow it. प्लीज, लिमिट होती है।

गंभीरी नदी के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्ययोजना

91. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ शहर में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी गंभीरी के बहाव क्षेत्र में भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त नदी के बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(2) क्या सरकार शहर की विभिन्न नदियों के बहाव क्षेत्र को भू-माफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी नहीं। नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ एवं नगर परिषद्, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्राधिकार में गंभीरी नदी के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण होना नहीं पाया गया है।

(2) जी हां। राज्य सरकार नदियों के बहाव क्षेत्रों में होने वाले अतिक्रमण को हटाने एवं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कृत संकल्पित है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, गंभीरी नदी के बहाव क्षेत्र खसरा नंबर 1719 एवं 1722 के मध्य निजी खातेदारों द्वारा नाले एवं बहाव क्षेत्र में अनधिकृत कब्जा व अतिक्रमण कर रखा है। क्या सरकार उक्त अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय, एक प्रश्न हो गया है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि नदी के बहाव में आने वाली भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। जो भी निर्माण कार्य है या जो सड़क बनाई गयी है, वह प्राइवेट खातेदारों के या नगर परिषद् की जमीन पर या नगर विकास न्यास की जमीन पर बनाई गयी है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, वहां धरना चल रहा है, ज्ञापन हुए हैं। मैंने आपको खाता नंबर दिया है। वहां बहाव क्षेत्र में पूरे शहर का मैटर है, थाने में केस दर्ज हुआ है उसका, मैं इतना कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी भी उतनी ही गंभीरता से दे रहे हैं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या यह सही है कि नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण द्वारा अवैध पुलिया का निर्माण कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार नदी के बहाव क्षेत्र में निर्मित उक्त अवैध पुलिया का निर्माण हटाने का विचार रखती है या नहीं रखती है? क्योंकि कोतवाली में 22 तारीख को इसकी एफ आई आर दर्ज हुई है। रात को मैंने एक बजे तक बैठकर इसकी एफ आई आर दर्ज करवाई है और निजी आदमियों ने वहां निकलने के लिए बनाई है, मैं इतना कह रहा हूं आपको।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने ही यह बताया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। मंत्री जी, नहीं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कलेक्टर से भी रिपोर्ट मंगवा ली है। यह कलेक्टर की भी रिपोर्ट आ गयी है। जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा तीन आदमियों की एक कमेटी बनायी गयी है। इसमें एक नगर परिषद् का आदमी था, एक नगर विकास न्यास का था और एक राजस्व विभाग का था। आपकी शिकायत पर उनसे पूरा सर्वे करवाया गया। उस शिकायत के अनुसार उन्होंने साफ-साफ यह लिख दिया कि 1727 रकबा 3.78 ये जो किस्म है, ये नदी के नाम पर दर्ज है। अब इसके अलावा मौके पर मुस्तकीम बिन्दु से नदी के किनारे पर जो कार्य किया गया, नदी के नाम पर दर्ज खसरे में किसी भी प्रकार अतिक्रमण नहीं पाया गया। यह रिपोर्ट कलेक्टर की है। कलेक्टर यू आई टी का चैयरमेन है, कलेक्टर भी है। आप ही के कहने पर यह सारी रिपोर्ट मंगवाई और आप कहते हैं तो मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ देता हूं कि यह है क्या। मौका जांच के अनुसार नदी से लगती हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इतना काफी है। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, हो गया। आप बैठिए प्लीज।

श्री जगसी राम।

रेवदर में वन विस्तार योजना हेतु स्वीकृत बजट

92. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर से जुड़े वनों के विस्तार हेतु प्रदेश में संचालित वन विस्तार योजनाओं के लिये विगत चार वर्षों की अवधि में बजट की स्वीकृति नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वन विस्तार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त बजट को उक्त वर्षों के दौरान खुर्द-बुर्द करके खानापूर्ति कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? उक्त के लिये किन-किन संवेदकों एवं अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अवधि के दौरान वन विस्तार कार्यों में की गई अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच टीम के साथ स्थानीय वन एवं

(श्री जगसी राम)

पर्यावरणविद् तथा संस्थाओं से भी भौतिक सत्यापन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रेवदर में वर्ष 2018-19 से अभी तक विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत विभाग द्वारा किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) विभाग द्वारा सामान्य प्रक्रिया के तहत कुछ कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन कराया जाता है। विधान सभा क्षेत्र रेवदर में विभाग द्वारा कराये गये भौतिक सत्यापन/मूल्यांकन का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत रेवदर विधान सभा क्षेत्र में 2019-20, 2020-21 व 2022-23 के अन्दर सभी में एक नये पैसे का काम नहीं हुआ है। एक तरफ सरकार ने बताया कि हम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना नाबार्ड के तहत और विभिन्न योजना के तहत, हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि सरकार हमारे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्दर वन क्षेत्र के अन्दर काम करवाना चाहती है या नहीं चाहती है? नंबर दो, मंत्री महोदय, आपसे ये जानना चाहूंगा कि नाबार्ड सिरोही मूलिया मगरी पर आपने पौधारोपण का 10 हजार का जो आकलन बताया है और दूसरे मौके पर बताया 10002, 49.27 परसेंट बताया है, यह कौनसा आंकड़ा है? मंत्री महोदय बताएं। नंबर तीसरा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दो प्रश्न हो गये हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, सबके दिये हैं, जो बजट आबंटन हुआ और व्यय हुआ। ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का कह रहे हैं उसमें 2018-19 में हुआ और उसके बाद में कोई खर्चा नहीं हुआ। यह योजना ही बंद हो गयी। जब योजना ही बंद हो गयी तो पैसा ही नहीं मिल रहा है और

(श्री हेमाराम चौधरी)

पैसा ही नहीं मिल रहा है तो खर्चा होने का सवाल ही नहीं है। इसी तरह से जितनी भी ये 13 योजनाएं हैं, 13 योजनाओं में जब-जब भी पैसा मिला है, उसमें व्यय हुआ है। वह आगे दर्शा दिया गया है। जब पैसा ही नहीं मिला, योजना ही बंद हो गयी तो फिर उसमें काम होने का सवाल ही नहीं है।

श्री जगसी राम (रेवदर): मंत्री महोदय, ये जो दूसरी योजना चालू है, यह आप बता दें कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आपने कौन-कौन से काम स्वीकृत किये और कौन-कौन से काम वर्तमान में चालू हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): ये नाबार्ड फेज III..

श्री जगसी राम (रेवदर): उसके अलावा जो सारी योजनाएं हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कहां जाएंगे? क्या प्रश्न है?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): मैंने कहा कि आपको मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन में पैसा नहीं मिला। 2018-19 में हुआ, उसके बाद में न कोई पैसा मिला, न खर्चा हुआ। नाबार्ड है, उस नाबार्ड के तहत मैं आपको बताऊं कि इसमें पैसा मिला है, उसके हिसाब से नाबार्ड फेज III, उसमें 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में मिला है। 2022-23 में नहीं मिला है। जो पैसा मिला है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, यह तो रिकार्ड पर है। अगला प्रश्न।

श्री जगसी राम (रेवदर): मंत्री महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक प्रश्न।

श्री जगसी राम (रेवदर): मंत्री महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि क्षेत्र के अन्दर काम जो हुए हैं, उसमें क्वालिटी और काम घटिया जो हुए हैं, खुर्द-बुर्द जो किए हैं, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं आबू रोड क्षेत्र के अन्दर बहादुरपुरा के अन्दर मूलिया मगरी, जो वन विभाग के द्वारा चारदीवारी बनाई गयी है, उसके अन्दर जो घटिया काम हुआ है, उसकी आप पुन: जांच करवा कर, उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवाएंगे क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): आप बता देना, मेरे विभाग के जिस अधिकारी से आप जांच करवाना चाहें, उस अधिकारी से कमेटी बनवाकर के जांच करवा देंगे। जांच करवाने को तो मैं तैयार हूं। अगर घटिया काम हुआ है तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, क्या सिस्टम करना चाहते हैं? अगला प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा। एक मिनट संयम जी, कटारिया जी बोलना चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, आपने दो चार्ट दिए हैं। एक परिशिष्ट 'अ' दिया है, एक परिशिष्ट 'ब' दिया है। 'अ' में आप कह रहे हैं कि नाबार्ड फेज-2 में भी आपको 4 लाख 91 हजार रुपया मिला, नाबार्ड फेज-3 में आपको 6 लाख 77 हजार रुपया मिला और नाबार्ड फेज-4 में आपको मिला है 23 लाख रुपया। ये सब आप बता रहे हैं और आप जो खर्चा बता रहे हैं वह केवल नाबार्ड-3 का खर्चा आप बता रहे हैं, वह भी नहीं है तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है, वह तो इसमें पूरा नहीं करता है। उन्होंने पूछा जो मूल्यांकन करने वाली एजेंसी है, नाबार्ड का ही मूल्यांकन करते तो फेज-2, फेज-3 और फेज-4, चारों में जो काम हैं, उसमें आप हमको उत्तर केवल फेज-3 का दे रहे हैं तो फेज-2 और फेज-4 का कहां है?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): नहीं, नाबार्ड का फेज, मैंने कहा कि ये 2021-22 और 2022-23 में है। पैसा मिला ही नहीं तो कहां से दें?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपका चार्ट बता रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): ये जो नाबार्ड है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड, आप विराजिए, मैं बताऊं आपको।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, एक मिनट रुकिए। मंत्री जी।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): परिशिष्ट 'ब' पर इसका मूल्यांकन दिया हुआ है। आपने परिशिष्ट 'अ' देखा, परिशिष्ट 'ब'..।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, जो आपने 'ब' में दिया है, उत्तर का परिशिष्ट 'ब' देखिए, उसमें आपने नाबार्ड-3 का ही दिया है। वे यह कह रहे हैं कि अलग फेज में भी पैसा आया है, उसका भौतिक सत्यापन हुआ या नहीं हुआ? ये उसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं। आपने जो उत्तर दिया केवल नाबार्ड-3 का दिया है, संलग्न परिशिष्ट 'ब' में, जबकि नाबार्ड फर्स्ट और सैकण्ड में भी पैसा आया, उसमें सत्यापन हुआ या नहीं हुआ है?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): हुआ है। यह हमारा मूल्यांकन विभाग है, प्रबोधन एवं मूल्यांकन विभाग, उसके द्वारा सब का मूल्यांकन हुआ है।

श्री अध्यक्ष: फिर थर्ड का ही क्यों दिया? उत्तर में सबका आना

(श्री अध्यक्ष)

चाहिए। संलग्न जो आपने उत्तर दिया, आपका जवाब देखें जो आपने दिया है, आपका जो 'ब' पार्ट है, उसमें केवल नाबार्ड थर्ड का ही लिखकर भेजा है। यह आप ही का उत्तर है। फिर जो नाबार्ड फर्स्ट और सैकण्ड, उसका जो पैसा आया, उसका सत्यापन हुआ या नहीं हुआ, उसकी जानकारी चाह रहे हैं।

श्री जगसी राम (रेवदर): यह उत्तर अधूरा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। आप बैठे। आपको उत्तर नहीं सुनना तो मैं अगला प्रश्न ले लूंगा। इतनी गम्भीरता से ले रहे हैं और आप खड़े हो रहे हो बीच में।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माननीय सदस्य ने कहा पैसा खर्च नहीं हुआ, मैंने कहा, माननीय सदस्य बताएं, उस अधिकारी से कमेटी बनाकर जांच करवाने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। आप बैठें, प्लीज। आप भाग संख्या-तीन का उत्तर देखें। आपने उत्तर दिया, तीन देखें आप। तीन में आपने लिख रखा है संलग्न 'ब'। 'ब' देखो, खोलो पीछे, उसमें नाबार्ड थर्ड का ही लिख रखा है। प्लीज, देखो उसमें। उसके अलावा, नाबार्ड फर्स्ट और सैकण्ड में भी पैसा आया। उसका भौतिक सत्यापन हुआ या नहीं हुआ, यह पूछ रहे हैं। इसमें नाबार्ड थर्ड का ही भौतिक सत्यापन है।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): उसके भौतिक सत्यापन की जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। अगर जांच की बात है तो जांच करवा दूंगा। जहां तक मूल्यांकन है, प्रबोधन एवं मूल्यांकन विभाग है, उसके द्वारा उसका मूल्यांकन होता है, वह रेण्डम सिस्टम से होता है। उसमें सारे कामों का नहीं हो सकता, उसमें जो काम रेण्डम के हिसाब से आते हैं, उसके हिसाब से होता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि न तो प्रश्न को पढ़ते हैं। फेज-4 में 2020-21 में इनको 12 लाख रुपये मिले, 2021-22 में इनको 8 लाख 56 हजार मिले। 2022-23 में इनको 1 लाख 92 हजार मिले और इस फेज-4 में इनके 23 लाख 35 हजार, 263 रुपये मिले। यह अकाउंट दे रहे हैं, यह केवल फेज-थ्री का दे रहे हैं, 6 लाख का। बाकी इतना बड़ा अमाउंट है, वह भी 2020-21 से शुरू हुआ फेज चार, उसका कोई हिसाब इसमें यहां नहीं दे रहे हो। यह प्रश्न का उत्तर या तो सच में जांचते समय ही कर दिया या विभाग इसमें ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दे पा रहा है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि इसको स्थगित करके विभाग से दुबारा उत्तर मंगाकर, आप जब भी चाहें तब इसको लगाएं। तब इसका स्पष्ट होगा कि पैसे का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): सभी कामों का मूल्यांकन नहीं होता है। थर्ड का ही हुआ है। पहले का मूल्यांकन नहीं हुआ तो उसका मूल्यांकन करवाने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: वे कह रहे हैं पहले का मूल्यांकन नहीं हुआ इसलिए। अगला प्रश्न। संयम लोढ़ा।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): जिसका मूल्यांकन हुआ उसकी सूचना दी आपको। जिसका मूल्यांकन नहीं हुआ है उसका आप चाहते हो तो मूल्यांकन करवा देंगे। अभी भी मूल्यांकन हो सकता है। आप जांच चाहते हैं, तो आप बता देंगे उस अधिकारी से जांच करवाने के लिए तैयार हैं। जिस अधिकारी में आपको विश्वास है मेरे विभाग में, उस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर, जांच करवाने के लिए तैयार हैं। जांच करवा देंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। संयम लोढ़ा।

अणगौर व आड़ा बांध के सुदृढ़ीकरण की कार्ययोजना

93. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बतीसा नाला सिंचाई परियोजना का कार्यादेश कब जारी किया गया? क्या यह सही है कि उक्त परियोजना का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ है? यदि हां, तो उक्त में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा अब तक कितना कार्य हो गया है व कितना होना शेष है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) जवाई पुनर्भरण के तहत जिला उदयपुर में स्वीकृत दो बाधों का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा?

(3) अणगौर एवं आड़ा बांध के सुदृढ़ीकरण का कार्य कब तक स्वीकृत किया जाएगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) बतीसा नाला सिंचाई परियोजना का कार्यादेश दिनांक 06.10.2018 को जारी किया गया।

(जल संसाधन मंत्री)

परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण का कार्य वर्तमान में पूर्ण नहीं हुआ है। बांध के निर्माण स्थल पर 14 ब्लाक में से 5 ब्लाक में स्थित सड़क के वैकल्पिक मार्ग का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 18.11.2021 को पूर्ण किया गया, जिसके कारण इन 5 ब्लाक में कार्य, वैकल्पिक मार्ग निर्माण के बाद ही प्रारम्भ हो सका। वर्ष 2020 एवं 2021 में कोविड-19 के कारण भी निर्माण कार्य में बाधा रही। वर्तमान में बांध का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 25 प्रतिशत कार्य किया जाना शेष है। प्रेशर स्प्रिंकलर सिस्टम की निविदा मार्च, 2023 में आमंत्रित की जानी प्रस्तावित है।

(2) जवाई बांध पुनर्भरण के तहत उदयपुर जिले में स्वीकृत दो बांधों की निविदा दिनांक 25.01.2023 को आमंत्रित कर ली गई है एवं निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

(3) अणगौर बांध के सुदृढ़ीकरण की डी पी आर भारत सरकार को भेजी थी, वह 31 तारीख को प्राप्त हो चुकी है तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

ओडा बांध के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रुपये 47.59 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी है। जैसे ही वह प्राप्त हो जाएगी, इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-प्रथम का उत्तर दिया है, वह वास्तविकता से परे है। नम्बर वन, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतनी जानकारी चाहता हूं कि आई आई टी से जो डिजाइन अप्रूव होकर आई जिस तिथि को, उसके बाद आपके जोधपुर कार्यालय में कितने महीने पड़ी रही?

नम्बर टू, बतीसा नाला में इस साल बरसात के समय, किस लेवल तक पानी रोक लेंगे? दूज और साड़मारिया का काम इस साल किस महीने में चालू करेंगे?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जून से पहले-पहले बतीसा नाला का पानी रोक लिया जाएगा। 75 परसेंट तो हो गया है, तीन महीने और काम करेंगे, 80-85 तक पहुंच जाएगा। जितना बांध बांध लिया जाएगा, उतना पानी हम इस बार जून महीने में रोक लेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह।

वल्लभनगर में सहकारी समितियों की स्थापना

94. श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो इसके खोले जाने के क्या प्रावधान हैं?

(2) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में कितनी ग्राम पंचायतें सहकारी समितियों से वंचित हैं?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में नवीन सहकारी समितियों की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति के गठन का प्रयास किया जाता है। जी.एस.एस. के गठन के निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

1. न्यूनतम सदस्य संख्या- 300,
2. हिस्सा राशि- 3 लाख रुपये,
3. अमानत- 1 लाख रुपये जी.एस.एस. हेतु एवं 75 हजार रुपये लेम्पस हेतु।

उपरोक्त निर्धारित मानदंड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की कार्यवाही की जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में कुल 71 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 38 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाना शेष है।

(3) जी हां। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के तहत आगामी 2 वर्षों में राज्य के 4171 शेष ग्राम पंचायतों में नई जी.एस.एस. का गठन किया जाएगा। उक्त घोषणा के तहत विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के शेष ग्राम पंचायतों में भी नई जी.एस.एस. स्थापित की जाएगी।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि वर्ष 2022-23 बजट

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

घोषणा के तहत राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों में नई जी.एस.एस. का गठन किया जाएगा, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि आपने इसमें आगामी दो वर्षों के लिए कहा है। हमारी सरकार के कार्यकाल के मात्र 6 से 8 माह बाकी रह गए, तो आप दो वर्ष में इसे कैसे पूर्ण कराएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं। माननीय सदस्य, उनकी भावना को सुन सकते हो, जो उनकी भावना है। (व्यवधान)

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): माफी चाहती हूं, आठ महीने रह गए तो आप इसे कैसे पूर्ण कराएंगे? (व्यवधान) आप आठ महीने में इसे कैसे पूर्ण कराएंगे? साथ ही, आपने इस विभाग द्वारा इसका कितना प्रचार-प्रसार किया है? हमारी 38 समितियां शेष हैं, इन्हें अतिशीघ्र पूर्ण कराने के लिए विभाग को निर्देश दीजिए।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): घोषणा सरकार द्वारा की जाती है, किसी पार्टी द्वारा नहीं की जाती, इसलिए यह क्रम जारी रहेगा। सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं जो भी जीएस.एस. खोलना चाहें, क्राइटेरिया पूरा कर दें तीन लाख रुपये और तीन सौ सदस्य, मैं उसी दिन खोलने की घोषणा कर दूंगा। इनके यहां दो जी.एस.एस. जो 6 महीने से नहीं खुल रहे थे, उनको आज खोल दिया गया है और डिले करने के कारण अधिकारियों को नोटिस दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। ज्ञानचंद पारख।

रोहट (पाली) में अतिवृष्टि से फसल खराबे का मुआवजा

95. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली की रोहट तहसील में वर्ष 2020 से 2022 तक अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि से फ़सलों का कितना-कितना प्रतिशत खराबा दर्शाया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त अवधि में किस-किस गांव में किस-किस वर्ष कितनी-कितनी राशि का काश्तकारों को अनुदान दिया गया एवं कितनी राशि का अनुदान दिया जाना शेष है तथा शेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) पाली ज़िले

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

की रोहट तहसील में वर्ष 2020 से 2022 तक बाढ़ से एवं वर्ष 2020 व 2022 में सूखे से फसल खराबा शून्य है तथा वर्ष 2021 (सम्वत् 2078) में सूखे से फ़सलों में 100 प्रतिशत खराबा हुआ है।

(2) तहसील रोहट में ख़रीफ़ फसल वर्ष 2021 (सम्वत् 2078) में सूखे में प्रभावित कुल 22,274 काश्तकारों में से 21,333 प्रभावित काश्तकारों को राशि रुपये 2093.53 लाख का कृषि आदान-अनुदान भुगतान किया जा चुका है।

शेष 941 काश्तकारों के भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 2020 व 2022 में सूखे या बाढ़ से कोई खराबा नहीं हुआ जबकि 2020 व 2022 में, माननीय मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कुछ पैसा यहां के प्रभावित काश्तकारों को मिला है और आपने खराबा शून्य बताया। अगर शून्य खराबा होता तो बीमा का पैसा नहीं मिलता इसलिए इसमें कहीं न कहीं विसंगति है। आपने 2021 में फसल में 100 प्रतिशत खराब बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा उसमें नहीं मिल रहा। फसल वह की वह है, इलाका वह का वह। एक एजेंसी है वह तो बता रही है कि खराबा हुआ, दूसरी एजेंसी बता रही है कि खराबा नहीं हुआ। कहीं न कहीं किसानों को इससे नुकसान होता है। कृपया, इस मामले को आप देखें कि किन वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा काश्तकारों को मिला है और किस आधार पर मिला है। हो सकता है कि आपके अधिकारियों ने जो गलत रिपोर्ट दी है उसको दुरुस्त करके उस प्रभावित काश्तकार को अपन लाभ पहुंचा सकें, एक तो मेरा यह आग्रह है। दूसरा मेरा आग्रह आपसे यह रहेगा कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न नहीं है, खाली आग्रह ही है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): प्रश्न है न। यह कहा है न मैंने।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न हो तो बता दें। आप कभी प्रश्न करते ही नहीं हैं, हर बार आग्रह ही कर रहे हो आप।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): नहीं, प्रश्न भी किया है।

श्री अध्यक्ष: आप ऐसे पूछो न कि क्या यह करोगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): यह पता लगा था। यह कहा है न, यह प्रश्न भी किया है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि यह आपके 2021 के 941 काश्तकारों को भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 2021 के बाद में 2022 पूरा चला गया है तो ये जो 941 काश्तकार हैं, उनको पैसा कब तक मिल जायेगा? यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

मेरा तीसरा प्रश्न है कि हर वर्ष आपके काश्तकारों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है जबकि वह की वह तहसील है। कभी आपके 20,536 हो जाते हैं, कभी आपके 21,554 हो जाते हैं तो कभी आपके 22,274 हो जाते हैं। आजकल तो सारा सिस्टम ही ऑनलाइन हो गया है। आप सारे काश्तकारों को ऑनलाइन एक बार करवा दोगे तो स्वत: ही एक बटन दबाते ही आपका सारा का सारा पैसा उसमें चला जायेगा, वरना होता क्या है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अजीब हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक मिनट। आप इनको ऑनलाइन करोगे क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जवाब दें। आप खुद ही प्रश्न पूछते हैं और खुद ही उत्तर देते हैं। मंत्री के पास तो कोई स्कोप ही नहीं बचता है। ऐसे कैसे होगा? माननीय मंत्रीजी।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहट तहसील में वर्ष 2021 में सूखे से प्रभावित भुगतान से शेष रहे 779 किसानों के डी.एम.एस. पोर्टल पर बिल जनरेट करके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। शेष 162 काश्तकारों के बैंक खाता सही करवाकर शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायेगा। कई बार क्या होता है कि एक भी खाता यदि गड़बड़ होता है तो बैंक वाले वापस लौटा देते हैं इसलिए हमने 779 के काम चालू कर दिये, जल्द पेमेंट उनका मिल जायेगा और 162 के लिए तहसीलदार को पाबंद कर दिया है कि वे भी यह तुरंत भुगतान करें।

जहां तक फसल बीमा और हमारा सवाल है, हमारा अलग है कि 33 परसेंट खराबे के बाद ही हमारे जो नियम हैं, केन्द्र सरकार के द्वारा जो बनाये हुए हैं, उसी के तहत हम लोग देते हैं जो जिस तरह से आंकड़े आते

(श्री गोविंद राम)

हैं। फसल बीमा की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका और इसका अलग-अलग है। उसमें वे कम्पनियां पेमेंट करती हैं और यह सरकार करती है, यह फर्क है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

अलवर से भरतपुर वाया सैमलाखुर्द रोडवेज बस का संचालन

96. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार अलवर से बगढ़ तिराहा, रामगढ़ (अलवर) वाया सैमलाखुर्द होते हुए भरतपुर तक रोडवेज बस संचालित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण प्रश्नगत मार्ग पर बस संचालन किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रूट है यह नेशनल हाईवे है, प्लस एक्सप्रेस हाईवे है उसका एक कट भी इसी रोड पर आ रहा है तो मुझे लगता है कि यहां बस की बहुत अधिक आवश्यकता है। क्या संसाधन प्राप्त होने के बाद मंत्रीजी, आप इस रूट पर अधिक बस लगा देंगे?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सैमलाखुर्द की बात माननीय सदस्या कर रही हैं, हमारी बगढ़ तिराहा से भरतपुर 38 सेवाएं चलती हैं और बगढ़ तिराहे से रामगढ़ होकर दिल्ली 25 सेवाएं चलती हैं। सैमलाखुर्द हम उन बसों में से कुछ बसों को डाइवर्ट कर सकते हैं, पर हमारे साथ दिक्कत एक यह है कि सैमलाखुर्द से मोर का प्लाजा अगर हम बस लायें तो एक बीच में धांधोली गांव पड़ता है जिसमें बस नहीं निकल पाती है। माननीय सदस्या, मैं अधिकारियों को भेज दूंगा, आप कोई ऐसा रास्ता बता दें कि वहां से बस आ सके तो हम जो भरतपुर हमारी बसें जा रही हैं 38 सेवाएं, उनमें से दो-तीन सेवाएं उस गांव से होकर हम कर सकते हैं। हमारी बसें निकल नहीं पाती हैं तो उसका कोई अल्टरनेटिव माननीय सदस्या बता दें तो मैं अधिकारियों को भेज दूंगा और हम वहां से बस संचालित करने की व्यवस्था करवा देंगे बशर्ते बस वहां से निकल सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता

97. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्ष 2022 में औसतन बेरोजगारी की दर क्या रही तथा बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी व औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से नियोजन किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक?

(3) प्रदेश में माह जनवरी, 2021 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने बेरोजगार पंजीकृत थे? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) विभाग द्वारा औसतन बेरोजगारी की दर के आंकड़ों का संधारण नहीं किया जाता है, तथापि बेरोजगारी को दूर करने हेतु रोजगार विभाग के स्तर पर रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। जिसके तहत विभाग द्वारा जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 244 जॉब फेयर्स का आयोजन कर 27,687 बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए प्राथमिक रूप से चयनित कराया गया है।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक 24,011 आशार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा कर उन्हें रोजगार के लिए योग्य बनाया गया जिनमें से 8,073 आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

निदेशालय, प्रशिक्षण (प्राविधिक शिक्षा) द्वारा वर्ष 2022 में 1,82,835 युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर उन्हें रोजगार के लिए योग्य बनाया गया तथा 7,151 आशार्थियों ने इस अवधि में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में जॉब प्राप्त किया है।

(2) इस विभाग के स्तर पर वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)

(3) विभाग के पोर्टल पर माह जनवरी, 2021 से माह दिसम्बर, 2022 तक 3,19,895 बेरोजगारों द्‌वारा पंजीयन कराया गया है। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, आपने यह कहा कि बेरोजगारी दर के आंकड़े सरकार के द्‌वारा संधारित नहीं किये जाते। सदके जाऊं आपको और आपकी सरकार को।

क्या यह सही है कि सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के राजस्थान प्रदेश के लिए समय-समय पर बेरोजगारी के आंकड़े जारी किये गये? यह आपके संज्ञान में है? क्या यह भी सही है कि बेरोजगारी के आंकड़े जो दिसम्बर, 2022 में जारी हुए उसमें 28.5 प्रतिशत बेरोजगारी है? यह आपके संज्ञान में है?

खण्ड-2 में आपने यह कहा कि सरकार के पास स्थानीय बेरोजगारों को सरकारी और औद्‌योगिक क्षेत्रों में नियोजन की प्राथमिकता से नियोजन करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तो क्या यह सही है कि देश के कई राज्यों में, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु में स्थानीय युवाओं को रोजगार में तरजीह देने की नीति बना रखी है? क्या आप भी अपने जन-घोषणा पत्र के अनुसार इस नीति को बनाना चाहोगे या नहीं? नहीं, तो क्यों?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि आपने जो सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का नाम लिया है, वह कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है। वह एक एन.जी.ओ. है, प्राइवेट संस्था है जो आंकड़े देती है तो सरकार उसको अनुमोदन, हम नहीं कर सकते। वह ऑनलाइन उपलब्ध है, आप वहां से आंकड़े लें तो आपको मुबारक, पहली बात।

दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हैं कि क्षेत्रीय युवाओं को प्राथमिकता देने की क्या कोई पालिसी हम ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार ऐसी मानसिकता रखती है और इसके ऊपर भविष्य में काम किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुलाहिजा फरमायें। इस खण्ड-2 में कहा है कि- 'इस विभाग के स्तर पर वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।' मुझे सदन में ये यह कह रहे हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है और अब कह रहे हैं कि पालिसी ला रहे हैं और मैंने सिर्फ इतना-सा पूछा था कि यह सी.एम.आई.ई. के आंकड़े आपके संज्ञान में हैं क्या? राजस्थान पूरे देश में दूसरे नम्बर पर है बेरोजगारी दर से।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैं माननीय सदस्य को फिर से यह बताना चाहता हूं कि यह सीएम.आई.ई. जो है यह कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है, यह एक एन.जी.ओ. है। ऐसी इस प्रकार की बहुत सारी एन.जी.ओज. काम करती हैं। वे अपने आंकड़े ऑनलाइन डालती हैं। आप वहां से उठायें और बात करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वे तो यह कह रहे हैं कि उस एन.जी.ओ. का आपके संज्ञान में है या नहीं, केवल यही पूछ रहे हैं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): या तो मुझे जवाब देने दें। माननीय सदस्य, आप बहुत सीनियर हैं और हम बहुत जूनियर हैं लेकिन जवाब हम ढंग से देंगे। जिस तरीके से आप सवाल पूछेंगे उस तरीके से यह जवाब मिलेगा।

मैं बिलकुल अपने शब्दों पर से वापस नहीं हट रहा हूं। निश्चित रूप से, आपने यह कहा कि इसके ऊपर कोई काम नहीं चल रहा है, निश्चित रूप से कोई पालिसी, आपने पूर्व के सवाल में सरकार की मानसिकता पूछी है कि क्या सरकार ऐसी मानसिकता रखती है क्या? मैंने कहा कि हां, सरकार ऐसी मानसिकता रखती है और भविष्य में ऐसी पालिसी का निर्माण किया जायेगा तो भविष्य की पालिसी और इस समय की कोई पालिसी के ऊपर काम में, यह दोनों बिलकुल अलग-अलग चीजें हैं और मैं अपना जवाब दे चुका हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अभी खबर मिली कि वह पालतू श्वान टू-बी अब नहीं रहा, मेरी संवेदना है, साहब।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने इंटरव्यू में यह बोला है।

प्रश्न संख्या 98

अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री गोपी चन्द मीणा।

कोटड़ी (भीलवाड़ा) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

99. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा प्रत्येक उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है? यदि हां, तो अब तक किन-किन उप खण्ड मुख्यालयों पर महाविद्यालय नहीं खोले गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी उप खण्ड मुख्यालय पर अब तक राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी नहीं। वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा अर्थात् 'वर्तमान में महाविद्यालय से वंचित रहे उप खण्ड मुख्यालयों पर सम्भावनाओं के परीक्षण हेतु नई नीति लाकर चरणबद्ध तरीके से महाविद्यालय खोले जायेंगे' की गयी है, जिसकी अनुपालना में महाविद्यालय से वंचित उप खण्ड मुख्यालयों पर संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाते हैं।

राजकीय महाविद्यालय से वंचित उप खण्ड मुख्यालयों की सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उप खण्ड मुख्यालय, कोटड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है तथापि उप खण्ड मुख्यालय, कोटड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोलने पर संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय विचार किया जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा अर्थात् वर्तमान में महाविद्यालय से वंचित रहे 45 उप खण्ड मुख्यालयों की सूची परिशिष्ट के रूप में लगायी गयी है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोटड़ी (भीलवाड़ा) में राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए विभाग द्वारा परीक्षण करवाया गया है? क्या सरकार महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: उत्तर आ गया न।

अगला प्रश्न। श्री कालीचरण सराफ।

चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट फोन

100. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो प्रदेश में कितने चिरंजीवी परिवार हैं तथा कितने चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन दे दिये गये हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): राजस्थान सरकार ने बजट 2022 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें लगभग 01 करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इस योजना के तहत तीन साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ मुफ्त स्मार्ट फोन दिये जाने हैं। प्रदेश में 1,37,82,951 परिवार (दिनांक 30.01.2023 तक) पंजीकृत हैं एवं आदिनांक तक किसी भी परिवार की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं दिया गया है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने 2022 के बजट में प्रदेश की 01 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन दिये जाने की घोषणा की थी। दूसरा बजट अब पेश होने वाला है और अभी तक स्मार्ट फोन नहीं दिये गये। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बिना बजटीय प्रावधान के यह घोषणा की थी? यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं दिये गये और अब कब तक दे दिये जाएंगे? किस कम्पनी को स्मार्ट फोन खरीदने के आदेश दिए गए हैं? राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण आया, उसमें भी स्मार्ट फोन के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो क्या आपने इस योजना को निरस्त कर दिया है या नहीं? आप कब तक फोन दे देंगे? इसके लिए अपने जवाब में बतायें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रावधान पूर्व में 1,200 करोड़ का किया। उसके बाद सप्लीमेंट्री डिमाण्ड में 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया और वर्तमान में 2,600 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। इन्होंने यह कहा कि बजट प्रावधान ही नहीं किया। बजट प्रावधान किया हुआ है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। आप और क्या पूछ रहे थे?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं पूछ रहा हूं कि फोन कब तक देंगे? देंगे या नहीं देंगे? घोषणा निरस्त तो नहीं की?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रियाधीन है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, आगे बढ़ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहते हैं। यह बजट घोषणा 2022-23 है और यह पूरा हो जाएगा 01 महीने 26 दिन के बाद। इस बजट की कोई सेंक्टिटी है या नहीं है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): सेंक्टिटी है, अध्यक्ष महोदय। तभी तो बजट प्रावधान किया हुआ है। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में एक तो सेमी कण्डक्टर सिम की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। केन्द्र सरकार के बजट में भी अभी मोबाइल फोन संबंधित करों में संशोधन के प्रावधान वगैरह हुए हैं। यह प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, आगे बढ़ जाएंगे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए प्लीज। अंकित नहीं होगा। गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। सीनियर आदमी हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

उच्चैन (नदबई) में संस्कृत विद्यालय की स्थापना

101. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र नदबई में संस्कृत विद्यालय खोले गए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नगरपालिका उच्चैन में संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) आदेश क्रमांक प.20 (1)शिक्षा-6/2015 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा शून्य नामांकन वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय को स्थानान्तरित कर नंगला जंगी ग्राम पंचायत बारहमाफी, पंचायत समिति उच्चैन में विद्यालय खोला गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(2) नगरपालिका उच्चैन में संस्कृत विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर नवीन विद्यालय खोलने का निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो शून्य नामांकन वाला राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंगला जंगी है, जिसको पिछले दिनों 18 फरवरी, 2022 को स्थानान्तरित किया गया है, उसका बजट कब तक आ जायेगा?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): नंगला में स्कूल खोला गया है। वहां पर बजट वगैरह का प्रावधान कर दिया जायेगा। अध्यापक लगा दिए जायेंगे। इसके साथ-साथ आपने उच्चैन में नयी प्राथमिक शाला मांगी है। उसकी जनसंख्या 8,713 है और आठ किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है। मैं आपके माध्यम से इनको आश्वस्त करता हूं कि उच्चैन में भी प्राथमिक शाला खोल दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 102 स्थगित।

सांगानेर में कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने के प्रकरण

102. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वर्षो में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को कृषि भूमि को अकृषि भूमि यथा आवासीय, कामर्शियल व औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं? जोनवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि भूमि को अकृषि भूमि यथा आवासीय, कामर्शियल व औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए जे डी ए को प्राप्त आवेदनों के संबंध में कितने प्रकरणों में आपत्ति दर्ज हुई हैं तथा अब तक प्राप्त आपत्तियों के अनुसार कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया व कितने लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

जावर माइन्स के खनन क्षेत्र के मलबे का निस्तारण

103. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अमृतलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि जावर माइन्स क्षेत्र की खानों से निकलने वाले मलबे को टीडी नदी व आस-पास ही डालने से उक्त मलबे से पहाड़ खड़े होने के कारण आस-पास रहने वाले लोग व पशु प्रभावित हो रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र के आस-पास ब्लास्टिंग से मकान, स्कूल व सरकारी भवनों में दरारें आ रही हैं तथा हैण्डपम्प व कुओं का पानी प्रदूषित होने से फसलें भी प्रभावित हो रही हैं?

(3) क्या सरकार उक्त मलबे को अन्य स्थान पर एकत्रित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उसकी क्या कार्ययोजना है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी नहीं। खान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम जावर के जावर माइन्स क्षेत्र में खनन कार्य भूमिगत (Under ground) पद्धति से होने के कारण मलबा नहीं निकलता है। भूमिगत खानों से निकलने वाला खनिज अयस्कत् (Ore) बेल्ट कन्वेयर एवं वाहनों के माध्यम से सीधा बेनिफिशियेशन प्लांट को जाता है एवं बेनिफिशियेशन के दौरान उत्पन्न टेलिंग्स को पाइप के माध्यम से निर्धारित स्थल पर सुवैज्ञानिक ढंग से सुखाकर भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित खनन योजना में निर्धारित ऊंचाई के टेलिंग डैम में निस्तारित की जाती है। क्षेत्र की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.01.2023 के अनुसार टीडी नदी या नदी के आस-पास मलबा नहीं पाया गया। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अतः इससे आस-पास रहने वाले लोगों एवं पशुओं के प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

(2) खान विभाग के अनुसार खनन कार्य भूमिगत (Under ground) पद्धति से खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारत सरकार की अनुमति के अनुसार कन्ट्रोल ब्लास्टिंग की तकनीक से होता है। क्षेत्र की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.01.2023 के अनुसार मकान, स्कूल आदि में दरारें आना नहीं पाया गया।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर खनन क्षेत्र के आस-पास स्थित कुओं, नलकूपों, पीजोमेट्रिक वैल के जल के नमूने एकत्रित कर उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। विगत तीन वर्षों में लिए गये नमूनों के विश्लेषण पश्चात् यह पाया गया है जल के नमूनों में पीएच,

(पर्यावरण मंत्री)

लैड, निकल, जिंक, क्रोमियम आदि की सांद्रता पीने योग्य पानी हेतु निधारित मानकों के भीतर या नगण्य (Not Traceable) पायी गई, जबकि कुछ नमूनों में आयरन, कॉपर, टोटल हार्डनेस, टोटल डिजोल्व्ड सोलिड, सल्फेट, फ्लोराइड आदि की सांद्रता पीने योग्य पानी हेतु निर्धारित मानकों से अधिक पायी गई, जिनके लिए भूगर्भीय/नैसर्गिक कारणों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है।

खनन क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र में फसलों पर प्रभाव के संबंध में कृषि विभाग से प्राप्त टिप्पणी अनुसार जावर माइंस के लगभग 1 से 2 किमी. की दूरी में भालडिया, नेवातलाई, सिंघटवाडा, पाडला ग्राम पंचायतें आती हैं। इस क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार किसी विशेष पोषक तत्व की कमी/अधिकता नहीं पाई गई है एवं रबी सीजन में बुवाई की गई चना, सरसों, गेहूं आदि फसलों के अंकुरण, बढ़वार एवं उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं आया है।

(3) खनन कार्य भूमिगत पद्धति से होने के कारण तथा मलबा नहीं निकलने के कारण इसे अन्य स्थान पर एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने जो रिपोर्ट दी है, हाथ से लिखी हुई यह बिलकुल असत्य है। क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु तीन एक्सपर्ट, जो इस खनन क्षेत्र को जानने वाले हों, की टीम बना कर जांच करवायेगी? दूसरा, मेरा यह प्रश्न है कि कब तक करायेगी? समय सहित बतायें। उस क्षेत्र में सिंघटवाड़ा, भालड़िया, नेवातलाई, पाडला और 20 ग्राम पंचायतें आती हैं टीडी नदी के सहारे। डैम से पानी का रिसाव होता है। लगातार हो रहा है, बरसात में भी होता है। उस पानी को पीने से पशु मर रहे हैं। इन्सान नहा नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार का पानी आया है। साबुन नहीं लग पा रहा है और बीमारी फैल रही है। हिन्दुस्तान जिंक के वहां से जो रिपोर्ट दी है, वह सही नहीं है।

(समय: 12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मेरा यही कहना है कि उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करा लें। जो जानते हैं उनकी कमेटी बनाकर जांच करा लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पोल्यूशन बोर्ड के अलावा माइनिंग डिपार्टमेंट और कृषि विभाग, दोनों से इस बारे में रिपोर्ट मंगायी गयी है। आप कह रहे हैं यह रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट तो माइनिंग डिपार्टमेंट की है। इधर कृषि विभाग की भी रिपोर्ट मेरे पास है, जिसके अनुसार फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) प्रदेश में बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं-

i. श्री जोराराम कुमावत,

ii. श्री गोपाल लाल शर्मा,

iii. श्री छगनसिंह,

iv. श्री समाराम गरासिया,

v. श्री जगसी राम,

vi. श्री सतीश पूनियां,

vii. श्रीमती संतोष,

viii. श्री वासुदेव देवनानी।

(2) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रा पर फेल करने का भय दिखाकर अवैध संबंध बनाने के दबाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से नष्ट फसलों का किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में मनरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों के कार्यों का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में गौण कृषि उपज मण्डी समिति, छीपाबड़ौद में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में विधायक मद से निर्मित सभी भवनों का उद्घाटन स्थानीय विधायक से नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में घुमन्तू, घुमक्कड़ व विमुक्त परिवारों को निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवाने के आदेश की पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली शहर के शहीद भगतसिंह कालोनी में पुलिस चौकी स्थापित करवाने के संबंध में।

(9) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सैम से प्रभावित क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(10) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश के संविदाकर्मियों को नियमित करने के संबंध में।

(11) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर शहर को नवीन जिला बनाने के संबंध में।

(12) श्री अभिनेश महर्षि, सदस्य की ओर से प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्याप्त परिलाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में लालच दिखाकर पोंजी योजनाओं में निवेश के नाम पर आमजन से की जा रही ठगी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती अनिता भदेल, श्री प्रताप सिंह, श्री ज्ञानचंद पारख, श्री अभिनेश महर्षि एवं श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

34] नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त-02 फरवरी 2023-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा शहर में बढ़ते अपराध एवं पुलिस प्रशासन से अपराधियों की सांठगांठ के कारण आमजन में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल में सौभाग्य योजना को पुनः प्रारम्भ कर विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में।

(3) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में मुख्य सड़कों पर खुले में बिक रहे मांस-मछली की अवैध दुकानों को अविलम्ब बन्द कराने के संबंध में।

(4) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के हाड़ीरानी महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में ग्राम पंचायतों में नियुक्त अस्थायी सुरक्षा गार्डों के नवीन पद सृजित कर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

(6) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती, 2022 में टीएसपी, नॉन-टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान कर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

(7) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में संचालित उद्योगों से निष्कासित रासायनिक पदार्थों से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से वर्ष 2021 में श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में हुए फसल खराबे का फसल बीमा क्लेम का बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोखा के गांवों की मिसिंग लिंक सड़कें एवं धार्मिक महत्व की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों के ऊपर से जा रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली के विकास कार्यों व योजनाओं में हो रही उपेक्षा के संबंध में।

(12) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से माउन्ट आबू वन्य जीव अभयारण्य को ईको सेन्सेटिव जोन घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर में शीतलहर से चौपट फसलों का किसानों को अविलम्ब पर्याप्त मुआवजा दिलवाने के संबंध में।

(14) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में शीतलहर से फसल खराबे का किसानों को अतिशीघ्र मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती अनिता भदेल।

अनुरोध एवं मांग

प्राप्त विशेषाधिकार प्रश्न पर सम्मति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य के लिये प्रस्तुत किया है। मैं सम्मति की प्रार्थना कर रहा हूं, आप सम्मति कब दे देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विधान सभा सचिवालय को आपका मिला है। अध्यक्ष इस पर निर्णय करेगा। श्रीमती अनिता भदेल। (व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों ने, जिन-जिन ने दिया है, विधान सभा सचिवालय को मिला है, मेरे नोटिस में लाये हैं, मैं उसको देखकर उसके बाद बात करूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रा पर फेल करने का भय दिखाकर अवैध संबंध बनाने का दबाव

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन के माध्यम से राजस्थान की शैक्षिक नगरी कहे जाने वाले

(श्रीमती अनिता भदेल)

कोटा शहर में संचालित राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार की करतूतों के बारे में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ें और हर मां-बाप का सपना होता है कि बेटियां उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करें और इस देश की आधी आबादी, जो महिलाएं हैं, वह किसी तरह से उत्पादकता में इस देश में सहयोगी बनें। लेकिन जिस तरह के काले-कारनामे आर.टी.यू. के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार द्वारा किये जा रहे हैं, उसने पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भी शर्मसार किया है और शिक्षकों को भी गिराने का काम किया है। गिरीश परमार और बिचौलिया अर्पित अग्रवाल के द्वारा किस तरह से छात्राओं को डराकर और धमकाकर उनको गलत प्रश्न-पत्र दिखाकर, यह कहकर कि यही प्रश्न-पत्र आने वाला है, एग्जाम में मैं आपको फेल कर दूंगा, यदि आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे और बिचौलिये छात्रों के द्वारा यह बार-बार कहना और छात्राओं पर दबाव बनाना, यह गिरीश परमार द्वारा एक बार ही यह घटनाक्रम नहीं किया गया है। इससे पहले 10 साल पूर्व भी कश्मीर की एक छात्रा के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया था...

श्री अध्यक्ष: कोर्ट में केस चल रहा है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): और इस दुर्व्यवहार की शिकायत छात्रा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को की, लेकिन कार्यवाही नहीं होने के कारण से एसोसिएट प्रोफेसर परमार को इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये और हिम्मत मिली और अभी तो दो छात्राओं ने ही एफ.आई.आर. दर्ज करायी है। मुझे लगता है कि सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन इसकी गंभीरता से जांच तो निश्चित रूप से बहुत सारी पीड़ित छात्राएं भी सामने आ सकती हैं। इस प्रकार के प्रोफेसर को बर्खास्त करना चाहिये। उसको नौकरी से हटा देना चाहिये और ऐसी बच्चियों को संरक्षण देना चाहिये ताकि वे बच्चियां निश्चित रूप से निडर होकर कालेज में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और वह जो मां-बाप हैं, उनको भी यह आश्वासन मिल सके कि यदि उनकी बच्चियां कालेज में जा रही हैं तो किसी प्रकार के प्रोफेसर की बुरी नजरें उनकी बच्चियों पर नहीं हैं। इतना ही निवेदन करना चाहूंगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह।

छीपाबड़ौद की गौण कृषि उपज मण्डी समिति में मूलभूत सुविधाएं

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, स्थगन पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लहसुन की स्पेशल मण्डी मात्र छीपाबड़ौद में है, जो कृषि उपज मण्डी, छबड़ा के अन्तर्गत आती है। कृषि उपज मण्डी लहसुन की पैदावार हाड़ौती में अधिक होने की वजह से गौण मण्डी लहसुन को जो जमीन आबंटित की हुई है, वह कम है। उसके बाद में सरकार से हमने मांग भी की तो 8 बीघा जमीन उन्होंने और अलॉट कर दी और वह जमीन मण्डी ने अपने पजेशन में अभी नहीं ली है, न ही वहां किसी प्रकार का काम चल रहा है। इसके साथ-साथ ही वहां पर मैन गेट पर अतिक्रमण हो रहा है, उससे व्यापारियों को और किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सी.सी. रोड भी जहां पर यह माल आक्शन होता है, लहसुन आक्शन होता है, वहां पर रोड अधूरा पड़ा हुआ है और पूरी दुकानों को जमीन होते हुए भी वहां पर दुकानें आबंटित नहीं की गयी है। इस प्रकार की भी हालत वहां पर देखने में आयी है, उससे व्यापारी बहुत परेशान हैं। यही नहीं, वहां पर जो बाउंड्रीवाल बनी हुई है, जो एग्जिस्टिंग मण्डी है, उसमें भी वह बाउंड्रीवाल नीची होने की वजह से वहां चोरी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं और रात को किसानों के जो ट्रैक्टर वहां पर खड़े रहते हैं, उनमें से लहसुन की चोरी आये दिन होती रहती है। साथ ही लहसुन की पैदावार वहां पर अधिक होने की वजह से हाड़ौती के सभी क्षेत्रों से वहां पर आता है। लहसुन आने की वजह से सड़कों पर जाम लग जाता है। यह जो 8 बीघा जमीन आबंटित हुई है, इसको मंडी प्रशासन अपने कब्जे में ले और उसकी बाउंड्री तुरंत बनाये ताकि किसानों को और व्यापारियों को कुछ आराम मिल सके। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली शहर की शहीद भगतसिंह कालोनी में पुलिस चौकी की स्थापना

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली का जो शहीद भगतसिंह नगर है, जहां बी पी एल क्वार्टर्स भी हैं और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, वहां अपराध की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब यह जो इलाका है वह सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, लेकिन वहां से काफी दूर है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

इस बेल्ट में जुआ, सट्टा, नशीली दवाओं का कारोबार, अवैध शराब का कारोबार और यहां तक कि देह व्यापार, यह सारा बड़ी मात्रा में हो रहा है। इसको लेकर वहां झगड़े और मारपीट भी अक्सर होती रहती है।

वहां का पुलिस विभाग भी मानता है कि चूंकि यह कोतवाली से बहुत दूर है और यहां कोई न कोई पुलिस चौकी होनी चाहिए जिससे वहां अपराधों पर निगरानी रखी जा सके और प्रभावी अंकुश किया जा सके। लेकिन मौहल्ले वालों के द्वारा बार-बार पुलिस विभाग को आग्रह करने के बाद भी, कोई स्थान नहीं मिलने की वजह से वहां चाहते हुए भी पुलिस विभाग चौकी खोल नहीं पा रहा है। अगर वहां अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है तो वहां निश्चित रूप से सरकार कोई न कोई जगह उपलब्ध कराकर चौकी के लिये पुलिस वाले तैनात कर दें, ताकि वहां के लोगों को अपराधियों से मुक्ति मिल जाये। वरना वहां के जो शांतिप्रिय लोग हैं, उनका वहां रहना और जीना दोनों दूभर हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैंने सट्टे और सूदखोरों के बारे में भी स्थगन प्रस्ताव में लिखा है। सट्टा और सूदखोरी का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन सट्टा भी कइयों की मौत का कारण बन रहा है। इन सूदखोरों की वजह से एक नहीं, पाली में पिछले 7 महीनों में लगभग 7 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। जितनी कठोर कार्यवाही इनके विरुद्ध होनी चाहिए, कहीं न कहीं कर नहीं पाते हैं, उसकी वजह से ये सटोरिये और सूदखोर बहुत बड़ी मात्रा में पनप गये। इनका खुद का, गुंडों का एक समूह होता है। अगर कोई व्यक्ति समय पर पैसा नहीं देता या समय पर ब्याज नहीं देता तो बाकायदा इनकी टीम उनके घर पर जाती है। उनको धमकाती है, मारती है, पीटती है, उनसे छीना-झपटी करती है। उसका परिणाम होता है कि मजबूरन उसको अपनी बेइज्जती से बचने के लिये या मार से बचने के लिये मौत को गले लगाना पड़ता है। आप पाली की घटनाएं देखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्लीज, थाने पर था। कहां जा रहे हैं आप?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): उनका अगर आप आंकलन करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि वाकई में इन सटोरियों और सूदखोरों की वजह से कई युवा अपनी जान गंवा बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: पुलिस चौकी की स्थापना करनी है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): इससे सरकार मुक्ति दिलाये।

श्री अध्यक्ष: ज्ञानचंद जी, आप इतने सीनियर हैं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): वह भी नियमों में है।

श्री अध्यक्ष: पुलिस चौकी की बात थी। नाम में कहां जा रहे हो आप? श्री अभिनेश महर्षि।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्याप्त परिलाभ की प्रदायगी

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी निष्ठा, लगन, समर्पण भाव से कठिन मेहनत करते हुए, अपनी सेवायें देते हुए समाज उत्थान के लिये, महिलाओं एवं बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिये कार्य किया जाता है। ये बच्चे देश का भविष्य हैं। कुपोषित बच्चे और अस्वस्थ महिलाएं नहीं रहें, यह हमारे प्रदेश का उद्देश्य है।

अध्यक्ष महोदय, इस उद्देश्य को प्राप्त करने में तब हम असफल हो जाते हैं, जब इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मूल कार्य से इनको हटाकर अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। तब और भी गम्भीर स्थिति पैदा हो जाती है, जब इन कार्यकर्ताओं को, इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को अतिरिक्त मानदेय का भुगतान भी नहीं किया जाता है।

इस विभाग के कर्मचारियों को इस तरह के कार्यों के लिये अलग से भुगतान किया जाये, लेकिन यह नहीं किया जाता है। यह इनके साथ में अन्याय है। इनकी ड्यूटी अन्य कार्यों में नहीं लगाई जाये। यदि लगा भी दी जाये, चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में जो कि पूर्णकालिक कार्य होता है, उसमें तो बिलकुल नहीं लगाई जाये। फिर भी किसी कारणवश अगर लगाई जाती है तो इनको अतिरिक्त मानदेय दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। केन्द्र और राज्य सरकार के हिस्से का भुगतान अलग-अलग किया जाता है। यह इनके साथ में अन्याय है। वह दोनों भुगतान एक साथ किये जाने चाहिए। इनकी ड्यूटी मेडिकल डिपार्टमेंट में देने के बाद, इनकी जो हाजिरी लगाई जाती है, वह आंगनबाड़ी में लगाई जाती है। पिछले बजट में जो इनके बढ़े हुए मानदेय दिये गये थे, उनकी घोषणा मात्र रही और इनको अभी तक भी नहीं दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पोषाहार बहुत ही घटिया है।

श्री अध्यक्ष: I will not allow.

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): बस, मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप मांगते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। गलत है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): पोषाहार बहुत ही घटिया दिया जा रहा है। उसको स्वयंसेवी समूहों द्वारा दिया जाता था पर अब ठेकेदारों द्वारा दिया जा रहा है इसलिए इसकी जांच करवाई जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप बोल किस पर रहे हैं? गलत बात है। प्लीज। हो गया धन्यवाद।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): इनके 600 रुपये और 1200 रुपये को बाद में बंद कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: I will not allow you next time. यह गलत बात है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): इनका वह पैसा कहां चला गया, पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: टापिक क्या होता है और पता नहीं आ जाते हैं किस पर? श्री राजेन्द्र राठौड़।

पोंजी योजनाओं में निवेश के नाम पर आमजन से ठगी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में संगठित गिरोह, क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी और इस प्रकार की अन्य कम्पनी बनाकर लगातार भोले-भाले किसानों को, मध्यम वर्ग को उनके निवेश का आकर्षक प्रतिफल देकर, लालच में लाकर ठगने का काम कर रहा है।

इसी जनवरी के तीसरे सप्ताह में सीकर जिला जहां से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी भी आते हैं, वहां एक कंपनी नैक्सा एवरग्रीन, यह करीब 20 हजार लोगों के 780 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गयी। इनका रजिस्टर्ड आफिस पिपराली, सीकर के अंदर था। एफ आई आर उद्योग नगर थाने के अंदर दर्ज हुई लेकिन आज भी उनकी न सम्पत्ति जब्त की गयी है, न उनकी जो लग्जरी गाड़ियां हैं, उनको जब्त किया गया है, न अकाउंट जब्त किये गये हैं।

इसके कर्ता-धर्ता सुभाष बिजारणियां, ये वही व्यक्ति हैं जो पहले फर्जी डिग्री के व्यापार में लगे हुए थे। अब इन्होंने अपना व्यापार बदला है। सुभाष बिजारणियां, विकास कुमार और बीरबल, यह सबके सब, आप तो जानते हो पनलावां, वहीं के रहने वाले हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर मंगलवार को यह एक ड्रॉ खोला करते थे। निवेशक जिसने 50 हजार रुपया जमा कराया, हर सप्ताह उसको 1353 रुपये लौटाया करते थे। इस आकर्षक योजना में इन्होंने फर्जी वीडियो बनाया और यह कहा कि यह एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी है। गुजरात में कई एयरपोर्ट बना रहे हैं। उस बहाने से इन लोगों को फंसाया। इनकी संख्या 20 हजार है। सारी शेखावाटी लूटी गयी।

मेरा आपसे निवेदन है कि एस ओ जी इसकी जांच करे, सम्पत्ति जब्त करे। जो The Banning of unregulated deposit schemes Act, 2019 आया, भारत सरकार ने किया, जो फरवरी, 2019 से लागू हो गया। कई राज्यों ने लागू कर दिया, लेकिन हम न जाने किस कारण से इसको लागू नहीं करना चाहते। The Banning of unregulated deposit schemes Act, 2019 अगर लागू हो जाये तो राजस्थान के अंदर भी महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तरह इन कंपनियों पर अंकुश लग जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार संज्ञान ले और इसमें न जाने क्यों आपका और आपके गांव का नाम आ रहा है लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनकी एक लग्जरी होटल में कांफ्रेंस हुई थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इधर, अध्यक्ष इधर बैठा हुआ है। आप दूसरे अध्यक्ष को एड्रेस कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उस कांफ्रेंस में कौन-कौन नेता गये थे? जिन नेताओं के कारण से इतने लोग भ्रमित हुए, इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा। माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संजीवनी की और इसकी दोनों की करा लो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संजीवनी की और इसकी दोनों की जांच करा लो सी बी आई से।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। यह आप दोनों के ऊपर हाउस ले रखा है क्या? हम कुर्सी पर हैं।

श्री संदीप शर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोटा शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाएं

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में पुलिस के कई अधिकारियों के आपराधिक कृत्यों में लिप्तता के चलते न केवल खाकी वर्दी ही शर्मसार हो रही है, अपितु आम जनता में कानून व्यवस्था एवं सरकार के निजाम के प्रति प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है।

अपराध की हर श्रेणी चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाकूबाजी, हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं, साइबर अपराध, सभी में पुलिस अधिकारियों एवं अपराधियों से सांठ-गांठ कर एवं स्वयं भी अपराध में लिप्तता के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

कोटा एक शैक्षणिक नगरी होने से सम्पूर्ण भारत में विख्यात है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कोटा चाकूबाजी व लूट, हत्याओं, चैन स्नेचिंग की घटना में अव्वल आ रहा है जिससे सम्पूर्ण भारत देश में कोटा आपराधिक घटनाओं से भी बदनाम शहर हो रहा है।

(समय: 12.18 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

कोटा में वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक चार सालों में 385 बार चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं जिसमें वर्ष 2018 में 62 चाकूबाजी की घटनाएं हुईं जो बढ़कर 2021 में 118 हो गयीं और अब वर्ष 2022 में 173 चाकूबाजी की घटनाएं हुई। सर्वाधिक चाकूबाजी की घटनाएं कोटा उत्तर विधान सभा क्षेत्र के नदी पार क्षेत्र में हुई हैं। वहीं दूसरी और नयापुरा चौराहे पर दुकान में घुसकर चाकूबाजी से लूट की घटना का मामला सामने आया है। सम्पूर्ण कोटा शहर दहशत में है। गत 2018 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गयी है और आमजन व व्यापारी में भय व्याप्त है।

अत: मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी से सदन के माध्यम से निवेदन है कि कोटा शहर में अपराधों की रोकथाम हेतु संबंधित विभाग को

(श्री संदीप शर्मा)

निर्देशित करें, ताकि कोटा अपराध मुक्त हो सके और महिलाओं व लोगों में व्याप्त भय का अंत हो सके।

श्री सभापति: श्रीमती मंजु देवी।

जायल में सौभाग्य योजना का पुनर्संचालन

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि गत वर्ष सौभाग्य योजना के तहत ढाणियों को इलेक्ट्रिफाइड करने के लिए ग्रुप बनाकर कार्य प्रारम्भ किया तथा रजिस्टर्ड ग्रुप की ढाणियों से 500-500 रुपये की राशि में जमा करवाई गई, लेकिन इस योजना को अचानक 15 मार्च, 2022 को बंद कर दिया गया। इस योजना के तहत वर्तमान में अनेकों ढाणियों में कार्य अपूर्ण रह गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में लगभग 2000 पोल खड़े किये गये हैं, लेकिन केबल और ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने से हजारों ढाणियों में विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि अविलम्ब मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के जो गांव एवं ढाणियां ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली से वंचित रही हैं, उनमें जल्दी ही विद्युत कनेक्शन कराकर ग्रामीण इलाके की इस समस्या का समाधान करें ताकि गांव-ढाणी में बैठे लोगों को रोशनी मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

सांगानेर में अवैध मांस-मछली की दुकानों का संचालन

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में डिग्गी रोड पर मालपुरा गेट से सवाई माधोपुर पुलिया के बीच, सुभाष कालोनी, मोक्ष धाम के सामने, शिकारपुरा रोड पर, सेक्टर 35, हाउसिंग बोर्ड प्रताप नगर पर, रामपुरा रोड सांगानेर पर, इंडिया गेट के आसपास, काला बड़ फाटक के पास, त्रिवेणी नगर पुलिया के नीचे गोपालपुरा बाईपास पर, मानसरोवर क्षेत्र में व वंदेमातरम् मार्ग सहित अनेक स्थानों पर खुले में सैकड़ों की संख्या में अवैध मांस-मछली की दुकानों का

(श्री अशोक लाहोटी)

संचालन हो रहा है। इन दुकानों में अवैध रूप से पशु-पक्षियों सहित अन्य जानवरों की कटाई-छंटाई मौके पर ही की जा रही है जो कि पूर्णतया प्रतिबंधित है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को आने-जाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई जा रही है। मांसमछली खाने वालों को शुद्ध व हाइजेनिक सामान मिले, इसके लिए भी सरकार के कुछ नियम बने हुए हैं। इसके लिए केवल स्लाटर हाउस में ही कटाई-छंटाई की जा सकती है। बेचने के लिए भी दुकानों में काले कांच लगे हुए हों, पर्दे इस प्रकार लगे हों कि बाहर से दिखाई न दे, इस तरह के प्रावधान हैं। सामान रखने के लिए डीप फ्रीजर सहित तमाम सुविधाएं होनी जरूरी हैं। ये प्रावधान किए हुए हैं।

अत: मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस प्रकार से खुले में बिक रहे मांस-मछली की अवैध दुकानें जो आसपास के वातावरण को दूषित कर रही हैं, उनको अविलम्ब बंद किया जाए तथा नियमानुसार ही लाइसेंसशुदा नियम पालन करने वाली दुकानों पर ही बेचान हो, इस हेतु सरकार अपने स्तर पर पुख्ता इंतजाम करे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा एक छोटी-सी बात और है।

श्री सभापति: बस हो गया आपका। आप 295 पढ़ चुके हैं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): इसमें कई लोगों ने वहां पर संगठित गिरोह बना रखे हैं। इनको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए।

श्री सभापति: श्री अमृत लाल मीणा।

सलूम्बर स्थित हाड़ीरानी राजकीय महाविद्यालय में सुविधाएं

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रकिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के हाड़ीरानी राजकीय महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकताएं हैं जो कि निम्न प्रकार हैं:-

यह महाविद्यालय उबड-खाबड़ पहाड़ी जमीन पर स्थित है, इसलिए इसके आसपास जमीन समतलीकरण की आवश्यकता है। महाविद्यालय भवन के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल नहीं है, जिसकी अत्यंत आवश्यकता है।

हाड़ीरानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर में आधारभूत सुविधाओं का

(श्री अमृतलाल मीणा)

भारी अभाव है। वर्तमान में यहां 2700 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिनमें से 80 प्रतिशत छात्र-छात्राएं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के हैं।

महाविद्यालय में वर्तमान में निम्नांकित सुविधाएं नहीं हैं:-

महाविद्यालय में भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गृह विज्ञान की एक भी प्रयोगशाला नहीं है। अत: वहां पर 5 प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है। शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कार्यों के लिए 15 कक्षा कक्षों की आवश्यकता है। वहां लगभग 1200 पुस्तकें हैं लेकिन पुस्तकालय एवं वाचनालय भवन का अभाव है। प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन खेल मैदान वहां उपलब्ध नहीं है इसलिए खेल मैदान की वहां अत्यंत आवश्यकता है। महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं सांस्कृतिक प्रतिभाओं से ओत-प्रोत हैं लेकिन आडिटोरियम का अभाव है।

माननीय सभापति महोदय, अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकरण की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुरदीप सिंह।

राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर सुरक्षा गार्डों के नवीन पदों का सृजन

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.4 पराविं/पीसी/ सुरक्षा गार्ड/2013/रागसेके/1157 दिनांक 06.04.2013 के द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर सुरक्षा गार्डों को पूर्णकालीन संविदाकर्मी के रूप में सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति दी गई थी। वर्तमान में उन सुरक्षा गार्डों को अनुबंधित राशि के अनुसार भुगतान किया जाता है। यह भुगतान प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। सुरक्षा गार्डों द्वारा पूरा भुगतान एवं समय पर नहीं दिए जाने की शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों पर विभाग द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है। यदि इन सुरक्षा गार्डों को दिए जाने वाली अनुबंधित राशि का भुगतान विभाग द्वारा पंचायत समिति के मार्फत दिलाया जाए तो गरीब सुरक्षा गार्डों को समय पर एवं पूर्ण भुगतान मिल सकेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों

(श्री गुरदीप सिंह)

में सुरक्षा गार्डों के नये पद सृजित कर इन सुरक्षा गार्डों को नियमित नियुक्ति की नियमानुसार कार्यवाही की जाए ताकि वर्तमान में नियुक्त संविदाकर्मी के रूप में नियुक्त सुरक्षा गार्डों को राहत मिल सके।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में आई टी क्षेत्र की सबसे बड़ी 10157 पदों पर कम्प्यूटर अनुदेशकों की भर्ती आयोजित की गई थी, किन्तु पेपर का जटिल स्तर होने के कारण और न्यूनतम प्रातांकों की बाध्यता तथा पेपर में विसंगति (4 प्रश्न डिलीट एवं 7 उत्तर चेंज) की वजह से आज 4015 पद रिक्त रह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, उक्त भर्ती में न्यूनतम प्राप्तांकों की बाध्यता थी, परंतु इस बाध्यता में दिव्यांगों, परित्यक्ता, विधवा, सहरिया इत्यादि को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई जिस कारण से इन सभी वर्गों के अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं हो पाए।

टी एस पी क्षेत्र में 888 पदों में से मात्र 175 पद भी भर पाए हैं एवं टीएसपी एवं नॉन टी एस पी में योग्यता बराबर रखी गई, जबकि टी एस पी एरिया में न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट देनी चाहिए थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए न्यूनतम प्राप्तांकों एवं टी एस पी, नॉन टी एस पी एरिया के छात्र-छात्राओं को न्यूनतम प्राप्ताकों में छूट दी जाए, ताकि रिक्त रहे पदों को भरा जा सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर (अनुपस्थित)। श्री बलवान पूनियां।

श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में फसल खराबे के बीमा क्लेम का भुगतान

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्री बलवान पूनियां)

श्रीमान् जी, 2021 खरीफ में बीमा कम्पनी ने मूंग व मोठ में फसलों के ज्यादा बारिश से बर्बाद हो जाने के बावजूद बीमा क्लेम देने से यह कहकर इंकार कर दिया कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने हमें लिखित में क्रोपकटिंग के लिए नहीं दिया, जबकि जिला हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर ने लिखित मे ए.आई.सी. कम्पनी के जिला मैनेजर को सूचित कर दिया। फिर भी बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि ने कुछ जगह क्रोपकटिंग के स्थान पर पहुंचकर भी दस्तखत नहीं किये। यही नहीं, उन्होंने झूठी शिकायतें दर्ज कराईं। भादरा विधान सभा क्षेत्र के लगभग डेढ़ दर्जन पटवार मंडलों में उनकी उपस्थिति में बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों ने दस्तखत भी और क्रोपकटिंग में को-विटनेस के रूप में ये दस्तखत मिले भी हैं। इसलिए हमारे हनुमानगढ़ जिले की 2021 की खरीफ की फसल मूंग-मोठ में क्रोपकटिंग से बीमा क्लेम निर्धारित करवाये जाएं।

अतः हमारी सदन से मांग है कि हनुमानगढ़ जिले व चूरू जिले के किसानों का क्रोपकटिंग से बीमा क्लेम निर्धारण हो तथा सेटेलाइट का विचार ही खतम किया जाए, क्योंकि उत्पादन का सटीक आंकड़ा क्रोपकटिंग से ही होता है। साथ ही क्रोपकटिंग के खेत रेण्डमली राजस्व बोर्ड ही तय करे, न कि बीमा कम्पनी की जियो टैगिंग से किये जाएं।

श्रीमान जी, क्रोपकटिंग में पारदर्शिता के लिए किसी भी जिले में किसी भी फसल का एक विभाग से क्रोपकटिंग कराने के बजाय कृषि विभाग और राजस्व विभाग दोनों की जोइंट टीम बनाकर हर पटवार मंडल में क्रोपकटिंग के सैम्पल लिये जाएं और फसल बीमा क्लेम 2021 खरीफ की फसल मूंग व मोठ का क्रोपकटिंग से ही निर्धारण करवाकर बीमा दिलवाया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

नोखा के गांवों की मिसिंग लिंक एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने व कई अति महत्वपूर्ण रास्ते जो आज भी डामरीकरण से वंचित हैं, इस हेतु कई बार मांग उठाई गई है जो निम्न हैं:-

1. अत्यधिक महत्वपूर्ण सड़कें- जेगला से सुरपुरा वाया रासीसर, खारा

(श्री बिहारीलाल)

से पांचू वाया सैंगाल धोरा, गजसुखदेसर से धुपालिया वाया झाड़ेली फांटा-नई तलाई स्कूल झाड़ेली-थावरिया जोगणिया का बाळा-बाढ़ काकड़ा, गोदारों की ढाणी हंसासर से देसलसर वाया खारा-कूदसू-हिंयादेसर, मुकाम मुख्य गेट से समराथल धोरा तक डिवाइडरयुक्त डबल रोड, जांगलू से ढिंगसरी वाया बरंगावाली नाडी-साथरी-खेजड़ली फांटा इत्यादि।

2. महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक सड़कें- धरनोक से नाथूसर, माडिया से घड्डू, उदासर से किशनासर, घड्डू से सोमलसर, सिंजगुरू से घड्डू, रामनगर उदासर से रायकों की ढाणी उदासर, बगसेउ से मैनसर, सांईसर से नांधड़ा, कुम्भासर से पांचू, सांईसर से बूंगड़ी, रायसर से मैयासर, बांगड़ा ढाणी चौराहा सांईसर से हनुमान नगर तक, जयपालों की ढाणी सारूण्डा से सुथारों की ढाणी सारूण्डा, नोखा रोड राठौड़ों की ढाणी से सुथारों की ढाणी सारूण्डा, सुथारों की ढाणियों से अर्जुन नाडी बगसेउ, दासनू से सिरोला फांटा रामदेवरा मार्ग, रायसर रोड से बू-कर्मसोत, जेगला से छींपानाडा, बरसिंहसर से जेगला, रायसर से दासनू, माडिया से रामनगर रायसर रोड सहित नई सड़कें बनाई जायें।

3. धार्मिक महत्व की सड़कें- किशनासर हियादेसर रोड से विश्वत माता मंदिर हिंयादेसर, रामदेव जी की खेजड़ी कक्कू से सैंगाल धोरा, बगरेवाला धोरा से जोधपुर सीमा तक, पिथरासर से नखत बन्ना धाम तक, भौम बिलनियासर से तेजाजी का मंदिर भौम बिलनियासर, भौम मैयासर डामर सडक से पीपासर सीमा तक, कालाभाटा कुण्ड से पलाना सीमा तक।

नेशनल हाईवे 754 K (ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे) निर्माण के दौरान भारी वाहनों के आवागमन से क्षेत्र की 15 महत्वपूर्ण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण भी किया जाये।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

राजकीय विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सरकार के निर्णय अनुसार प्रदेश में राजकीय भवनों, परिसरों अर्थात् विद्यालय भवनों, राजकीय भवनों, खेल मैदानों, विद्यालय परिसरों के ऊपर से निकलने वाली हाईटेंशन विद्युत लाइनों को राजकीय रूप से शिफ्टिंग का आदेश

(श्री हमीर सिंह भायल)

पारित है, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम ने उक्त कार्यों का पिछले 4 वर्षों से लंबित कर रखा है। कई स्थानों पर लाइन के नीचे मात्र गार्डिंग की जा रही हैं एवं कुछ पत्रावलियां लंबित पड़ी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक 16 से 20 विद्यालयों पर हाईटेंशन लाइनों का खतरा मंडरा रहा है जिसकी सूची डिस्कॉम एवं माननीय मंत्री महोदय को दे रखी है, लेकिन कार्य नहीं किया जा रहा है। हाईटेंशन लाइनों से छात्र-छात्राओं पर खतरा मंडरा रहा है। विभाग कार्य करने में घोर लापरवाही कर रहा है और सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री से विशेष आग्रह है कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र के 16 से 20 विद्यालयों से हाईटेंशन लाइनें शिफ्ट करवाकर राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

मावली की विकास कार्यों व योजनाओं में उपेक्षा

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर मुझे सदन में यह विचार व्यक्त करते हुए क्षोभ का अनुभव हो रहा है कि राज्य सरकार विगत 4 वर्षों से मावली विधान सभा क्षेत्र की विकास कार्यों व योजनाओं में निरन्तर उपेक्षा कर रही है। मावली के बागोलिया बांध को भरने की डी पी आर 5 वर्ष पहले बन चुकी है, लेकिन वर्तमान सरकार ने भरे सदन व सदन के बाहर बार-बार मांग करने के बावजूद सरकार ने कोई स्वीकृति देना तो दूर, योजना के लिए केन्द्र सरकार से पैसे की मांग तक नहीं की।

मावली में राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने 2019-20 व 2020-21 के वजट में घोषणा की पर कोई काम नहीं हुआ, तो अन्ततः यह कालेज भवन डी.एम.एफ.टी. से बनाने का फैसला हुआ। विगत वर्षों में डी.एम.एफ.टी. मद से स्वीकृत कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुए हैं। उदयसागर की नहरें कच्ची व टूटी हुई हैं पानी व फसलें दोनों खराब हो रही हैं। नहरों की मरम्मत व शेष नहरों को पक्का न करने से क्षेत्र के कृषक त्रस्त हैं। नहरों के मरम्मत के काम पर केवल पत्राचार हो रहा है। घासा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में भी निरन्तर मांग होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। राज्य सरकार ने विगत 4 वर्षों में मावली से छोटे कई कस्बों को

(श्री धर्मनारायण जोशी)

नगरपालिका का दर्जा दिया, लेकिन इसमें भी मावली की उपेक्षा की। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विकास में भेदभाव चिंताजनक है। मेरा निवेदन है कि विकास कार्यों की स्वीकृति व क्रियान्विति में राजनीतिक नजरिया न रखा जाए और मावली विधान सभा क्षेत्र के लम्बित कार्यों व योजनाओं को सरकार शीघ्र स्वीकृति देकर क्षेत्र के विकास को गति दे।

(समय: 12.36 बजे)

(श्री सी. पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया। श्री जगसी राम कोली।

रेवदर में शीतलहर से चौपट फसलों का मुआवजा

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत सरकार से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर में प्रतिवर्ष टमाटर, अरण्डी, सौंफ, रायडा, आलू, पपीता की बम्पर पैदावार होती आयी है। इस बार भी रेवदर विधान सभा क्षेत्र के सभी किसानों के प्रत्येक रकबे पर उक्त फसलों की भरपूर बुआई, निराई, गुड़ाई से बगर-फल आने से इस वर्ष पुनः बम्पर पैदावार लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन जनवरी 2023 के दौरान समूचे रेवदर विधान सभा क्षेत्र में हिमपात, पाला, शीतलहर से खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई है। फसलों के चौपट हो जाने से क्षेत्र का किसान घोर निराशा में डूबा हुआ है। किसानों को भारी आर्थिक, मानसिक नुकसान से इनका श्रम-परिश्रम प्रकृति की मार से बेकार हो गया है। सरकार से आग्रह है कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों की उक्त नष्ट हो चुकी फसल की नियमानुसार खसरा गिरदावरी जांच करवाकर पीड़ित किसानों को अधिकतम आर्थिक मुआवजा देकर राहत दी जावे।

श्री अध्यक्ष: श्री कालूराम।

डग में शीतलहर से फसल खराबे का मुआवजा

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में दिनांक 15 से 18 जनवरी, 2023 को पाला गिरने व शीतलहर चलने से धनिया, चना, मसूर, सरसों, गेहूं, कलोंजी आदि रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पाला गिरने व शीतलहर से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाई जाए व किसानों को

(श्री कालूराम)

खराब हुई फसल का उचित मुआवजा दिलवाया जाए। साथ ही, पाला गिरने से खराब हुई फसलों को आपदा में सम्मिलित किया जाए ताकि किसानों को बीमा क्लेम मिल सके। विगत की फसल सोयाबीन व अन्य फसलें अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई थीं जिनकी गिरदावरी भी की जा चुकी है। उनका मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला न ही बीमा क्लेम मिला। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कई लोगों के मकान गिर गए थे, उनका मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला। मैं सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को उचित मुआवजा व बीमा क्लेम अतिशीघ्र दिलवाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 25 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-18 दिनांक 16.09.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-225 दिनांक 02.09.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: प.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-19 दिनांक 16.09.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-226 दिनांक 02.09.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: प.5(18)वित्त/कर/2022-20 दिनांक 13.10.2022 जिसके द्वारा एन.टी.पी.सी. लिमिटेड द्वारा एन.टी.पी.सी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: प.6(2)वित्त/कर/2021-21 दिनांक 19.10.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.6(2)वित्त/कर/2019-149 दिनांक 30.03.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

5. अधिसूचना संख्या: प.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-22 दिनांक 14.11.2022 जिसके द्वारा राजस्थान विनिधान प्रौन्नति स्कीम, 2022 के अधीन पात्र किसी उद्यम के पक्ष में निष्पादित भूमि के क्रय या पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;
6. अधिसूचना संख्या: प.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-23 दिनांक 14.11.2022 जिसके द्वारा राजस्थान विनिधान प्रौन्नति स्कीम, 2022 के अधीन पात्र इकाइयों द्वारा 10000 वर्गमीटर से अधिक धारित भूमि पर देय भूमि कर में छूट प्रदान की गई है;
7. अधिसूचना संख्या: प.5(12)वित्त/कर/2022-24 दिनांक 24.11.2022 जिसके द्वारा खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान, जोधपुर के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;
8. अधिसूचना संख्या: प.24(1)वित्त/कर/2021-44 दिनांक 22.09.2022 जिसके द्वारा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2022 के अन्तर्गत राजस्थानी फिल्मों के संबंध में मल्टीपैक्स/सिनेमाघर में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) का कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है;
9. अधिसूचना संख्या: प.12(15)वित्त/कर-2022-46 दिनांक 30.09.2022 जिसके द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा 2 से 15 तक के प्रावधानों को प्रभावी होने की तिथि निर्धारित की गई है;
10. अधिसूचना संख्या: प.12(15)वित्त/कर-2022-47 दिनांक 30.09.2022 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: प.12(15)वित्त/कर/2022-48 दिनांक 04.10.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-152 दिनांक 30.03.2020 में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: प.24(6)वित्त/कर/2022-50 दिनांक 13.10.2022 जिसके द्वारा फिल्म "ऐ जिन्दगी" के संबंध में मल्टीपैक्स/सिनेमाघर में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) का कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रतिपूर्ति किये जाने का निर्णय लिया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

13. अधिसूचना संख्या: प.12(97)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-52 दिनांक 31.10.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2022-103 दिनांक 23.02.2022 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: प.12(97)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-53 दिनांक 31.10.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2022-104 दिनांक 23.02.2022 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या: प.12(32)वित्त/कर/2022-55 दिनांक 10.11.2022 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2022 के अन्तर्गत विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

16. अधिसूचना संख्या: प.12(15)वित्त/कर/2022-56 दिनांक 17.11.2022 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: प.12(15)वित्त/कर/2022-77 दिनांक 30.11.2022 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

18. अधिसूचना संख्या: प.12(30)वित्त/कर/2019-पार्ट-I-85 दिनांक 28.12.2022 जिसके द्वारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2016-17 से 2017-18 की अवधि के लिये जल संरक्षण उपकर जमा करने में विलम्ब होने पर देय ब्याज को सशर्त माफ किया गया है;

19. अधिसूचना संख्या: प.12(15)वित्त/कर/2022-86 दिनांक 30.12.2022 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

20. अधिसूचना संख्या: प.12(15)वित्त/कर/2022-87 दिनांक 30.12.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

21. अधिसूचना संख्या: प.12(15)वित्त/कर/2022-88 दिनांक 30.12.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

22. अधिसूचना संख्या: प.12(15)वित्त/कर/2022-89 दिनांक 30.12.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-43 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;
23. अधिसूचना संख्या: प.12(15)वित्त/कर/2022-90 दिनांक 30.12.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-50 दिनांक 29.06.2017 में संशोधन किया गया है;
24. अधिसूचना संख्या: प.12(97)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-91 दिनांक 31.12.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2022-103 दिनांक 23.02.2022 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं
25. अधिसूचना संख्या: प.12(97)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-92 दिनांक 31.12.2022 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.12(11)वित्त/कर/2022-104 दिनांक 23.02.2022 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

जयपुर विकास प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के 9 वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, एक बात।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात नोटिस में है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 72वां वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2021-22)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 72वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के वार्षिक/ प्रगति प्रतिवेदन

(वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018-19 एवं 2019)

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा-40 के अन्तर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के 14 वार्षिक/प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018-19 एवं 2019 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2021-22)

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों पर पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2019-20)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22)

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 27(5) के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

वार्षिक प्रतिवेदनों की अनेक अध्यक्षीय व्यवस्थाओं के पश्चात् भी विलम्बित प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आसन ने कई बार व्यवस्था दी। आज हमारे सामने 2012-13 के प्रतिवेदन आ रहे हैं और आपके विश्वविद्यालय का देखें तो 2006-07 का आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहीं न कहीं यह लाइबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे। एक को कर दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने इसके लिए चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई है और उसमें निर्णय करने के बाद मैं सदन को अवगत करवाऊंगा। मैं भी आपकी चिन्ता से सहमत हूं कि वार्षिक प्रतिवेदन समय पर आने चाहिए। आप बोलेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, यह बात सही है कि आपने कमेटी बनाई है। मैं उसका स्वागत करता हूं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यह प्रोब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन आप यह भी देखिए कि 2012-13 का 2014 में पेश हो जाना चाहिए था। 2014 से लेकर के जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आप मंत्री

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

रहे, आपने पूरे पांच साल तक एक भी पेश नहीं किया। खेद तो आपको प्रकट करना चाहिए। मैं तो कर रहा हूं प्रकट। 2018-19 और 2020-21 के लेट हुए हैं तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, लेकिन आप तो 5-5, 6-6 साल तक नहीं करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ये आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने एक बार भी टोका हो तो बताओ। आपने टोका क्यों नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी विजिलेंस के लिए आपको धन्यवाद, पर फिल्म में कभी आपकी भूमिका इधर होती है, कभी खलनायक भी होते हैं, कभी नायक भी होते हैं। आप नायक हो तो नायक का ध्यान रखो, खलनायक हो तो खलनायक का ध्यान रखो। हम आशा करते हैं कि आप अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावशाली ढंग से करते रहेंगे। जो बातें आप अभी नोटिस कर रहे हैं, जब आपको मौका मिले तो उनका पूरी तरह से पालना करने का काम करें, लेकिन यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है कि वार्षिक प्रतिवेदन पर जो हमारी व्यवस्था है, उसमें समय पर यहां प्रतिवेदन आने चाहिए। उसमें जो कमी खामी है, उस पर बैठकर चर्चा करके उसको स्ट्रीम-लाइन करने का काम करेंगे।

माननीय सदस्यगण, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद पर माननीय मुख्य मंत्रीजी 5 बजे भाषण देंगे। प्रतिपक्ष के नेता माननीय कटारियाजी 4 बजे भाषण देंगे। हमारे पास 4 बजे से पहले का समय उपलब्ध है। प्रतिपक्ष एवं पक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं, वे समय की लिमिट में अपनी बात कहें। आसन पर बैठे हुए को टोकने का अवसर नहीं मिले। मैं आशा करता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य हैं वे समय का ध्यान रखकर अपनी बात कहेंगे, जिससे 4 बजे माननीय कटारियाजी अपनी बात को प्रारम्भ कर सकें। श्री बाबूलाल नागर।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं।

(श्री बाबूलाल नागर)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने 4 साल से लगातार बजट पेश किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि वर्ष 2021-22 में राजस्थान ने 11.4 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल की है। अध्यक्ष महोदय, सरकर के लिए यह अपने आप में कीर्तिमान है, 01 वर्ष में 11.4 प्रतिशत आर्थिक विकास दर हासिल करना। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा।

(समय: 12.46 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, पूरे राज्य में इस बीमा में राज्य के 88 प्रतिशत लोग शामिल हैं। जहां तक हम राष्ट्रीय स्तर का प्रतिशत देखते हैं तो 41 प्रतिशत है। राजस्थान में 88 प्रतिशत लोग इसमें कवर हो रहे हैं। निश्चित रूप से, सरकार राइट टू हेल्थ ला रही है। हमारे 88 प्रतिशत लोग पहले ही बीमा में कवर हैं।

सभापति महोदय, चिरंजीवी बीमा योजना में अब तक राज्य में 31 लाख 58 हजार लोगों का उपचार किया गया है। कैशलैस इलाज में लगभग 3 हजार 625 करोड़ रुपये का व्यय राजस्थान में हुआ है। यह भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए निरोगी राजस्थान योजना प्रारम्भ की, दवाइयों और जांच की सुविधा राजकीय अस्पतालओं में नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

राज्य के जितने भी राजकीय चिकित्सालय हैं, आई पी डी, ओ पी डी सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्दर नवम्बर, 2022 तक 948 करोड़ रुपये सरकार ने व्यय किये हैं और 7 करोड़ 50 लाख मरीजों को उसमें लाभान्वित किया है।

सभापति महोदय, राजस्थान में आवश्यक दवा की जो सूची है, 1326 दवाइयां, 928 सर्जिकल्स, 185 सुशर्स को शामिल किया हुआ है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है सभापति महोदय, जहां प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज चरणबद्ध रूप से खोले जा रहे हैं। बारह जिलों में मेडिकल कालेज की स्थापना प्रक्रियाधीन है। चालीस प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार वहन कर रही है। 19 मेडिकल कालेज विभिन्न जिलों में संचालित हैं।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, वर्ष 2022-23 में किसानों को दिसम्बर माह तक 16,402 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया है। यह अब तक का सबसे ज्यादा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने वाला आंकड़ा है।

सभापति महोदय, दिसम्बर, 2018 से अब तक राजस्थान में 3,406 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर अब हमारी क्षमता 23,489 मेगावाट हो गयी है। यह भी राजस्थान में अपने-आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, राजस्थान में चार साल में 3,27,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन, 2,13,000 से अधिक बी पी एल श्रेणी के विद्युत कनेक्शन जारी किये गये। पहले 8-8, 9-9 साल का इसमें वेटिंग पड़ रहा था पर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला किया फरवरी, 2022 तक का, उसकी आज प्रक्रिया चल रही है।

सभापति महोदय, प्रदेश के 16 जिलों में पहले से ही किसानों को दो ब्लाक्स में विद्युत आपूर्ति की जा रही है और जो 14 जिले हैं जिनमें हमारा जयपुर जिला भी शामिल है, अप्रैल, 2023 से इन 14 जिलों में दो ब्लाक्स में दिन में बिजली देने का काम राजस्थान में शुरू होगा।

सभापति महोदय, दिसम्बर, 2018 से नवम्बर, 2022 तक किसानों के बिजली के बिल में 60,755 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 लाख 63 हजार शहरी क्षेत्र में 4 लाख 96 हजार घरेलू कनेक्शन जारी हुए हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना मई, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक 12 लाख 88 हजार किसानों को करीब 1,727 करोड़ रुपये का राजस्थान में अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। सभापति महोदय, 8 लाख 93 हजार किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। राजस्थान में जहां कम पानी है ऐसे किसानों का शून्य बिल आ रहा है, उनके कृषि कनेक्शनों में भी।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री घरेलू अनुदान योजना में अब तक 3,972 करोड़ रुपये से भी अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। लगभग 39 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिल भी शून्य हो गया है राजस्थान में। 39 लाख घरेलू ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका सभापति महोदय, एक पैसा भी बिल नहीं आता है, जो एक लट्टू दो लट्टू जलाते हैं वो राजस्थान में अपने घरेलू निशुल्क बिजली का उपयोग कर रहे हैं, सरकार उनका पैसा दे रही है।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, दिसम्बर, 2018 से अब तक 11,727 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, 132 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र, 1,690 मेगावाट क्षमता के हाईब्रिड संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं राजस्थान में। हमारी सरकार ने 400 के.वी. का एक ग्रिड सब स्टेशन, 220 के 5 ग्रिड सब स्टेशन, 132 के.वी. के 24 ग्रिड सब स्टेशन, 33 के.वी. के 546 सब स्टेशन हमारे यहां स्थापित किये हैं।

सभापति महोदय, 'समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान' के सोच के साथ 2022-23 का प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने पेश किया। कृषि और संबंधित क्षेत्रों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये 11 मिशन कृषि बजट में मुख्य मंत्री जी ने लागू किये हैं।

सभापति महोदय, 2011 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना शुरू हुई। पिछली सरकार आयी, उस सरकार ने किसानों को दो रुपये जो अनुदान दिया जा रहा था उसको बन्द कर दिया। प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष में अनुदान दो रुपये से बढ़ाकर पांच रुपये प्रति लीटर कर दिया। इससे करीब 4 लाख 63 हजार दुग्ध उत्पादक हमारे शामिल हैं राजस्थान में, उन किसानों को फायदा मिला।

सभापति महोदय, प्रदेश के गोवंश के संरक्षण में इन चार वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। गौशालाओं के भरण-पोषण के लिये पहले सहायता राशि 6 माह के लिए थी, उसको बढ़ाकर मुख्य मंत्री जी ने नौ माह की। बड़े पशुओं के अब 40 रुपये कर दिये, छोटे पशुओं के 20 रुपये कर दिये। लम्पी महामारी आयी, इसमें भी सरकार ने कारगर कदम उठाये। मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान के सारे विधायकों को लम्पी में दस-दस लाख रुपये विधायक कोष से दवाइयां खरीदने का प्रोविजन किया और भामाशाहों ने भी पूरा योगदान दिया। लम्पी पर भी हमारी सरकार ने कंट्रोल किया।

सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन की संख्या 31 मार्च, 2022 को 90 लाख 28 हजार थी और दिसम्बर, 2022 तक यह बढ़कर 94 लाख हो गयी। बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक सुरक्षा में भी हमारी सरकार ने काम किये। अनाथ बच्चे, 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को पांच सौ रुपये प्रति माह से बढ़ाकर मुख्य मंत्री जी ने एक हजार रुपये किये और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे थे उन बच्चों को मिलने वाली सहायता 01 हजार मिलती थी उसको आज मुख्य मंत्री जी ने 25 सौ रुपये प्रति माह किया।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, इसी तरह दिव्यांग छात्र-छात्राओं को कार्यस्थल पर जाने के लिये 2022-23 में 2 हजार स्कूटी वितरण की जा रही थीं, आज हम पांच हजार स्कूटी दे रहे हैं दिव्यांग भाई-बहनों को। राजस्थान की सभी महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य जागरूकता एवं नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण हेतु आई एम शक्ति उड़ान योजना शुरू की है। प्रथम चरण में 39 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। द्वितीय चरण में 51 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

सभापति महोदय, इसी तरह आंगनबाड़ी के जो कार्मिक हैं उनके लिए 1 अप्रैल, 2022 से 20 प्रतिशत वृद्धि की है। इसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारी सरकार को कोरोना का सामना करना पड़ा, लम्पी का सामना करना पड़ा और कोरोना और लम्पी में मैंने स्वयं ने देखा है इन आंगनबाड़ी की बहनों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन-रात, मेरा तो यह मानना है कि इन्होंने दिन-रात मेहनत करके कोरोना में जाग्रति का बहुत बड़ा काम किया है। घर-घर जाग्रति अभियान चलाया, पैम्फ्लेट बांटे, उस समय इन्होंने जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और यह आंगनबाड़ी तो हमारे राजस्थान में ही हमारे देश की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी जी ने बांसवाड़ा में गढ़ी तहसील से प्रारम्भ की थी और आज पूरे भारत में एक वट वृक्ष की तरह विशाल रूप ले चुकी है। सभापति महोदय, मेरा आग्रह है, हालांकि पिछले बजट में बीस प्रतिशत मुख्य मंत्री जी ने इसमें वृद्धि की है लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आंगनबाड़ी की ये जितनी भी बहनें हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, आशा सहयोगिनी हैं, साथिन हैं, इनको नियमित कर्मचारी बनाया जाये। इसके अलावा इनको कम से कम 18,000 रुपये निश्चित मानदेय दिया जाये क्योंकि जिस परिस्थिति में यह जान को जोखिम में डालकर काम करती हैं, इनको यह मानदेय बहुत कम मिलता है। कोरोना में मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। शिक्षा कर्मियों ने, कार्मिकों ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन मेरा यह दावा है कि आंगनबाड़ी की इन कार्यकर्ताओं का चिकित्सा कर्मियों से कम योगदान नहीं रहा है। चिकित्सा कर्मियों ने तो इलाज किया है लेकिन इन्होंने जान जोखिम में डालकर, घर-घर जाकर जो जागृति की, मास्क वितरण करना, लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिये, निश्चित रूप से हमें इन आंगनबाड़ी की बहनों को और अच्छी तरह से देखना चाहिये।

(श्री बाबूलाल नागर)

(समय: 13.00 बजे)

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने राजस्थान में नरेगा योजना को खतम-सा कर दिया था। इस बार हमारे प्रभावी क्रियान्वयन से नरेगा में लोगों को रोजगार देने में राजस्थान देश में अव्वल है। सभापति महोदय, 2022-23 में अब तक 22 करोड़ 12 लाख 53 हजार मानव दिवसों का सृजन किया गया है, जो कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है।

सभापति महोदय, सरकार ने 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान चलाया। जो हमारे लंबित कार्य रह गये, उसका फोलो-अप कैम्प किया। फोलो-अप कैम्पों में 74,160 पट्टे जारी किये। गांव की तर्ज पर शहरों में भी मुख्य मंत्री जी ने रोजगार सुनिश्चित करने के लिये शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। प्रति व्यक्ति 100 दिवस रोजगार की उपलब्धता की है। सरकार में कोई भूखा न सोये, इसके लिये मुख्य मंत्री जी ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इसमें 8 रुपये में लोगों को सम्मानपूर्वक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सभापति महोदय, इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। सरकार को इसका और भी फैलाव करना चाहिये।

सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 में रीको ने हमारे 17 औद्योगिक क्षेत्र की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। मेरे यहां बिचून में भी अभी हाल ही में एक जारी हुआ है, हालांकि यह 2019 के बजट का था लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको अब जल्दी से स्थापित किया जाये।

सभापति महोदय, विधायकों को 10 करोड़ रुपये मिसिंग लिंक और नॉन-पेचेबल के लिये दिये गये। यह एक ऐसा यादगार काम था, जो सड़कें सरकार के नोर्म्स में नहीं आ रही थीं, उन सड़कों को हमने मिसिंग लिंक के नाम पर बनाया। इससे पूरे राजस्थान में सरकार की प्रशंसा हो रही है।

सभापति महोदय, 2022-23 में 480 ग्रामीण, 195 शहरी, 13 प्राथमिक राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में रूपान्तरित किया गया, यह सरकार का अभिनव प्रयोग है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी इस बार बजट में, हालांकि हमारे यहां 19 जगह महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल की हैं, इनकी इतनी डिमांड है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, बच्चे वेटिंग में हैं, राजस्थान में जितने ज्यादा अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेंगे, उतना ही राजस्थान में हमारा शिक्षा तंत्र मजबूत होगा।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, 2022-23 में 1054 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे उच्च माध्यमिक विद्यालय किया है। कल्ला जी, उसमें मेरे यहां अभी एक ही किया है, मेरे हिसाब से इसमें आप दो और कर देते। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मेरे दो और कर दें। आपने 3,834 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया, कोई राजनीति नहीं, कोई अनुशंसा नहीं। राजस्थान के जितने सैकण्डरी विद्यालय थे, सारे विद्यालयों को आपने उच्च माध्यमिक विद्यालय किया। निश्चित रूप से इसका राजस्थान में बहुत अच्छा संदेश गया।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई। कक्षा 1 से 8 तक लगभग 69 लाख विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। बच्चों को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बनाने के लिये यह भी एक महती योजना है।

सभापति महोदय, 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 69 लाख विद्यार्थियों को यूनिफार्म के दो-दो सैट एवं सिलाई के लिये 200 रुपये प्रति विद्यार्थी दिये जा रहे हैं। कल्ला जी, यह 200 रुपये कम हैं, बच्चे पीड़ा व्यक्त करते हैं। हालांकि मैं खुद वितरण करने के लिये गया हूं, आपकी यूनिफार्म के लिये बच्चे हंस-हंस कर, नाच-नाच कर आपका स्वागत कर रहे हैं, सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन यह सिलाई के 200 रुपये बहुत कम पड़ते हैं इसलिए इसको भी बढ़ाना चाहिये।

सभापति महोदय, 2022-23 में राजस्थान में राज्य सरकार ने करीब 117 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले, 61 कन्या महाविद्यालय, 29 कृषि महाविद्यालय खोले। गत चार वर्षों में 240 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोल दिये हैं। राजस्थान में 200 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का निर्माण भी आपने चालू कर रखा है। 60-70 साल में राजस्थान में जितने महाविद्यालय बने, उतने आपने राजस्थान में चार साल में सरकारी महाविद्यालय बना दिये, निश्चित रूप से यह भी एक अच्छा प्रयास हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कल्ला जी को कि आपने शिक्षकों की भर्ती शुरू की। इन विद्यालयों के प्रति इतना आकर्षण हुआ है, जितनी जल्दी हो आप इन शिक्षकों की भर्ती करके विद्यालयों को दे दें तो मैं समझता हूं कि पूरा राजस्थान आपकी जय-जयकार करेगा।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, राजीव गांधी स्कालरशिप फोर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, 2021 राजस्थान में लागू की है। इसमें प्रति वर्ष 200 होनहार विद्यार्थियों का शीर्ष 150 विदेशी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन के लिये पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है। मुख्य मंत्री जी ने यह एक ऐसी ऐतिहासिक योजना लागू की है, राजस्थान सरकार ने इतना ऐतिहासिक काम किया है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी, बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षण संस्था में गरीब का बेटा भी बिना एक पैसा खर्च किये सरकार के खर्च पर नि:शुल्क वहां अध्ययन कर सकता है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान में ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया। इन खेलों में 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। मेरे यहां खुद मुख्य मंत्री जी शुभारंभ करने के लिये आये। उस दिन मैंने मुख्य मंत्री जी से एक ही आग्रह किया था कि आप पंचायत समिति लेवल पर ध्यानचंद स्टेडियम राजस्थान में खोलना चाह रहे हैं, आपने शुरू भी कर दिया है, लेकिन राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक में बच्चों का जो जज्बा, जो जोश देखा है, बच्चे झूम रहे थे। सभापति महोदय, बच्चे इतने खुश थे, मैंने उस दिन आग्रह किया कि राजस्थान की तमाम पंचायतों में पंचायत लेवल पर आपको मॉडल खेल मैदान बनाने चाहिये। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा, मेरे यहां 60 ग्राम पंचायतें हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी की, सरकार की मंशा के अनुसार 64 खेल मैदान सैंक्शन हो गये। आज हमारे युवाओं में इतना जोश है, छात्र-छात्राओं में इतना जोश है कि 50 लाख रुपये का एक मॉडल खेल मैदान पंचायत स्तर पर यह सरकार बना रही है। आज तो खेल से सरकारी नौकरी भी मिलती है। सरकार ने सरकारी भर्ती में दो परसेंट आरक्षण लागू कर रखा है, इसलिए निश्चित रूप से हमारे बच्चों को फायदा होगा।

सभापति महोदय, खरीफ 2022 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में 65 लाख 62 हजार हैक्टेयर क्षेत्र का बीमा कर 2 करोड़ से अधिक फसल बीमा पालिसी आपने सृजित की हैं, यह एक अच्छा प्रयास है। रबी में भी आपने 2022-23 में दिसम्बर, 2022 तक एक करोड़ से भी अधिक पालिसी सृजित की हैं। सभापति महोदय, मैं इस संबंध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन कम्पनी के कर्मचारियों ने किसानों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात कर रखा है। इन्होंने किसान की जो खरीफ की फसल थी, उसकी सर्वे रिपोर्ट में हेरफेर की है और अपने अनुसार कम्पनी के पोर्टल पर अपलोड कर दी है। सभापति

(श्री बाबूलाल नागर)

महोदय, मेरे पास रिकार्ड है। मेरे क्षेत्र के चोरू गांव में बद्रीनारायण, उसका जब सर्वे हुआ तो उसके हस्ताक्षर कराये, उसकी 4.5 हैक्टेयर जमीन सर्वे फार्म पर दर्शायी। इसके बाद कम्पनी वालों ने उसको कम्पनी के पोर्टल, 1 हैक्टेयर पर 2.56 कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसान, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, तीनों का पैसा, इनको जितना पैसा देते हैं, उससे इन्होंने इतना गड़बड़जाल फैला रखा है। यह कोई बड़ी कम्पनी है, कोई बहुत बड़े सेठ की है। देश का बहुत बड़ा सेठ इस कम्पनी का मालिक है। इसने जितने षड्यंत्र कर रखे हैं, भ्रष्टाचार कर रखे हैं, सभापति महोदय, मैं सबूत दे सकता हूं कि इस कम्पनी के लोग खुद सर्वे करने नहीं आते हैं। इन्होंने भी ठेके पर दे दिया है और उनको इस बात के लिए दे दिया है कि किस तरह से किसानों की जमीन की नाप कम करें। किस तरह से किसानों को 50-50, 100-100 रुपये, सभापति महोदय, मेरे पास कई फार्म हैं, जिसमें उनका जो मैसेज आया, 100 रुपये, 80 रुपये और आप तीन, चार और पांच हजार रुपये ले रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा अच्छी है, इतने बड़े लेवल पर सरकार ने फसल बीमा पालिसी सृजित की है लेकिन जब किसान को फायदा ही नहीं हो रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अच्छा हो सरकार खुद, नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक पार्ट राज्य सरकार का, एक पार्ट केन्द्र सरकार का और एक पार्ट किसान का। जितना पैसा उस कम्पनी को दिया जा रहा है, जितना पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके 10वें हिस्से का पैसा भी किसान को नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार को खुद की अपनी पालिसी लानी चाहिए। यह प्रधानमंत्री बीमा योजना थोड़े ही है, यह तो किसानों को ठगने की योजना हो गयी। इसलिए सभापति महोदय, मैं इस पर सरकार का ध्यान चाहिए। सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे दूंगा। मेरे पास उनके दस्तावेज हैं कि कैसे-कैसे उन्होंने फर्जीवाड़े किये हैं।

सभापति महोदय, कृषि उपज मण्डी दूदू को बजट घोषणा में, मैंने आज भी मंत्री जी से कहा था, बजट में दूदू की मण्डी को स्वतन्त्र मण्डी बनाने की बात की थी, यह पूरा समय चला गया। दो साल किसानों के काले कानून के आ गये थे, उसके चक्कर में स्वतन्त्र मण्डी नहीं बनायी, लेकिन अब तो बनाओ। मैं तो यह भी कह रहा हूं कि जुरिस्डिक्शन का प्रोब्लम नहीं है। मेरा क्षेत्र ही है, मेरे यहां दे दें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। 10-15 करोड़ का वहां बना हुआ है। आपको केवल स्वतन्त्र मण्डी घोषित करनी है। इसी तरह बजट

(श्री बाबूलाल नागर)

में दूदू से भाटीपुरा एक राजमार्ग के लिए मुख्य मंत्री जी ने 127 करोड़ की घोषणा की थी, उसकी सैंक्शन निकल गयी। मैंने इसमें थोड़ा-सा निवेदन दूदू में बाईपास बनाने के लिए किया था। सरकार उसमें मान गयी, बाईपास तय कर दिया। सभापति महोदय, अब मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो, दूदू से भाटीपुरा की रोड का काम चालू करें।

सभापति महोदय, इसी तरह बजट घोषणा में बिन्दु 77 में जनसंख्या दबाव के कारण विकास की दूरगामी योजना-सैटेलाइट टाउंस बनाने की सरकार ने घोषणा की थी। चाकसू, बस्सी, चौमूं, बगरू, फागी एवं चन्दवाजी, इनके लिए मास्टर प्लान के साथ मैट्रो/लाइट रेल से जोड़ने की डी पी आर बनाया जाना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब आपने लोगों को आस जगा दी है, जब आपने डी पी आर बनाने की घोषणा की, सभापति महोदय, अभी तक इसमें आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बजट घोषणा 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में दस लाख नये परिवारों को जोड़ने की बात की। यह खाद्य सुरक्षा केन्द्र सरकार का है। जब देश में मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, यू पी ए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने पूरे मुल्क में इसको लागू किया था। अभी खाद्य मंत्री जी भी बैठे हैं। राजस्थान में आपने फार्म भरवाये। आपने इस योजना में शहरी क्षेत्र में 31 श्रेणियों को, ग्रामीण क्षेत्र में 28 श्रेणियों को योग्य माना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 16 लाख 20 हजार 90 आवेदन प्राप्त हुए। अब तक केवल 2 लाख 43 हजार 266 परिवारों को आपने जोड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में साढ़े 13 लाख पैंडिंग हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपका जो पोर्टल, उसमें आपने अभी खोला। आपने अभी-अभी भूमिहीन परिवारों का खोला है पर अभी भी लघु कृषक और सीमान्त कृषक के पोर्टल को खोला ही नहीं है। इनके पोर्टल पर इनके आवेदन दर्शा ही नहीं रहे हैं। राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में लघु और सीमान्त कृषक हैं जो कि पात्रता रखते हैं। इस खाद्य सुरक्षा के पात्रता रखते हैं, लेकिन जब पोर्टल में ही नहीं दिखा रहे हैं तो उससे काफी गरीब लोगों को, किसी कारण से उनकी बन्द हो गयी थी, किसी कारण से तीन महीने उनका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं लिया, कट गया, मजदूरी में चले गये, कोरोना में नहीं लिया। गरीब लोग हैं, भूमिहीन का आपने अभी-अभी खोला ही है। उसका भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जब यह सरकार इतना

(श्री बाबूलाल नागर)

लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है, राजस्थान में ऐसी-ऐसी योजना ला रही है, जो न कभी बनी थी और न कभी बनेगी। आम आदमी को केन्द्र बिन्दु मानकर यह सरकार काम कर रही है। उस जमाने में जब 4 रुपये 60 पैसे, 70 पैसे, बी पी एल को गेहूं मिलता था, राजस्थान में प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दो रुपये किलो में गेहूं किया। जब देश में दो रुपये किलो में खाद्य सुरक्षा लागू हुआ तो हमारे यहां पर एक रुपये था। हमेशा मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता रही। उस जमाने में जब बी पी एल हट गये थे, उनको इंसटेंट बी पी एल में जोड़ा ताकि गेहूं से वंचित नहीं हो। हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है और गरीब को केन्द्र बिन्दु मानकार योजना बनाती है, तो मैं समझ रहा हूं कि आपको कोई न कोई तरीका निकालकर, आपने जब दस लाख का कहा है, अभी तक आपने दो, तीन, चार लाख ही जोड़े हैं, दस लाख में तो आप वैसे ही बजट घोषणा में थे, मंत्री महोदय, आपको इसमें निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी के साथ बैठकर, ये राजस्थान के गरीबों का मामला है, उनको रोटी मिल जाये और अब तो स्थिति ऐसी आ रही है, नि:शुल्क गेहूं मिलने वाला मामला है, गरीब को गेहूं नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको दिखवायें।

सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं और आपसे यही आग्रह करता हूं कि जुग जियो सरकार भी जुग जियो, जो ऐसा कल्याणकारी बजट, केवल घोषणा ही नहीं, इसको राजस्थान में लागू करके दिखाया, एक मैसेज दिया कि सरकार में घोषणा ही नहीं की जाती है, जो कहते हैं उसको करते हैं, यह आपने साबित किया। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने 23 जनवरी को विधान सभा में 281 बिन्दुओं वाला अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सरकार के कामकाज का आईना होता है। हम सबको पता है कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां बतायीं, लेकिन ये उपलब्धियां केवल बजट घोषणा और कागजों में सिमटकर रह गयीं। हमको

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

पता है कि धरातल पर जनता या मजदूर को इन घोषणाओं का कोई लाभ नहीं मिला है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोक कल्याण के कार्य जैसे-पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, सुरक्षा, इन बिन्दुओं पर काम करते हुए आम जनता की भलाई के लिए काम करे। चार वर्षों से सरकार अपने घरेलू झगड़ों से नहीं उबर पायी है, इस वजह से लोगों की क्षति हुई है।

बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, उनको अधिकारी भी धरातल पर उतार नहीं पाये हैं। हम सबको पता है सरकार ने चार वर्ष में जो-जो भी घोषणा की है, चाहे वह विकास पथ निर्माण की हो, चाहे मिनी विकास पथ की हो, चाहे पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला की हो, चाहे प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोलने की, चाहे मोहल्ला क्लिनिक खोलने की हो, चाहे किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा हो, चाहे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे गरीब परिवार का खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने हेतु चार वर्ष से लंबित मामले हों। बजरी माफिया, जो कि पूरे प्रदेश स्तर पर कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जब कोई भी घटना घटित होती है तो अपराध करने में भी पीछे नहीं हटते।

राज्य सरकार ने जो नौकरियां देने का वादा किया, वह भी आज धरातल पर नहीं उतरा है।

सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं किसानों की बात करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। जिस प्रकार राज्य सरकार ने समृद्ध किसान, खुशहाल किसान की बात की है, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत साबित हुई है। जब किसानों को बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, समय पर डी ए पी या यूरिया की सप्लाई नहीं होती है और डी ए पी मिलती है तो भी अधिक मूल्य पर उनको बाजार से लेनी पड़ती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में भी पिछले कई महीनों से बिजली की अघोषित कटौती ने किसानों को, आमजन को, सभी को परेशान कर रखा है। चाहे 6 घंटे थ्री फेज बिजली की बात हो, चाहे 18 घंटे सिंगल फेज बिजली देने की बात हो, दिन में बिजली देने की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ घोषणा बनकर रह गयी हैं।

आज राजस्थान को बिजली के क्षेत्र में सरकार आत्मनिर्भर बताती है, परन्तु जो हालात हमारे सामने हैं, गांव में न तो बिजली है, न ट्रांसफार्मर हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि किसान मित्र योजना के तहत लगभग 8

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

लाख 93 हजार किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है, मैं कहना चाहता हूं कि जब बिजली आ ही नहीं रही है तो बिल तो अपने आप ही शून्य हो जाएगा। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार कहती है कि हम 72 घंटे में ट्रांसफार्मर देंगे, लेकिन 72 घंटे तो छोड़िए, किसानों को 72 दिन में भी ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहे हैं। किसान हर दिन विद्युत कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। मेरे यहां नये कनेक्शन की बात करूं तो जिन किसानों ने 2018 के बाद में डिमांड जमा कराए हैं, एक साल से ऊपर हो गया है जब मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की कि हम किसानों की जो वरीयता सूची है, इसको खतम करके सभी किसानों को कनेक्शन जारी करेंगे, यह घोषणा आज भी मात्र घोषणा बनकर रह गयी हैं। किसान विद्युत कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। एक वर्ष पूर्व डिमांड जमा होने के उपरांत भी आज खम्भे खड़े कर दिए, कहीं केबल नहीं डली है, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचे हैं। यह आज एक लंबित मामला हो गया है।

सभापति महोदय, आपने 98 नम्बर पाइंट पर कहा, भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन जब गांव के व्यक्ति को समय पर बिजली, समय पर पानी, समय पर चिकित्सा, शिक्षा, अच्छी सड़कें, ये सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिलेगी तो भारत की आत्मा गांवों में जरूर बसती है, लेकिन राजस्थान सरकार यहां पर सुविधाएं पहुंचाने में विफल रही है।

राज्य सरकार ने हमारे जो ट्यूबवैल की घोषणा की, उसमें कई ट्यूबवैल आज भी लंबित हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के फारकिया ग्राम की बात बताना चाहूंगा कि वहां पर ट्यूबवैल खुदे लगभग एक साल पूरा होने को आया है, परंतु आज भी बिजली विभाग और पेयजल विभाग में आपसी सामंजस्य नहीं होने की वजह से वह कनेक्शन अभी तक भी लंबित हैं।

कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। हम सबको पता है कि आज राजस्थान साम्प्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा है, चाहे 8 अप्रैल, 2019 को टोंक में हो, चाहे 24 सितम्बर, 2020 को डूंगरपुर में हो, चाहे 11 अप्रैल, 2021 को बारां में हो, 19 जुलाई, 2021 को झालावाड़ में हो, 2 अप्रैल, 2022 को करौली में हिन्दू नववर्ष के मौके पर हो, चाहे 22 अप्रैल को अलवर जिले में मंदिर तोड़ने को लेकर हो, चाहे 2 मई, 2022 को जोधपुर के जालौरी गेट पर श्री परशुराम जयंती और

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

ईद को लेकर आपसी झगड़ा हो, 10 मई को भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में युवक की हत्या हो, चाहे 27 जून, 2022 को उदयपुर में बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें गला काटकर हत्या वाला प्रकरण हो, चाहे 11 मई को हनुमानगढ़ में विश्व हिन्दू परिषद कार्यकर्ता पर हमला हो। यह शांत प्रदेश है और हम सबको पता है पुलिस प्रशासन, केवल साम्प्रदायिक तुष्टिकरण के लिये सरकार द्वारा पुलिस तंत्र को फेल और निकम्मा बनाया जा रहा है। प्रदेश में 85 प्रतिशत साम्प्रदायिक घटना अंजाम दी जा रही है।

बात करें प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो अपहरण, डकैती, मर्डर में राजस्थान नंबर वन है। कहते हैं कि जहां का राजा केवल अपनी कुर्सी बचाने के उद्देश्य से ही काम करता है तो उस देश का धणी-धोरी कोई नहीं होता है। आज प्रदेश की पुलिस का स्लोगन बदलकर 'आमजन में भय और अपराधियों में सांठगांठ' वाला हो गया है। आए दिन कोई न कोई गैंग सामने आ रही है। कोई न कोई नए गैंग बनते हैं और खुले आम हमारी सरकार को चुनौती देते हुए भरे बाजार में ही घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। चाहे गोलीबारी हो, चाहे अपहरण हो, चाहे डकैती हो, राज्य में अपराधियों को कोई डर नहीं है कि ये घटनाएं अंजाम देने से हमारा क्या होगा।

हम अगर बिजली की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी राजस्थान सरकार में आत्मनिर्भर होने के बावजूद जीरो रीडिंग के बिल भेजकर, अगले महीने हजारों के बिल भेजकर आमजन से मनमाने बिल वसूली करने की बात की जा रही है। किसानों को पूरे समय बिजली उपलब्ध नहीं करायी जा रही है और जो बिजली दी जा रही है वह भी कड़ाके की ठंड में मध्य रात्रि में दी जा रही है।

पेयजल योजना में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की बात करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। पेयजल में हमारे मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार नसीराबाद वृहद ग्रामीण पेयजल योजना की जब घोषणा की तो हमें लगा कि समय पर पेयजल उपलब्ध होगा। नसीराबाद ग्रामीण पेयजल योजना की स्वीकृति अभी तक जारी नहीं हो पाई है और न ही इसके टेंडर लगे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि जब घोषणा हो गयी तो आम जनता से जुड़ी हुई इस योजना को क्यों रोका जा रहा है? जल जीवन मिशन के माध्यम से केन्द्र सरकार ने जो हर घर नल पहुंचाने की, नल से

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

जल पहुंचाने की जो जिम्मेदारी ली है, उसके लिये हम सब केन्द्र सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी, जो यह महती योजना लेकर आए और आम जनता और गरीबों को गांव में गुणवत्तायुक्त पेयजल पहुंचे इसकी व्यवस्था के लिये यह योजना लेकर आए हैं। हमारे प्रदेश में कई योजनाएं बन रही हैं, परंतु मैं पेयजल मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि जो यह नसीराबाद ग्रामीण पेयजल योजना है, इसको रोका जा रहा है, इसको जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं क्योंकि इसमें अनेक पंचायतें हैं। समय पर पेयजल सप्लाई नहीं हो पा रहा है और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस योजना के नहीं पहुंचने से आम जन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इससे जुड़े हुए गांव चाहे रामसर हो, चाहे श्रीनगर हो, पुष्कर विधान सभा के भी गांव इस योजना के माध्यम से जुड़ेंगे तो इस योजना को जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए। पेयजल विभाग में हम जब भी बात करते हैं तो कहते है कि जब तक आपका रिजर्वेशन आफ वाटर सिंचाई विभाग से नहीं बढ़ेगा तब तक आपको पेयजल के लिए इस योजना का अप्रूवल हम नहीं कर सकते हैं और न ही यह अप्रूव्ड होगी। इस योजना के बजाय हमारे जल जीवन मिशन के माध्यम से हर गांव में छोटी-छोटी योजनाएं बनाई जाएं ताकि अगर ये योजना शुरू नहीं हो पाए तो लोगों को पानी उपलब्ध हो पाए। जड़वासा जो हमारा ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर है, वह अभी तक भी पेयजल के किसी सोर्स से नहीं जुड़ पाया है। वह बीसलपुर पेयजल योजना से अभी नहीं जुड़ा है। आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी जड़वासा की पेयजल योजना को भी मंजूरी दी जाए। राजस्थान पेयजल की दृष्टि से बहुत पीछे है। हम सबका यह मानना है कि जल जीवन मिशन की योजना जल्दी से जल्दी पूरी की जाए।

सिंचाई एक महत्वपूर्ण विषय है और हमारे किसानों की समृद्धि तभी आएगी जब हम किसानों के लिए सिंचाई के सोर्सेज को डवलप करेंगे। सिंचाई के लिये हमारी केन्द्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम समय पर पूरा करें। हमारे किसानों को कुओं के माध्यम से सिंचाई के लिए कनेक्शन समय पर जारी किये जाये।

सभापति महोदय, आज हम सबको पता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भामाशाह योजना में तीन लाख के इलाज का प्रावधान किया और केन्द्र सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की,

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

जिसमें पूरे भारत में अनुबंधित प्राइवेट हास्पिटल में पांच लाख तक का इलाज नि:शुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है, आपने दोनों को मिलाकर नया नाम चिरंजीवी कर दिया है। भामाशाह योजना में महिलाओं की डिलिवरी हो, चाहे सिजेरियन हो, चाहे बच्चेदानी का आपरेशन हो, भामाशाह योजना में शामिल था पर आपने चिरंजीवी योजना में इसको शामिल नहीं करके महिलाओं के साथ कुठाराघात किया है। हम सब यह मांग रखते हैं कि महिलाओं की इन बीमारियों को भी चिरंजीवी में शामिल करें। आयुष्मान योजना में पूरे भारत में अनुबंधित हास्पिटलों में इलाज नि:शुल्क था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे चिरंजीवी में शामिल कर राजस्थान तक सीमित कर दिया है। राजस्थानियों को पूरे भारत में पांच लाख तक के नि:शुल्क इलाज से वंचित करके आपकी सरकार ने कुठाराघात किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पीसांगन जो सी एच सी भी है और उप खण्ड स्तर का चिकित्सालय है, वहां पर चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, महज एक डाक्टर वहां पर उपलब्ध है, इनको किया जाए। जो मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना है, इसमें जब मरीज यहां पर पहुंचते हैं तो आधी बार तो मशीनें खराब मिलती हैं या बंद मिलती हैं। डाक्टर से पूछने पर वे कहते हैं कि हमारे डायरेक्टर साहब के स्तर पर मशीनों को ठीक होने का अनुबंध हो रखा है, इसलिए वहां से जब आएंगे तब ही ठीक होगी। यह योजना धरातल पर सुचारु रूप से चले, इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

शिक्षा के क्षेत्र में हम सबको पता है। आपने पैरा नम्बर 187 में कहा है कि 1 हजार 43 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा 3 हजार 834 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। 548 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 143 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। साथ ही, राजकीय विद्यालयों को अंग्रेज़ी माध्यम के राजकीय विद्यालयों में रूपान्तरित किया गया है। क्रमोन्नत विद्यालयों के सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में शिक्षकों की परेशानी से हमारे विद्यार्थी परेशान हैं। विद्यार्थी अपनी शिक्षा बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। डी

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

एम एफ टी के माध्यम से भी 4 या 5 विद्यालयों को ही कमरों की सुविधा दी गई है। इसका भी दायरा बढ़ाते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें हॉल का निर्माण हो, कमरों का निर्माण हो ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।

मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार प्राइवेट स्कूलों में पानी-बिजली की मूलभूत सुविधाएं होती हैं हमारे सरकारी विद्यालय में भी, जो जल जीवन मिशन में ग्रामीण आबादी के बीच विद्यालय हैं, उनमें नल कनेक्शन जारी किया जाए। राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्णय हो, ताकि सभी विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बिजली के क्षेत्र में, नसीराबाद छावनी परिषद् में एक महीने से रोड लाइट में विद्युत कटौती सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में हो रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार और नगर परिषद् व नगरपालिकाओं के बिल भी बकाया हैं, उसी अनुपात में छावनी परिषद् का बकाया है, इस पर भी निर्णय लिया जाए। हमारी समय-समय पर जिला कलेक्टर साहब से भी वार्ता हुई है। एम डी साहब, बिजली विभाग के और अधिकारी बैठकर इस पर निर्णय करें, क्योंकि सभी नगरपालिकाओं में लगभग बकाया रहता है। किसी में 50 लाख, किसी में 90 लाख, छावनी परिषद् में भी 35 लाख के लगभग बकाया है। छावनी परिषद् के साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। आम जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। हम सबको पता है, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से डकैती, चोरी की घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है, आपराधिक तत्व हावी हो रहे हैं। कानून-व्यवस्था की स्थिति नसीराबाद छावनी परिषद् में खराब हो रही है। इसको सुधारने के लिए अविलम्ब विद्युत कनेक्शन को चालू करवाकर, इनका आपस में समन्वय करके, आगे जारी रखा जाए। मार्च के आस-पास इनका जो भी निस्तारण हो, उसके हिसाब से और नगरपालिकाओं में जो सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया कराती है, वही छावनी परिषद् में भी कराए।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय पीसांगन उप खण्ड मुख्यालय है, वहां पर राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां भी राजकीय महाविद्यालय की स्थापना आगामी वर्ष में शुरू हो।

अभिभाषण के पैरा नम्बर 177 में राज्य सरकार ने सड़कों का जिक्र

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

किया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे नसीराबाद में दिसम्बर 2020 में, करीब एक वर्ष के लिए आंदोलन हुए। मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में 10 करोड़ की सड़कें पास कीं, वे आज भी टेंडर की प्रक्रिया में हैं। टेंडर लगभग पूर्ण हो चुके हैं, पर अभी तक भी काम शुरू नहीं हुआ है। पिछले बजट में 5 करोड़ की नॉन-पेचेबल, मिसिंग लिंक योजना में जो सड़कें स्वीकृत हुई हैं उनमें कई सड़कें आज भी शुरू नहीं हुई इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर कार्यवाही की जाए। स्टेट लेवल पर एक मोनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, ताकि बजट घोषणा में जो इस प्रकार की देरी कर रहे हैं उन पर कार्यवाही की जाए। किस वजह से रोड शुरू नहीं हुई उन पर कार्यवाही करके काम चालू करवाया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिले।

कानून व्यवस्था की स्थिति में मैं नसीराबाद विधान सभा की बात करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने बायोडीजल प्राधिकरण का गठन किया और बायोडीजल को ईंधन के रूप में काम लेने की मान्यता दी। नसीराबाद में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा काम है, यहां ट्रांसपोर्टर को परेशान करने के लिए, जिनको लाइसेंस जारी कर रखे हैं उनके लाइसेंस पर अनावश्यक रूप से पुलिस थानों पर दबाव बनाकर, या किसी कारणवश इन पर कार्यवाही के नाम पर जबरन दबाव बनाने का काम राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार से हमारी मांग है, इसमें एफ आई आर दर्ज हुई, राजस्थान हाईकोर्ट ने उस समय उसको खारिज करते हुए, जब्त वाहनों को छोड़ने का आदेश दिया। हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने उस आदेश को रिलीज करने का आर्डर जारी किया, उसके बाद भी इसमें विलम्ब करते हुए अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। अत: मोनिटरिंग करते हुए पुलिस मुख्यालय से आदेश जारी किए जाएं, कि इस तरह के काम-काज में, जहां लाइसेंस जारी हो चुके हैं, प्रक्रिया के अनुसार काम-काज हो रहा है, वहां आम जनता को परेशानी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाए।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 2022 में चना समर्थन मूल्य पर खरीद किया। सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान में चना से ज्यादा बाजरा, रायड़ा, गेहूं का उत्पादन होता है। सरकार ने जिन्स वालों की नई खरीदी करके, चना भी अंतिम समय में खरीद किया। सभी किसानों ने अपनी जिन्स बाजार में बेचकर इतिश्री की। किसानों को बाजरा 2350 की जगह 1500-1600 रुपये में बाजार में बेचना पड़ा। आज सरकार की उदासीनता के कारण किसानों को कम कीमत पर बाजार में बेचना पड़ रहा है।

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

किसानों को बिना ब्याज मिलने वाले अल्पकालीन ऋण में भारी कटौती की गई है। प्रत्येक किसान को कोआपरेटिव सोसायटी के माध्यम से एक से डेढ़ लाख तक अल्पकालीन ऋण ब्याज मुक्त दिया जाता है, वह चार वर्षों में 15 हजार से 20 या 25 हजार तक सीमित हो गया है। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इसकी सीमा बढ़ाई जाए तथा किसानों को समय पर यह ऋण उपलब्ध करवाया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन विभाग की मांग रखना चाहता हूं। कोविड के समय परिवहन की रोडवेज बसों को बंद किया गया। उसके बाद राज्य सरकार ने इन बसों को बेच दिया या उपलब्ध नहीं करा पाए, उस कारण से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बड़े रूट, चाहे उप खण्ड मुख्यालय हो, जिला चिकित्सालय को जोड़ने वाले हों, हाईकोर्ट हो या जिला न्यायालयों को जोड़ने वाले हों, विद्यार्थियों को व सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि समय पर परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होने से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

कई बार विद्यार्थी एग्जाम के टाइम बसें उपलब्ध नहीं होने पर एग्जाम नहीं दे पाते। पीसांगन उप खण्ड मुख्यालय पर कोविड के समय हर घंटे रोडवेज बस की सुविधा उपलब्ध हुई पर आज सिर्फ दो बसें अजमेर जिला मुख्यालय के लिए है और एक मात्र बस जयपुर के लिए है। इस व्यवस्था को और सुधारा जाए। हमारे और भी बड़े क़स्बे हैं, रामसर हो या श्रीनगर हो, यहां से अजमेर मुख्यालय को जोड़ने वाली बसें भी नियमित रूप से नहीं चल रही हैं। बसों को बंद कर दिया गया है, इनको पुन: शुरू किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब तक बसें उपलब्ध नहीं हों तब तक सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाए कि जो बसें निजी परिवहन सेवा से उपलब्ध हो जाएं, उनको परमिट जारी किए जाएं, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

पैरा 152 में आम जनता को पब्लिक फ्रेंडली वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनाने की बात कही। मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि स्वागत कक्ष बनाने से पुलिस के व्यवहार में आम जनता के प्रति कोई सुधार होना अभी अपेक्षित है। पुलिस थानों में परिवादियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वह उचित नहीं है।

(श्री रामस्वरूप लाम्बा)

पैरा नम्बर 21 में प्रदेश को निरोगी राजस्थान की ओर अग्रसर किया है। हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, इनको सुचारु किया जाए।

पैरा नम्बर 266 में राजस्थान को शूरवीरों की धरा बताया। देश की रक्षा के लिए सैकड़ों वीर सपूतों ने बलिदान दिया।

श्री सभापति: समय है आज, कोई दिक्कत नहीं।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): इसी सन्दर्भ में मेरा आपसे आग्रह है, देश का चौथा स्तम्भ कहा जाने वाला मीडियाकर्मी है वह आज सुरक्षित नहीं है। इन पर लगातार हमले हो रहे हैं। साथ ही दस साल पहले हमारे मुख्य मंत्रीजी ने नायला में मीडियाकर्मियों को पत्रकार आवास योजना के तहत प्लाट देने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी 571 आवासी एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं, इनकी भी सुनवाई की जानी चाहिए।

पैरा नम्बर 191 में विद्यार्थियों को आपने यूनिफार्म के दो सैट एवं सिलाई के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी के दिये हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि ऐसा टेलर मुझे भी बता दें जो 200 रुपये में दो सैट यूनिफार्म की सिलाई कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बच्चों के साथ मजाक कर रही है।

पैरा नम्बर 107, 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021' के तहत आम जनता से जुड़े मामले अधिकारियों के सामने दर्ज हुए हैं पर यह कहते हुए परेशानी होती है कि इनका निस्तारण आज भी लंबित है। आपने 74 हजार 160 पट्टों का जिक्र अपने अभिभाषण में किया है, लेकिन अभियानों में जो आम लोगों की समस्याएं आयीं उनका जिक्र आज तक नहीं हो पाया है।

जो हमारे पर्यटन और धार्मिक स्थल हैं, उनको जोड़ने की राजस्थान सरकार ने बजट में जो घोषणा की है, उसको भी आज तक पूरा नहीं किया है। जो धार्मिक दृष्टि से हमारे महत्वपूर्ण कस्बे हैं, चाहे मंदिर हैं, उनको आज तक भी, चाहे वे सड़कविहीन हों या सुविधाविहीन हों ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में और बोल लें आप।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि 'जिस प्रकार सरकार ने झूठों का फिर जुमला फेंका सत्ता के चौबारों से, जनता अब नहीं मूर्ख बनेगी 23 में दुबारा से।'

यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती शोभारानी कुशवाह (अनुपस्थित), श्री विट्ठल शंकरजी अवस्थी (अनुपस्थित)। श्री रूपा रामजी मुरावतिया।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपालजी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

महोदय, हजारों सालों से जब-जब मनुष्य पृथ्वी पर आया है तो सच और झूठ, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, यश और अपयश की लड़ाई हुई है, होती रहती है, होगी भी। जब सच अपना प्रभाव दिखाता है, ताकत में आता है, सच के अनुसार कार्य होते हैं तो सतयुग की तरफ जाते हैं और जब सच कमजोर पड़ने लगता है व असत्य, अधर्म की जीत होने लगती है तो फिर मानव पर संकट आता है।

मैं इन्हीं दो लाइनों से यह बात आपके माध्यम से सरकार को भी कहूंगा और आपके माध्यम से मैं जो भी मेरी बात सुनेगा, उसको यह कहने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि सच की जीत होती है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जीत उसी की होगी जो योजनाबद्ध तरीके से संगठित होकर ताकत के साथ लड़ेगा। मैं अकेला बैठा हूं, चार आदमी बैठे हैं, दो आदमी बंदूक लेकर, पिस्तौल लाकर मारकर चले गये तो मैं तो मर गया, मेरी जीत कब होने वाली है?

माननीय कल्ला साहब विद्वान हैं, संस्कृत और हिंदी के ज्ञाता हैं। मिलें तो आइये करेंगे चर्चा, हम भी आपके भ्राता हैं और यह ही हो रहा है आज भी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): देखो, एक बात बताऊं, सत्यमेव जयते और सत्यम् परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और आपने जहां तक कहा, 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।' जब-जब धर्म की हानि होती है, धर्म पर संकट आता है तो वह ऊपर वाला अवतार लेता है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मोदीजी ने अवतार लिया है।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, जीओ और जीने दो किसे कहते हैं? मैं शास्त्रों में तो ज्यादा नहीं जाता, ज्यादा मैं नहीं जानता हूं क्योंकि I am not a graduate, I am only 'EE' means double eleven. लेकिन मैंने मेरे जीवन को अनुभव के आधार पर जीया है। An experience is better than knowledge. आप संतोष किसे कहते हैं? साधु-संत, ऋषि-मुनि, ज्ञानी-ध्यानी, तपस्वी यह कहते हैं कि संतोष रखो संतोष, तो मैंने यह पूछा

(श्री रूपा राम)

समारामजी को कि साहब, संतोष है काहे को? नीमनी है, फलकटी है, पालो है, खल है, धान है, है क्या? How we will right the real definition of satisfaction? संतोष है क्या? कई चीजें आज हमारे पास पड़ी हैं, हमने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। जीयो और जीने दो, यह कहावत चरितार्थ कैसे होती है? जीओ और जीने दो की कहावत भी अच्छे-अच्छे लोग यह नहीं बता सकते कि इस कहावत को चरितार्थ कैसे करें।

मैं अकेला बैठा हूं या चार आदमी बैठे हैं, दो अपराधी प्रवृत्ति के लोग आये, अपराध करके चले गये, मारकर चले गये, अब हम जीने वाले कब हैं? इसलिए इस पर भी मेरा यह सोच है जो मैंने चिंतन और मंथन किया है, अगर आप निश्चिंत होकर बैठे हैं, अपने नियम-कायदे, धर्म के अनुसार जी रहे हैं, सच्चाई और अच्छाई के साथ जी रहे हैं और आप पर यदि किसी की बुरी नजर है, चाहे वह धर्म के आधार पर हो सकती है, व्यापार के आधार पर हो सकती है, राजनीति के आधार पर हो सकती है, तो आपको उस पर नजर रखना है। उसने अगर आपको मार दिया या शरीर से खतम कर दिया तो फिर जीओगे कैसे? पहले आपको जीना है, उसके बाद में जीने देना है।

यह मैं ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा इतना ही बोलूंगा इसमें, लेकिन यह मेरे जीवन की सच्चाई है। मैं आज भी कह रहा हूं कि जब-जब सत्य की ताकत बढ़ी है, जब-जब सच्चाई समाज, राजनीति, व्यापार और हमारे सभी जगह पर अगर व्याप्त हुई है तब तो हम यह कह सकते हैं कि सतयुग है। सतयुग और कलियुग, यह पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कभी यूं ऊंचा जाता है और फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और जब-जब असत्य की ताकत बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, तब-तब मैं यह सोचता हूं कि कलियुग आता है या आदमी दु:खी होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप गाकर बताओ। सतयुग आता और कलियुग आता है, यह आप गाकर बताओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभिभाषण पर बोलें। हां, प्लीज, बोलिये।

श्री रूपा राम (मकराना): Please don’t disturb me. भूल जाऊंगा फिर मैं।

चार साल में सरकार ने क्या किया? इन चार साल में सरकार ने

(श्री रूपा राम)

क्या किया? चार साल में एक ही गुनाह करते रहे, धूल लगी चेहरे पर और शीशा साफ करते रहे। अपने दोषों को दूसरे राज्य से या दूसरों से तुलना करके अपनी गलतियों को छिपाना जनतंत्र में और प्रजातंत्र में हितकर नहीं है। बच भी जाओगे जमाने की नजरों से लोगों को लूट-लूटकर, सज़ा जरूर पाओगे, वहां जब ऊपर जाओगे तो रोओगे फूट-फूटकर।

अब मैं ऐसी बात कहूंगा सदन में जो किसी के पक्ष में नहीं है और किसी के खिलाफ नहीं है। बस, चोर की दाढ़ी में तिनका है। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, हे पिता परमेश्वर, हे ईश्वर, यह मेरा संविधान है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जिन लोगों ने, हजारों-करोड़ों लोगों ने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, मैं उनको भी साक्षी मानकर यह कह रहा हूं कि राजनीति में अच्छे और सच्चे लोग हैं लेकिन मेरे दाता, उनकी संख्या कम पड़ रही है, थोड़ी बढ़ाओ। जो राजनीति में अच्छे और सच्चे हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, जो अपनी सेवा नहीं करते, एक तपस्वी जीवन जीते हैं उनकी संख्या बढ़ा मेरे दाता, उनकी संख्या बढ़ा मेरे प्रभु और जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, बदले की भावना से राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, हे पिता परमेश्वर, उनको सद्बुद्धि दे दे, नहीं तो वे और बड़ा नुकसान करेंगे, इसलिए यह उन लोगों के लिए है।

हम आज चुनकर यहां आये हैं यह एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, तो ऐसे मार्ग पर चालिये, मेरा यह लिखा हुआ है, ऐसे मार्ग चलिये जिसमें कम हो भीड़, औरन को सुख दीजिए खुद सह लीजिए पीड़। राजनीति, यह है सच्चाई कि ऐसा मार्ग, आज सच्चाई और अच्छाई के मार्ग में आप सबको यह पता है कि भीड़ कम है। वह ट्रैफिक खाली रहता है करीब-करीब इसलिए ऐसे मार्ग चालिये जिसमें कम हो भीड़, औरन को सुख दीजिए और खुद सह लीजिए पीड़।

मैं अब टू द पाइंट शब्दों पर, हमारी जो कार्यशैली है, माननीय सभापति महोदय, लोगों की, आने वाले बच्चों की, युवाओं की हम पर नजर है, जनता हमसे प्रेरणा ले रही है, वह हमसे सीखना चाहती है। मुझे कल किसी ने कहा कि जब सदन चलता है तो गांवों में अपराध कम क्यों होता है तो मैंने कहा कि आपका क्या मतलब है? हम सब इधर आ जाते हैं, इसलिए कह रहा

(श्री रूपा राम)

है क्या? यह सच है कि सदन चलता है तो गांवों में अपराध कम होता है और इसलिए होता है कि प्रशासन सजग रहता है। लेकिन वह क्या कह रहे हैं? उसने मजाक में ही कहा होगा भले ही। उसने कहा, एम एल ए साहब, जब सदन चलता है तो गांवों में अपराध कम होते हैं। इसका मतलब आप सारे एक जगह हो जाते हो न। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन, शासन सजग रहता है कि सदन चल रहा है, छोटी-मोटी गलती नहीं हो। इस पर मैं आपको यही कहूंगा कि कोई भी सरकारी योजना चाहे विकास की है, मैं यह दावे के साथ कहता हूं तब तक उस योजना को, कार्य को हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह सफल है या जनहित में है। कब तक? जब तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगती, तब तक हम किसी भी छोटी सी छोटी विकास की योजना के लिए हम यह नहीं कह सकते कि हम इसमें सफल हो गये या विकास हो गया।

सभापति महोदय, शायद पहला अभिभाषण होगा जिसमें भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस बताया। मैंने जीरो टोलरेंस पर दो-तीन बार चिन्तन किया। सो गया मैं रात को। 12 बजे उठकर फिर मैंने सोचा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टोलरेंस भ्रष्टाचार करने के लिए है या नहीं करने के लिए है। आज एक भी ऐसी संस्था बता दीजिए। आप सरकार के जन प्रतिनिधि हैं, सबके लिए तो नहीं कह रहा हूं, आपको किस बात का डर है? मत करना मौज मस्ती, राजस्थान नहीं, आपका घर है। एक दिन यहां से हमें भी, शायद मैं दुबारा यहां आऊं या नहीं आऊं, लेकिन आपमें और हम में यह विश्वास होना चाहिए कि हमने जो किया है, हमारी आत्मा को साक्षी मान कर किया है। इसलिए भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा तालमेल हो रहा है।

माननीय, जब कानून व्यवस्था शिथिल होगी, कानून व्यवस्था कमजोर पड़ेगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जब कोई भ्रष्टाचारी, लुटेरा, रिश्वतखोर, कमीशनखोर अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से धन इकट्ठा करके ताकतवर और मजबूत होता है तो लोग उनका भी अनुसरण करेंगे। जब-जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो कानून को प्रभावित करता है और जब कानून कमजोर पड़ता है तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

ईश्वर साक्षी है कि मैं यह कह रहा हूं कि राज्यपालजी के अभिभाषण पर उनसे जबरदस्ती बुलवाया जाता होगा। आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा है। कल परसों एक-दो विद्वान माननीय सदस्यों ने तो कहा कि यह ठीक नहीं है। आप ढाई साल पहले वहां से बोलते तो यह ढाई साल के वक्त में उठापटक हुई

(श्री रूपा राम)

है और कहीं सही कार्य नहीं हुए हैं तो हमको पहले मौका मिल जाता। एक तो मैं यह कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में तालमेल एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है, आप उस पर ध्यान रखिए।

सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य के बारे में भी कहना चाहता हूं। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं कि पेय और खाद्य पदार्थों में अगर मिलावट है तो फिर स्वास्थ्य का मतलब ही नहीं है। हम भी गांवों में जाते हैं। आप आज इस बात का ध्यान कीजिए कि दस में से आठ मौतें हृदयाघात की वजह से हो रही हैं और दो कैंसर की वजह से हो रही हैं। कारण क्या है? क्या कोरोना का प्रभाव है या खाद्य पदार्थ है या लोग चाय पीते हैं मीठी? मैं मना करता हूं। कहता हूं कि चाय में चीनी कम लिया करो। आज आप किसी की जांच कीजिए, शुगर मिलेगा ज्यादा। इसलिए बड़ा दु:ख होता है कि आज चाहे गरीब से गरीब हो, पैसे वाला हो, आज हम शुद्ध पदार्थ खाने और पीने का प्रयास नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, डाक्टर साहब कहते हैं कि आप सलाद खाइए। नहीं मरने वाला होगा तो भी सलाद खा कर दो-तीन महीने में बीमार हो जायेगा। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा कौन बचाव करेगा? आने वाली पीढ़ी कैसे सुरक्षित रहेगी? आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे इसलिए स्वास्थ्य और मिलावट के बीच में एक तालमेल है। अगर हम मिलावटी या अशुद्ध चीजें खायेंगे या रासायनिक खाद दी हुई चीजें ज्यादा खायेंगे तो फिर हम चाहे कितने ही डाक्टर लगवायें, कुछ नहीं होगा।

मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी को भी कह दूं कि हास्पिटल जहां-जहां हैं, बीच-बीच में मेरी बात कह दूं नहीं तो मेरे क्षेत्र के लोग कहेंगे कि केवल गाना या भजन सुना कर तो नहीं आया है, क्योंकि जब मैं खड़ा होता हूं तो लोग आशा करते हैं, क्योंकि मैं गायक हूं। मुझे खुशी है कि मैं गायक हूं औरजब जरूरत पड़ती है तो गाता हूं।

(समय: 13.56 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

ये मेरे लिए बदले गये हैं या वक्त ने बदला है। (व्यवधान) बोल रहा हूं। दोनों में कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा। वह कह दें कि मैंने नहीं सुना और यह कह दें कि मैंने नहीं सुना। मैं तो हूं जाद वह समय लेंगे अपने-आप बांट।

(श्री रूपा राम)

सभापति महोदय, मैं एक-एक शब्द बोलूं तो सरकारी अस्पतालों में न तो पूरे डाक्टर हैं। मैं बोल रहा हूं वह आप भी जानते हैं। इसमें हम चार साल से कह रहे हैं। इसमें आपका झगड़ा भी हो सकता है आपस में, लेकिन परिवार का झगड़ा हो तो पड़ोसियों को नुकसान होता है। आपके और सरकार के झगड़े से राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें शायद आप भी सुखी नहीं हैं। आप अपनी आत्मा से कह दीजिए कि आपके चार साल में आपका क्या फायदा हुआ? हमारा इसमें कोई फायदा-नुकसान नहीं है। मेरे जैसे आदमी का तो बिलकुल नहीं है। मेरा राजनीतिक पद इतना बड़ा भी नहीं है कि आपके गिरने से मैं खड़ा हो जाऊंगा। इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, मैं चार साल में सिर्फ एक ही बार कुछ अध्यापकों की बदली के कुछ कागज लेकर माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मिला था और मैंने लोगों को कहा कि अपने यहां पांच-सात दिन में अध्यापक लग जाएंगे। उनको सिर्फ पांच-छह महीने हो गये। उन्होंने कहा कि आपकी बी जे पी में चलती तो है नहीं। वह अध्यापक अभी तक नहीं लगे। इसका नुकसान तो जनता का ही हुआ न। मेरा तो क्या है, दुबारा का पता नहीं।

बिजली के मामले में इतना कह रहा हूं कि बिजली से आप और मैं दोनों ही दुःखी हैं। ताज्जुब की बात है कि किसान रात को 12, 1 और 2 बजे उस फसल में खड़ा रहता है। आप खड़े होकर दिखाइए। बच्चों की पढ़ाई के मामले में देख लो। ज्योंही शाम होती है, फोन आता है और वह कहते हैं कि शाम को ही क्यों काटते हैं? एक्स ईएन साहब को कहते हैं तो वह कहते हैं कि लोड शाम को ही पड़ता है। लोग पीकर, दवाई लेकर भी बात कर लेते हैं कि अबकी बार आपको देख लेंगे। मैंने कहा कि भाई, मेरा तो अभी टिकट ही फाइनल नहीं हुआ, मुझे कहां से देख लेगा? मैं आत्मा से कह रहा हूं कि चार साल में जितने लोगों की शिकायतें सुनी हैं या अपशब्द सुने हैं, बहुत मुश्किल से धैर्य से सुन पाते हैं। हम जन-प्रतिनिधियों का इतना-सा तो फर्ज होता है कि हमें सुनना चाहिए। वह कभी क्या बोल जाते हैं और कभी क्या, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। सभापति महोदय, बिजली के मामले में मैं जितना कहूं उतना कम है। मेरे साथी भाई रामस्वरूपजी ने लिखकर अच्छी तरह एक-एक चीज बता दी। बिजली आती नहीं है, तार टूटे पड़े हुए हैं। कब आती है, कब जाती है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हर गांव में बिलावणों है, चक्की है, पानी की मोटर है। लोग कहते हैं कि बिजली दो घंटे काटो, जबकि मैं कह रहा हूं कि आज का

(श्री रूपा राम)

हर आदमी बिजली पर निर्भर है, आश्रित है। मैं समझता हूं यह कांग्रेस सरकार बिजली के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित रही है। आपने सबसे ज्यादा जनता को दुःखी किया।

सभापति महोदय, मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो कानून व्यवस्था तो इस कदर कमजोर पड़ गयी, थानों में लिखा होता है कि अपराधियों में डर, हो उलटा रहा है, अपराधियों में मौज मस्ती। मैं कह रहा हूं कि जिस राज में जिस दिन, जिस वक्त माफिया, अपराधी प्रवृत्ति या भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग, जन-प्रतिनिधि और अधिकारी इन तीनों का जब गठजोड़ हो जाता है तो फिर जनता के लिए बचने का कोई साधन नहीं रहता है। आज ज्यादातर इनका गठजोड़ हो रहा है। माफियाओं का और भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट जन-प्रतिनिधियों का जो गठजोड़ हो रहा है, यह गठजोड़ खतरनाक है। ठीक है, कभी-कभी आप उधर से कहते हो, हमारी कोई बात होती है जैसे हमारे विद्वान साथी राजेन्द्र जी अच्छे बोलते हैं तो उनके लिये आप कहते हो कि गिरेबान में झांकिये। इसका मतलब यह गिरेबान में झांकते-झांकते पांच-पांच साल बदलकर जनता को हम बेवकूफ बनाते रहेंगे। हमारी कुछ-न-कुछ गिरेबान में कमी रही होगी और आपने तय कर लिया कि आपकी गिरेबान में कमी है तो हम उधर आयेंगे। दोषों से बचने के लिये आज जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी सरकार की है और इसको अगर आप नेगेटिव में लेते हैं, डायल्यूट करते हैं तो आरोप लगा देते हैं कि आप अपनी गिरेबान में झांकिये।

(समय: 14.00 बजे)

एक माननीय सदस्य: गाना तो गा दो।

श्री रूपा राम (मकराना): गाने के लिये अलग से कोई प्रोग्राम रखो न।

मैं खनन विभाग की एक-दो बात कहूंगा। खनन विभाग में जिस तरह नये अलाटमेंट को लेकर बंदरबांट होती है, जिस तरह से लाखों रुपये रिश्वत देने के बाद में भी, आप जांच करा लीजिये और जांच क्या, वह तो पता ही है, कहां से कहां जाता है। मैं विधायक होने के साथ-साथ मेरे सामने एक-दो मंत्रीजी भी बैठे हैं और हमने यह महसूस किया है कि ये लोग इतने मजबूत हो गये, मैं बताऊं न, मेरी सोच अलग से है। लोग यहां कहते हैं बेईमान और ईमानदार में फर्क होता है। एक आदमी असत्य, कपट और बेईमानी करके अवैध तरीके से खूब बादाम-पिस्ता खाकर दंड बैठक लगाता है और एक ईमानदारी से बिलकुल भूखा बैठा है। अब कुश्ती होगी तो जीतने की संभावना उसी की होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): जवाब मैं देऊं दो मिनट में?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप का भाषण दो मिनट में समाप्त करें। बाकी माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं।

श्री रूपा राम (मकराना): बैठ रहा हूं। दो मिनट और बोल दूं मैं।

खनन विभाग की जो मैंने बात बतायी, उसमें भी जांच हो। दूसरा, मैं आपसे यह आशा रखूंगा कि पानी है, बिजली है, सड़कें हैं। जब हम हमारे घर में ट्यूबवैल 6-7 लाख रुपये में खोद लेते हैं तो उसके 20-20 लाख रुपये मंजूर हो जाते हैं। मैंने बड़े अधिकारियों से जाकर कहा कि आप इतना क्यों करते हो? वे कहते हैं हमारी गाइडलाइन है। इसकी भी आप जांच करो कि इतने पैसे जाते कहां हैं? ये पैसे तो गरीब जनता के हैं। दूसरा, सड़क के मामले में अच्छी बात बता रहा हूं। आज सीमेंट की सड़क जिसमें दो-ढाई का मसाला लगता है, उसमें भी आप 6 साल की गारंटी देते हो। ऐसी सड़कें, आज भाखड़ा बांध का जो मसाला है, वह आज तक नहीं टूटा, तो मैंने पहले कहा था कि हमारे मकराना में 20 साल पहले ऐसी सड़क बनी थी, वह आज तक भी वे वैसी ही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के मुद्दे पर कहूंगा। राजकीय कृषि महाविद्यालय, मौलासर को उच्च शिक्षा विभाग से हटाकर कृषि विभाग के अधीन करने के बाबत कृषि छात्र-छात्राएं 11 दिन से धरने पर बैठे हैं, जिनमें पांच-छह छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य भी बिगड़ा है। इस पर आप थोड़ा ध्यान देवें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई लाइन भूल गया हूं तो बाद में कह दूंगा। नमस्कार। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती शोभारानी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): एक मिनट, इन्होंने यह कहा कि संतोष आज तक मेरे समझ में नहीं आया तो आपकी इजाजत हो तो मैं इनको समझ देता हूं।

'सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।'

यह तो रामचरितमानस का है। आप समझ गये होंगे, नहीं तो इसको और समझा दूं। गीता में लिखा है-

'सुखे-दु:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।'

जो व्यक्ति सुख में, दु:ख में, लाभ में, अलाभ में, जय और पराजय में, इन सब में समभाव रखता है, वह संतोषी है।

श्री रूपा राम (मकराना): एक मिनट, प्लीज मुझे बोलने दो।

श्री सभापति: प्लीज, विराजिये। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रूपा राम (मकराना): सही बात कहने के टाइम पर तो आप बोलने नहीं दे रहे हो। संतोष है क्या, परिभाषा क्या है? कमाकर खाना है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्रीमती शोभारानी।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में शिक्षा के क्षेत्र में काफी विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है। इसके लिये मैं आभार व्यक्त करती हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किये हैं, ये गरीब बच्चों के लिये मील का पत्थर साबित होंगे। इसके साथ ही गरीब बच्चों के लिये जो फ्री में ड्रेस दी गयी है, वह बहुत ही सराहनीय है।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में धौलपुर जिले की शान मचकुंड महाराज के लिये राशि देकर बहुत ही पुण्य का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के क्षेत्र में जिन गांवों में कभी 70 सालों में रोड नहीं बने थे, उन गांवों में रोड डलवाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ग्रामीण के साथ-साथ शहर में भी 7 करोड़ की सड़कें मंजूर हो चुकी हैं, जिनका कार्य चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीन मेडिकल कालेज पूरा कराकर एक मिसाल कायम की है, क्योंकि ज्यादातर सरकारों में मैंने देखा है कि जो सरकार काम शुरू करती है, दूसरी सरकार उसको बंद करा देती है, लेकिन यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की इंसानियत है कि पिछली बी जे पी की सरकार ने जो मेडिकल कालेज शुरू किया था, उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरा कराया है।

माननीय सभापति महोदय, इन सभी योजनाओं से बढ़कर जो पूरे देश में मिसाल कायम की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, वह है चिरंजीवी योजना और इंदिरा रसोई, जिसका सीधा-सीधा लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है। इसकी जितनी तारीफ की जाये, उतनी कम है। इस तरह लगभग हर क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जनता-जनार्दन का ख्याल रखा है।

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

माननीय सभापति महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आखिरी बजट में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय पूरे प्रदेश के साथ-साथ धौलपुर विधान सभा का भी जरूर ध्यान रखेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम सा।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, उसमें सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार के द्वारा पूर्व में क्या कार्य कराये गये हैं और आने वाले समय में सरकार का क्या विजन होगा, इसका उल्लेख किया जाता है, लेकिन माननीय सभापति महोदय, महामहिम के श्रीमुख से इस अभिभाषण के माध्यम से जो-जो बातें सरकार ने कहलवाई हैं या पूर्व की घोषणाओं के बारे में जो वाहवाही लूटने का प्रयास किया है, वे सत्य से कोसों दूर हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का यह तीसरा कार्यकाल है मुख्य मंत्री के नाते और मुझे इस सदन में पहली बार आने का मौका मिला है। चार वर्षों में माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैंने सदन में बोलते हुए भी देखा है, बाहर सभाओं में बोलते सुना है। एक शब्द का वह बहुत उल्लेख करते हैं 'सुशासन' का, लेकिन आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि अलवर जिले में, जिस जिले से मैं आता हूं, उस जिले ने कांग्रेस पार्टी को पांच विधायक दिये, दो बहुजन समाज पार्टी के दिये, जो हाथी के चिह्न पर जीतकर आये थे, लेकिन उस विधान सभा क्षेत्र की जनता और ब.स.पा. की सुप्रीमो बहन मायावती उन हाथियों को भी ढूंढ रही हैं और दो निर्दलीय विधायक जीतकर आये तथा दो हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतकर आये। ब स पा वाले भी कांग्रेस में चले गये। निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया, लेकिन ऐसा कैसा सुशासन है कि अलवर जिला मुख्यालय, जहां हमारा ए.डी.एम. सैकण्ड का पद रिक्त है, वहां एक कार्यवाहक अधिकारी काम देख रहे हैं। जिस संस्था से विकास के काम शुरू होते हैं, जिला परिषद्, नगर परिषद्, नगर विकास न्यास, जिला परिषद् में सी ई ओ जिला परिषद् का पद खाली है। नगर विकास न्यास में सचिव का पद खाली है, आयुक्त नगर परिषद् का पद खाली है, एस डी एम

(श्री संजय शर्मा)

का पद खाली है। इतना बहुमत जब अलवर जिले ने दिया है तो यह कैसा सुशासन माननीय मुख्य मंत्री जी अलवर जिले की जनता को दे रहे हैं? सभापति महोदय, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यदि मैं पानी की बात करूं, आदरणीय वसुन्धरा राजे जी के शासन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अलवर शहर में प्रतिदिन पेयजल की सप्लाई होती थी, लेकिन पिछले 4 वर्षों में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दे रहे हैं। वह भी बीस मिनट से तीस मिनट के करीब देते हैं। कभी बिजली का बहाना लेकर के, कभी सबमर्सिबल का बहाना लेकर के कि खराब हो गयी, पानी की सप्लाई बाधित हो जाती है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2019-20 के बजट में चंबल से अलवर तक पानी लाने के लिये 4,718 करोड़ की परियोजना की घोषणा की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस योजना पर एक इंच काम नहीं हुआ। 2021-22 में ईसरदा बांध परियोजना को लेकर इसी पवित्र सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी। इस योजना को लेकर के जब मैंने प्रश्न लगाया तो जलदाय मंत्री जी ने इस पवित्र सदन में बताया कि 7 साल बाद यदि ईसरदा बांध में पानी सरप्लस हुआ तो अलवर शहर सहित अन्य 14 विधान सभा क्षेत्रों को पानी उपलब्ध होगा।

माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर की मैं बात करूं तो जुलाई, 2022 से लेकर के 10 जनवरी, 2023 तक स्थानांतरणों की जब रोक खुली हुई थी, स्थानांतरणों पर रोक नहीं थी, उसमें जलदाय विभाग के नगर उप खण्ड प्रथम में श्री मुकुल निर्वाण, ए.ईएन., श्री नरेन्द्र मीणा, ए.ईएन., श्री मुकेश मीणा, ए.ईएन., श्री त्रिलोक मीणा, ए.ईएन., श्री मनिन्दर सिंह जी बैसला, ए.ईएन. ये 5 ए.ईएन. साहब पिछले 7 महीने में आये और गये। अब श्रीमती विमला सैनी जी वहां कार्यरत हैं। वे कब चली जायेंगी उसका पता न तो हमको है और न वहां के अधिकारियों को है।

यदि मैं उप खण्ड-द्वितीय की बात करूं तो ए.ईएन. श्री सोहन प्रकाश जी, ए.ईएन. श्री मोहन सिंह जी मीणा, ए.ईएन. श्री गणेशी लाल जी वर्मा, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, ये ए.ईएन. भी आये और गये। यदि मैं उप खण्ड-तृतीय की बात करूं तो राजेश सेन जी आये और गये। वर्तमान में कोई पाराशर जी

(श्री संजय शर्मा)

मौजूद हैं। मैंने इसको लेकर के जलदाय मंत्री जी से आग्रह किया था कि ऐसी कौन सी संस्था जयपुर के अंदर है, जो अधिकारी आते हैं और 15 दिन बाद स्थानांतरण कराकर चले जाते हैं। पानी की समस्या कहीं न कहीं इन अधिकारियों के स्थानांतरण के कारण भी हो रही है। शहर में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन यदि डिस्ट्रिब्यूशन सही हो जाये तो हमको निश्चित रूप से पूरा पानी मिलने लग जायेगा।

सभापति महोदय, मैंने पिछले बजट में भी मांग की थी कि सिलीसेढ़ बांध जो अलवर शहर की लाइफ लाइन हो सकता है, उससे हमको पानी दिलवाया जाये। उसको लेकर के जलदाय विभाग ने 36 करोड़ की योजना राज्य सरकार के पास भेजी है। आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी सिलीसेढ़ से अलवर पानी की योजना को अपनी अनुमति प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री जी यहां विराजमान हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक मॉडल सी एच सी बनाने की घोषणा की थी। तत्कालीन चिकित्सा मंत्री जी ने हमसे प्रस्ताव मांगे थे। हमारे दिये हुए प्रस्ताव की घोषणा भी कर दी गयी थी। चिकित्सा विभाग ने मुझसे सवा करोड़ के करीब उस डिस्पेंसरी को क्रमोन्नत करने के बाद उसके निर्माण में जो पैसा चाहिए था, उसके लिए मांग की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उस डिस्पेंसरी को चिकित्सा विभाग के आदेश के तहत निरस्त कर दिया गया। उसमें यह कहा गया कि यह प्राथमिक क्षेत्र है, सिटी डिस्पेंसरी है। उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि मेरे वहां पर सरकारी राजीव गांधी अस्पताल है, जनाना अस्पताल है, सैटेलाइट हास्पिटल है। बाकी हमारी शहरी सभी प्राथमिक डिस्पेंसरीज हैं। उसके बाद जो हमारा मॉडल सामुदायिक भवन है, उसको निरस्त करने का काम किया। वह आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके चिकित्सा महकमे ने किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के भेदभाव का वातावरण अलवर शहर की जनता के साथ न करें। कृपा करके उस मॉडल सी एच सी को पुन: स्थापित करके काम करने का मौका दें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

(श्री संजय शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं स्वायत्त शासन विभाग की बात करुं तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 7 करोड़ की सड़कों के प्रपोजल नगर परिषद् के माध्यम से मंगवाये थे। जिन सड़कों का निर्माण पी डब्ल्यू डी विभाग को करना था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि नगर परिषद् द्वारा 7 करोड़ के प्रपोजल डी एल बी में भेज दिये गये। डी एल बी के डायरेक्टर ने उन प्रपोजल्स पर अपनी सहमति प्रदान कर दी, लेकिन पी डब्ल्यू डी विभाग द्वारा आज तक उन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है।

उसी के साथ-साथ अलवर में शालीमार योजना में सीवर लाइन व एस टी पी निर्माण का कार्य, वैशाली नगर से एम आई ए तक फोर लेन सड़क का कार्य एवं नाला निर्माण, हीराबास, काली मोरी में 200 फीट बाई पास का एवं रूपवास आर ओ बी से हनुमान सर्किल तक नाला निर्माण कार्य किया जाना था लेकिन उन पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अलवर शहर में यातायात के दबाव को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कंपनी बाग़ में बेसमेंट पार्किंग की घोषणा की थी, जिसके लिये 40 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बावजूद विभाग द्वारा आज तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, 2022-23 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत अलवर शहर को स्मार्ट सिटी में लिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज तक स्मार्ट सिटी पर एक भी काम शुरू नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा मंत्री जी यहां मौजूद हैं। चिकित्सा मंत्री जी, अलवर शहर में 550 बेड हैं। सरकारी अस्पताल हो, जनाना अस्पताल हो, उनको मिलाकर के लगभग 750 बेड हमारे यहां हैं। उद्योग मंत्री जी जब मंत्री नहीं थीं, विधायक के नाते जनाना अस्पताल में गयी थीं। एक-एक बेड पर 2-2, 3-3 को लिटाया हुआ था। 750 बेड हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आपके विभाग ने एक आदेश जारी करके 47 नर्स ग्रेड-फर्स्ट के पद खतम कर दिये हैं। साथ ही अन्य पदों की बात करूं तो टोटल 164 पद अलवर शहर के अंदर समाप्त किये गये हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि

(श्री संजय शर्मा)

हमारे यहां फिजिशियंस की कमी है, डाक्टर्स की कमी है। वहां से बार-बार मांग आती है कि हमारे पद बढ़ाये जायें। विभाग ने, क्या कारण है कि इन पदों को खतम करके हमारे हितों के साथ कुठाराघात किया है? उसके लिये भी चिकित्सा मंत्री जी यहां विराजमान हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे पदों का सृजन करके जो निरस्त किये हैं, उनको भी दें और इसे बढ़ाने की कृपा करें। सभापति महोदय, साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जनता क्लिनिक की बात की थी, वह कोसों दूर है।

माननीय उद्योग मंत्री जी यहां विराजमान हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2021-22 में उद्योग लगाने के लिये बानसूर, रामगढ़, मालाखेड़ा और रैणी में तथा 2022-23 में कैरवा, कोटकासिम में उद्योग लगाने के लिये रीको को अधिकृत किया था, लेकिन वहां केवल बोर्ड लगाने के अलावा आज तक उद्योग विभाग द्वारा, रीको द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, जो हमारे उद्योग लगे हुए हैं, उन उद्योगों के लिये किसानों से जमीन तो ले ली जाती है, लेकिन जमीन लेने के बाद, उद्योग लगने के बाद वहां हमारे किसान के बेटे को रोजगार नहीं दिया जाता है। जब आप पहले उद्योग मंत्री थे, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, मैंने उस वक्त भी मांग की थी। हमारे अलवर शहर की बेटी अब उद्योग मंत्री है, मैं उनसे भी मांग कर रहा हूं कि अलवर जिले के उद्योगों में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान अलवर जिले के बच्चों के लिये, अलवर जिले के किसान के बेटों के लिये किया जाये। इससे निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या से हम लड़ सकेंगे, बेरोजगारी की समस्या को दूर भी कर सकेंगे।

सभापति महोदय, यदि मैं अपराध की बात करूं तो अलवर जिले में 2019 में थानागाजी गैंग रेप की जो घटना हुई थी उससे पूरे भारत में अलवर ही नहीं, अपितु पूरे राजस्थान की छवि खराब हुई थी। साथ ही 2022 में मूक-बधिर बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ, उसके कारण भी पूरे देश के अंदर राजस्थान की छवि खराब हुई थी।

सभापति महोदय, मेरा जिला वह जिला है, जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के जिला कलेक्टर तक रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार होते हैं। मेरा जिला वह जिला है, जहां पार्षद से लेकर चेयरमैन तक रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार होते हैं। मेरा जिला वह जिला है, जहां विधायक का बेटा बलात्कार के

(श्री संजय शर्मा)

आरोप में गिरफ्तार होता है। मेरा जिला वह जिला है जहां विधायक का बेटा रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार होता है।

सभापति महोदय, जब माननीय राहुल गांधी जी अलवर आये थे तो उनकी सुरक्षा के लिये बीकानेर से फोर्स आयी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वह फोर्स अलवर शहर के अम्बेडकर नगर में यू आई टी के सामुदायिक भवन में ठहरी हुई थी। उस पर आपराधिक तत्वों ने हमला किया और उन पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। पुलिसकर्मी घायल हुए, उनको जयपुर रैफर किया, लेकिन वे अपराधी आज तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

माननीय सभापति महोदय, किशनगढ़ थाने में कल ही एक घटना घटी है। एक गैंग रेप का अपराधी, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस गांव में जाती है, उसको पकड़ भी लेती है, लेकिन एक राय होकर पुलिस पर हमला होता, पुलिस को पीटा जाता है और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस घायल होती है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि जिस तरह से अलवर में अपराधीकरण हुआ है, अलवर में अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, तो उस पर निश्चित रूप से कठोर रूप से कदम उठाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, यदि मैं बिजली की बात करूं तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रति माह एक हजार रुपये बिल में छूट देकर किसानों को राहत दी थी। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आदरणीय वसुन्धरा राजे जी ने साढ़े आठ सौ रुपये प्रति माह बिजली के बिल में छूट दी थी, लेकिन तीन साल तक आपकी सरकार ने उस योजना को बंद रखा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि तीन साल तक किसान को लगभग एक, सवा लाख रुपये का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान में राहत देने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती इन्द्रा मीणा।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, 15वीं राज्य विधान सभा के अष्टम सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती इन्द्रा)

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं युवाओं पर आती हूं क्योंकि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा के लिए, कालेज शिक्षा के लिए मैं बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादा जोर भी मैं उसी पर देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 1 लाख 41 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं एवं लगभग 1 लाख 81 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अब तक कुल 1 हजार 186 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा चुका है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी कांग्रेस की सरकार ने इन चार साल में 3 लाख नौकरियां देने का वादा किया है उनमें से लगभग जब 5 साल पूरे होने में आएंगे तब तक कम्प्लीट 3 लाख नौकरियां दी जा चुकी होंगी। अधिकतर भर्तियों में नौकरियां दी जा चुकी हैं और कुछ पर काम चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे चार साल के कार्यकाल के अंदर हम समझ सकते हैं कि इस राजस्थान के इतिहास में इन चार सालों का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मेरी 35 साल की उम्र है और मैंने आज तक इस तरह के विकास कार्य जीवन में कभी नहीं देखे। उस परिस्थिति में जब दो साल कोरोना में हमारे खराब हो चुके हैं, उस परिस्थिति में भी आज मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो पूरा चहुंमुखी विकास इन चार सालों में कराया गया है। अब लगता है कि यह जो बजट सत्र आने वाला है, इस बजट सत्र में कोई विशेष मुद्दे रहे ही नहीं और जो विशेष मुद्दे रहे हैं थोड़े-बहुत, उनको हमें उम्मीद है इस बजट सत्र में पूरा कर लिया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, 2022-23 में 1 हजार 54 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। 3 हजार 843 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। इसी प्रकार 548 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। माननीय सभापति महोदय, यह बी जे पी और कांग्रेस वाले विधायकों के लिए अलग-अलग नियम नहीं था और पूरे राजस्थान के अंदर सभी को समान रूप से विद्यालय क्रमोन्नत करने का सरकार ने काम किया, किसी प्रकार का भेदभाव यहां पर नहीं किया गया। राजस्थान का चौथा स्थान इस देश में शिक्षा को लेकर है।

(श्रीमती इन्द्रा)

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके साथ-साथ उनका पोषण स्तर भी बेहतर हो, इसके लिए बच्चों को दूध और यूनिफार्म की व्यवस्था भी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले कर दी है। माननीय सभापति महोदय, इससे 63 लाख 22 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभांवित हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में यदि मैं कालेज शिक्षा की बात करूं तो कॉलेजों के अंदर उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 2022-23 के अंदर कुल 117 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, जिनमें से एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी महाविद्यालय खोला गया है। वर्ष 2022-23 में 61 नवीन कन्या महाविद्यालय खोले गए, जिनमें से एक मेरे विधान सभा क्षेत्र का कन्या महाविद्यालय भी शामिल है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया गया।

माननीय सभापति महोदय, 50 प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत में क्रमोन्नत किया गया, उनमें से एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्रमोन्नत किया गया है। 5 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले गए हैं, उनमें एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी खोला गया है। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री महोदय चार साल में सरकार की जो स्कीम लेकर आए हैं उनका यह आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार की जन-कल्याणकारी योजनाएं इस प्रदेश में लेकर आए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगी कि कल जो केन्द्र सरकार का बजट पेश हुआ, उसमें महिलाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया जबकि युवा और महिला इस देश में 90 प्रतिशत आबादी में हैं। महिलाओं की आधी आबादी है जबकि युवा 60 परसेंट अपना अधिकार रखते हैं। कुल मिलाकर दस परसेंट लोगों को लाभ देने के लिए काम किया गया है जो कि इस जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा है।

माननीय सभापति महोदय, शब्दों की जादूगरी कल केन्द्र के बजट में देखी गई है, जो जनता के हित में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जी एस

(श्रीमती इन्द्रा)

टी में कोई कटौती नहीं की गई, सरकारी नौकरियों का बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है और बेरोजगारों का कोई ध्यान नहीं रखा गया।

माननीय सभापति महोदय, ई आर सी पी योजना पूर्वी राजस्थान की एक बहुत बड़ी योजना है। केन्द्र सरकार से पूर्वी राजस्थान आस लगाए हुए बैठा था, लेकिन कल के बजट में ई आर सी पी का कोई जिक्र नहीं किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि मानगढ़ धाम में माननीय प्रधान मंत्रीजी आए थे और वहां हमारे आदिवासियों का बहुत बड़ा स्मारक है। उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की आदिवासियों की मांग थी, लेकिन सभी आदिवासियों को निराशा हाथ लगी है। कुछ दिन पहले माननीय मोदीजी आसीन्द में मालासेरी डूंगरी आए थे, वहां पर भी बहुत बड़ा गुर्जर समुदाय आया, उसे बहुत बड़ी उम्मीद प्रधान मंत्री जी से थी, लेकिन उसे भी निराशा ही हाथ लगी।

माननीय सभापति महोदय, कुछ दिन बाद प्रधान मंत्री जी का दौरा नांगल प्यारीवास बन रहा है। नांगल प्यारीवास इसलिए बन रहा है कि एन एच ए आई के रोड का उद्घाटन करना है। एन एच ए आई का रोड अभी तक पूरा हुआ नहीं है, उससे पहले उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधान मंत्री जी पधार रहे हैं। मैं समझ सकती हूं कि यह चुनावी साल है और आदिवासी एस टी बहुल क्षेत्र में आकर एस टी के लोगों को गुमराह करने की बात उनकी सोच में है, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आदिवासियों को देना है, अगर पूर्वी राजस्थान के अन्दर आपको कुछ करना है तो ई आर सी पी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना होगा तब जाकर पूर्वी राजस्थान का भला हो पाएगा। यह आप ही की योजना है, आप ही के द्वारा घोषणा की गई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र की मोदी सरकार ने इस राजस्थान को और इस देश को छलने का काम किया है। मैं चाहूंगी कि जनता इन चीजों को आगे सहन नहीं कर पाएगी और मुंह तोड़ जवाब आने वाले समय में देगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि 8 सालों में किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई और अरबपति मित्रों को 72 हजार करोड़ रुपये माफ करने का केन्द्र की मोदी सरकार ने काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, इन चार सालों में हमने देखा है कि

(श्रीमती इन्द्रा)

राजस्थान की सरकार ने चहुंमुखी विकास करने का काम किया है। मैं यह कह सकती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब से लोकतंत्र चालू हुआ है, जब से चुनाव होने चालू हुए जब से सरकारें बनना चालू हुई हैं आज तक इतने सालों के सभी पूरे कामों को जोड़ा जाए और इन चार सालों के कामों को जोड़ा जाए तो वे आधे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा है कि सरकारें पांच साल के कार्यकाल में घोषणाएं किया करती थीं, कालेज की घोषणा हो गई तो अगले 5 साल, 10 साल में उनकी बिल्डिंग बना करती थी। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक की नहीं, दो की नहीं, तीन की नहीं, चार-चार कालेज की घोषणा हुई है, उन चार-चार कालेजों की बिल्डिंग बनना शुरू हो गई हैं तथा चुनाव से पहले सारी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, देश में नफरत बढ़ती जा रही है, पर उन पर केन्द्र की मोदी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे और कोई बात हो, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन मेरे विधान सभा क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके अलावा बजट में जितनी भी आज तक घोषणाएं हुई हैं, मैं कहना चाहूंगी कि इस विधान सभा का एक भी बजट ऐसा नहीं रहा, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई, जो जनता की हितकारी हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो तहसील हैं और दोनों तहसीलों में नये हास्पिटल बनाये जा रहे हैं। चार-चार, पांच-पांच पी एच सीज का काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकारों में घोषित हुई उन पी एच सीज का बजट भी इस सरकार में दिया गया है और सभी का काम चालू है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि राज्यपाल जी के अभिभाषण का मैं समर्थन करती हूं और मैं कहना चाहती हूं कि इस तरीके का कार्यकाल, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल इन चार सालों का रहा है। हम इनका समर्थन करते हैं और आगे जो बजट आएगा इस सत्र का, उसमें भी आप लोग

(श्रीमती इन्द्रा)

देखेंगे कि किस तरीके का जन हितकारी बजट जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (अनुपस्थित)। श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो राज्यपाल महोदय से अभिभाषण पढ़ाया, उसको अगर अपन देखें तो वह सत्य से कोसों दूर है। आज चाहे हमारा पुष्कर विधान सभा क्षेत्र हो, चाहे अजमेर जिला हो, चाहे हमारा पूरा प्रदेश हो, उसमें आप कोई सा भी क्षेत्र देख लो। उसमें अगर अपन बिजली की बात करें तो बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरायी हुई है। बिजली की अघोषित कटौती से आम जनता परेशान है, किसान परेशान है। इसके साथ ही, आये दिन किसानों के कृषि कनेक्शन हैं, उन पर ताबड़तोड़ वी सी आर भरी जा रही हैं। साथ ही जो गरीब मजदूर लोग हैं, जब वे दिन में मजदूरी करने चले जाते हैं तो पीछे से बिजली विभाग के अफसर/अधिकारी आते हैं और शीट भरकर चले जाते हैं, जिससे आज लोगों में आतंक का एक माहौल तैयार हो रहा है। साथ ही, अगर अपन कृषि कनेक्शनों की बात करें तो सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की कि बाकी बचे हुए कृषि कनेक्शन हम जल्दी देंगे, लेकिन वे कृषि कनेक्शन न के बराबर लगे हैं। कोई घरेलू कनेक्शन लेने जाता है तो उसको भी बिजली के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ जगह कनेक्शन देने की प्रक्रिया भी चालू हुई, लेकिन डिस्काम के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है। अगर कहीं खम्बा लग गया तो तार नहीं है, कहीं तार लग गया तो मीटर नहीं है और अगर मीटर भी लग गया तो उसके अन्दर बिजली नहीं आती है।

दूसरा, 2019 से जब से आपकी सरकार आयी है, लगातार बिजली बिलों के अन्दर बढ़ोतरी हो रही है। जब बिजली का बिल आता है तो उसको देखकर लगता है कि घर के अन्दर, बिजली के तार के अन्दर तो करंट नहीं आ रहा है लेकिन उन बिलों के अन्दर जरूर करंट आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम पानी की बात करें तो मेरे

(श्री सुरेश सिंह रावत)

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बहुत सारे गांव और ढाणियां ऐसी हैं जहां पीने का पानी कई महीनों तक नहीं पहुंचता है। जब लोग पानी पीने के लिए नल खोलते हैं तो पानी आने के बजाय उसके अन्दर हवा आती है। माननीय सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत घर-घर जल कनेक्शन के लिए योजना लागू की, बजट भी स्वीकृत हुआ और हमारे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों के अन्दर उस प्रोजेक्ट पर काम भी चालू हुआ, लेकिन अभी तक वह कछुआ चाल से चल रहा है। इसके अलावा हमारा जो रूपनगढ़ कस्बा है, वह किशनगढ़ से सटा हुआ है और पूरा का पूरा जल जीवन मिशन की योजना से दूर है। हमारे अजमेर उप खण्ड के भी कुछ गांव बचे हुए हैं, हमारे पुष्कर उप खण्ड के भी कुछ गांव और ढाणियां बची हुई हैं तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो इसके अन्दर जो बचा हुआ जल जीवन मिशन का काम है वह भी जल्दी से जल्दी चालू हो, इसकी घोषणा करें।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, अगर हम सड़कों की बात करें तो जो हमारी पिछली माननीय वसुन्धरा जी की 2013 से 2018 तक सरकार थी, उसमें हमारे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का जाल, ऐतिहासिक जाल बिछा, सड़कों की मरम्मत हुई और कई नई सड़कें भी बनीं। लेकिन वर्तमान में 2019 से लेकर अब तक न के बराबर सड़कों का निर्माण हुआ, जिसको अगर अपन सीधी भाषा में कहें तो 'ऊंट के मुंह में जीरा' है। जब सड़कों पर चलते हैं तो समझ में नहीं आता कि सड़क के अन्दर गड्ढा है या गड्ढे के अन्दर सड़क है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आप सरकार को निर्देशित करें कि आम जनता सड़कों पर चलती है तो कम से कम सड़कों की जो दुर्दशा है, वह तो ठीक करे।

माननीय सभापति महोदय, बिजली, पानी की इन सब समस्याओं को देखकर, जब हम गांवों में जाते हैं तो आम जनता नारा लगाने लगी है। पहले तो राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं वे ही नारा लगाते थे, लेकिन अब आम जनता भी नारा लगा रही है कि 'बिजली-पानी दे न सकी, वह सरकार निकम्मी है और इस निकम्मी सरकार को हमें बदलना है', यह नारा आमजन के मुंह से हमें सुनने को मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम कानून-व्यवस्था की बात करें तो

(श्री सुरेश सिंह रावत)

आप देख ही रहे हो कि आये दिन जब सुबह हम अख़बार देखते हैं तो कभी कोई किसी को गोली मार देता है, किसी क्लब के सामने खुलेआम फायरिंग करके चला जाता है। हत्या, डकैती, बलात्कार, लूटपाट, चोरी-चकारी जैसे संगीन अपराध आम बात हो गई है। इसलिए सरकार को असत्य वाहवाही लूटने के बजाय इसके ऊपर भी बिलकुल ध्यान देना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो सरकार का कोई भी विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सारे के सारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दोनों हाथों से आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम इनके घोषणा पत्र की बात करें तो घोषणा पत्र के अन्दर जो इन्होंने वादे किये, वे वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। बेरोजगारों और किसानों को गुमराह करके, उनके साथ धोखा करके, छलावा करके ये सरकार में तो आ गये, लेकिन सवा चार साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। बेरोजगार उम्मीद लगाये बैठे हैं कि 3500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, लेकिन 35 पैसे भी आज तक उनके खाते में नहीं गये। किसानों ने सोचा कि पार्टी ने घोषणा की है, घोषणा पत्र में शामिल किया है कि किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारों पर मार और तब पड़ जाती है, जब बार-बार सरकार के कुशासन और कुप्रबन्धन की वजह से पेपर लीक हो रहे हैं। बार-बार पेपर लीक होने से बेरोजगारों में हताशा, परेशानी है और अब बेरोजगारों ने इकट्ठे होकर, संयुक्त होकर तय किया है कि 2023 में सरकार का पेपर लीक हम भी करेंगे और ऐसे संकल्प के साथ वे सरकार से बदला लेने को आतुर हैं।

अभी हाल ही में फसलों का खराबा हुआ। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जवाब देंगे तो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि राजस्थान के किसान और विशेष तौर से अजमेर में हमारे पुष्कर के आसपास आंवले की बड़ी खेती होती है, गुलाब की खेती है, और भी नाना प्रकार के फलों की खेती होती है, जो बिलकुल सारे के सारे नष्ट हो चुके हैं तो उनके मुआवजे के लिए उचित पैकेज की घोषणा करें। इसके अलावा भी हमारे

(श्री सुरेश सिंह रावत)

यहां गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, चने की फसल है, लगभग सभी फसलें चौपट हो गई हैं तो आज राजस्थान के किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करें, जिससे उनको राहत मिले सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं जहां से विधायक आता हूं, वह तीर्थराज पुष्कर एक अन्तराष्ट्रीय स्तर का स्थान है। देश और दुनिया के लोग वहां आते हैं। पिछली सरकार में माननीय वसुन्धरा जी ने लगभग 24 करोड़ का एन्ट्री प्लाजा के नाम से एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया था। वह लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार भी हो गया है और 2018 में उसका लोकार्पाण भी कर दिया। अभी हाल ही में, अभी नवम्बर, 2022 में प्रशासन द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी को गुमराह करके, वहां मेले के अन्दर बुलाया, वे मेले में आये, हमने स्वागत किया, मैं भी गया था, लेकिन जिस एन्ट्री प्लाजा का लोकार्पण 2018 में कर दिया गया, उसी एन्ट्री प्लाजा का लोकार्पण नवम्बर, 2022 में भी कर दिया। आपने तो 2018 से लेकर 2022 तक उसकी सुध तक नहीं ली। आज वह जर्जर अवस्था के अन्दर है। आपने सिर्फ असत्य वाहवाही लेने के लिए उसका लोकार्पण कर दिया। उसका लोकार्पण कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसकी सुध लीजिए। उसकी व्यवस्था के लिए जो कर्मचारी लगाने हैं, वे लगाइये। आप पर पैसों का भार भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा मन्दिर का जो ट्रस्ट है, उसके पास करोड़ो रुपये पड़े हैं, पैसे वहीं से जाने हैं। उसका सफलतापूर्वक संचालन हो, उसकी व्यवस्था भी आप लोगों को करनी चाहिए। हम पिछले कुछ महीनों से पुष्कर विकास की बड़ी-बड़ी बातें सुन रहे हैं कि जयपुर से टीम आ रही है, सर्वे कर रहे हैं, पर अभी एक ईंट भी पुष्कर के अन्दर नहीं लगी है।

माननीय सभापति महोदय, सिर्फ घोषणाओं से कुछ नहीं होता है। तीर्थराज पुष्कर सरोवर के अन्दर गन्दा पानी जाता है, उसकी रोकथाम अति आवश्यक है। उसके लिए कोई व्यापक योजना बनाएं।

इसके अलावा अजमेर से लेकर मेड़ता रेलवे लाइन की वर्षों से मांग है। केन्द्र सरकार ने बजट में इसकी स्वीकृति भी की थी और उसका सर्वे भी चालू है, लेकिन राज्य सरकार को रेलवे को नि:शुल्क जमीन देनी है। मैं मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार रेलवे विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराये, जिससे कि रेल लाइन का काम प्रगति करे।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

इसके अलावा भी हमारे पुष्करराज के अन्दर सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, अलग से एलिवेटेड रोड बने। इसके तहत एक ब्रह्मा कोरिडोर के नाम से माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट के अन्दर घोषणा करें, जिससे हमारे तीर्थराज में आने वाले यात्रियों को सुविधा मिले। यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, तारीख 23 जनवरी, 2023 के दिन राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में पधारकर जो भाषण दिया, उसका मैं समर्थन करता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डा. जितेन्द्र सिंह, विधायक ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा, उसका मैं समर्थन करता हूं।

कहने की बात यह है कि लोगों की आदत पड़ गई है कि किसी का विरोध करना है तो विरोध ही करना है, उससे फायदा होगा। यह आपके ऊपर क्या लिखा हुआ है, दुनिया में इस पर अमल करने की कोई जरा भी परवाह नहीं करता है। इंसान का फर्ज बनता है कि असलियत और सच्चाई छिपानी नहीं चाहिए और सच्चाई की बात हमेशा तहेदिल से रखनी चाहिए।

कांग्रेस एक सिद्धान्तवादी, दुनिया का सबसे पुराना राजनैतिक दल है। इसने क्या बुराई की? इस देश में विदेशी हुकूमत सौ साल रही। उस हुकूमत को इस देश से बाहर निकालकर इस मुल्क को आजाद कराया, यह कांग्रेस की पहल और देन है। आजादी के बाद में पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में जन-कल्याणकारी सरकार का निर्माण हुआ और उन्होंने सिद्धान्तों के तौर पर लोक सभा और विधान सभाओं में नियम और कानून बनाकर के एक योजनबद्ध तरीके से मुल्क को आगे बढ़ाने के तौर-तरीके बनाये, जिस पर इस मुल्क ने तरक्की की।

आज जो परिस्थिति है और आज लोगों की जो आदत है, अगर यह पूरी जमीन का सेटलमेंट स्टेट में नहीं होता और प्रत्येक खातेदार को खातेदारी हकों के पट्टे और नक्शे नहीं दिये होते तो लॉ एण्ड आर्डर सम्भालने में स्टेट को बहुत मुश्किलें होतीं। आज कानून और व्यवस्था सही चल रही है तो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जिनको राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा

(श्री अमीन खां)

जाता है, मोहन लाल सुखाड़िया ने यह सेटलमेंट करवाकर और नाथूराम जी मिर्धा के हाथ से काश्तकारी अधिनियम विधान सभा में पेश कराया और वह पास हुआ, जिसके जरिये प्रत्येक गरीब जमीन का मालिक है, उसको कोई हटा नहीं सकता है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो गरीब आदमी को चूल्हा बनाने की जगह भी नहीं मिलती और रूबाब अनेक खड़े हो जाते। इतनी बड़ी सूझबूझ गरीब इंसान के लिए इस कांग्रेस ने रखी। जिस पश्चिमी राजस्थान एरिया से मैं आता हूं, वह रेगिस्तानी क्षेत्र है। पूर्वी राजस्थान के लिए जितना भी पैसा केन्द्र से, राज्य से आता था, वह सारा पश्चिमी राजस्थान में अकाल राहत कार्यों के लिए लगाया जाता था, तो भी उनको पूरी रिलीफ नहीं मिलती थी।

डा. मनमोहन सिंह ने देश में नरेगा एक्ट कानून बनाकर पार्लियामेंट से पास करवाया। आज रिलीफ किसी तहसील में इश्यू करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और लाखों करोड़ों रुपये उस कानून के तहत गरीबों को किसी न किसी काम के माध्यम से मिल रहा है। यह कांग्रेस की नेताओं की सूझबूझ और समझदारी है। यदि कोई आदमी इसको रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता है।

पश्चिमी राजस्थान के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा लगती है और वहां पर कई सुविधाओं का अभाव था। इन अभावों की वजह से राज्य कर्मचारी, केन्द्रीय कर्मचारी, जिनकी तैनाती होती, वे रहना पसन्द नहीं करते थे, तबादला करवाकर इधर आ जाते थे। उस वक्त की सुखाड़िया सरकार ने 11 रेगिस्तानी जिलों में एक प्रतिबन्ध लगाया कि यहां पर शिक्षा, बिजली और पी एच ई डी के तहत कर्मचारी रहते हैं, उनका तबादला इन जिलों से बाहर नहीं किया जाए तो उससे काफी मदद मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस प्रतिबन्ध को खतम किया और वह प्रतिबन्ध खतम होने से वहां पर राज्य कर्मचारियों की काफी जगहें हमेशा के लिए खाली रहती हैं।

मैं कहना चाहूंगा, उस वक्त की देश की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने देश की सीमाओं के जिलों में बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया और राजस्थान में 4 बॉर्डर के जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनको कम से कम 250 करोड़ रुपया हर साल बी ए डी पी के तहत मिलते थे। उन प्रोग्रामों की वजह से राज्य कर्मचारियों के क्वार्टर बनें, वहां छोटे-छोटे गांवों में पक्की सड़कें बनीं। वहां छोटी-छोटी स्कूलों, सब सेन्टर्स के अच्छे

(श्री अमीन खां)

मकान बने, जिससे कर्मचारी रहने लगे। उसके बाद में डा. मनमोहन सिंह भारत के प्रधान मंत्री बने तो वहां की जनता, वहां की जनता के नुमाइन्दों की शिकायत पर बाड़मेर, जैसलमेर जिलों को पिछड़ा जिला घोषित कर दिया और पिछड़े जिले की मद में कम से कम चार सौ करोड़ रुपये इन दो जिलों को सालाना विकास के लिए मिलने शुरू हो गये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी। बोर्डर एरिया डवपलमेंट का प्रोग्राम खतम किया गया और एक पैसा भी नहीं मिलता है और पिछड़े जिले का जो मद था, वह भी सारा बन्द कर दिया। आज उस मद में भी एक पैसा नहीं मिल रहा है।

मेरा सीमावर्ती क्षेत्र है, यहां के कई हमारे साथी आये हैं। राजस्थान में सबसे अच्छी सड़कें मेरे एरिया में हैं, वे सड़कें अच्छी बनी हैं तो यह भारत सरकार के बी ए डी पी प्रोग्राम की वजह से। अगर वह प्रोग्राम नहीं होता तो उस रेगिस्तान में गाड़ी चलाना सभी के लिए मुश्किल होता। आज अलवर, भरतपुर भी मैंने देखे हैं, इनमें गाड़ियां चलाना इतना आसान नहीं है जितना हमारे रेगिस्तान में शानदार ढंग से गाड़ियां चलती हैं वह बी ए डी पी के प्रोग्राम से हैं। उस प्रोग्राम को जो बन्द किया है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भी हम नहीं मानते और गरीब अवाम के हित में भी नहीं मानते। बी जे पी की गवर्नमेंट ने उस प्रोग्राम को बन्द किया।

राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने उस एरिया में, जहां जैसलमेर जिले की आबादी सबसे कम है और उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है 38 हजार वर्ग किलोमीटर और पास में बाड़मेर जिला जो है उसका 28 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया में क्षेत्रफल है। इनमें कई बार लोग पैदल चले और मंजिल तक पहुंचने की दूरी अधिक होने की वजह से पानी बीच में खतम हो जाने से कई लोगों की मौतें हो गईं। जैसलमेर जिले में सुथार मण्डी के नाम से एक कस्बा है, वह सुथार, पीने के पानी की वजह से, रास्ते में पानी नहीं मिला, खतम हो गया, उस वजह से उसका नाम सुथार मण्डी रखा गया। आज उस धरती पर राजस्थान की सरकार ने और अशोक गहलोत ने इन्दिरा गांधी नहर का पानी पहुंचाया जिससे हजारों मण अनाज वहां पैदा हो रहा है और पेड़पौधे भी वहां दिख रहे हैं। मेरा खुद का भी उस तहसील में एक मुरब्बा है। जब हम उसको सम्भालने, वहां काश्त करने गये तो एक महीने रहे थे तो लकड़ी एक फुट भी कहीं गीली या सूखी नहीं मिली। गाय के चरने की घास है, जिसका

(श्री अमीन खां)

मशहूर नाम सेवण घास है, उस घास को जलाकर के हमने रोटी पकायी और चाय बनायी। आज उस जमीन पर हजारों-लाखों दरख़्त हरे रंग के खड़े हैं। कांग्रेस की सरकार ने इतने बड़े पिछड़े हुए इलाके में इस तरह का बन्दोबस्त किया, जो काबिले तारीफ है।

हम चाहे उर्दू का पक्ष करें, चाहे कोई संस्कृत का पक्ष करें, चाहे कोई राज्य भाषा राजस्थानी भाषा का पक्ष करें, इससे लोगों को हम बलवान नहीं बना सकते। बलवान इंग्लिश मीडियम शिक्षा के बिना कोई परिवार नहीं हो सकता है, यह आज भी हम देख रहे हैं। अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें उन गरीब इलाकों में खोल दी हैं, जहां गरीब बच्चों को कहीं भी अंग्रेजी नसीब नहीं होती थी। आज वह अंग्रेजी में गांव-गांव में पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे लोगों को उम्मीद जगी है कि हम भी इस अंग्रेजी के जरिये कभी सरकारी अफसर बन सकते हैं।

इसके साथ ही पीने के पानी में फ्लोराइड जमीन में बहुत ज्यादा है, अंडरग्राउंड जल का अभाव है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इन्दिरा गांधी नहर के मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल से पोकरण, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर से इस नहर के पानी से पीने के पानी का बन्दोबस्त किया, उससे आज वहां सभी को पीने का मीठा पानी मिल रहा है।

हमारे उस एरिया से यह एरिया बहुत दूर रह जाने से कोई जरिया नहीं था। नर्मदा नहर से 5-6 सौ करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत करके तहसील गडरा रोड, बाड़मेर जिले की तहसील रामसर में पीने के पानी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसका पानी गांव में अभी पहुंचना शुरू हो गया है और वंचित गांवों के लिए प्रयास जारी है। साल के अन्दर-अन्दर सभी गांवों में नर्मदा नहर का मीठा पानी पहुंच जायेगा।

इसके साथ ही स्कूलें बहुत जबरदस्त क्रमोन्नत की हैं। बिना कहे की हैं, उसमें कोई बी जे पी की सीट में स्कूल नहीं छोड़ी है, न कांग्रेस की सीट में छोड़ी है। जो उन्होंने क्षेत्रफल और पापुलेशन और बच्चों की संख्या के सर्वे के आधार पर स्कूलों का क्रमोन्नयन किया है, वह निष्पक्ष किया गया है। सरकार की नीयत साफ थी कि कोई शिक्षा से वंचित न रह जाये।

अन्त में, मैं सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि हमारा एरिया अभी तक भी शिक्षा में पूरे हिन्दुस्तान में और पूरे राजस्थान में सबसे पीछे है

(श्री अमीन खां)

और पहले मैंने बताया कि इस कारण से कर्मचारियों के तबादले हो जाते हैं, जिससे जगह हमेशा खाली रहती है। उदाहरण के तौर पर मैं शिव क्षेत्र का बताना चाहता हूं कि मैंने एक अतारांकित प्रश्न से मालूम किया तो पता चला कि आठ सौ पद शिव विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों के खाली हैं। आप अन्दाज करो कि एक विधान सभा क्षेत्र में आठ सौ-सात सौ मास्टरों के अगर पद खाली हैं तो इस आधुनिक युग में लोगों के साथ शिक्षा के मामले में अन्याय रहेगा। मैं मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि किसी भी ढंग से सरकार के पास कई जरिये हैं, हम जानते हैं कि मास्टरों की भर्ती होती है, पेपर लीक हो जाते हैं चोरी से, कई मामलों में हाईकोर्ट से स्टे आ जाता है तो समय पर मास्टर पहुंचाने में सरकार भी मजबूर होती है, तो फिक्स-पे पर जो बच्चे ट्रेंड हैं, बी एड हैं, एस टी सी हैं, उनको लगाया जाकर स्कूलों के मास्टरों के पद भरे जाने चाहिये। सरकारी मास्टर लगते ही अपने-आप बगैर एतराज वे सीधे घर चले जायेंगे, ताकि गरीबों के बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, वरना ये गरीब पिछड़े इलाके की वजह से और पिछड़ जायेंगे।

यही बात कहते हुए मैं पुनः डा. जितेन्द्र सिंह ने जो राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, उसका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं सदन को कि सर्वसम्मति से राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा देवी।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): सभापति महोदय, आज मुझे बोलने का मौका दिया, अपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वैसे मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में खूब सारी सड़कें भी दीं और खूब सारे हास्पिटल भी दिये, पर जो ट्रोमा सेन्टर की आपने पहले घोषणा की, वह ट्रोमा सेन्टर अभी तक मेड़ता सिटी में नहीं बना। ट्रोमा सेंटर नहीं होने के कारण कई घटनाएं हो गईं और 7-8 लोगों की मौत भी हो गई। बड़ा कस्बा है, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां आप जल्दी ही ट्रोमा सेंटर बनाने की घोषणा करें। मैं जब से विधान सभा में आयी हूं, तब से यही मांग कर रही हूं कि मेड़ता सिटी में 100 बेड का हास्पिटल होना चाहिये। इस ओर अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 100-100 किलोमीटर दूरी में हास्पिटल नहीं है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि 100 बेड का हास्पिटल मेड़ता सिटी में

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

होना चाहिये। सी एच सी मेड़ता रोड में है और जसनगर, पादू और रैण सी एच सी को जोड़ कर आप पी एच सी करें, पी एच सी से सी एच सी करें और लांबा, लीलिया, लाड़वा गांव में पी एच सी खोलें।

(समय: 15.00 बजे)

दूसरी मेरी मांग पुलिस थानों की है। जसनगर, रियांबड़ी में नये थाने खोलने की घोषणा करें। मेड़ता सिटी में एडिशनल एस पी कार्यालय की घोषणा करें। मेडता बड़ी सिटी है, इस बार आप बजट में यह भी घोषणा करें।

मेड़ता सिटी में गंदा गटर का पानी नाली में खुले में चल रहा है। नाली चॉक होने के कारण रास्ते पर पानी आ जाता है। रास्ते पर गंदा पानी आने के कारण बीमारी फैलती है। मेड़ता सिटी मीरा नगरी है, बड़ा कस्बा है। मैं आपसे मांग करती हूं कि वहां आप सीवरेज लाइन डालने की कृपा करें।

रियांबड़ी में मैं एक कालेज की भी मांग कर रही हूं। गरीब, दलित, किसान का बच्चा बाहर नहीं जा सकता, वह रियांबड़ी में पढ़ सके, इसलिए वहां एक कालेज की भी आप घोषणा करें। रियांबड़ी बहुत बड़ा गांव है।

वैसे मुख्य मंत्री जी ने बहुत सारी रोड दे दीं। रियाबड़ी से बीटन और मेड़ता सिटी से गोटन तक रोड की आप घोषणा करें। वह काफी टूटी हुई है, इसलिए लोगों की मांग है कि मुख्य मंत्री जी इसकी घोषणा करें।

लाइट के बारे में आप सबने बताया, मैं भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहती हूं कि शाम को भगवान की पूजा के समय आपकी सरकार लाइट काट देती है। सात घंटे लाइट आप देते हो, उस सात घंटे में भी झटका लगा-लगाकर लाइट आती है। लाइट के कारण किसान का बेटा पाणत करके सोता है और एक घंटे में लाइट वापस आ जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सात घंटे बराबर लाइट दें ताकि किसान अपनी खेती आराम से कर सके। वैसे 24 घंटे आपको लाइट देनी चाहिये ताकि बच्चा आराम से पढ़ सके और बच्चा पढ़ लिखकर आगे नाम रोशन कर सके।

20-40 ट्यूबवैल और 100 हैंडपम्प की आप घोषणा करें। हमारे मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में आपने घर-घर पाइप लाइन डाल दी और घर-घर कनेक्शन भी आप लोगों ने कर दिया लेकिन अभी तक कोई गांव ऐसा नहीं है जहां घर घर पानी पहुंच गया हो, न ही किसी ढाणी में है। आप गांव का सर्वे करा के

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

देख लेना, रोड भी तोड़ दी और पानी भी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि या तो मीठा पानी चालू करवा दें, नहीं करावें तो ट्यूबवैल दें और 100 हैंडपम्पों की आप घोषणा करें।

मैं आपको आंगनबाड़ी की बात बताना चाहूंगी। मेड़ता सिटी की एक महीने से मांग चल रही है कि आंगनबाड़ी में जो महिला नौकरी करती है, वह महिला अभी तक दुःखी है। वह घर का काम करती है, 4-5 हजार रुपये उस महिला को मिलता है। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज के समय में 5 हजार में कुछ नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि उन महिलाओं को पक्की नौकरी मिले और उनकी तनख्वाह भी आप बढ़ायें ताकि वह गरीब महिला अपने बच्चों का अच्छी तरह से पालन कर सके।

दूसरा, मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में सब लोगों की मांग है कि मेड़ता जिला बने। वैसे मेड़ता जिला बनने के लायक भी है। पहले राजा महाराजा के समय मेड़ता जिला था पर अभी आपने मेड़ता को जिला नहीं बनाया। मैं मांग करती हूं कि मेड़ता जिला बने। मेरे सुनने में आया है कि मेड़ता को ब्यावर में डाल रहे हैं, सुनने में आया है कि ब्यावर जिला बन रहा है। मेरी मांग है कि मेड़ता को ब्यावर में न डालकर मेड़ता को ही जिला बनायें। मैं आपसे मांग करती हूं कि मेड़ता को जिला बनाया जाये। हास्पिटल में डाक्टरों की कमी को पूरा करें। आपने स्कूल खोल दीं, स्कूलों में टीचर नहीं है। आज कई सरकारी स्कूल जर्जर स्थिति में हैं। आप गांव में जाकर देखो, बच्चों को बाहर बैठा कर पढ़ाया जा रहा है। आप स्कूलों की मरम्मत करावें। आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दीं पर वहां कोई टीचर नहीं है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप बजट में घोषणा करें। मेड़ता सिटी बड़ा गांव है, मीरा की नगरी है, आप कई लोग तो मीरा नगरी के दर्शन के लिये आते हैं तो मीरा बाई के नाम आप एक बड़ी घोषणा करें। मेड़ता सिटी में 100 बेड का हास्पिटल बनाना जरूरी है और जिला बनाना भी जरूरी है। धन्यवाद।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 34)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 34वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 02 फरवरी, 2023 को मध्याह्न पश्चात् 1:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2023 से गुरुवार, दिनांक 16 फरवरी 2023 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2023	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 का उपस्थापन
शनिवार, दिनांक 11 फरवरी 2023 रविवार, दिनांक 12 फरवरी 2023	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 13 फरवरी 2023	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद।
मंगलवार, दिनांक 14 फरवरी 2023 बुधवार, दिनांक 15 फरवरी 2023	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।
गुरुवार, दिनांक 16 फरवरी, 2023	1-अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2022-23 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन। 2-अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2022-23 (द्वितीय संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान, पारण एवं तत्संबंधी विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2023 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 3-आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 34वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 34वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री सुभाष पूनिया।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): सभापति जी, 23 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद जो यह वाद-विवाद प्रतियोगिता है, इसे प्रतियोगिता ही मानो, उधर से भी बोले और इधर से भी बोले, उस पर आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आंकड़ों के मायाजाल में नहीं फंसकर सीधे-सीधे मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कालेज खोले। 2021-22 के बजट में कालेज तो दे दी, बजट भी अलाट हो गया, हमने जमीन भी दे दी, लेकिन अभी तक बिल्डिंग का काम चालू नहीं हुआ है। यह नमूना इस सरकार का है। वहां न कालेज लेक्चरर्स हैं, न छात्रों के बैठने के लिए फर्नीचर है, तो यह नमूना है इस सरकार का।

मैं पानी के मामले में जाऊं। मैं, मेरा विधान सभा क्षेत्र राजस्थान प्रदेश के अन्तिम छोर पर है, आपके शेखावाटी से आता हूं। चार हरियाणा प्रदेश की विधान सभा टच करती हैं। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की 2021-22 के बजट में घोषणा हो गयी। बजट स्वीकृत हो गया, लेकिन बजट स्वीकृति के बाद मैंने पिछले सत्र में भी सरकार को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था और जलदाय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि हम 31 मई तक टेंडर कर देंगे और अब अगला बजट सत्र चल रहा है। बड़ी शर्म की बात है। हमें इस सदन में कहते हुए भी शर्म आ रही है और ये वाहवाही लूट रहे हैं। किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं? मेरे यहां पर हजार-हजार फीट गहरा जाने के बाद भी पानी नहीं है और आने वाले समय में गर्मी में पेयजल की जो समस्या होगी, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आमजन जब सड़क पर आयेगा, तब सरकार का क्या हाल होगा? सरकार का हाल तो अभी आपने जन आक्रोश यात्रा में देख लिया था। बहुत जल्दी यह सरकार तो जाने वाली है, लेकिन जितने दिन भी हो, कम से कम आपने बजट घोषणाएं, क्या ये बजट घोषणाएं होती हैं, मंत्री कुछ बोलता है। क्या यह असत्य का पुलिन्दा है? इसके ऊपर आप विचार करें, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं।

(श्री सुभाष पूनिया)

हमारे चिकित्सा मंत्री बैठे हैं, निश्चित रूप से बहुत भले आदमी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कोविड काल में सी एच सी मॉडल बनाने के लिए एक-एक करोड़ रुपये, एक-एक एम एल ए से इन्होंने मांगे थे। हमने एक-एक करोड़ रुपये दे दिये। हमने मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवा दिये, लेकिन वहां पर टेक्निकल स्टाफ नहीं है। उसकी वजह से आज जितने भी मेडिकल उपकरण हैं, वे धूल फांक रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है। आज मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन्होंने जो मॉडल सी एच सी घोषित की है, वहां मात्र 30 बेड हैं। वहां पंचायत समिति हेडक्वार्टर है, सब-डिविजनल हेडक्वार्टर है, म्युनिसिपैलिटी हेडक्वार्टर है। मैंने दो सत्रों में लगातार आग्रह कर दिया है, लेकिन आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन सी एच सी हैं, उन तीनों में 30-30 बेड से ज्यादा बेड नहीं हैं, इसलिए गरीब आदमी इलाज कराने कहां जायेगा? यह भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। नि:शुल्क दवाइयों की बात रही तो आप देख रहे हैं कि चिरंजीवी योजना में भी क्या हो रहा है। इन खामियों को ठीक करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के कान के ऊपर कोई जूं भी रेंगेगी?

अब मैं बिजली के बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं। सभापति जी, आप और हम शेखावाटी क्षेत्र से आते हैं। बिजली का मुद्दा अपने यहां सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। बिजली के क्षेत्र में, हम बचपन में थे, तब से सुनते आये हैं, सरकारें कोई भी रही हों, कहते थे कि हम इतनी बिजली बनायेंगे, हम आकाश से बिजली बनायेंगे, हम पाताल से बिजली बनायेंगे, हम हवा से बिजली बनायेंगे और हमारे पास इतनी बिजली होगी, इतनी सरप्लस बिजली होगी कि हम अन्य प्रदेशों में उस बिजली को बेचने का काम करेंगे। आज भी बिजली कटौती के नाम पर पूरे प्रदेश की जनता किस तरह से परेशान है, आज तक इन सरकारों से कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझता था कि आपकी सरकार इसमें कुछ करेगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पायी।

बूंद-बूंद सिंचाई के नाम पर करोड़ों रुपये उन किसानों से ले लिये जिन किसानों ने ब्याज पर पैसा लिया। उन्होंने ब्याज पर पैसा लेकर डिमांड नोटिस भरने का काम किया पर आज तक उनको कनेक्शन देने का काम नहीं किया। जिन किसानों ने पैसा दे दिया, वे किसान बूंद-बूंद सिंचाई के बिल की जो रेट आयेगी, वह नहीं भर पायेंगे। इसलिए अगर उनको राहत देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का किसान लाभान्वित होगा। बिजली के मामले

(श्री सुभाष पूनिया)

में आपने कह रखा है कि जब भी किसी किसान का ट्रांसफार्मर जलेगा, उसको 72 घन्टे में हम ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवायेंगे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, मेरे क्षेत्र में तो 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, यह बड़े शर्म की बात है।

कानून व्यवस्था के बारे में मेरे पक्ष और विपक्ष के, पक्ष के लोग तो बड़ी वाहवाही कर रहे थे, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं निकलता है और हम बलात्कार के मामले में नम्बर-वन पर हैं, हम रंगदारी मांगने के मामले में भी। आजकल पता नहीं, कौन-कौनसी गैंग है। आपस में गैंगवार हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की आपने जो व्यवस्था दी है चूंकि मुख्य मंत्री जी के खुद के पास ही गृह मंत्रालय है, इस प्रदेश में आज अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में इस प्रदेश को ला रखा है। यह बड़े शर्म की बात है, फिर भी पीठ थपथपा रहे हो। पता नहीं, कहां से ऐसी सरकार आयी है। मैं तो चाहता हूं कि बहुत जल्द ही यह सरकार जाये और सुशासन आये। चार साल से ऊपर का जो कुशासन और जंगलराज आज प्रदेश में है, उससे निश्चित रूप से जनता आक्रोशित है।

श्रीमान जी, मैं सड़क की बात करूं। सड़क के मामले में हमें 10 करोड़ की सड़कें विधायकों की अनुशंसा के ऊपर दी गयी थीं, लेकिन आज तक उन सड़कों का प्रस्ताव तो हमसे मांगा नहीं। एक बार कलेक्टर साहब ने कहा कि आप एक बार प्रस्ताव दे दो, लेकिन हमने जो प्रस्ताव दिये, वे सारे के सारे प्रस्ताव तो नहीं आये और पता नहीं दूसरे प्रस्ताव कहां से आ गये। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई सड़कें दें तो कम से कम आपस में भेदभाव नहीं हो। मेरे क्षेत्र में जो सड़कों का हाल है, इसके लिए मैंने पहले भी बजट में बोला है। अब भी मैं बता रहा हूं कि पचेरी बालोद जो कि हरियाणा बोर्डर की सड़क है। वह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जो कि 15 किलोमीटर की है। उसको अतिशीघ्र पूरा किया जाये, क्योंकि वहां अब भी लोग धरने पर बैठे हैं। दूसरी कि खांदवां से सांतोर सड़क है, जो कि नारनौल के बोर्डर को टच करती है। वह सड़क अगर दी जायेगी तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र लाभान्वित होगा। मुझे लगता है कि दोनों जिलों, सीकर और झुंझुनूं में भारतीय जनता पार्टी का अकेला विधायक है, इसलिए मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको मुझ से कोई दुश्मनी होगी, लेकिन जनता से दुश्मनी नहीं निकालें, यह मेरा आपसे आग्रह है।

(श्री सुभाष पूनिया)

श्रीमान जी, हमारे यहां म्युनिसिपैलिटी है और छोटी-सी म्युनिसिपैलिटी है। उसमें दस दिन से ज्यादा कोई भी ई ओ नहीं रहता है। डवलपमेंट कहां से होगा? आप रिकार्ड उठाकर देखें, एक-एक कर्मचारी का 15-15 बार स्थानान्तरण होता है। स्थानान्तरण का यह जो धन्धा चल रहा है, जिसको अपन बता रहे हैं कि क्या यह लघु उद्योग है। मुझे तो लगता है कि यह बहुत बड़ा उद्योग है। इसलिए इससे आप निजात दिलायें, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपनी सरकार बचाने के लिए इन लोगों को छूट दे रखी है। इस तरह की छूट अगर नहीं दें तो ठीक रहेगा। लेकिन सिवाय इसके आपने कुछ किया ही नहीं और बेरोजगारों के साथ जो अन्याय किया है। किसानों का कर्जा तो आपने माफ कर ही दिया? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर आपने बेरोजगारों को भत्ता दे ही दिया? बेरोजगार लोगों को अभी आपने ताजा-ताजा तोहफा दिया और राजस्थान प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में पेपर लीक मामले में नम्बर एक पर रहा है, यह बड़े शर्म की बात है। मैं नहीं कहता, आपके पूर्व उप मुख्य मंत्री ने खुद कहा है कि पेपर लीक कहां से हुए हैं। क्या कोई जादूगरी से हुए हैं? तो यह बड़े शर्म की बात है। आपके ही इस सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि एक फॉर्च्यूनर में जितने बैठकर आते हैं, हम उतने जीतकर आएंगे। यह हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कहते। आपकी सरकार चलाने के लिये क्या हमने ''नाकारा'' कहा था, क्या हमने ''निकम्मा'' कहा था, क्या हमने ''गद्दार'' कहा था, क्या हमने ''रगड़ाई'' के लिये कहा था? और तो और इस कांग्रेस में शायद ''कोरोना'' भी आ गया, यह तो हमने नहीं कहा। फिर भी कोई बात नहीं जनता देख रही है।

रही बात नंदीशाला की, तो आपने शुरुआत में ही बजट जब पेश किया था तब कहा था कि हम पंचायत समिति हैडक्वार्टर के ऊपर नंदीशाला खोलेंगे। आपने वह नंदीशाला खोल दी है? सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): आपका आखिरी बजट है। अबकी बार भी आप खोल दें तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कृषि मंत्री जी कि उन्होंने हमारी मांग पर स्पेशल गिरदावरी, जो पाला पड़ा है किसानों

(श्री सुभाष पूनिया)

पर, उसके ऊपर स्पेशल गिरदावरी कराने का काम किया है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो गिरदावरी करवा रहे हैं, उसमें इनको आप पाबंद कीजिए, वहां के जो गिरदावर हैं, पटवारी हैं 20 और 25 परसेंट खराबा दिखा रहे हैं, लेकिन खराबा ज्यादा हुआ है। सभापति जी, 80-80 परसेंट सरसों का खराबा हुआ है, इसको भी आप ध्यान में लें। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो पाले से खराबा हुआ है तो किसानों को राहत देने के लिए चार माह का बिल माफ करें। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। आपने मेरे को समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि चार साल में जो राजस्थान की दिशा और दशा दोनों बदलकर रख दी, आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो असली लीडर और असली नेता होने का परिचय दिया है, जिन्होंने कोरोना के समय में जनता का ध्यान रखा, जनता को परेशानी नहीं हुई, जनता का इलाज करवाया। सरकार के द्वारा यह निर्देश दे दिया गया कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिये। सरकार के ऐसे मुखिया, आज हमारे राजस्थान को तरक्की की ओर लेकर जा रहे हैं।

पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रदेश में निरोगी राजस्थान के नाम से चिरंजीवी योजना लागू की और गरीब किसान के स्वास्थ्य के प्रति सोचा। आज चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 5 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा की सुविधा दी जा रही है। यह बात सही है कि जब किसी घर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका पूरा परिवार बरबाद हो जाता है। मैंने इसको देखा है। मेरे क्षेत्र में 5 लड़कों की अभी पिछले दिनों दुर्घटना से, एक्सीडेंट से डैथ हुई हैं। उनको चिरंजीवी योजना के तहत 5-5 लाख रुपये मिले हैं। एक लड़का घायल हुआ है, उसे 2.5 लाख रुपये मिले हैं। प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी को इस योजना का लाभ मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा केवल 41 परसेंट है और प्रदेश में 90 प्रतिशत के करीब है।

(श्री गोपाल लाल मीना)

यह माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी की वजह से ही सम्भव हो पाया है, जो इतनी बड़ी स्कीम लेकर आये हैं। एक्सीडेंट हो जाता था तो ये खबर सुनकर लोग पहले पैसे वाले के पास जाते थे और पैसे लेकर फिर इलाज के लिये हास्पिटल जाने का काम करते थे। आज 108 में जाएंगे, उसको लेकर जाएंगे, इलाज फ्री कराएंगे और घर पर छोड़ेंगे। यह हमारे राजस्थान की जनता की सुरक्षा का एक काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी बड़ी योजना जिसके अंतर्गत उन्होंने ये सोच रखी और राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य लाभ देने का काम किया है।

इस योजना के अंतर्गत अब तक 31 लाख 58 हजार लोगों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। बी जे पी की सरकार में स्वास्थ्य के मद पर 10 हजार करोड़ रुपये था जिसको बढ़ाकर हमारी सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये कर दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो पूरी प्रदेश की जनता को स्वस्थ देखना चाहते हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो प्रदेश और वह व्यक्ति आगे बढ़ता है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच और दवा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में आई पी डी व ओ पी डी में आज नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना में नवम्बर, 2022 तक करीब 949 करोड़ रुपये व्यय कर 7 करोड़ 50 लाख मरीजों को लाभान्वित किया गया है। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। चिरंजीवी योजना पूरे राजस्थान में अच्छी साबित हो रही है। लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर रही है। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, सी एच सी, पी एच सी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, ये सभी हमारे विधान सभा क्षेत्रों में खोले गये हैं। मैं पिछले बजट में भी बोला था और अबकी बार भी कहना चाहूंगा कि चिरंजीवी योजना का तो लाभ सबको मिल रहा है, चाहे हमारे माननीय सदस्य रामलाल जी हैं, ये भी चिरंजीवी योजना का फायदा ले रहे हैं। ये भी इस योजना से खुश हैं, लेकिन अब क्या करें, विपक्ष में बैठे हैं, बुराई नहीं करेंगे तो हमारे नंदलाल जी मीणा ने, नंदलाल जी मीणा हैं, पूर्व सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी आपकी तरह ही कुछ बोला था, मैं नहीं कहना चाहता।

चिरंजीवी योजना पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में लागू है और इसको पूरे भारत में लागू करना चाहिये। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कई मंचों से,

(श्री गोपाल लाल मीना)

लिखित में आदरणीय प्रधान मंत्री जी को लिखकर दिया है कि पूरे देश की जनता को इस चिरंजीवी योजना का लाभ मिलना चाहिए और ऐसी योजना लेकर आनी चाहिये। आपने देखी होगी राजस्थान की परिस्थिति, फिर भी 90 प्रतिशत लोगों को चिरंजीवी योजना के अन्दर अब तक लिया जा चुका है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 41 प्रतिशत लोगों को यह फायदा मिल रहा है।

स्वास्थ्य के रूप में इसको थोड़ा-सा बढ़ाएंगे तो मेरा सुझाव है सरकार से कि जो पी एच सी है, अगर हर पंचायत स्तर पर पी एच सी रहे तो मैं कहना चाहूंगा कि इस चिरंजीवी योजना का लोगों को और भी ज्यादा फायदा मिल सकेगा। जब शिक्षा के स्तर पर हर ग्राम पंचायत पर सीनियर स्कूल है, वैसे ही पी एच सी हर पंचायत स्तर पर हो जाती है तो लोगों को इसका बहुत फायदा मिल पायेगा।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने न केवल पूरी जनता का ध्यान रखा, जो हमारे प्रदेश में तमाम कर्मचारी हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखते हैं और उसके लिए राज्य के समस्त सरकारी कर्मचारी/अधिकारी, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल, 2004 के बाद हुई है, उनकी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की गयी है। आज पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी खुश हैं। बी जे पी की सरकार ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी। आज भी भारत सरकार के कर्मचारियों को ओ.पी.एस. नहीं दी जा रही है। एन.पी.एस. जो शेयर मार्केट पर आधारित है, यह कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।

मैं मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी है। इनको देखते हुए हिमाचल प्रदेश व छत्तीसगढ में भी ओ.पी.एस. लागू की जा चुकी है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि पूरे देश में होना चाहिए। कर्मचारी जब 60 साल बाद नौकरी से घर जाते हैं तो ओ.पी.एस. से हर महीने उनको तनख्वाह आएगी जिससे वह अपना खर्चा चला पाएंगे। उनका आने वाला जीवन भी सुरक्षित कर दिया गया है।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। प्रदेश में भी हुआ है। मेरे क्षेत्र में 200-250 करोड़ रुपये से रोड्स का काम हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): कुछ बन गई, कुछ बनेंगी। जहां 70 साल में सड़कें नहीं बनीं, वहां सड़कें बनी हैं। 85 किलोमीटर स्टेट हाईवे हमारे क्षेत्र में मिला है। वैसे तो मेरा क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी एरिया है, फिर भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में करीबन 85 किलोमीटर नये स्टेट हाईवे दिए हैं, जिससे लोगों को आवागमन का फायदा मिल पाएगा। अगर क्षेत्र तक जाने के लिए सड़क होगी, तो उस क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। उन्होंने 15 करोड़ रुपये, 5 करोड़ तो पहले और 10 करोड़ रुपये पिछले बजट में, हर विधान सभा में 15-15 करोड़ रूपये मिसिंग लिंक के दिए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। गांवों का आवागमन मिसिंग लिंक से जुड़ा है। हम जाते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं कि आज इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जुडने का काम हुआ है। आने-जाने का फायदा हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने छोटी सी छोटी चीज को भी ध्यान में रखते हुए काम किया है, चाहे स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है।

वर्ष 2022-23 में किसानों को हमारी सरकार द्वारा दिसम्बर तक 16,402 करोड़ रुपये से अधिक का फसल ऋण बिना ब्याज के दिया है। पूरे प्रदेश में सहकारिता को गति प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 में दिसम्बर तक 418 पैक्स एवं 49 नये लैम्पस का गठन किया गया है। 12 करोड़ की लागत से नई ग्राम सेवा सहकारी गोदामों का निर्माण किया गया है। ग्राम स्तर पर स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से एक करोड़ रुपये की लागत से गौ माता के लिए गौ आश्रय स्थल बनाए जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बना दिए?

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): हमारी सरकार ने गौ माता के संरक्षण के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। इसका काम किया जा रहा है। बड़ा काम है हमारे क्षेत्र में 13 ज़िले हैं उनके लिए संजीवनी। आदरणीय प्रधान मंत्री की योजना है कि केवल सपने दिखाएं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने ई आर सी पी योजना का निर्णय लिया है। पूर्वी राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें 13 ज़िलों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मेरा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ भी शामिल है। हमारी सरकार द्वारा केन्द्र को बार-बार पत्र लिखा जा चुका है कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया। पूर्वी राजस्थान की जनता से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): जबकि हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने पिछले बजट में 9 हजार 600 करोड़ रुपये का इसमें प्रस्ताव रखा और लागू किया। उनकी सोच है, उन्होंने कहा भी है कि केन्द्र सरकार करे, अच्छी बात है, हम उनसे निवेदन करते हैं, लेकिन अगर वह नहीं भी करेगी तो हमारी सरकार इस योजना को पूरी करके रहेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): हमारी सरकार के पास जितने पैसे रहेंगे उस आधार पर हम इस योजना को पूरा करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है, अगर 13 ज़िलों को ई आर सी पी नहीं दी जाएगी तो मैं समझता हूं...

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): आदरणीय मोदी जी दो-तीन बार बड़ी मीटिंग्स में बोल भी चुके हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, यह क्या हो रहा है बीच-बीच में? कितना ही समझा दो, आप बिलकुल नहीं मानते। जरूरी है आपका हर बात में बीच-बीच में बोलना?

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): उसके बावजूद भी इस योजना को लागू नहीं किया जा रहा है।

श्री सभापति: विराजें प्लीज, सहयोग करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, राज्य का हर एक व्यक्ति, अच्छा जीवन जीने के लिए राज्य सरकार से मूलभूत सुविधाओं की उम्मीद करता है, लेकिन इस सरकार ने राज्य की जनता को चार साल में सुशासन की बजाय कुशासन उपलब्ध कराया। चार साल के शासन में राज्य सरकार द्वारा जो भर्तियां की गई उनमें बेरोजगारों के साथ अन्याय किया गया, युवाओं को ठगा गया, बेरोजगारों को ठगा गया। रीट भर्ती, सैकण्ड ग्रेड के पेपर लीक हुए, उसमें सरकार पूर्ण रूप से विफल रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि

(श्री गोपी चन्द मीणा)

वर्तमान में हमारे सांसद किरोड़ी लाल जी मीणा लगातार धरने पर बैठे हैं। मैं सी बी आई जांच की मांग करता हूं। सी बी आई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा।

सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में एक नमूना बताना चाहता हूं। चार साल में जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नहीं, हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए हैं। अपराध इतने बढ़े कि जो नमूना पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ एक नम्बर पर आया तो मेरा जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र आया। इसमें सरकारी कार्मिक को फर्जी टीचर बनाकर उसके नाम की एस एस ओ आई डी जारी करके, फर्जी टीचर बनाया गया और 1 करोड़ 20 लाख रुपये फर्जी उठाये गये। राज्य के नेताओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया, उसको बचाने का प्रयास किया गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसी तरह एक सरकारी स्कूल शकरगढ़ में भी कार्मिक ने फर्जीवाड़ा करके 1 करोड़ 20 लाख रुपये का भ्रष्टाचार किया।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहाजपुर में आये दिन सरकारी आयोजनों में चाहे साइकिल वितरण समारोह हो, वार्षिक उत्सव हो, इन समारोह में विद्यालयों में राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैंने सदन में भी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष महोदय से बराबर मांग कर रहा हूं फिर भी यह अपराध नहीं रूक रहे। हिस्ट्रीशीटर लोग, अपराधी लोग वहां मंच पर जाकर कार्य कर रहे हैं। चार साल में हमारे जहाजपुर विधान सभा में ही नहीं, सम्पूर्ण प्रदेश में विद्यालयों की स्थिति खराब है। प्रिंसिपल हटा दिए, टीचर्स हटा दिए, सब्जेक्ट टीचर हटा दिए। विद्यालय तो खोल दिए, सैकण्डरी स्कूल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोल दिए लेकिन स्टाफ नहीं लगाया। मैं सरकार से चाहता हूं कि रिक्त पद भरे जाएं ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे वहां जहाजपुर में बिजली की समस्या है। किसानों को रात को बिजली दी जाती है और वह भी कटौती करके दी जाती है और किसान यह कहता है कि बिजली नहीं मिल रही है। अफसर लोड सेटिंग का बहाना कर लेते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली की व्यवस्था की जाये। जो शहर में अंडर ग्राउंड केबल डाली जा रही है या बिजली की लाइन का काम किया जा रहा है उसमें भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मैं इसकी भी उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग करता हूं।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

सरकार 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने की बात करती है लेकिन 72 दिन तक भी ट्रांसफार्मर्स नहीं दिये जाते हैं और उसमें भेदभाव अपनाया जा रहा है। कोटड़ी में तो 250 ट्रांसफार्मर्स, अब ए.ईएन. कह रहा है कि पहले वाले ने बेच दिये तो मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि किसानों के साथ न्याय करे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करे।

मैं मेरे जहाजपुर के कोटड़ी उप खंड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। सरकार ने बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में यह कहा कि उप खंड स्तर पर महाविद्यालय खोला जायेगा तो कोटड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मैं मांग करता हूं।

कानून-व्यवस्था की बात करें तो पूरे प्रदेश में लूट, हत्याएं, अपराध, डकैती, अपहरण, भू-माफिया, बजरी-माफिया इतने पनप गये हैं और मेरे जहाजपुर में तो सरेआम थाने में अपराधी पिस्टल लेकर जाता है। उसको भी थाने के अधिकारी बचाने का प्रयास करते हैं और लूट, हत्या के प्रकरणों में सज़ा दिलाने के बजाय उन अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जितने भी अपराध हो रहे हैं, शकरगढ़ थाना, जहाजपुर थाना, कोटड़ी थाना में अपराधियों के साथ मिलकर पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और भय का एक माहौल पैदा किया जा रहा है तो मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। जिन पर पहले से ही गंभीर प्रकृति के आरोप हैं उन अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इसका एक नूमना बताना चाहता हूं कि कोटड़ी में पंचायत समिति का कबाड़ दो ट्रक बेच दिया था, उसका विकास अधिकारी ने 2015 में मुकदमा नं. 145/2015 दर्ज करवाया था। कोटड़ी थाने का प्रकरण है लेकिन सात साल के बाद भी पुलिस ने चालान पेश नहीं किया और वह अपराधी, हिस्ट्रीशीटर एस.एच.ओ. के बराबर जाकर बैठते हैं और अपराध कारित करते हैं। इसमें प्रश्न के जवाब में मेरे को यह दिया कि अपराधियों को पुलिस ढूंढ रही है तो ऐसे तो कहां से न्याय मिल पायेगा? एक 104/2010 का प्रकरण, 12 साल हो गये, अभी तक भी चालान पेश नहीं किया है तो ऐसे संगीन अपराधों में 10 साल तक, 12 साल तक यदि न्याय नहीं देंगे तो फिर उनको कब न्याय मिलेगा?

(श्री गोपी चन्द मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लंबित प्रकरणों में जल्दी से जल्दी न्याय दे। हिस्ट्रीशीटर जिनके 22-22 मुकदमे हैं, मेरे पास लिस्ट है, ऐसे अपराधियों को खुले में सरकार संरक्षण प्रदान कर रही है। मैं न्याय की उम्मीद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर एस.डी.एम. भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया गया है, लेकिन उसको बचाया गया है। कोटड़ी में एस.डी.एम. का पद रिक्त है, तहसीलदार का पद रिक्त है, सारे पद रिक्त हैं। एक ही आदमी के पास दो-दो जगह का, तीन-तीन जगह का चार्ज दिया जा रहा है। ए.ईएन. और बी.डी.ओ. का पद रिक्त है। बी.डी.ओ. की जगह ए.ईएन. को कार्य देकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और करोड़ों रुपये के घोटाले किये जा रहे हैं। वहां एक-एक पंचायत में एक-एक करोड़ की स्वीकृति जारी करके फर्जीवाड़े से पैसा उठाया जा रहा है। बी.डी.ओ. नहीं है। 12-12, 15-15, 20-20 बी.डी.ओ. लगा दिये और बदल देते हैं। ई.ओ., अधिशासी अधिकारी लगाकर दूसरे दिन आर्डर आता है, बदल देते हैं। विकास कार्य ठप हैं और सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की नीयत से पद रिक्त रखे जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट दागी अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटायें और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं कि पंचायती राज विभाग में, पंचायत समिति, कोटड़ी में दो साल होने के बाद भी विकास का जो पैसा है, सड़क, नाली का, जो कल्याणकारी योजनाओं का, दो साल के बाद भी 20-22 बी.डी.ओ., विकास अधिकारी बदल दिये जाते हैं और विकास के कार्यों को रोका जा रहा है। पंचायत समिति स्तर की जो राशि है राज्य सरकार और भारत सरकार की, वह दस से बारह करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार तो दे या नहीं दे, लेकिन जो जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारत सरकार पैसे भेजती है, वे विकास कार्य भी पूरे नहीं किये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि अच्छा बीडी.ओ. लगाकर विकास कार्य करवाया जाये, जनहित के कार्य किये जायें।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ग्राम पंचायत ऐसी है जिसमें सरकारी टीचर्स, सरकारी

(श्री गोपी चन्द मीणा)

कर्मचारी, 2012 में डैथ हो गयी और 2022 तक फर्जी भुगतान नरेगा में उठा रहे हैं। सर्तकता समिति, जिला प्रशासन ने जांच कर ली, लेकिन ऐसे भ्रष्ट कार्मिकों को अभी भी उन्हीं पदों पर बैठाया जा रहा है और करोड़ों रुपये का घोटाला किया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी हमने पंचायती राज सहित सभी विभागों से जांच की मांग की। हमारे पास सबूत हैं, तथ्य हैं फिर भी ऐसे भ्रष्ट दोषियों को बचाया जा रहा है। मैं इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से मेरे जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि शकरगढ़ में नेशनल हाईवे 148-डी गुजर रहा है जहां पर आये दिन वहां पर दुर्घटना होती रहती हैं। मैं वहां पर पी.एच.सी. से सी.एच.सी. क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। अमरगढ़ में पी.एच.सी. खोलने की मांग करता हूं। गोलछा ग्रुप के द्वारा मैंने, 108 खराब थी, भामाशाह को तैयार करके दो 108 लीं, लेकिन जिला प्रशासन की हठधर्मिता से उसको उप खंड स्तर जहाजपुर और कोटड़ी से दो साल से भीलवाड़ा में लगा रखा है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें ताकि जनता को लाभ मिल सके। जो गोलछा से मैंने 108 डोनेट करवायी वह भी हमें उपलब्ध नहीं हो रही है। यह बात मैंने माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में भी लायी थी और पत्र के माध्यम से लिखित में भी दिया। वह जांच में दोषी पाया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

कोटड़ी में सड़क के लिए निवेदन है। कोटड़ी चारभुजा नाथ की नगरी है, सम्भाग का सबसे बड़ा स्थान है। हजारों-लाखों श्रद्धालु वहां पर आते हैं और आये दिन जाम लग जाता है तो मैं सदन के माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि कोटड़ी में बाईपास का निर्माण हो। पीपलूंद में बाईपास का निर्माण हो। महत्वपूर्ण सड़कें जो हमारी गुढ़ा से देवपुरा, अधेपुर से बागीदार घाटे पर सड़क बनास नदी पर बनाई जाये ताकि आने-जाने वाले यात्रियों को 20 किलोमीटर दूरी का सफर नहीं करना पड़े। बनास नदी में पुलिया का निर्माण किया जाये, ओडया खेड़ा से घाटा रानी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जहाजपुर में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह तो है ही, लेकिन हमारे जहाजपुर में प्रशासन के द्वारा, एस.डी.एम. के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा भ्रष्टाचार किया

(श्री गोपी चन्द मीणा)

जा रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया, धरना-प्रदर्शन किया। सरकारी जमीन पर, बेशकीमती जमीन, नेशनल हाईवे की जमीन, आबादी की जमीन, सरकारी जमीन, फोरेस्ट की जमीन में कब्जा किया जा रहा है और जिला प्रशासन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी कार्यवाही नहीं होती है तो मैं सरकार से यह चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिह्नित करके कार्यवाही करे। जो भू-माफियों को संरक्षण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए भी मैं मांग करता हूं।

जहाजपुर में अभी सहकारिता के चुनाव हमारे चल रहे हैं। सहकारिता के चुनाव में राज्य की जनता, अभी नमूना देखा ही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी मालाखेड़ा डूंगरी पधारे थे तो वहां पर जन सैलाब उमड़ा था। लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे मोदीजी की रैली में। मैं यह कहना चाहता हूं राज्य की सरकार तो जा ही रही है। समय बचा हुआ है चास्छह महीने, चुनाव तो जीत नहीं सकती लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन हमारे जो जी.एस.एस.एस. के चुनाव हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के दुर्भावनापूर्वक आवेदन रिजेक्ट किये जा रहे हैं, निर्विरोध चुनाव किये जा रहे हैं, धांधली की जा रही है तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष चुनाव करे लोकतंत्र की रक्षा करे। आने वाले समय में, 2023 में जनता इसका जवाब देगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के 23 जनवरी, 2023 के दिये हुए अभिभाषण पर डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, वीरता के साथ त्याग, तपस्या और बलिदान इस राजस्थान के कण-कण में है। 23 जनवरी, 2023 को राज्यपाल महोदय ने महाराणा प्रताप से लेकर पन्नाधाय, वीर दुर्गादास, भामाशाह, मीरा बाई, नानी बाई और खेजड़ली की अमृता देवी का भी जिक्र किया। जिस समाज से मैं आता हूं, अमृता देवी का जिक्र राज्यपाल महोदय ने इसलिए किया है कि

(श्री किसनाराम विश्नोई)

230 साल पहले अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में जोधपुर जिले के पास खेजड़ली गांव में 363 वृक्षों की रक्षा के लिए एक मात्र समाज, विश्नोई समाज के लोग शहीद हो गये वृक्षों को बचाने के लिए। जिसकी जरूरत इस प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, विश्व में है। पिछले दो साल आक्सीजन की वजह से यह जरूरत पड़ी। इन वृक्षों को, पर्यावरण को बचाने के लिए 363 लोग, एक मात्र समुदाय का जो इतिहास है वह खेजड़ली, जोधपुर जिले का है, वह माननीय राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है, जिस समुदाय से मैं आता हूं।

सभापति महोदय, डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी के धन्यवाद प्रस्ताव पर मैं मेरी सहमति प्रदान करते हुए कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की पिछले चार सालों एक ही थीम रही है कि सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म। थीम को लेकर प्रदेश में ढांचागत और व्यवस्थित विकास करने का प्रयास किया है जिसकी माननीय राज्यपाल महोदय ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इस प्रदेश में चाहे चिरंजीवी योजना में लागू की, दस लाख रुपये तक का इलाज फ्री किया, प्रदेश के अन्दर आम आदमी की जांच फ्री की, नि:शुल्क दवा दी, दुर्घटना होने पर पांच लाख रुपये तक का मुआवजा दिया। उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देश के किसी भी प्रदेश में ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा।

(समय: 15.51 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, खूब सारा जिक्र किया गया, लेकिन ऐसा उदाहरण पूरे देश और विश्व के अन्दर नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले चार सालों के अन्दर 33 मेडिकल कालेज खोलने की बात हो, सी एच सी खोलने की बात हो, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात हो, खूब सारा ढांचागत काम किया। आम आदमी, गरीब आदमी को नि:शुल्क इलाज देने की व्यवस्था राजस्थान प्रदेश में जो है, वैसा उदाहरण पूरे हिन्दुस्तान में नहीं है। इसका जिक्र प्रधान मंत्रीजी ने भी कोरोना काल में किया। ऐसी व्यवस्था दूसरे किसी प्रदेश में नहीं है।

मेरे साथियों ने सड़कों का जिक्र किया। सड़कों का जाल पूरे राजस्थान में बिछाया। चाहे स्टेट हाईवे की बात हो, चाहे सड़कों के सुदृढ़ीकरण की बात हो, वह सब किया। यही नहीं, पिछले बजट के अन्दर 257 राजस्व गांवों को मुख्यमंत्री सड़क योजना से जोड़ा गया। यह एक रिकार्ड है। आज तक प्रधान

(श्री किसनाराम विश्नोई)

मंत्री सड़क से जोड़ा गया था पर पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 257 राजस्व गांवों को मुख्यमंत्री सड़क योजना से जोड़ा। यही नहीं, 10 करोड़ रुपये तक की सड़कें विधायक महोदय की अनुशंसा पर देने की परम्परा पहली बार हुई। जनप्रतिनिधियों का मान और सम्मान किया गया है। हमारे सामने बैठे साथी जिक्र कर रहे थे 10 करोड़ का कि विधायक का अगर किसी ने सम्मान किया है तो प्रदेश के मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने किया है। सामने बैठे साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अभी जिक्र कर रहे थे, रियायती दर पर 30 लाख रुपये तक का फ्लैट देने का भी का, सभी को समान रूप से देने का काम अशोक गहलोतजी ने किया है। आपको भी दिया गया है। उन्होंने सबको समान रूप से देखा है। अशोक गहलोतजी हमारी मारवाड़ की धरती से आते हैं। मारवाड़ की धरती का पानी गहरा है। पुरखों की कहावत है कि गहरे पानी का आदमी बहुत गहरा होता है, सबका समान रूप से सोचता है। इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि आप भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करो, चाहे फ्लैट देने की बात हो, चाहे सड़क देने की बात हो।

मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश में खूब काम हुआ है। चाहे कालेज खोलने की बात हो, चाहे कन्या कालेज खोलने की बात हो। अमीर के आदमी बच्चे अंग्रेजी की पढ़ाई करने के लिए शहरों में जाते थे और गरीब आदमी का केवल सपना ही हुआ करता था कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी मेरे बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेज पाता। 1700 स्कूल राजस्थान प्रदेश में खोलकर गरीब के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जोड़ा इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही, 3300 स्कूल्स को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की बात हो, आठवीं की नवीन स्कूल खोलने की बात हो, सब किया। शिक्षा के ढांचे को मुख्य मंत्रीजी ने मजबूत किया है।

पानी के क्षेत्र में सामने बैठे साथियों के माध्यम से भी प्रयास किया गया कि भारत सरकार को कहिएगा कि जल जीवन मिशन में 90 परसेंट हिस्सा दिया जाए, ताकि मरुस्थलीय इलाके में राजस्थान जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, घर-घर पानी देने की बात जो कही गयी थी, 90 परसेंट राशि नहीं दे पाये। मुख्य मंत्रीजी ने आगे बढ़कर करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट मंजूर किए जिसमें 50 परसेंट हिस्सा है और घर-घर पानी देने की बात हुई।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

मैं इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के थर्ड फेज में केन्द्र से इमदाद की बात थी। केन्द्र से इमदाद नहीं मिलने के बावजूद भी 1,456 करोड़ रुपये की थर्ड फेज की योजना स्टेट फण्ड से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरू की जो 209 किलोमीटर मदासर से लेकर जोधपुर तक की थी। इसमें जोधपुर और पाली के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा।

डाक्टर जितेन्द्र सिंजीजी ने जो प्रस्ताव रखा है, उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि ऐतिहासिक काम किया गया है। चिरंजीवी योजना देश का उदाहरण है। पहला राज्य और पहला मुख्य मंत्री होगा जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। यह इतिहास राजस्थान के खाते में लिखा गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गौशालाओं के लिए कहना चाहूंगा। आप हमेशा गायों की बात करते हो, गायों के रक्षक बने हुए होते हैं। प्रदेश की सरकार 90 प्रतिशत गौशालाओं के लिए देती है। आप केवल गायों की बात ही करते हो, गायों की रक्षा के लिए आपने कभी ठोस कदम नहीं उठाया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी एक मिनट ही हुआ है।

इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि बिजली के क्षेत्र में खूब सारे सिस्टम को मजबूत किया गया है। 400 के.वी. जी एस एस की बात हो, 220 के.वी. जी एस एस की बात हो, 132 के.वी. जी एस एस की बात हो, ढांचागत सिस्टम को मजबूत किया गया है। घरेलू बिजली की 50 यूनिट फ्री की गई क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे रात को पढ़ाई करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब लम्बा भाषण नहीं हो सकता। धन्यवाद। हो गया, प्लीज।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि खेल प्रतिभा को खोजने के लिए पहली बार ग्रामीण ओलम्पिक खेलों की शुरुआत की गई जिसमें 30 लाख प्रतिभागी खेले।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बस। खतम हो गया।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): बस एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। प्लीज, नीचे बैठें। बैठें, हो गया। आप नये हैं। सीखना नहीं चाहते क्या? श्रीमती गंगा देवी।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद देती हूं। मुख्य मंत्रीजी मेरा काम कर रहे हैं इसलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे क्षेत्र में काफी अंग्रेजी स्कूल खोलीं। गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ पाता था तो गरीब के बच्चे का सपना पूरा किया। इसके लिए मैं गहलोत साहब को धन्यवाद देती हूं क्योंकि गरीब का बच्चा भी अब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सकेगा।

नगरपालिका के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 10 करोड़ रुपये की सड़क बनवायी। विधायकों का मान-सम्मान माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत साहब ने रखा है। इस बात के लिए भी मैं उनको धन्यवाद देती हूं।

मेरे क्षेत्र के अन्दर स्कूल और डिस्पेंसरी और बड़े अस्पताल भी खुले, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूं। मेरा क्षेत्र शहर के नजदीक है, राजधानी में है। मैं जो भी मांगती हूं, मुख्य मंत्रीजी मुझे देते हैं। इनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। चार साल के कार्यकाल में से दो साल कोरोना के चले गये, फिर भी जनता को महसूस नहीं हो रहा कि दो साल काम नहीं हुआ। चार सालों के अन्दर गहलोत साहब ने इतना सारा काम करवा दिया कि गहलोत साहब यह कहते हैं मांगते-मांगते आप थक जाएंगे विधायक, लेकिन गहलोत साहब देते-देते नहीं थकेंगे। इस बात के लिए भी मैं गहलोत साहब को धन्यवाद देती हूं। बजट के लिए गहलोत साहब के फोन आते हैं कि जो मांगना चाहते हो, वह मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। विपक्ष वाले तो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन गांधीवादी मुख्य मंत्री देने वाला है, थकते नहीं हैं।

मैं गांवों में पंचायतों में जाती हूं। गांव में पहले कोई बीमार हो जाता था तो जमीन और जेवर-गहने गिरवी रखकर इलाज करवाते थे। कर्जा कर लेते थे तब भी इलाज नहीं होता था, इधर-उधर भटकते रहते थे। चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपये का इलाज गहलोत साहब ने शुरू किया है। उनको मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको भी धन्यवाद देती हूं। जय हिन्द।

(समय: 16.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो कुछ भी मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और इस सरकार की प्रगति रिपोर्ट मिली है, उसी के आधार पर अपनी बात कहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस सदन के नेता मेरी बात को तर्क के साथ, कि मैंने कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गलत तथ्य के आधार पर बात कही हो तो उसको जरूर काटें, तब तो मुझे लगेगा कि वास्तव में मेरी कहीं न कहीं भूल हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से, सदन के नेता तो मौजूद नहीं हैं, पर फिर भी मैं पढ़ना चाहता हूं। यह जो अभिभाषण है 23 तारीख का, जिसके बारे में आप और हम सब चाहते हैं कि 13 जिलों की पानी की समस्या हल हो, इसमें किसी की भी राय भिन्न हो ही नहीं सकती, हर व्यक्ति की इसमें सहमति रहती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि या तो इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गयी या सोच में मिस्टेक हो गयी, या क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका पेज नंबर 18 और पैरा नंबर 170, 'इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिये मानसून के दौरान चंबल नदी की सहायक नदी बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिंध, गंभीरी इत्यादि नदी बेसिनों में जल अपवर्तन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है।' इस परियोजना द्वारा राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता तथा 2 लाख हैक्टेयर नये क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा, अब मैं सोचता हूं कि 2051 में अगर यह योजना पूरी होगी तो हम तो भगवान के यहां जा चुके होंगे। हम तो इस योजना का कोई स्वरूप देख नहीं पायेंगे। यह या तो कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गयी, तो इसको सुधार लेना और प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो तो आप सब सचेत हो जाना कि जिस योजना के बारे में आप दे ताली, दे ताली बजा-बजाकर थक गये हो, वह 2051 में पूरी होगी, तब हममें से आधे से अधिक लोग भगवान के यहां जा चुके होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, यह कल्याण सिंहजी के द्वारा 15वीं विधान सभा के प्रथम सत्र में जो भाषण पढ़ा है, उस पर ही सरकार का पूरा पांच साल का काम टिका हुआ है। मैं उसके बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पैरा नंबर 10, जिस पर आप दे ताली, दे ताली देकर थक नहीं रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं- 'सरकार ने जन-घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार कर, आमजन के लिये किये गये वादों को पूरा करने के साथ ही, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाये हैं। यह नीतिगत दस्तावेज वर्तमान सरकार की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सभी विभागाध्यक्ष को 100 दिवसों की कार्ययोजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिये हैं।' मतलब 100 दिन में आपको, जो-जो आपने घोषणाएं की हैं, वह राज्यपाल महोदय के मुंह से आपने कहलाने का प्रयास किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो इनकी हकीकत है, यह एक और डाक्यूमेंट है आपका, जिसको आप जन घोषणा-पत्र रोज बोलते हो। आज मैं आपका जन घोषणा-पत्र दिखाता हूं कि आप वास्तव में देखने का प्रयास करो। आपने घोषणा की थी कि 10 दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ कर देंगे। यह नहीं कहा कौनसा ऋण माफ करेंगे, कृषि ऋण, कृषि ऋण में सभी आते हैं। वर्तमान सरकार द्वारा बन्द किये गये लगभग 20 हजार स्कूलों की समीक्षा कर नये सिरे से प्रारम्भ किया जायेगा। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में शत-प्रतिशत बिजली 24X7 आपूर्ति करना सुनिश्चित की जा रही है और किसानों को 8 घंटे तक बिजली दी जायेगी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, मेरे माध्यम से सारी राजस्थान की जनता भी इस बात को सुने कि जो राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा था, 100 दिन में जिस कार्ययोजना को बनाया था, उसी को पढ़ रहा हूं, शिक्षित बेरोजगार वर्ग को 3500 रुपये प्रति माह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। यह बेरोजगारी भत्ता शिक्षित बेरोजगारों को दिया जायेगा। अर्थ शायद अलग-अलग निकलते हों तो आप समझाना। सरकार ने संविदाकर्मी, NRHM, NUHM कर्मियों, पैराटीचर्स, उर्दू पैराटीचर्स, लोकजुम्बिश कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षाकर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों के अन्तर्गत... (व्यवधान) आपके आने के पहले मैंने एक पैरा पढ़ा है, वैसे आपको पता लग गया होगा। आपने ईस्टर्न कैनाल को, जो हमारे राज्यपाल महोदय से पढ़ाया, उसमें आपने लिखा है कि 2051 में पूरा होगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): सुन लिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सुन लिया, तब तो ठीक है। धन्यवाद आपको। अब इस पर गौर भी कर लेना और अगर मैंने गलत पढ़ा हो या प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो ठीक करा देना।

'विभागों के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों की समस्या का यथोचित समाधान कर नियमित किया जायेगा। राजस्थान प्रदेश में युवाओं के लिये अधिकाधिक रोजगार का सृजन करना तथा प्रदेश में सभी राजकीय विभागों में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रिक्त पड़े स्वीकृत पदों को समयबद्ध रूप से पूरा करना।' अब आप बताइये इसमें क्या हुआ है? मैंने कोई चीज इसमें गलत पढ़ दी हो तो आप मुझे करेक्ट कर देना, आपके सब विद्वान अधिकारी भी यहां बैठे हुए हैं, मेरी बात को आगे ले जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपने यह जो किसान कर्जा माफी की बात की है, आपने सहकारिता का जो ऋण था, वह तो माफ किया, लेकिन आपने 2020-21 की जो बजट घोषणा है, उसके बिन्दु संख्या 68 द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से समन्वय कर वन टाइम सेटलमेंट द्वारा करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उसकी कुछ पालना नहीं हो पायी। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये आपने केन्द्र सरकार को लिखा, 3 लाख से अधिक किसान हैं। मेरे एक प्रश्न के जवाब में विधान सभा में बताया। राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये जवाब के अनुसार, सभी माननीय सदस्य मेरी बात को सुनना और जहां आपको लगे कि मैं गलत तथ्य दे रहा हूं तो आप मुझे जरूर मदद करें। जवाब के अनुसार तीन साल में 22,215 किसानों को कुर्की के नोटिस दिये गये, यह मेरे प्रश्न के जवाब में है, जिनमें से 18,817 किसानों की जमीनें कुर्क हुईं। इसमें कुछ जिलों की इन्होंने संख्या दी। अलवर में 4,010, जयपुर में 2,945, गंगानगर में 2,888, हनुमानगढ़ में 1,906, भरतपुर में 1,690 और चूरू में 1,359, यह मेरे प्रश्न के जवाब में दिया है। आपकी यह जो माफ करने वाली बात थी, इसके भरोसे किसान रहा और उसकी जमीन कुर्क हुई।

आपने कहा ग्रामीण कृषक उपभोक्ताओं का बिजली बिल हमने माफ किया है। अब ईमानदारी से बताओ, वसुन्धराजी ने अपनी पिछली सरकार के समय में किसान का 10 हजार तक का बिल, किसान को नहीं देना था, उसको सरकार ने जमा कराना शुरू कर दिया था और अगर यही योजना लागू रहती तो 60 महीने में उनको 50 हजार रुपये की रिलीफ मिलती कि नहीं मिलती? आपने तीन साल तक उसे बंद रखा और अभी आपने मई, 2021 को इसे पुन: चालू किया और आपने इसको 2,000 बढ़ाकर, बजाओ ताली, उसको मिला तो केवल 23 हजार रुपये और उसको घाटा हुआ 27 हजार रुपयों का, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपने वास्तव में किसान को मदद की है तो एक बार योजना को बंद करना, उसको 30 हजार रुपयों का घाटा करना और फिर उसके बाद घोषणा करके और सदन में ताली पिटवाना और जो खड़ा हुआ, वह यही बोलता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खाद वितरण की व्यवस्था के बारे में, मैं आपका ही पढ़ रहा हूं। आपने अपनी 2019-20 की जो घोषणा की थी, उसमें बिन्दु संख्या-19 में खाद की पर्याप्त आपूर्ति हेतु 1 लाख मीट्रिक टन DAP एवं 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया के अग्रिम भंडारण की बात कही है। यह अग्रिम भंडारण हो गया क्या? अगर हो गया तो लाठी खाने की जरूरत क्या पड़ी? किसानों को खाद के लिये लाइन में खड़ा क्यों होना पड़ा? जब आपने भंडारण 2019-20 के बजट में ही कर दिया था तो फिर यह स्थिति आयी क्यों? आपने डिमांड कितनी क्रियेट की थी यूरिया और DAP के लिये? आपने डिमांड कौनसी तारीख को की और आपको कौनसी तारीख को कितना-कितना खाद मिला? आपको खाद पर्याप्त मिला। आपने 8 लाख मीट्रिक टन मांगा, आपको 12 लाख मीट्रिक टन दिया और उसके बाद भी आप व्यवस्था नहीं कर सके, इसलिए वितरण की व्यवस्था न होने के कारण से किसान घंटों तक इस ठंड के मौसम में खड़ा रहा। यह आपकी काबिलियत का तरीका मैं बता रहा हूं।

मैं भी इसकी तारीफ करता हूं कि आठवीं क्लास तक के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का अवसर मिला। इसको कोई ना नहीं कह सकता। राजस्थान की जनता के लिये बहुत खुशी है। मन को इससे प्रसन्नता होती है। आपने महात्मा गांधी का नाम लिया। महात्मा गांधी के नाम से स्कूल शुरू किया। यह आपकी बजट घोषणा 2019-20 की थी, कब? 2019-20, अभी अपन किसमें आ गये? 2023-24 में। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, कृपा करके राजस्थान की जनता को मेरे इन सवालों का जवाब देकर संतुष्ट करना।

महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय के नाम से आपने 1,700 विद्यालय प्रारम्भ किये। 1,700 विद्यालयों में से एक पद भी आपने स्वीकृत किया हो तो उसकी तारीख बता देना। एक पद भी आपने स्वीकृत किया हो तो बता देना। बिना स्वीकृति के किसी भी अध्यापक को आप लगाओगे तो वेतन वहां से नहीं उठ सकता। वेतन किसी न किसी दूसरे स्कूल से आयेगा। इसका मतलब आपने 1,700 हिन्दी मीडियम जो स्कूल थे, उन स्कूलों के अध्यापकों को यहां व्यवस्था के लिये लगाकर उनको भगवान भरोसे छोड़ा कि नहीं छोड़ा? उसमें से भी आप देखो, आपने सलेक्शन का तरीका निकाला था। पहले चरण में आपने व्यवस्थित इंटरव्यू

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करके अध्यापकों का सलेक्शन किया था लगाने के लिये। दूसरे चरण में आपने कहा कि जो हिन्दी मीडियम के हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के अध्यापक हैं पढ़ाने वाले, उनको लगा दो। जो आपका तीसरा चरण है, दुर्भाग्य है राजस्थान के उन बच्चों का कि तीसरे चरण में आपने सब में अपने भाई, भतीजों को भर दिया। जरूरत हो या मत हो। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां लगे हुए शिक्षकों का पोस्टमार्टम करो कि यह कौन हैं, कहां से आये हैं और कैसे आये हैं?

मैं आपको फिर विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोल सकता, उसको आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से दूसरे स्कूलों से ट्रांसफर करके, उनको राहत देने का काम किया है। इससे उन बच्चों का भला नहीं होगा। बच्चे जिंदगी भर आप और मुझको याद करेंगे कि मुझे अंग्रेजी के नाम से पढ़ने के लिये भेजा तो सही, लेकिन वहां पढ़ाने वाला मास्टर ही अंग्रेजी नहीं जानता।

स्वयं आपका डायरेक्टर नागौर के एक स्कूल में गया। जाकर के उसने वहां के प्रिंसिपल से कहा कि अंग्रेजी की 2 लाइन तो बोल, तो उसको सस्पेंड कर दिया। उसका क्या दोष है? दोष तो लगाने वाले का है कि उसको क्यों लगाया। मतलब, ऐसी दुर्गति करने के बाद, अब आप बताओ विद्यालय में पुस्तकालय और प्रयोगशाला का कोई पद नहीं है। लेकिन आज की तारीख में यह जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, इनमें आपने पुस्तकालय अध्यक्ष लगा रखे हैं, प्रयोगशाला सहायक लगा रखे हैं। यह केवल तनख्वाह देने के लिये और अपने बच्चों को एडजस्ट करने के लिये बनाते हैं या स्कूल के उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिये बनाते हैं?

अभी आपने शिक्षाकर्मी स्कूल के बारे में कहा था, हमने तो नहीं कहा था कि आप ऐसा करो। आपने कहा, आपने घोषणा-पत्र के साथ पैराटीचर्स और इन सभी को कहा कि सारी समस्याओं का यथोचित समाधान और नियमित किया जायेगा। मैंने नहीं कहा आपको लिखने के लिये कि आप 'नियमित किया जाये' लिखो। आपने लिखा, उसका हुआ क्या? बी.डी. कल्ला साहब की कमेटी बना दी। उस कमेटी ने 4 साल में रिपोर्ट दी क्या? कोई हल निकला क्या? नहीं निकला।

उसके बाद आपने क्या किया है कि 11.01.2022 को आपने कहा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि हम इसके लिये नियम बनायेंगे, नियम बनाकर के इसमें अध्यापक लेंगे। मैं सोचता हूं कि जब आपको इन शिक्षाकर्मियों के वोट चाहिए थे तब तो आपने उनकी कोहनी पर गुड़ लगा दिया कि हम आपको नियमित करेंगे। बच्चा लालच में आया। स्वाभाविक है वह चाहे मेरी बच्ची हो चाहे आपका बच्चा हो, उसके मन में आयेगा कि कम से कम यह तो होगा, लेकिन वह नहीं हुआ।

आपने अभी जो नियम निकाला है, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। वह नियम इस बच्चे की मदद नहीं कर रहा है। वह बच्चों को डुबो रहा है। जो 1 लाख 10 हजार संविदाकर्मी को आप नियमित करोगे न, वह आपको बाद में समझ में आयेगा। इस कारण से आपने इस 15वीं विधान सभा के मेरे एक उत्तर में बताया था कि शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स और पूर्व की भांति जो कार्य करते हैं, उन्हें संविदा का दर्जा देने की परम्परा नहीं रही है। ऊपर मैंने राज्यपाल के अभिभाषण कहा, उसमें वर्ड टू वर्ड लिखा कि संविदाकर्मी में आकर के इनको लाभ मिलेगा। इनका आपने नहीं किया। अब आपने क्या किया है? एक नई योजना विद्या संबल निकाली है कि इसमें आप आओ, एप्लाई करो। उसके कारण से लाखों बच्चों ने, एक बार रिकार्ड मंगाकर इनको कहना कि आप बोलो कि कितने बच्चों ने विद्या संबल योजना में अपनी दरख्वास्त दी है, वह लाखों में है। उसके बाद आपने 14 तारीख को एक आदेश जारी कर दिया। सब कुछ काम कर दिया उन बच्चों ने। 400 करोड़ रुपया उन बच्चों का आपके यहां एप्लाई करने में लगा है। उसके बाद आपने निकाला कि इसको स्थगित किया गया। उसको स्थगित करने के बाद आपके डायरेक्टर ने आज की तारीख में 10 हजार इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, इनमें भर्ती के लिये उन्होंने एक आदेश निकाला। उस आदेश में आपने लिखा है, यह जो आपने नये नियम बनाये हैं, Rajasthan Contractual Hiring Rules, 2022, इसके नियम 6 में आपने क्या लिखा है? इसके तहत ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष रखी गयी है। अब यह जो आपका संविदाकर्मी है, यह तो 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से काम कर रहा है। यह तो 40 साल की उम्र पार कर गया। इसको तो आपने बाहर निकाल दिया। यही है न अभिप्राय इसका?

फिर इसका नियम 13, संविदाकर्मियों को एकमुश्त वेतन, अध्यक्ष

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

महोदय, आप भी अध्यापक रहे हो, मैं तो स्कूल अध्यापक रहा हूं, लेकिन मन में अभी भी अध्यापक का थोड़ा-बहुत अंश बचा है, बहुत दुख होता है, जब हम इस तरह के काम करते हैं तो मन को कष्ट होता है। एक मुश्त वेतन 10,400 रुपये हर महीने का प्रावधान किया गया है जो 9 वर्ष पूरा करने पर 18,500 रुपये तथा 18 साल पूरा करने पर 32,300 रुपया मिलेगा। इस प्रकार नियमित कर्मचारियों के समान काम करने के बाद भी उनका वेतन इससे काफी कम होगा, जबकि आपका मिनिमम वेज कितना है? क्या मेरा यह अध्यापक, यह जो शिक्षा कर्मी है, यह कानून के तहत मिनिमम वेतन पाने का भी अधिकारी नहीं है? हर बच्चा तो सुप्रीम कोर्ट लड़ने नहीं जा सकता है, लेकिन हम तो जा सकते हैं, हम तो समझदार आदमी हैं।

इसमें लिखा है, सालों से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की उनकी पहले से की गई सेवा पर 9, 18 साल वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब उसकी पुरानी सर्विस गई। नहीं मिलेगा, सेवा काल की गिनती, समझने का प्रयास करो, कम से कम बनाते समय पढ़ लिया करो भले आदमी, नियमित होने की दिनांक से चालू होगी। इसका मतलब यह जो आप अभी 2 फरवरी को कर रहे हो, उनकी गिनती पुरानी तो सब गई, इसके बाद गिनती शुरू होगी। इन नियमों के लागू होने के बाद भी यह कर्मचारी, सरकार के स्थायी कर्मचारी नहीं होगे। जब तक कि वह जिस विभाग अथवा योजना की संविदा पर काम कर रहा है, उसको सरकार नियमित पद पर कन्वर्ट नहीं करती। यदि नियमित होने के बाद भी नियम 20 के तहत संविदाकर्मी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नियमित किये जायेंगे, उसमें कम से कम 5 वर्ष तक संविदा पर काम करना पड़ेगा। यह है हमारे संविदाकर्मियों के प्रति आपकी हमदर्दी। वोट पाना हो जब तो नियमित करने का गुड़ लगाते हो और बाद में ऐसे नियम बनाते हो जिससे वह बैठकर के रोयेगा। आपका विभाग क्या कर रहा है? कोई देखने वाला भी है कि नहीं? मैंने तो जब इसको पढ़ने का प्रयास किया तो बहुत अफसोस हुआ।

यह गार्गी पुरस्कार हमने 1998 में शुरू किया था। वह इसलिए किया था कि जो गांव का बच्चा, 10वीं और 12वीं के बोर्ड में जिन बच्चों के 75 परसेंट से अधिक अंक आते हैं, उनको हमने 2 साल की पढ़ाई के लिए 3 हजार रुपया प्रति वर्ष देकर उनकी मदद की। मैं बताता हूं, यह सब विद्वान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

साथी आपके बैठे हैं, मेरी बात को नकारना कि मैं यह आंकड़े गलत इकट्ठे करके ले आया हूं। वर्ष 2021-22 में 70,914 एवं 2022-23 में 1,43,929 छात्राओं को अभी तक गार्गी पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कृत नहीं किया गया है। बातें करते हो।

आप केवल तर्क के लिये तर्क करो तो आपकी इच्छा है। अभी आपने देखा होगा मेधावी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण की योजना आपने बनायी। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 और वैकल्पिक बोर्ड में 10वीं और 12वीं में 75 परसेंट से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रथम 6 हजार स्थानों पर आने वाले विद्यार्थियों को और जिले की मेरिट में आने वाले 70 प्रतिशत से अधिक वाले 100 बच्चों को, यह सब मिलाकर के 3300 बच्चे होते हैं। इन 3 हजार 300 मेधावी विद्यार्थियों को गत 3 वर्षों से लैपटॉप के स्थान पर टैबलेट दिए जाने के आदेश हुए। कुल 65 हजार 100 टैबलेट एवं वर्ष 2022-23 के 27 हजार 900 टैबलेट, कुल 93 हजार टैबलेट, अभी तक वितरित नहीं हुए हैं, अभी तक वितरित नहीं हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करिए, स्कूल खुले और बिना अध्यापक के स्कूल खुले तो उस बच्चे का भला नहीं कर रहे हो। वह बच्चा जो अंक लेकर आएगा वे उसके पीछे जिंदगी भर तक चिपके रहेंगे। उसका दर्द तो उसको ही महसूस होगा। मैं आपको तस्वीर बताता हूं। आपके माध्यमिक शिक्षा के स्वीकृत और कार्यरत पद हैं क्योंकि ज्यादा पढ़ूंगा तो समय अधिक लगेगा। आपके आचार्य का पद है, बिना आचार्य के कोई स्कूल चल नहीं सकता। बाकी स्टाफ कमजोर होगा तो चल जाएगा पर प्रिंसिपल सही हुआ तो वह बच्चों को ठीक प्रकार से एजुकेशन देगा। 16 हजार 360 पद हैं माध्यमिक स्कूलों में उनमें से 6 हजार 581 पद खाली हैं। आपके वाइस प्रिंसिपल 12 हजार 421 में से 10 हजार 201 पद खाली हैं। व्याख्याता 54 हजार 163, मंत्री महोदय, केवल और केवल जनता के पैसों से आनन्द करना ही हमारी जिन्दगी का उसूल है तो लो आनन्द। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई चिन्ता नहीं। भगवान देख रहा होगा आपको, और कोई नहीं देखेगा आपको। 54 हजार 163 में से 14 हजार 382 पद आज की तारीख में खाली हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष के 1 हजार 98 हैं जिनमें से 782 पद खाली हैं। प्रयोगशाला सहायक, केवल कुल 442 ही हैं सैकण्डरी एजुकेशन में, उनमें से 250 खाली हैं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आपके मन में इसके बारे में कुछ न कुछ विचार जरूर आना चाहिए कि जिस जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए भेजे जाते हैं। बहुत अफसोस है कि सैकण्डरी स्कूल शिक्षा में 3 लाख 36 हजार 270 कुल पद हैं, उनमें से 1 लाख 17 हजार 251, यानी 33 परसेंट पद खाली पड़े हैं। एजुकेशन क्या होती है और कैसी होगी, यह तो वह बच्चा ही बताएगा, मैं नहीं बता सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आपके प्रारम्भिक शिक्षा में 2 लाख 8 हजार 237 कुल पद हैं, उनमें से 39 हजार 300 पद आज की तारीख में खाली हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो रीट के बारे में कहते हैं, मुझे बहुत दु:ख इस बात का हुआ था कि रीट का पेपर जिस प्रकार से आउट हुआ, उस गोरखधंधे को किसी ने भी समझने का प्रयास नहीं किया। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि उन लाखों बच्चों को परीक्षा केन्द्र जाने के लिए आपने फ्री बसों की व्यवस्था की। मैं राजस्थान की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि जिसने उन बच्चों को अपना बच्चा समझकर अपने किचन से रोटी बनाकर, हर सेंटर के बाहर कोई न कोई रोटी और अपना खाना लेकर खड़ा था और उस बच्चे को दिया था। वह बच्चा लटक कर गया, ऊपर से गया, नीचे से गया, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या देखा होगा, जिस बोर्ड के अध्यक्ष, जारोली नाम के व्यक्ति हैं उनको आपने सस्पैंड किया तो उसके खिलाफ आगे कार्यवाही क्यों नहीं बढ़ाई? आपने अपने भाषण में कहा कि कोई भी अधिकारी, अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री राजस्थान ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोई भी अधिकारी या कोई मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर जारोली को क्यों इन्वॉल्व किया?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब आगे बताता हूं। यहां मुख्य सचिव महोदय भी बैठे हैं। इस रीट की परीक्षा के लिए आपके मुख्य सचिव ने 15.09 को सवेरे 11 बजे एक मीटिंग की, शाम को 5 बजे वी सी से फिर की। मीटिंग करने के बाद सारी व्यवस्था उन्होंने अपने कलेक्टर, एस पी को संभलाई थी कि आपके पास ये जो पेपर आएंगे और जो आंसर बुक आएगी, उसको किस तरह से आप ले जाओगे। मुख्य मंत्री महोदय, अफसोस तो मुझे तब यह पढ़कर हुआ कि आपके यहां 23.09 को, मुख्य मंत्रीजी, इस रीट की परीक्षा के लिए मीटिंग ली और अध्यक्षता में परीक्षा की तैयारी की समीक्षा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मीटिंग, प्रश्न पत्र और ओ एम आर शीट को कोष कार्यालय, आपकी मीटिंग का पत्र पढ़ रहा हूं, क्या हो रहा है? कोष कार्यालय, उप कोष कार्यालय, पुलिस थानों के माल खाने में रखे जाने के निर्देश हैं फिर जयपुर में उक्त निर्देशों की अवहेलना कर शिक्षा संकुल में पेपर क्यों रखे और किसने रखे? किसने रखे और क्यों रखे? आप सबसे भी मेरी कोई अदावत नहीं है, पर मेरे को उन बच्चों की चिंता जरूर है कि जिनके कारण से वो आज दिन तक लटक रहे हैं। जयपुर जिले में शिक्षा संकुल में रखे गए पेपर की सुरक्षा के लिए जिन लोगों को लगाया गया उनमें से कालेज शिक्षा से सेवानिवृत्त व्यक्ति श्री प्रदीप पाराशर को को-आर्डिनेटर और उनके साथ को-आर्डिनेटर चार व्यक्ति श्री सुभाष यादव, बी एस बैरवा, सहायक निदेशक, कालेज शिक्षा एवं ध्यान सिंह गोठवाल, निजी स्कूल स्टाफ एवं श्री रामकृपाल मीणा, निजी स्कूल संचालक को लगाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रीट पेपर लीक होने के बाद जब चौतरफा दबाव बढ़ा तो आपने इनके खिलाफ कार्यवाही की। उसके थोड़े दिन बाद उनको बहाल करके वापस उसी जगह लगा दिया। उक्त व्यक्तियों को लगाने के आदेश किस अधिकारी ने दिए? इन लोगों को, प्राइवेट लोगों को जब आपने जिम्मेदारी अपनी मीटिंग में एस पी और कलेक्टर को दी थी तो फिर इन प्राइवेट लोगों को किसने लगा दिया? इस बारे में मैंने पिछली बार भी आपके सामने निवेदन किया, लेकिन आपने मेरे उस पर ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करो और अगर कलेक्टर दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? उसमें भी मुझे बहुत अफसोस है कि क्या कहें। मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि वहां पर डबल लॉक की चाबी जिस आदमी के पास है, वहां से अगर पेपर निकल जाए तो राजस्थान का बच्चा किसको दोष देगा? किसको दोष दें? आप उस सीमा तक नहीं पहुंचे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जब वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा पेपर लीक हुआ, आप सब लोगों को दु:ख होगा, यह पेपर लीक नहीं हुआ, एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। इस तरह का पहली बार हुआ। यह तो ठीक है कि उदयपुर एस पी को सूचना मिल गई बच्चे के द्वारा ही। अगर यह बच्चे के द्वारा सूचना नहीं मिलती तो कितनी गाड़ियों में कितने बच्चे बैठकर घूमते रहे, रात को आठ बजे उनको गाड़ी में बैठाया और रात को दो बजे उनको पेपर दिया। उस पेपर में उनको आंसर कौनसे हैं, उस पर टिक किया हुआ था। यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो एस पी ने पीछा करके सवेरे सवा चार बजे इन लोगों को सभी साधनों सहित रेड हैंडेड पकड़ लिया। अब आपने इसको सस्पैंड कर दिया, उसको सस्पैंड कर दिया, क्या निकलेगा इससे? आखिर यह पेपर निकला होगा तो कहीं एक जगह से निकला होगा, जिसके पास पेपर पहुंचा होगा वो आसमान से उड़कर थोड़े आया होगा? पेपर पहुंचाने वाला कोई होगा। इसलिए मैं बारम्बार कह रहा हूं कि जब तक आप चोर की मां को नहीं मारोगे, इन बच्चों के भविष्य को आप सुधार नहीं सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपको उच्च शिक्षा का ढांचा बताता हूं। उच्च शिक्षा के प्रति आप पता नहीं इतने क्या कर रहे हो, यह फोकट, वो फोकट, वो फोकट, वो नहीं मिलेगा तो भी वो बच्चा पढ़कर खड़ा हो जाएगा, आप कर क्या रहे हो उलटा? केवल खुश करने के लिए?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर प्रदेश में 490 राजकीय कालेज हैं, इनमें 9 हजार 60 पद आज की तारीख में खाली हैं और ये पद 2017 से रिक्त चल रहे हैं। सहायक आचार्य के कुल 4 हजार 617 पद खाली हैं। ये सब मिलाकर 50 परसेंट हो जाता है। महाविद्यालयों में 27 में केवल पुस्तकालयाध्यक्ष हैं, 28 में शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं। 90 प्रतिशत महाविद्यालयों में लेखाकार कार्यरत नहीं है। महाविद्यालयों में 70 प्रतिशत से अधिक प्रयोगशाला सहायक के पद रिक्त हैं, लेकिन विद्यार्थियों के हित में, बेरोजगारों के हित में पदों पर नियुक्ति करने के बजाय आपने उन लोगों को झुनझुना पकड़ा रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको और बताता हूं कि आपने क्या कमाल कर रखा है। राज्य भर में अधिकतर महाविद्यालय प्राचार्य से विहीन हैं। अब आप इसमें देखिए, जितने भी कालेज हैं उनमें 'नैक' आवश्यक होता है। इस 'नैक' के तहत 490 में से समझो, सुनो, 490 महाविद्यालयों में से 69, केवल 69 महाविद्यालयों में 'नैक' प्राप्त किया हुआ है, बाकी किसी में नहीं है। इनमें भी केवल 4 कालेज हैं जिनको 'ए' ग्रेड मिली है। यही नहीं, केवल 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको 'ए' ग्रेड मिली हुई है, एक राजस्थान विश्वविद्यालय और एक सुखाड़िया विश्वविद्यालय। बाकी जितने विश्वविद्यालय हैं वे सारे के सारे इस आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं करते हैं। अब मैं आपको विश्वविद्यालय की दशा बताता हूं। चाहे गलती मेरी रही हो या मेरी सरकार की रही हो पर हम उस बच्चे के प्रति अन्याय नहीं कर सकते। हमने की तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमको भी सज़ा मिली थी, लेकिन ये विश्वविद्यालय चल रहे हैं? मजाक हो रही है? क्या कर रखा है? पैसे बचाने का धन्धा कर रहे हो और फिर लोगों को फोकट में बांटकर ठगी का धन्धा करना चाहते हो।

मैं बताता हूं आपको। दुर्भाग्य है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1,016 शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं उनमें से 525 पद खाली हैं, 51 परसेंट। इसी तरह से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 656 पद हैं, जिनमें से 375 पद, 57 परसेंट खाली हैं। उदयपुर विश्वविद्यालय में 218 हैं, इसमें 27 परसेंट। यह जो आपका अजमेर का विश्वविद्यालय है, इसमें 66 परसेंट पद खाली हैं। कोटा विश्वविद्यालय में 45 परसेंट पद खाली हैं। महाराजा गंगासिंह विधि विश्वविद्यालय, बीकानेर में 71 परसेंट खाली हैं। कितने? कुल पद कितने हैं गंगासिंह में? 59 और उनमें से 42 पद आज की तारीख में खाली हैं। यह जो महावीर विश्वविद्यालय खुला है इसमें 27 में से 16 पद खाली हैं। इससे भी आगे सीमा लांघ गई है और ये जो आपने चार विश्वविद्यालय अलवर, भरतपुर, सीकर और बांसवाड़ा में खोले हैं यहां एक भी अध्यापक सलेक्ट हुआ ही नहीं है और 30 में से 30 पद खाली हैं। क्या विश्वविद्यालय चला रहे हो और क्या करना चाहते हो, इसका पता ही नहीं है। दुर्भाग्य तो उस दिन आया जिस दिन कुलपति अपनी डिग्री पूरी नहीं करता है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सुखाड़िया विश्वविद्यालय का कि उनके पास डिग्री है या नहीं है। उनकी जांच हुई और जांच होकर संभागीय आयुक्त ने रिपोर्ट दे दी है, जिसमें उसके पास दस साल प्रोफेसर का एक्सपीरियंस नहीं है, वह प्रूव हो गया, लेकिन फाइल दबाकर बैठे हैं और कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय, इसकी भी दस साल की पूर्ति नहीं हो रही है।

इसी तरह से आपने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी जी को एक नहीं, तीन-तीन विश्वविद्यालय का चार्ज दिया और अब उनको घर जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यू जी सी की मान्यता की पूर्ति नहीं है।

यह जो आपकी नि:शुल्क जांच योजना है जिसके लिए दे ताली, दे ताली करते हो, उसके मैं आपको फिगर देता हूं कि दे ताली कितनी सही है और कितनी गलत है। मैं आपको बताता हूं कि यह योजना जो आपने शुरू की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसका मैंने आपको सदन में धन्यवाद दिया था। आप सदन का मेरा रिकार्ड उठाकर देखना, मैंने कहा था कि आपने बहुत अच्छी लागू की है जिससे गरीब को मदद मिलेगी, लेकिन इसकी जब दशा देखता हूं तो बहुत दुख होता है। 2015-16 में कुल लाभार्थी थे 2 लाख 29 हजार और 134 करोड़ रुपया इसमें मिला था। उसके बाद 2016-17 में हो गया 2.39, फिर 2017-18 में हो गया 2 करोड़ 2 लाख, घटा। फिर 2018-19 में 2.14, जितना हमने पहले 2 लाख 39 हजार कवर कर लिया था, वह भी आपकी जांच में लाभार्थी कवर नहीं हो रहे हैं। फिर 2019-20 में और घटकर 2.28 और 2020-21 में कोरोना के कारण से 1.34 तथा उसके बाद 2021-22 में एक करोड़ 92 लाख 42 हजार 214 लोगों ने लाभ लिया। पैसा भी आप देखो तो 2018-19 में 167 करोड़, फिर उसके बाद 2019-20 में 253, फिर उसके बाद 260 करोड़ और अभी यह जो 2022-23 है, जिसके बारे में दे ताली, दे ताली, उसमें आपने कुछ जांचें हैं, वे जांचें भी कम की हैं और इसके फिगर देखेंगे तो बड़े आश्चर्यजनक लगते हैं कि केवल 233 करोड़ रुपये आप खर्च कर पाये हो। आपके फिगर तो यह नहीं बता रहे हैं पर केवल और केवल ताली पीटने के अलावा आपने कुछ नहीं किया है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में 2020-21 में राज्य सरकार का पैसा 462 करोड़ है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त हुआ 527 करोड़, अन्य से प्राप्त हुआ 1 करोड़ 54 लाख, कोविड फण्ड आपदा से आपको मिले हैं 139 करोड़ और सब मिलाकर 1,130 करोड़ रुपया आपके पास नि:शुल्क दवा का हो गया और आपने वितरण कितना किया? 655 करोड़, 58 परसेंट। उसके बाद 2021-22 में इसी तरह से आपका है 536, केन्द्र का है 511 और कोविड का है 324, सब मिलाकर 1,400 करोड़ रुपया आपको मिला है और 1,200 करोड़ रुपया। अबकी बार आप कहां हो? इसमें या तो मेरे आंकड़े गलत हैं या आपके अधिकारी ने जो रिकार्ड मुझे दिया वह गलत है, दोनों में से कोई गलत होना चाहिए। 2022-23 के दिसम्बर तक जो आप बता रहे हो उसमें आपको 910 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है लेकिन यह ज्यादा प्राप्त हुआ है और इस ज्यादा को कहां किया है आपने? आपने बड़ा कमाल का काम किया है। आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधानों के विरुद्ध औषधि, सर्जिकल सूशर्स, सेनेटरी नैपकिन हेतु दिनांक 31.12.2022 तक राशि 1,357 करोड़ रुपया इसमें से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उठाया है। 1,357 करोड़ रुपया नैपकिन के लिए आपने उठाया है, तो आप कर क्या रहे हो राजस्थान का? कहां ले जाना चाहते हो? यह देखो आप।

अब आप इसमें देखिये। आप बार-बार दे ताली-दे ताली, दस लाख-दस लाख तो पहले वाले ने कुछ नहीं किया न? यह भामाशाह योजना कब शुरू हुई थी? उसके लिए कम से कम एक शब्द तो बोल दो। हिन्दुस्तान में पहली बार अगर किसी ने गरीब के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है तो उसका नाम है वसुन्धरा राजे सिंधिया। हिन्दुस्तान में कहीं भी शुरू नहीं हुई थी। उन्होंने शुरू कब की थी, यह आपने देखा होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राजेन्द्र जी नहीं बजा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बजा रहा हूं मैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं भी बजा रहा हूं, दिक्कत क्या है? अच्छा काम करें तो नहीं बजाना है क्या? सौगन्ध खा ली है तो खा लो। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, यह प्रथम में 13.12.2015 से शुरू हुई और यह 2019 दिसम्बर तक। उसके बाद आपके पास आ गई आयुष्मान, पैसा था तभी तो देते थे, बाकी कहां से लाते थे? बजट में कोई प्रावधान कर रखा होगा उसी में से दिया होगा? न तो उन्होंने अपने घर से दिया, न आप अपने घर से दोगे। फिर उसके बाद में केन्द्र की आयुष्मान योजना आ गई जो 01.09.2019 को आ गई थी। उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण किया। आपने प्रथम चरण जिसका नाम बदला, क्योंकि आपको नाम से एलर्जी है, तो नाम से एलर्जी तो आपको जनता बतायेगी कि नाम से एलर्जी का अर्थ क्या होता है। भामाशाह खराब शब्द था? आपने देखा होगा कि प्रथम चरण में और अभी आप जो दस लाख के लिए दे ताली-दे ताली, यह कब से शुरू हुई है? यह अप्रैल से है और कुछ दिया है या नहीं दिया और दिया है तो इसकी संख्या बता देना कि कितना पैसा दिया है। यह सारा पैसा केन्द्र का आया है, आपने नहीं उठाया। आप यह जवाब में दे देना कि आयुष्मान का जो पांच लाख रुपया उन्होंने किया वह आपने उठाया या नहीं उठाया या आपने अपनी जेब से दिया है।

इसी तरह से आपने जनता क्लिनिक, जनता क्लिनिक, क्यों धोखा देते हो जनता को? कमाल करते हो। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो, अध्यक्ष महोदय, मैं चकित रह गया, मेरी भी नॉलेज नहीं थी, यह ईमानदारी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से कह रहा हूं। यह जो जनता क्लिनिक है इसमें केन्द्र की शहरी हेल्थ वैलनैस सेंटर योजना के तहत आपको पैसा आया, 15वें वित्त आयोग से आया, आपको 106 करोड़ रुपया मिला और आपको यह कहा था कि 142 सेंटर आपको बनाने हैं। आपने अभी तक क्या किया है? 38 बनाये हैं। पैसा है आपके पास और पैसा होते हुए भी आप 38 जनता क्लिनिक अभी तक प्रारम्भ कर पाये हैं और बाकी आपके अभी पाइप लाइन में हैं।

अब यह जल जीवन मिशन, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छा राज्यपाल महोदय से कहलवाया है। उनको तो पढ़ना पड़ता है जो हम और आप लिखकर देते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिन्दु संख्या 164 - 'जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 39 हजार 521 गांवों में 10 हजार 655 सिंगल और मल्टी विलेज योजनाओं तथा 133 वृहद् परियोजनाओं सहित 69 हजार 940 करोड़ रुपये' की आपने यह सारी योजना रखी है और आपने सच को तो स्वीकार कर ही लिया। अब तक आपने जो इतने सालों तक राज किया, हमने भी 70 साल में किया। इस योजना के आने से पहले आपके यहां केवल और केवल 11 हजार घरों में कनेक्शन थे। इस योजना के आने के बाद अब हम 31 लाख 26 हजार से अधिक परिवारों को कनेक्शन पहुंचा रहे हैं।

अब मैं आपको जल जीवन मिशन की तस्वीर बताता हूं। यह 15 अगस्त, 2019 से शुरू हो गया था और इसके तहत आपको 2024 तक 50 लीटर प्रति परिवार को देना था। राजस्थान में 2024 तक 1 करोड़ 5 लाख 30 हजार 58 परिवारों को नल कनेक्शन द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य था। इसके विरुद्ध 11 लाख 74 हजार 131 घरों में नल कनेक्शन इस योजना के चालू होने से पहले राजस्थान में थे। 25.01.2023 तक 21 लाख 28 हजार 946 कनेक्शन हुए हैं। वह भी तब जैसे अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि केवल टोंटी खड़ी कर दी, पानी आया ही नहीं, वह तो अलग है। यह सारा मिलाकर हमने 31 परसेंट कवर किया है। प्रदेश में कुल 43 हजार 207 गांवों में शत-प्रतिशत जल देना है। कितना? शत प्रतिशत देना है। आपके ये विद्वान साथी बैठे हैं, ये रोजाना आ जायें तो इनका थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। सदस्य बोलता है न, वह फालतू बातें नहीं बोलता है। इनको कुछ सीखने के लिए मिलता है, पर इन सबको फुर्सत नहीं है। यह दुर्भाग्य है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं जितना लेटेस्ट इकट्ठा कर पाया, वह मैंने करने का प्रयास किया है। राजस्थान में 43 हजार गांवों में से 1 हजार 572 गांवों को हंड्रेड परसेंट नल की टोंटी पहुंची है और 22 हजार 118 गांवों में कार्य प्रगति पर है, लेकिन 19 हजार 517 गांवों में काम चालू ही नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि केन्द्र ने आपको, इस बारे में नकार देना कि केन्द्र ने इस योजना के तहत आपको 27 हजार करोड़ रुपया दिया या नहीं दिया और आपने खर्च कितना किया है। 25.01.2023 तक का आंकड़ा बता रहा हूं, 2 हजार 749 करोड़ रुपया कुल खर्च किया है। 27 हजार करोड़ में से 2 हजार 749 करोड़ रुपया। आप इस योजना की दशा देखो। मतलब, कोई पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता है। मेरी भी गलती रही, मुझे इन सब रिकार्ड को देखने से समझ में आया कि यह तो हराबोर हो रहा है और दे ताली, दे ताली, हाथ घिस गये होंगे तालियां देते-देते।

आपको इस योजना की क्रियान्विति का असंतुलन बताता हूं। अभी तक जैसलमेर में केवल 7.44 प्रतिशत पूर्ति हुई है, बाड़मेर में 15.97 प्रतिशत पूर्ति हुई है, डूंगरपुर में 13.03 प्रतिशत पूर्ति हुई है, बांसवाड़ा में 13.45 प्रतिशत, प्रतापगढ़ में 13.75 प्रतिशत, उदयपुर में 18.61 प्रतिशत और धौलपुर में 12.95 प्रतिशत गांवों में आपने नल से पानी पहुंचाया है। यह आपकी योजना की दशा है।

अब आप नाराज होंगे कि हमने फ्री रजिस्ट्रेशन कर दिया। ये होम डिपार्टमेंट के सब विद्वान जो यहां विराजे हुए हैं मैं भी उस डिपार्टमेंट में रहा हूं। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी चला जाए, इन कुछ मुकदमों के बारे में अगर कोई कम्प्लेंट करता है तो उसको एफ आइ आर दर्ज नहीं करें, ऐसा बहादुर बहुत कम दिखाई देता है, कभी नहीं होता है। आपने देखा कि लूट, अपहरण, बलात्कार, नकबजनी और चोरी, ये पांच हैड ऐसे हैं, जिनमें कोई न नहीं कर सकता। हां, किसी के थप्पड़, घूंसा लग गया होगा, किसी ने किसी के खिलाफ कर दिया होगा, हो सकता है उसमें करें या न करें, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूं, 2018 में लूट के मुकदमे 1,022 हैं और आज की तारीख में 2022 में 1,622 हैं। इसका मतलब 36 परसेंट लूट के प्रकरण 2018 से 2022 तक बढ़े हैं। अपहरण के 34 प्रतिशत बढ़े हैं, बलात्कार के 38 परसेंट बढ़े हैं, नकबजनी के 32 परसेंट बढ़े हैं और चोरी के 28 परसेंट बढ़े हैं। अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? आप कहते हो, एफ आई आर करने के कारण, आपको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वह नमूना भी बताऊंगा कि एफ आइ आर की क्या स्थिति होती है। मेरे सब अधिकारी यहां बैठे हैं। बलात्कार के मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। यह कहां से आया है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट से। जहां देश में 2021 में बलात्कार के 30 हजार 16 मामले दर्ज हुए, वहीं अकेले राजस्थान में 30 हजार में से 6 हजार 337 प्रकरण दर्ज हुए हैं और दिसम्बर, 2022 तक यह संख्या बढ़कर 7 हजार 93 हो गई है।

इसी तरह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। 7 हजार 945 मामले दर्ज हुए हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। महिलाओं के अपहरण के मामले में भी राष्ट्रीय स्तर पर कुल 70 हजार मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें से आपके यहां 5 हजार 964 मुकदम दर्ज हुए हैं जिसके बारे में आपको और मुझे चिन्ता करनी चाहिए थी। अनुसूचित जाति अत्याचार, इसमें भी मैंने वे ही तीन हैड ले लिये हैं, हत्या, बलात्कार। अनुसूचित जाति अत्याचार में 2018 की तुलना में 2022 में 47 परसेंट अपराध बढ़े हैं। मैंने 2018 से 2022 की तुलना की है, अनुसूचित जनजाति के 56 परसेंट अपराध बढ़े हैं।

एक बात आप बार-बार कहते हैं न, आपको और मुझे अख़बार के माध्यम से आंख खोलनी चाहिए। हमारे यहां 1 जनवरी, 2019 से पॉक्सो एक्ट है। जो छोटी बच्चियों के साथ घटना, दुर्घटना हुई, उसको पॉक्सो एक्ट के तहत तैयार करके मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमे कितने दर्ज हुए हैं? 6 हजार 467, उसमें से आपने एफ आर कितनी लगाई है? 1350, 20 परसेंट। अगर उसने किसी पर इतने भयंकर अपराध का दोष लगाया है तो मुकदमा दर्ज करवायें, उसे जेल भेजो। जिसने गलत रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसको जेल भेजो, लेकिन ऐसे काम को छोड़ देना, इसका मतलब हम अपराध रोकना नहीं चाह रहे हैं। अगर उसने गलती की है तो दण्ड दें, लेकिन मुझे दु:ख है, जो 20 परसेंट राजस्थान का एफ आर है, उसमें 42 परसेंट एफ आर अकेले भरतपुर जिले का है। यह क्या हो रहा है? 38 परसेंट एफ आर अलवर जिले की है।

माननीय सभी सदस्यों, इस बारे में गहराई से विचार करें! आखिर यह हो क्या रहा है। साम्प्रदायिक हिंसा के बारे में तो सब रिकार्ड टूट गये हैं। करौली का दंगा तो सब लोगों ने देखा है। आपके ये अधिकारी भी जानते होंगे, आपसे स्वीकृति लेकर धार्मिक जुलूस निकाला था और एक मोहल्ले विशेष में जाकर ऊपर पत्थर ही पत्थर, दे पत्थर, आपकी पुलिस भाग गई और दो घन्टे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तक बाजार जलता रहा। करौली छोटा-सा शहर, आपका एस पी सो रहा था क्या? पांच मिनट में फोर्स लेकर पहुंचकर जलती हुई दुकानों को नहीं बचा सकता था क्या? दो घन्टे तक दुकानें जला दीं। जिस प्रकार से छीपाबड़ौद की घटना हुई, आपने देखी होगी, वह आपके ध्यान में है। आपके जोधपुर में हुई वह भी आपको ध्यान में होगी। एक के बाद एक, चित्तौड़गढ़ में हुई, बड़ी सादड़ी में हुई, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई। पुलिस को सूचना देने के बाद, उस आदमी ने चार दिन तक दुकान बन्द रखी, एस पी के पास रोया कि मेरे पास रोज फोन आता है। वह आदमी आइडेंटिफाई हो गया, उसको थाने में बुलाया और बुलाकर के समझौता कराया और उसको छोड़ दिया। उसके ठीक एक घन्टे बाद उसको वापस फोन आया कि नहीं, तेरा सर कलम करूंगा और सर कलम हो गया। क्या कमाल है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मारने वाला कौन था?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आदमी था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : बी जे पी का था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, बी जे पी का था। मुझे लगा दो फांसी, मैं खड़ा हूं न। बी जे पी हो तो कोई चिन्ता नहीं है, बी जे पी का है तो उसको भी फांसी लगाओ। मैं बीच में आ जाऊं, तब बोल देना, कैसी बात करते हो? पीपाड़ शहर में जुलूस निकला, उसमें सर कलम के नारे लगे या नहीं लगे? ये बताना। आप कोटा में पी एफ आई को तो जुलूस निकालने के लिए स्वीकृति देते हो। हम हमारी रामनवमी का जुलूस निकालते हैं तो धारा 144 लगाते हो। रोजे के समय तो बिजली मिलेगी, रोजे के दिन तो बिजली नहीं कटेगी और हमारे त्यौहार में बिजली कटेगी। इसकी आपको कोई चिन्ता नहीं है तो मनों में वैमनस्य पैदा होगा या नहीं होगा? आप जान-बूझकर वैमनस्य ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार के नमूने आपके सामने रख रहा हूं। मुझे इस बात का बहुत दुख है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it, मैं फिर कह रहा हूं। माननीय सदस्य, यह बताना गलत है। माननीय सदस्य, I will name you. ये बन्द कीजिए, इसको नीचे रखिये। माननीय कटारिया जी, आप वाइंड करें।

सदन कूप में

(माननीय सदस्य श्री बलवान पूनियां एवं श्री गिरधारीलाल द्वारा सदन कूप में पोस्टर प्रदर्शन एवं धरना)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान की ए सी बी को इस सदन में धन्यवाद दिया, आज भी देता हूं। उन्होंने जिस प्रकार के सोलिड केस बनाये हैं उसके कारण से राजस्थान की पुलिस का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, लेकिन हमने उसको गर्त में कर दिया। हम उसकी परमिशन ही नहीं देते हैं, 4-4, 5-5 साल तक यदि आप अभियोग की स्वीकृति नहीं देंगे तो कैसे कंट्रोल होगा? मैं नाम बताता हूं आपको। यह उच्च न्यायालय ने आपको कहा कि तीन महीने में इस प्रकार के प्रकरण होते हैं उनको आप स्वीकृति दो। नीरज के. पवन, आई ए एस आफिसर है, 2017 से पेंडिंग पड़ा है। निर्मला मीणा, आई ए एस है, 2018 से प्रकरण अभी तक स्वीकृति में पड़ा है। निशु कुमार अग्निहोत्री, आर ए एस है 2018 से पड़ा हुआ है। नरेन्द्र कुमार थोरी, 2018 से पेंडिंग पड़ा है, अरुण प्रकाश शर्मा, 2018 से पेंडिंग पड़ा है, विजय सिंह नाहटा, 2019 से पेंडिंग पड़ा है, ओम प्रकाश चन्देरिया, 2019 से है, आस मोहम्मद, 2019 से है। मतलब इससे भी हद हो गई, मैं क्या बताऊं अब आपको, सवाई माधोपुर का चेयरमैन ट्रेप में तीस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। दो महीने तक जेल काट करके आया और इन्होंने वापस उसको ड्यूटी पर लगा दिया। क्या है यह? यह किस सीमा तक जा रहे हो? यह वोटों की खेती न आपके काम आयेगी न मेरे काम आयेगी, यह देश ही काम आने वाला है। यह वोटों की खेती के पीछे पागल मत होवो।

इस तरह से सारे कुएं में भांग पड़ी हुई है मैं कहां जाऊं? मुझे बहुत दु:ख है। लक्ष्मण गौड़ जैसा आई जी पकड़ा जाता है। धन्यवाद देता हूं ए सी बी को कि उन्होंने कम से कम हाथ डाला, उसका कुछ नहीं हुआ। सत्यवीर सिंह को पकड़ा, उसका नहीं हुआ। इन्दर सिंह राव, कलेक्टर, बारां पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। मनीष अग्रवाल, एस पी पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। दिव्या मित्तल अभी-अभी पकड़ी गयी है, उसकी आप कार्यवाही कर रहे हो और यह जो मनीष बेनीवाल है, यह मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह जोधाराम इंस्पेक्टर घूसखोरी में गोवा में पार्टी करते हुए पकड़ा गया। वह फिर से नौकरी पर लग गया। बी डी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कुमावत, आर ए एस जो चार लाख की रिश्वत लेते हुए 2019 में पकड़ा गया था। ऐसे पांच अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति से राज्य सरकार ने इन्कार कर दिया। अभियोजन स्वीकृति से इन्कार कर दिया। यह हिम्मत, अभिलाष टांक, क्या-क्या नमूने हैं राजस्थान के, ये एस पी साहब हैं, शराब तस्करी में पकड़े गये, इनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। बहुत अजीब है।

आपने कहा था न कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ायेंगे। अब आप देखो, वर्ष 2019-20 के बजट में आपने कहा था पैरा-41 में- '31,770 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है, जिससे राज्य विद्युत उत्पादन में सरप्लस हो गया है।' सरप्लस हो गया है तो फिर रात को बिजली क्यों दे रहे हो? फिर क्या कारण है? उस किसान के मन को क्या पीड़ा है और आपको अफसोस होगा कि 1500 से लेकर 2000 किलो मेगावाट बिजली आप 12 रुपये से लेकर 20 रुपये में खरीद करके कंज्यूमर को दे रहे हो। यही नहीं आपने तो और इससे भी...

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, प्लीज वाइंड अप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं टाइम पर खतम करने का प्रयास करूंगा। मैं आपके टाइम को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जहां रुक जाऊंगा वहां रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है।

आपने देखा होगा यह अपनी यूनिट है जिसमें 3,890 बनती, उन सबको आपने बन्द कर रखी है और केवल और केवल अडाणी से हम केस हार गये, उसके कारण से अडाणी को पहले 2022 तक 4.20 रुपये प्रति यूनिट इतने सालों में अब तक एक्स्ट्रा देना पड़ता है। हर कंज्यूमर को, वह आपने उसमें दिया है और यही नहीं, अभी आपने देखा होगा कि अभी इस अक्टूबर महीने में उसके साथ आपने फिर एक किया है। उसमें आपने कहा है कि 2022 से लेकर 2027 तक प्रति बिल में 7 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ करके आप उसे और पेमेंट करोगे। राजस्थान की जनता पर सरचार्ज के नाम से 9,100 करोड़ रुपये से अधिक आपने ले लिया। फ्यूल चार्ज के नाम से जो आपने पैसे बढ़ाये हैं न, वह सभी सीमाओं को लांघ गया है।

बिजली कंपनियों का घाटा, जब हम आये थे उस समय 83 हजार करोड़ का घाटा हो गया। हमने उदय योजना में 62 हजार करोड़ लेकर के वापस इन बिजली कंपनियों को स्टैंड किया था और आज की तारीख में,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अध्यक्ष जी, मेरा कैलकुलेशन है, 90 हजार करोड़ से अधिक वापस बिजली कंपनियां घाटे में चली गई हैं। ये किसी भी दिन बन्द हो जायेंगी।

यह जो आप कहते हो न कि राष्ट्रीय रोजगार योजना शहर में चालू कर दी, आपके इतने फोटो लगे हैं कि पचास फीट में पांच बड़े-बड़े पोस्टर लगे होंगे। राजस्थान के केवल और केवल शहरी सौ दिन का आपने जो रोजगार दिया है उसके पोस्टर का जो खर्चा हुआ है वह राजस्थान की जनता के सामने एक बार रख दो और वास्तव में लगे कितने लोग हैं? आपने समय की सीमा बांध दी है, मतलब सभी में कमियां आ रही हैं। मेरे पास यह 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के सारे आंकड़े हैं। यह सौ दिवस का आपने जो रोजगार इस बार दिया है वह है 1 लाख 42 हजार, जबकि आपका 12 लाख तक का पहुंचा हुआ है 2020-21 में। 2019-20 में 8 लाख पहुंचा है। 2021-22 में 9 लाख और इस बार केवल 1 लाख 42 हजार। यह जो आप कार्यदिवस-कार्यदिवस कहते हो न, शहर में कौन करेगा सवा सौ रुपये में नौकरी? इंटरव्यू लेता है, आपका और मेरा। घर बनाने के लिए जब जाते हैं न उस मजदूर के पास जहां वह खड़ा है तो वह इंटरव्यू लेता है उसके बाद आता है। कौन आयेगा इस पैसे में? केवल खानापूर्ति करने के लिए आपने बार-बार इतने होर्डिंग्स और पोस्टर लगाये हैं।

इसी तरह से नन्दीशाला, दे ताली, दे ताली। हाथ थक गये। आपने घोषणा की थी 2019-20 के बजट में। आपने पैरा संख्या 11 में कहा था 'प्रत्येक पंचायत समिति में नन्दीशाला स्थापित की जायेगी' अब बता देना कितनी पंचायत समितियों में नन्दीशाला हैं? 16 जिलों में है केवल और आपने फिर बार-बार कह करके कि हम हर पंचायत लेवल पर नन्दीशाला स्थापित करेंगे। बजाओ ताली, स्थापित कहां हैं? है तो बताओ, कम से कम कि इस जगह स्थापित हो गयी।

मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, मैं तारीफ करने के लिए खड़ा नहीं हूं लेकिन केन्द्र ने जिस योजना को बनाया, हण्ड्रेड परसेंट लोगों को जाति, धर्म सबसे ऊपर उठ करके हण्ड्रेड परसेंट लोगों को लाभ देने का प्रयास किया है। हण्ड्रेड परसेंट, हम जो भी योजना बनाते हैं न वह झुनझुना देकर के अपने हाथ में रखते हैं, कोई आपका स्वागत करे, साफा पहनाये तो देना है बाकी नहीं देना।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

27 लाख करोड़ रुपये का इस कोरोना काल में पैकेज दिया जो जी डी पी का 13 परसेंट है। प्रधानमंत्री अन्न योजना में जो अस्सी करोड़ लोगों को तो मिल ही रहा है, अभी कल के बजट में और घोषणा की कि बारह महीने और पांच किलो राशन और एक किलो दाल मिलेगी। एक देश एक राशन, कौन बी जे पी है, कांग्रेस है, यह नहीं देखा। आप थर्मामीटर लगाकर देखते हो बी जे पी-कांग्रेस। हम लोग मनुष्य का ध्यान रखकर काम करने वाले लोग हैं, हम इन्सान को इन्सान समझते हैं। उसका धर्म, जाति कुछ भी हो सकती है, कोई चिन्ता नहीं है। आपने देखा होगा, प्रधान मंत्री के द्वारा जो आवास योजना है उस आवास योजना में अभी जो आपको केन्द्र ने दिया है, कल के बजट में ही 79 हजार...

सदन कूप में

(भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। एक मिनट कटारिया जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: सदन का समय बढ़ाया जाता है। कटारिया जी, प्लीज।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कोशिश कर रहा हूं। कल के बजट में ही प्रधानमंत्री आवास में, आप इन्दिरा आवास देते थे न जो थोड़े दिन बाद उनकी खिड़कियां और दरवाजे तक खोल ले जाते थे। इस आदमी ने कम से कम जाति, धर्म नहीं, जो उनकी सूची में आ गया, तीन

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करोड़ लोगों को आवास बना करके दिये और अभी के बजट में 79 हजार करोड़ रुपये और रख करके 66 परसेंट और बढ़ाया है।

स्वच्छ भारत में 11 करोड़ से अधिक लोगों को दिया है। पी एम किसान निधि में किसी जाति, धर्म को नहीं देखा। जिसके खाते में जमीन है न उन सब 11 करोड़ 30 लाख किसानों को 1 लाख 82 हजार करोड़ रुपया उनके खाते में डाला। बटन दबाते ही 17 हजार करोड़ होता है। जिन्दगी में कभी बटन दबाकर पैसे ट्रांसफर किये हैं क्या? केवल और केवल बांटने जाते थे, आधा थैला भर कर ले आते थे और कहते थे मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। ऐसे मजे आते हैं?

यह जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना 9 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति, जो आप बहुत तारीफ करते हो न, यह पहला प्रधान मंत्री है जिसने योजनाबद्ध कहा कि हर बस्ती को लाइट का पोल पहुंचाऊंगा और पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? 19 हजार गांव बाकी थे। यह जो जन-धन योजना का खाता खुला है न, इसने रोका है भ्रष्टाचार। बाकी तो बांटने वाला जो भी आपका भाई या मेरा लड़का जाता था न शाम को थैले में कुछ बचाकर लाता था। 45 करोड़ लोगों का बैंकिंग खाता खुला है। यही नहीं इससे जो डाइरेक्ट ट्रांसफर हुआ है वह 22 लाख करोड़ रुपये सीधे के सीधे ट्रांसफर हुए हैं।

(भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उसके कारण से 2.22 करोड़ रुपये का आयुष्मान भारत केवल राजस्थान के लिए नहीं, यह पहला प्रधान मंत्री है जिसने हिन्दुस्तान के पचास करोड़ लोगों को इस आयुष्मान के अन्दर चूज किया है पर वह भी आपको नहीं दिखता है। एक बार नाम ले लेते तो कोई तकलीफ हो जाती क्या? आपने कहा कि हमने इतने मेडिकल कालेज खोले, 70 साल राज कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? उस समय क्या हो गया था? उस समय आपको ध्यान नहीं आया कि मेडिकल कालेज की जरूरत है? अब क्योंकि देश के प्रधान मंत्री ने हर जिले में मेडिकल कालेज खोला, इस कारण से आपने भी खोला तो दे ताली, दे ताली।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(समय: 17.00 बजे)

मैं भी 40 साल से राजनीति में हूं। यह पहला प्रधान मंत्री है जिसने हिन्दुस्तान की दो वैक्सीन निकालकर, हिन्दुस्तान का पहला वैक्सीन बनाने का अगर श्रेय किसी ने प्राप्त किया है तो उसका नाम नरेन्द्र मोदी है। 220 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिलाने का अगर किसी ने रिकार्ड बनाया है, जिसकी वजह से आप और हम यहां सुरक्षित बैठे हैं, यह उसकी बदौलत बैठे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में बोलना नहीं है। सवेरे उठते ही एक पत्थर फेंकने का काम करते हैं, इसके कारण से यह राजनीति गन्दी हो गई है। राजनीति पत्थर फेंकने वालों की हो गई।

मेरी प्रार्थना है कि मेरी इन बातों को इन अधिकारियों से पूछकर, अगर मैंने कोई आकड़ा गलत इकट्ठा किया तो आप उसको डिनाई कर देना और अगर नहीं है तो राजस्थान की इस दुर्दशा पर आप और मैं बैठकर दो आंसू बहायें, जिससे उस सात करोड़ जनता के मन को संतोष हो। इन नकलचियों से बचाओ, इनसे रोको मेरे बच्चों के भविष्य को। इतना ही निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आई विल नेम यू, माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, चुपचाप सुनें या फिर बाहर निकल जाएं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं अपील करूंगा कि आपका प्रोटेस्ट हो गया, कृपा करके आप स्थान पर बैठ जाएं। आपकी भावना का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है।

धरना समाप्त

(श्री बलवान पूनियां एवं श्री गिरधारीलाल, माननीय सदस्यों द्वारा धरना समाप्त)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सदन के पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किये। उस दिन मैं देख रहा था कि राज्यपाल महोदय को अनावश्यक रूप से अभिभाषण पढ़ने नहीं दिया गया जबकि कोई मुद्दा नहीं था। मैंने देखा उस दिन एक मात्र माननीय सदस्य कैलाश मेघवाल और एक इनके अध्यक्ष पूनियां जी, वे अकेले खड़े रहे और हमारे नेता, प्रतिपक्ष सबको गुमराह

(श्री अशोक गहलोत)

करके यहां वैल में लाये और उनके अभिभाषण को बोलने नहीं दिया गया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसका कारण भी है, हमारी चार साल की उपलब्धियां राजस्थान के इतिहास में दर्ज हो गई हैं।

अभी माननीय नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे थे। मुझे बहुत दुःख है, वैसे तो उनका पूरा ही भाषण भावनाओं से भरा असत्य का पुलिंदा था, कोई दम नहीं था। मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप नेता, प्रतिपक्ष हैं, डेमोक्रेसी में आपका सम्मान है, मैं आपके एक-एक बिन्दु का जवाब बनाकर असेंबली समाप्त होते ही आपको भेजूंगा और उसकी कापी पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों को भेजूंगा, तब आप पूरी तरह से एक्सपर्ट होंगे, खाली भावनाओं में बहकर ताली बजवाना एक बात है। आपको आकड़ों की जानकारी नहीं, आपको भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं। आप खाली भावनाओं में बहकर ताली बजवा रहे हो। मेरे ख्याल से आपने इस साल का सबसे बड़ा असत्य अभी बोला कि हमारे हिन्दुस्तान में तमाम जाति, धर्म, वर्गों को लेकर प्रधान मंत्री चल रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट चल रही है। इससे बड़ा असत्य तो कोई हो ही नहीं सकता है। हमारी पार्टी का मुद्दा ही यही है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान क्या है? यही तो है कि देश में शांति, भाईचारा, प्यार-मुहब्बत रहे, यही तो हमारी सोच है। हमारी सोच है देश में बंटवारे की तरह की भावना नहीं बने, सब हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी एक रहें। नेता प्रतिपक्ष, मुझे इस बात का जवाब देंगे, बी जे पी का एक भी मुस्लिम मेम्बर न लोक सभा में है, न राज्य सभा में है, न यूपी में है। आप लोग किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? एक इतना बड़ा धर्म, जिसकी 20 परसेंट आबादी हो, आपकी पार्टी ने एक टिकट नहीं दिया, न लोक सभा में, न यूपी में, न राज्य सभा में। आप किस मुंह से सबको साथ लेकर चलने की बात करते हो? स्कीम बनेगी सरकार की, चाहे राज्य की हो, चाहे केन्द्र की हो, सबके लिये बनती है। आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो चुनाव आ रहे हैं, आप सबको हाईकमान के सामने अपने नंबर बढ़ाने हैं। आप 75 साल के हो चुके हैं और 75 साल के बाद आपकी पार्टी की सोच है कि वह शिफ्ट कर देती है। आज मैं जो आपका भाषण सुन रहा था, मुझे लगा कि आप केवल मोदी जी को इम्प्रेस करने के लिये बोल रहे हो, आपके भाषण में कोई दम नहीं है। आप किस रूप में बोल रहे थे?

आप आयुष्मान भारत की बात करते हो। आपको मालूम है उसमें कैप

(श्री अशोक गहलोत)

लगी हुई है? आपको मालूम है खाली 19 परसेंट लोगों को राजस्थान में, हम उसकी स्कीम लेकर आये या आपकी भामाशाह योजना थी, आपने ताली बजवा दी कि हिन्दुस्तान में सबसे पहला काम हमने किया, क्या किया? 19 परसेंट लोगों को आप दे रहे थे। आपको मालूम है भामाशाह और चिरंजीवी योजना में कितना बड़ा फर्क है? आज राजस्थान में चिरंजीवी योजना में 90 परसेंट कवरेज किया है। पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान की चर्चा हो रही है। हमारे नवाचार की चर्चा हो रही है, चाहे वह चिरंजीवी योजना हो, चाहे ओ पी एस हो। उड़ान योजना हो, शहरी रोजगार योजना हो, इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, कितनी योजनाओं को गिनाऊं मैं आपको? आज लोगों को कितना रिलीफ मिला है, राजस्थान उस बात का गवाह है। आप हर स्कीम को बिना समझे हुए 19 परसेंट किसे कहते हैं, उसमें कैप है। इंश्योरेंस कंपनी को 1065 रुपये देने का उसमें कैप है, हम 1775 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं। किसकी बात आप करते हो, आप कम्पेयर करना चाहते हो? मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने खूब देख लिया, आपने चार साल निकाल दिये, आपने क्या भूमिका निभाई? आपने जन आक्रोश रैली निकाली, यात्रा निकाली। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कहीं आपको जन दिखा? कहीं आपको आक्रोश दिखा? आपकी धज्जियां उड़ गईं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, प्लीज, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): न जन था, न आक्रोश था। पूछ रहे थे आक्रोश किस बात का है, यह तो बताओ, हम तो संतुष्ट हैं। एक के ऊपर एक शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पानी की, बिजली की शानदार योजनाएं बन रही हैं। शानदार सड़कें बन रही हैं। घर-घर पेंशन मिल रही है, एक करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी हमारी थीम में है। क्या बात करते हो? किसान खुश है, उनके लिये अलग बजट पेश किया। देश में कितने राज्यों ने किया? हमने उनका एलोकेशन डबल कर दिया। अभी आप कह रहे थे कि वसुन्धरा जी ने 833 रुपये दिये, आप बड़े गिना रहे थे। 833 रुपये दिये कब? कोड आफ कंडक्ट लगने के चार दिन पहले और वह भी बैक डेट में। कोड आफ कंडक्ट लग चुका था। चार दिन पहले एक पेज लगाकर बैक डेट में 833 रुपये की घोषणा कर दी, बिना बजट के कर दी। हमारी सरकार आई, हमने साल भर लगाया होगा, बाकायदा हमने बजट में प्रोविजन किया, 1000 रुपये प्रति किसान दिये। आज लगभग 9 लाख किसानों का जीरो बिल आ रहा है।

(श्री अशोक गहलोत)

किसकी बात कर रहे हैं? पूरे सदन को मालूम होगा कि किस प्रकार से किया? वह भुगतान भी हम लोग कर रहे हैं।

हमने 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 14 हजार करोड़ रुपये उसमें खर्च हुए, उसके अन्दर आपके 06 हजार करोड़ थे। आपने 50 हजार तक का किया और बाद में करने की घोषणा की, हमारे ऊपर डाल दिया। हमने वह भी मंजूर किया। आपने राष्ट्रीयकृत बैंकों का कहा। ठीक है, मैं उसी के अन्दर लिख रहा हूं। हम आज भी उस पर कायम हैं। आप अगर बड़ेबड़े करोड़पतियों के करोड़ों-अरबों रुपये माफ कर सकते हो, एन पी ए कर सकते हो, वन टाइम सैटलमेंट कर सकते हो तो क्या कारण है कि आज राजस्थान के अन्दर उन किसानों, जिनसे हमने वादा किया है, आप उनका वन-टाइम सैटलमेंट करवा दीजिये। किसान का हिस्सा आयेगा, वह हम भरेंगे।

आपका आधा, 35 मिनट का भाषण तो खाली शिक्षा पर ही था। नेचुरल भी है। आप टीचर रहे हैं, सामान्य टीचर रहे हैं। आपका अपना अनुभव है। हम चाहेंगे कि आपके अनुभव का लाभ लें। जिस प्रकार से आपने 35 मिनट इसमें जाया किये, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रात और दिन का फर्क है। चाहे इंग्लिश स्कूल खोलने की बात हो, चाहे भर्ती करने की बात हो। आप तो इतने अनुभवी हैं, मुझे बता दीजिये कि किस सरकार में साढ़े तीन लाख के लगभग नौकरी लग रही हैं। हमने 1 लाख 47 हजार नौकरियां दीं, 1 लाख 25 हजार की नौकरियां प्रोसेस के अन्दर हैं, इन्टरव्यू और एग्जाम हो रहे हैं और 1 लाख की हमने घोषणा कर रखी है। आप मुझे बता दीजिये कि आप जो आंकड़े दे रहे हैं कि इतने खाली, इतने खाली। क्या आपके वक्त में खाली नहीं रहे थे? खाली हमेशा रहते हैं, भरने की प्रक्रिया होती है।

आपने खुद ने स्वीकार किया कि हमने ट्रांसपोर्ट फ्री किया। खाली ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं किया। हम लोगों ने बाकायदा जिला कलेक्टरों को कहकर, जिसका आपने भी हिन्ट दिया था कि जनता ने साथ दिया, मैं मानता हूं। हमने खुद ने तय किया, खाली रोडवेज में नहीं, प्राइवेट बसों का किराया भी हम देंगे। हमारे करीब 26 लाख अभ्यर्थी थे। रात को कहां रूकेंगे? कहां खाना खायेंगे? हमने कलेक्टरों को कहकर व्यवस्था की। आप सब लोगों ने भी उसमें सहयोग किया होगा। उन लोगों को खाना भी मिला, रहने की व्यवस्था भी की। पेपर लीक हो गया। पेपर लीक तो वैसे हर राज्य में हो रहे हैं, वह अलग बात है। आप कहेंगे कि वहां हो रहे हैं तो क्या यहां होना जरूरी है। मैं आपकी बात

(श्री अशोक गहलोत)

को मानता हूं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर तो गुजरात में, बिहार में, आन्ध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सब जगह लीक हो रहे हैं। आपके वक्त में 13 बार पेपर लीक हुए। राजस्थान पहला राज्य है, जिसने उन लोगों को जेल के सीख़चों में बन्द किया है। हमने उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। हमने इसी असेम्बली के अन्दर कानून पास किया है। हमने नौकरियों से बर्खास्त किया है। किस राज्य ने ऐसा किया है? आप बता दीजिये।

आपके वक्त में, शायद आपको मालूम होगा, आप गृह मंत्री थे। सब-इंस्पेक्टर का पेपर आउट हो गया और 80 लोग नौकरी में चले गये। आप बताइये। 2014 की उस समय की प्रेस कटिंग मेरे पास है। 80 लोग नौकरी के अन्दर चले गये, पेपर आउट होने के बाद भी। आप उनको रोक नहीं पाये। वह सरकार आपकी थी। हमारे राज्य सभा के माननीय सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह मुद्दा ऐसा है जिस पर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती है। यह मुद्दा ऐसा है, यह राष्ट्रव्यापी समस्या है कि हम इसको कैसे हल करें। आप जो सुझाव देंगे, हम उसको मानेंगे। हम चाहेंगे कि अभ्यर्थी का भविष्य, पढ़ता है, कोचिंग करता है, पैसा खर्च होता है, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, पर जिस प्रकार से पेपर आउट हो रहे हैं, सरकार की तरफ से, एस ओ जी की तरफ से कोई कमी रही हो, उसको आप हमें बतायें, हम उसको दूर करेंगे। इतना बड़ा इश्यू है।

आज ऐसा समय बदल गया है कि हमारे कुछ साथी तो बेरोजगारों को लेकर आन्दोलन करने लग जाते हैं, नौकरी देने के लिए। उन्हें भड़काते हैं। वे पढ़ाई कब करेंगे? सड़कों पर अगर वे लोग आयेंगे तो वे लोग पढ़ाई कब करेंगे? बच्चे कब पढ़ाई करेंगे? बच्चों को तो कोई नेता मिलना चाहिए, खुश हो जाते हैं। यही स्थिति राजस्थान में बनी है। हमारे राज्य सभा के नेता, मेम्बर आफ पार्लियामेंट, लोगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या तुक है? सरकार ने कोई कमी रखी है? सी बी आई जांच करके क्या कर लेगी? सी बी आई ने कोई जांच पहले भी की है क्या? कितने राज्यों में सी बी आई जांच दी गयी है? और तो और, यू पी के अन्दर तो एजेंसियों ने मना कर दिया है कि हम तो पेपर के हाथ ही नहीं लगायेंगे, हम तो पेपर नहीं लेंगे, एग्जाम नहीं करायेंगे। ऐसी स्थिति में हम चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसको पक्ष और विपक्ष मिलकर तय करे कि कैसे, चाहे हमें कमेटी बनानी पड़े। अध्यक्ष महोदय, आपकी भी इच्छा थी, कमेटी बने, कुछ भी बने, हमें मंजूर है, पर

(श्री अशोक गहलोत)

किसी भी कीमत पर पेपर आउट नहीं होने चाहिए। यह हमारा सुनिश्चित दृढ़ निश्चय है। हम चाहेंगे कि उसको आपको बतायें कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, इसमें हम आप सबका सहयोग चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के कामों से हमारे नेता, प्रतिपक्ष और तमाम साथी बौखलाये हुए हैं। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की परफोर्मेंस तारीफए-काबिल है, कोरोना के बावजूद, आपने कोरोना की तारीफ नहीं की। कोरोना के मैनेजमेंट के अन्दर हम हिन्दुस्तान में नम्बर-वन पर हैं। हमें आप सबका सहयोग मिला, धर्म गुरुओं का मिला, आम जनता का मिला। आपको याद है, उस वक्त मैंने आप दो सौ मेम्बर और पार्लियामेंट मेम्बर से बात की थी। मुझे गर्व है कि सबने साथ दिया। भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश और दुनिया में चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी आपके मुंह से तारीफ का एक शब्द भी नहीं आया।

केरल के अन्दर सरकार रिपीट इसलिए हो गयी, क्योंकि उनके हिसाब से कोरोना मैनेजमेंट अच्छा और शानदार रहा। हम उनसे कम नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो केरल में हुआ, वही राजस्थान में होगा, हमारी सरकार रिपीट होगी। आप देखेंगे कि कोरोना का मैनेजमेंट हमारे लिये गेम चेंजर होगा। हम लोगों ने कोई कम मेहनत नहीं की। किस प्रकार मैनेजमेंट किया, डाक्टर जानते हैं, नर्से जानती हैं, राजस्थान के लोग जानते हैं, जो तकलीफ में आये थे। हम लोगों ने आक्सीजन की कमी नहीं आने दी। हम लोगों ने केन्द्र सरकार पर भी दबाव रखा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी और गर्व होगा कि आज इन सब स्थितियों के बावजूद भी आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है, उसके कारण से आज हम देश के अन्दर जी डी पी में नम्बर 2 पर आ गये हैं। नम्बर-1 आन्ध्र प्रदेश 11.4 परसेंट और देश के अन्दर राजस्थान नम्बर-2 पर है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि 11.04 परसेंट है, जबकि आपके शासन के अन्दर, 2018-19 के अन्दर आप लोग जी डी पी में 2.37 पर आ गये थे। उसके बाद कोरोना भी आ गया, आर्थिक हालात भी बदल गये, उसके बाद भी 11.04 परसेंट हमारी विकास दर रही है। इस बात को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? हमने घोषणा-पत्र के 80 परसेंट वादे पूरे किये हैं, 20 परसेंट प्रगतिरत हैं। हम लोगों ने 94 परसेंट बजट घोषणाओं की स्वीकृति जारी कर दी है।

(श्री अशोक गहलोत)

अध्यक्ष महोदय, अगर हम पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी देखें तो आप पायेंगे कि राजस्थान के अन्दर जो भी चुनाव हो रहे हैं। आपके वक्त में, जब आपकी सरकार थी, 8 बाई-इलेक्शन हुए आप 6 चुनाव हारे थे। क्या आपको याद है? अभी हमारे वक्त में, 9 चुनाव हुए, उनमें से हमने 7 चुनाव जीते हैं। बी जे पी की एक जगह जमानत जब्त हो गयी है। एक जगह थर्ड नम्बर पर रहे, यह आप मत भूलो। जनता माई-बाप होती है, कुछ सोचकर हमें जिताया होगा और कुछ सोचकर आपकी जमानत जब्त करवायी होगी। आप यह ध्यान में रखें।

अध्यक्ष महोदय, कल केन्द्रीय बजट आया था। उसमें सब जगह एलोकेशन उन्होंने कम कर दिया। कृषि बजट में 5 परसेंट, फसल बीमा में 12 परसेंट, किसान सम्मान निधि में 13 परसेंट, मनरेगा में 33 परसेंट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट 31 परसेंट कम किया। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन (पी डी एस) तक का 30 परसेंट कर दिया। कैमिकल फर्टिलाइजर पर 21 परसेंट कम कर दिया, रूरल डवलपमेंट का 12 परसेंट कम कर दिया। आप सोच सकते हैं, यह आपके नये मॉडल की बात है। नर्सिंग कालेज की, जो कि कल बजट में घोषणा की गयी, मुझे खुशी है कि जो काम हम कर रहे हैं, हर जिले में मेडिकल के साथ में एक नर्सिंग कालेज खुलेगी, वह काम कल भारत सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि कोरोना के अन्दर भी हमने राजस्थान में जो-जो एस ओ पी जारी की थी, हमारे गृह मंत्रालय से, उसी एस ओ पी के 90 परसेंट केस लेकर भारत सरकार एस ओ पी जारी करती थी, वह हमारा वक्त था, हम भूल नहीं सकते हैं। हमें गर्व है कि हम लोगों ने इस प्रकार की तैयारी की कि जिसके कारण केन्द्र सरकार को फोलो करना पड़ा।

मेडिकल कालेज की बात करते हैं, बड़ा गर्व कर रहे हैं आप लोग। क्या यह एन डी ए गवर्नमेंट ने फैसला किया था, हर जिले में मेडिकल कालेज खोलने का? यू पी ए गवर्नमेंट का फैसला था। सात जगह फैसला हो गया। आपके स्वास्थ्य मंत्री बन गये माननीय विधायक चूरू के, ये ले गये चूरू के अन्दर चुराकर, चूरू ले गए चुराकर उस सात में से। बता दीजिए, ले गए चूरू? अल्टीमेटली वापस हमारी सरकार आयी और हमें मिलना ही था, क्योंकि हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। भारत सरकार ने मांगे हमसे डेटा, दिये उनको, आज पूरे जिलों के अन्दर करीब-करीब हम लोग, उस पर भी आप ऐसी बातें बोल रहे हैं, जैसे केन्द्र सरकार पैसे भेज रही हो। आप कुछ तो ये कहते कि केन्द्र सरकार को भी चाहिए इस प्रकार राज्यों की मदद करे, चाहे पानी की योजना

(श्री अशोक गहलोत)

हो, हमारे वक्त में 90:10 परसेंट था और जल जीवन मिशन आया है, 50:50 परसेंट है। फिफ्टी परसेंट उनका और फिफ्टी परसेंट हमारा। अब बताइए क्या राज्य सरकारें इसको अफोर्ड कर सकती हैं?

मेडिकल कालेज के अन्दर 60:40 परसेंट है। राज्यों का हिस्सा भी उसके अन्दर है। यह नहीं भूलना चाहिए, इस प्रकार से आप तारीफ करते हैं अपने प्रधान मंत्री जी की और आपकी केन्द्र सरकार की। इसलिये मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार से नवाचार हमने किए, मैंने बताया आपको।

अध्यक्ष महोदय, कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है मेरे को निमोनिया हो गया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय मुख्य मंत्री जी जितना बोल सकें, उतना ठीक है। पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बहुत शुक्रिया आपका, परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे सब नेता बैठे हैं तो प्रयास करता हूं कि कुछ बातें बताऊं आपको। मैं धन्यवाद करता हूं कटारिया साहब का कि कल जब मेरी बात हुई आपसे पेपर लीक के बारे में तो आपने चिन्ता प्रकट की थी मेरे निमोनिया होने के कारण से, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बी जे पी के चार साल और हमारे चार साल, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादा उछल-कूद आप ही करते हैं। स्कूल शिक्षा, कोई नई प्राइमरी स्कूल नहीं खोली, हमने खोली हैं। चार साल का आंकड़ा है, नेता, प्रतिपक्ष महोदय, आपको मैं विशेष कहना चाहूंगा कि आप इसको जरा गौर से सुनना। कोई नई प्राइमरी स्कूल नहीं खोली, हमने 266 नई प्राइमरी स्कूलें खोलीं। 178 प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी स्कूल में कन्वर्ट किया आपने, हमने 1453 प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी में कन्वर्ट किया। आपने 307 अपर प्राइमरी को सैकण्डरी में किया, हमने 1127 अपर प्राइमरी को सैकण्डरी में किया। कालेज, आपने 81 कालेज खोलीं, हमने 210 कालेज खोलीं, उनमें 94 महिलाओं की हैं। आपने एक कृषि कालेज खोला, हमने 42 कृषि कालेज खोले हैं। आपने आयुष हेल्थ वैलनेस सेंटर की बात की है, जीरो आपने किया, हमने 1000 आयुष हेल्थ वैलनेस सेंटर खोले हैं। आपने जीरो ब्लाक आयुष हास्पिटल खोले, हमने 77 जगह ब्लाक आयुष हास्पिटल खोले हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

आपने ग्रामीण विकास के अन्दर 21 हजार 586 करोड़ खर्च किये, हमने 56 हजार 257 करोड़ खर्च किये। आपने 76 हजार 816 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, हमने 1 लाख 85 हजार 657 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं।

मनरेगा में आपने 16 हजार 792 करोड़ खर्च किये, हमने 36 हजार 601 करोड़ खर्च किये। बुजुर्ग पेंशन आपने 5 हजार 345 दीं, हमने 20,722 दीं। एकल नारी पेंशन आपने 856 दी, हमने 8,160 एकल नारी को दी हैं। कहां 856 और कहां 8,160? दिव्यांग पेंशन 425 करोड़ दिए आपने, हमने 2,170 करोड़ दिए हैं दिव्यांगों को। पालनहार योजना में आपने 29 करोड़ दिए, हमने 2,130 करोड़ दिए हैं। रीको के अन्दर 10 औद्योगिक क्षेत्र आपने बनाए, हमने 62 बनाए हैं। अशोक लाहोटी साहब ने कहा कि घोषणाओं का क्या हुआ तो घोषणाओं का यह हुआ कि 62 बने हैं और बाकी लगातार प्रगति पर हैं। 1,894 भूखण्ड आपने आबंटित किये, हमने 5,100 भूखण्ड आबंटित किये। कोई कम्पेरिजन है? चार साल की परफार्मेंस आपकी और हमारी, कोई कम्पेरिजन है क्या?

मेडिकल एजुकेशन, एक मेडिकल कालेज खोली आपने, हमने 6 खोली हैं। 2 नर्सिंग कालेज खोलीं, हमने 25 खोली हैं और बाकी खुलती जा रही हैं। एम बी बी एस की 150 सीटें व पी जी की 50 सीट आपने बढ़ाई, हमने एम बी बी एस की 1,380 सीटें बढ़ाई हैं और पी जी की 558 सीटें बढ़ाई हैं। कहां 50 और कहां 558 सीटें बढ़ाई हैं? कितना बड़ा जम्प है? यह क्रांतिकारी काम है।

सड़क, 19 हजार 472 करोड़ रुपये खर्च किए आपने, हमने 25 हजार 285 करोड़ खर्च किये हैं। 49 हजार 888 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ आपके वक्त में, हमने 54 हजार 922 तो निर्माण पूरा कर दिया है और 46 हजार के लगभग चल रहा है और पूरा मिलाकर 01 लाख किलोमीटर के लगभग सड़कें बनेंगी हमारे वक्त में।

मेडिकल एण्ड हेल्थ, सात सब-सेंटर बनाए आपने, हमने 500 सब-सेंटर बनाए हैं। कोई कम्पीटिशन है क्या? सब-सेंटर से पी एच सी 7, सब-सेंटर टू पी एच सी 363, कोई मुकाबला है? पी एच सी टू सी एच सी 23, पी एच सी टू सी एच सी 206, उप-जिला अस्पताल जीरो, हमारे वक्त में उप-जिला अस्पताल 41, जीरो जिला अस्पताल आपके समय और हमारे वक्त में 21 जिला अस्पताल। आपके टाइम पर एक सैटेलाइट अस्पताल और हमारे वक्त में 8 सैटेलाइट अस्पताल। आपके वक्त में 565 हास्पिटल बेड बढ़ाए, हमने 6 हजार 705 हास्पिटल बेड बढ़ाए हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

बिजली के कनेक्शन, आपने दिए 1 लाख 77 हजार 226, हमने दिए 3 लाख 27 हजार 449, क्या मुकाबला करेंगे परफार्मेंस का? कोई मुकाबला करने की स्थिति है क्या आपकी? उन्नीस-बीस हो तो मुकाबला होता है। बिना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक घंटा बोलकर। जवाब भी दूंगा मैं आपको। जो आप बोले हैं, उनको मैं सुन रहा था। आपकी खासियत है कि आप भावना में भावुक होकर बोलते हैं। असेम्बली के अन्दर तो फिर भी आप कंट्रोल में रहते हैं, असेम्बली के बाहर तो कोई आपको कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। जिस प्रकार आप बोलते हैं, टी वी के सामने आते ही धज्जियां उड़ाते हैं हम सब लोगों की। हम जानते हैं कि यही तो आर एस एस के कैडर की खासियत है।

खेत की तारबंदी, आगे सुनिए आप, अभी आगे सुनिए आप, 2 लाख 1 हजार मीटर आपने बनाई, हमने 26 लाख 54 हजार मीटर। फसल बीमा, इससे पूरा दर्पण आपके सामने आ जाएगा, इस लिस्ट से, ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फसल बीमा, 5,822 करोड़ चार साल के अन्दर, हमारे वक्त में, ज्ञानचंद पारख जी ने इस बारे में बात की थी, हमारे वक्त में 18 हजार 177 करोड़, कोई मुकाबला है क्या? बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कृषि बिजली अनुदान, आपने दिए 31 हजार 940 करोड़, हमने 60 हजार 754 करोड़ दिया किसानों को बिजली का। आई जी एन पी इम्पोर्टेंट कैनाल है हमारी जिसमें आपके वक्त में लगभग जीरो रीलाइनिंग हुई थी। हमने 108 किलोमीटर रीलाइनिंग पंजाब में और राजस्थान में की है। सरहिन्द फीडर, जीरो लाइनिंग, हमने 84 किलोमीटर रीलाइनिंग की है। नये ए डी एम आफिस, कोई नहीं खोला आपने, हमने 7 खोले हैं। एस डी ओ आफिस कोई नहीं खोला आपने, हमने 27 खोले हैं। नये तहसील आपने 17 खोले, हमने 61 खोले हैं। उप-तहसील 4 खोले, हमने 74 खोले हैं। नये राजस्व ग्राम 435 बनाए, हमने 931 बनाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक का मामला बहुत गम्भीर है। मैं फिर कहना चाहूंगा, अपील करूंगा कि जिस प्रकार से यह पूरे देश में एक ऐसी गैंग बन चुकी कि आर्मी के अन्दर, डी आर डी ओ के अन्दर, राजस्थान हाईकोर्ट के अन्दर दो महीने पहले हो गया और परसों गुजरात में हो गया। क्या वहां पर सड़कों पर बच्चे आए? कोई सोच नहीं सकता। यह चिन्ता का विषय होना चाहिए। इस पर सुझाव देने वाली बात करें कि किस प्रकार से इनसे निपटें। मैंने पहले भी कहा, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। आप जो भी सुझाव देंगे,

(श्री अशोक गहलोत)

उनको हम लोग चाहेंगे कि हम सब मिलकर इसके ऊपर ऐसी चीज पैदा करें जिससे भविष्य में यह स्थिति नहीं बने।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह वापस बताना चाहूंगा, क्योंकि हेल्थ सेंटर हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी का है। आपने दवाइयों की तारीफ तो की, बाकी आपने जो आलोचना की है, आपकी आलोचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं। पूरी कंट्री में अभी ओ.पी.एस. के बाद चिरंजीवी योजना की चर्चा है। कृपा करके, आपके 25 लोक सभा मैम्बर हैं, जाकर कभी मिलियेगा, दो बातों के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना है कि प्रधान मंत्री जी दौसा आ रहे हैं। इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। या तो अपन सब दिल्ली चलें, पी एम हाउस के अन्दर। प्रधान मंत्री निवास पर जाकर मिलें, वे चाय पिलाएंगे तो चाय भी पी लेंगे और साथ में उनको ई आर सी पी का वादा भी याद दिलाएंगे। उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। इतनी तो उनकी याददाश्त है कि वह अपने वादे को इमिजिएटली कैच कर लेंगे कि हां, वास्तव में मैंने बोला था। आप कहोगे तो साथ में रिकार्डिंग ले आएंगे, याद दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि आप इसको सीरियसली लें। यह प्रदेश के फ्यूचर से जुडा हुआ है।

आपकी शुरुआत मैंने अभी टीवी के अन्दर देखी है, आप बोल रहे थे कि 2050 तक का प्लान बता दिया, जब तक तो हम दुनिया में रहेंगे ही नहीं। भगवान करे आप 2050 तक दुनिया में रहो। यह आप कैसे इंटरप्रिटेशन करते हो, कैसे करते हो, समझ के परे है।

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में थर्ड फेज चल रहा है अभी इंदिरा गांधी कैनाल का। थर्ड फेज पूरा होगा पांच साल बाद, जब भी होगा। कल्पना रही कि 2050 तक मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं तब तक का इंतजाम हो जाएगा। उसी ढंग से यह ई आर सी पी पूरी होगी तो 2050 तक आराम हो जाएगा तेरह ज़िलों के अन्दर, इसका मतलब यह होता है। आप उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे हो। इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, गुमराह कर रहे हो, ताली बजवा रहे हो। यह लोग समझ नहीं पा रहे और आप ताली बजवा रहे हो। ऐसी ताली मत बजवाओ। आप हमें तो कटाक्ष करते हो, ताली बजवा दी, ताली बजवा दी। हमारी तालियां बजती हैं तो जस्टिफाई होती हैं और आपकी तालियां जस्टिफिकेशन वाली नहीं होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, आपको और हम सबको इस बात का

(श्री अशोक गहलोत)

गर्व होना चाहिए। सबके घरों में तकलीफ आती है। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा मुद्दा है, नेता, प्रतिपक्ष आप भी एग्री करेंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य देश में हर व्यक्ति के लिए बड़े मुद्दे हैं। हमने शिक्षा में बहुत गर्व का काम किया है। टीचर्स नहीं हैं कमी रही है, हम भी दुःखी हैं, आप भी दुःखी रहे। बाड़मेर, जैसलमेर में क्या स्थिति बनती है, हम जानते हैं। हम भी दुःखी हैं, बहुत दुःखी हैं। दुख को हम सबको बांटो, हम आपके साथ हैं। आज स्कूलों में टीचर्स नहीं होते हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर्स नहीं होते हैं, कौन सरकार नहीं चाहेगी? हर सरकार के वक्त यूनिवर्सिटी बनी हुई है कोई कॉमन बात नहीं है। मिलकर बात कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। अच्छे काम हो रहे हैं, पूरे प्रदेश वासियों को गर्व होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक एक्स-एम एल ए साहब ने मुझे कहा, जब मैंने 2012 के अन्दर पहली बार दवाइयां फ्री की थीं। उन्होंने कहा कि अब लड़कियां बच जाएंगी। तब मैं उनकी बात को समझा नहीं। मैंने पूछा, क्या मतलब? उन्होंने कहा कि साहब, गांव में जब लड़का बीमार पड़ता है तो बाप अस्पताल उठाकर ले आता है, लड़की बीमार पड़ती है तो उसको नहीं लाते कि ठीक हो जाएगी। चाहे मरो तो मरो। अब आपने दवाइयां फ्री कीं तो अब लोग अस्पताल में जाएंगे। आप मर्म समझ लीजिएगा। वह मर्म समझकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज जो कुछ हमने किया है यह देश के अन्दर इतिहास बन चुका है।

हम मोदी जी को कहते हैं, आगे आइये, आगे आइये, दो कामों के लिए। एक तो भारत सरकार के अन्दर, केन्द्र में सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ जो डा. मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी के वक्त बना था। राइट टू इन्फार्मेशन, राइट टू एजुकेशन, महात्मा गांधी नरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, दो रुपये किलो गेहूं, तीन रुपये किलो चावल। उसी प्रकार से देश के अन्दर कानून बने। पूरे मुल्क में एक समान, बुजुर्गों को, बूढ़े मज़दूरों को, दिव्यांगों को, एकल नारी को, इन सबके लिए पार्लियामेंट में पेंशन का एक्ट बने, सरकारें कोई आओ-जाओ। जैसे नरेगा को मानना पड़ रहा है, आर टी ई को मानना पड़ रहा है भारत सरकार को। फूड सिक्योरिटी एक्ट को मानना पड़ रहा है। हमारी सरकारें बदल गयीं, यू पी ए आ गई, एन डी ए आ गई। मोदी जी, ऐसा कानून बनाओ जो कि पूरी कंट्री में, दुनिया के विकसित राष्ट्रों की तरह, यह वक्त आ गया। आप भी विश्वगुरू बनने की बात कर रहे हो। वह तब बनेंगे, जब मिनिमम रिक्वायरमेंट जिंदा रहने की मजदूर को भी मिले। बुढ़ापे में वह अपना काम नहीं कर सकता,

(श्री अशोक गहलोत)

घर बैठे उसको वीकली पैसा मिले। इस प्रकार से क्यों नहीं हम लोग कानून बनाएं? यह मैं उनसे अपील करता हूं।

मैं कहना चाहूंगा हमने हेल्थ सेक्टर में 7 परसेंट बजट रखा है। 10 हजार करोड़ का डबल 20 हजार कर दिया। यूनिवर्सल हेल्थ केयर हमारा सपना है। राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं आपके हस्तक्षेप से जल्दी पास होगा।

आज 31 लाख लाभार्थी चिरंजीवी के अन्दर हैं। खाली आई पी डी की कह रहा हूं। ओ पी डी में तो करोड़ों से ऊपर हो गए हैं। आई पी डी के अन्दर भी प्राइवेट सेक्टर व गवर्नमेंट मिलाकर 31 लाख लाभार्थी हो चुके हैं।

इंश्योरेंस कवरेज में, नेता, प्रतिपक्ष महोदय आपका ध्यान विशेष आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा, आप बिना जानकारी के बोलते रहते हैं। मैंने क्यों कहा? इंश्योरेंस कवरेज 2015-16 में आपके 19 परसेंट थी भामाशाह की। आज 90 परसेंट मैंने कहा आपको। यू पी में आज भी 16 परसेंट हैं। महाराष्ट्र में 22 परसेंट हैं, पंजाब में 25 परसेंट, हरियाणा में 26 परसेंट, मध्यप्रदेश में 38 परसेंट, गुजरात में 44 परसेंट है। हमने 90 परसेंट कर दी।

रोजाना सवा लाख जांचें फ्री हो रही हैं। रोजाना नि:शुल्क जांचें सवा लाख से डेढ़ लाख हो गई। सभी ज़िलों में नर्सिंग कालेज बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर खुशी होगी कि एम एम आर, आई आई एम आर, आप तो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, आप समझ सकते हैं, इसका महत्व क्या है। पीकू-नीकू का क्या महत्व है, आप समझ सकते हैं। आप हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। कोटा में हमारी बदनामी हुई थी, वह भी आपको मालूम है। आज नीकू-पीकू की संख्या इतनी बढ़ गई कि राजस्थान के अन्दर अब वह स्थिति नहीं रहेगी। कोरोना ने उन सबको और बढ़वा दिया।

मैं आपको कहना चाहूंगा, इम्पोर्टेंट बात है। एम एम आर जो 1998 में 501 था, मतलब मोर्टेलिटी रेट मरने वाली माताओं का, 501 से अब हम लोग 113 पर आ गए। हमें गर्व होना चाहिए। उसमें आपकी सरकार भी थी, हमारी सरकार भी आई थी। जो 1998 से मैं बात कर रहा हूं। पिछले दो वर्ष में हमें गर्व है, हमने इन दो वर्षों के अन्दर और 28 परसेंट काम किया। आई एम आर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1998 के अन्दर 81 थी, आज वह 32 पर आ गई, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। नीकू-पीकू की संख्या हमने चार गुना

(श्री अशोक गहलोत)

बढ़ा दी है। खुशी की बात यह है कि आज राजस्थान में 95 परसेंट प्रसव अस्पतालों में होने लग गए हैं। उसी से आपके एम एम आर, आई एम आर में फर्क पड़ा है, आप समझ सकते हैं। राष्ट्रीय औसत से यह 7 परसेंट ज्यादा भी है। राजस्थान का संस्थागत प्रसव देश के स्तर से हमारा 7 परसेंट ज्यादा है, यह हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात होनी चाहिए। टीकाकरण हमारा पहले वर्ष 2015-16 में, आपके वक्त में 58 परसेंट था और अब 81 परसेंट है। अस्पतालों में जो बेड बढ़े हैं वे 60 परसेंट बढ़े हैं। आक्सीजन आई.सी.यू. बेड की संख्या तीन गुना अधिक हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने कार्य किया है, उसके लड़कियों के ड्राप-आउट कम हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खुली है, पर आपने आलोचना भी की। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कोई कम बात नहीं है। पहले अलाऊ नहीं था प्राइवेट सेक्टर। हमारे वक्त में 1998 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी उस वक्त मंत्री थे तब हमने शुरू किया प्राइवेट सैक्टर को। पहले यूनिवर्सिटी 6 थीं, हमारे वक्त में, जब हम पहले सरकार में आये थे, आज 6 से बढ़कर 22 सरकारी यूनिवर्सिटी बन गयीं। उसमें से 18 हमारे वक्त में बनीं। कुल 89 यूनिवर्सिटी बन चुकी हैं राजस्थान के अन्दर, उनमें 57 कांग्रेस के वक्त में बनी हैं। नर्सिंग कालेज 25, यह तो मैं बोल चुका हूं, एग्रीकल्चर कालेज भी।

नेशनल अचीवमेंट सर्वे, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2021 का है, यह भारत सरकार का है। राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर औसत स्कोर के आधार पर प्रथम चार राज्यों में रहा है। परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI-D) के सत्र 2020-21 में प्रथम तीन जिले सीकर, झुन्झुनूं और जयपुर ने उत्कर्ष श्रेणी में काम किया है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। इस पर, अवार्ड में लगातार 2020-21, 2020-21, 2022-23 में देश में प्रथम स्थान पर रहा है राजस्थान।

राजस्थान की 'शिक्षा में बढ़ते कदम, कार्यक्रम के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगभग 50 लाख विद्यार्थियों का डेढ़ करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन किया जो रिकार्ड है। जो जम्बूरी स्काउट का, मैं इसको बहुत महत्व देता हूं। हालांकि, मुझे यह शिकायत है, आपकी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी से कि हमने उस वक्त में भी जम्बूरी, यह 56 साल बाद आ रही थी राजस्थान के अन्दर, दस करोड़ रुपये सैंक्शन किये हुए थे पर हमारी गवर्नमेंट चली गयी। मुझे इस बात का दुःख है कि उन्होंने उस

(श्री अशोक गहलोत)

जम्बूरी को कैंसिल कर दिया। सोशल वर्क का यह मामला था। अभी हमने वापस 40 करोड़ रुपये खर्च करके उसको करवाया है। राष्ट्रपति महोदया वहां पर आयी हैं। राष्ट्रपति आते हैं वहां पर। प्रधान मंत्री आते हैं। हमने रिक्वैस्ट की मोदीजी से भी, प्रधान मंत्री महोदय वहां आ नहीं पाये, पर आपके केन्द्रीय मंत्री आये मिस्टर ठाकुर। कोई राजनीति नहीं की हम लोगों ने उसके अन्दर और एक ऐसे अच्छे काम को भी वसुन्धराजी ने, पता नहीं किसने सलाह दी, राजेन्द्र राठौड़ साहब बहुत नजदीक थे उनके, इनकी सलाह ही रही होगी? तो आप तो, खैर, पता नहीं। पता नहीं यह तो आपका अंदरूनी मामला है। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप सब जानते हो। कारण क्या है बताओ तो सही। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में जो ध्यान आकर्षित किया गया है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रिन्यूएबल में हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा क्षमता में भी राजस्थान देश में प्रथम है और आर.आर.ई.सी.एल. को 22वां राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार मिला है। बिजली के जी.एस.एस. के निर्माण को तय समय में पूरा करने में परेशानी हो रही है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद में जो जी.एस.एस. बनने थे या पावर प्लांट बनने थे, उनमें जरूर हमें तकलीफ आ रही है, वह थोड़ा डिले हो रहा है, इस बात का हमें दु:ख है।

एक लाख करोड़ रुपये के सोलर क्षेत्र में निवेश के एम.ओ.यू. हुए हैं। भड़ला के अन्दर, जोधपुर के भड़ला में वह देश का सबसे प्रथम सोलर पार्क बना है।

सड़कों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम लोग बहुत आगे हैं। उद्योगों में हमारा एम.एस.एम.ई. एक्ट बना, तब से ही 16 हजार से अधिक इकाइयों को फायदा मिला है। बाकी पचपदरा रिफाइनरी हो या चाहे अन्य हो, अशोक लाहोटी ने कहा कि उद्योग बंद हो गये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रीको के आंकड़े मैंने आपको बता दिये, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ते ही जा रहे हैं।

कृषि आधारित उद्योगों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनस, एग्रो एक्सपोर्ट में दो करोड़ रुपये तक की सब्सिडी है। कृषि बजट हमने अलग से पेश किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगली बार भी हम अलग बजट पेश

(श्री अशोक गहलोत)

करने जा रहे हैं कृषि का। अभी कृषकों का मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से हजार रुपये हमने दिये और उससे 9 लाख के करीब किसानों का बिजली बिल कम हो गया। आम उपभोक्ताओं के लिए हमने 50 यूनिट बिजली फ्री की, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके कारण से और 150 और 300 का हमने स्लैब कम किया, उसके कारण से उपभोक्ता को इससे 9 हजार करोड़ रुपये का फायदा मिला और 50 यूनिट खतम करने से 39 लाख लोगों के जीरो बिल आने लगे राजस्थान के अन्दर, यह बात मैं कहना चाहूंगा।

उड़ान योजना का यह सपना है कि यह बहुत अच्छी ढंग से चले और इसका लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उप नेता जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो आपने इसको स्कूलों में शुरू किया था। अब हमने राजस्थान भर में लागू किया है पूरे प्रदेशवासियों के लिए। कोई भेदभाव नहीं है उसके अंदर। मैं यह चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष इसमें सहयोग करे, गरीब परिवार तक यह बात पहुंचे, उसका लाभ पहुंचे। अमीर लोग जब नैपकिन काम ले सकते हैं तो गरीब लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? बांझ बन जाती हैं औरतें, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बार-बार इन्फेक्शन होता है, कैंसर हो जाता है तो ऐसे कामों में मैं यह समझता हूं कि पक्ष और विपक्ष सबको आगे आकर इसमें रुचि लेनी चाहिए, यह मेरा मानना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कानून-व्यवस्था की बात की गयी, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि जिस प्रकार से एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट है, उसमें यदि आप विश्लेषण करेंगे तो यह पाएंगे कि राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी है पर फिर भी जो पर्सेप्शन आपने बनाया है, उसका मैं आपको लाभ नहीं लेने दूंगा, नेता, प्रतिपक्ष महोदय। पर्सेप्शन बनाना अलग बात है, सच्चाई दूसरी होती है। मैंने क्रांतिकारी काम किये हैं। सरकार बनते ही मैंने वे काम किये जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए हैं। कोई कम बात नहीं है कि एफ.आई.आर. को आप कम्पल्सरी कर दो। (व्यवधान) आप जो करते हो, भगवान जानता है आपको, भगवान जानेगा। आपने हमारे ऊपर कह दिया, मैं आपको कह रहा हूं, आप जाने और आपकी अंतरात्मा जाने, परंतु मैं यह कह सकता हूं कि एफ.आई.आर. कम्पल्सरी नहीं थी तो लोग भगा देते थे थानों से गरीबों को और अच्छे-अच्छे लोगों को। एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते थे। रेप हो गया किसी परिवार के अंदर तो वह जिंदगी भर तड़पता था कि एफ.आई.आर. लॉज नहीं हो पायी मेरी, न होगी। वह जब तक मरता नहीं

(श्री अशोक गहलोत)

आदमी, तब तक परिवार रोता कि मेरी बेटी के साथ रेप हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। आज कम से कम उसकी हिम्मत होने लगी है। हालांकि, उसका दुरुपयोग भी हो रहा है जो आज इसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया कि कुछ फर्जी भी होने लगे हैं, मैं इस बात को मानता हूं। यह भी आपने ठीक कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, वह कार्यवाही भी हम करवाएंगे, परंतु इतना बड़ा फैसला हुआ है उसके क्या लाभ मिले, इस सम्बन्ध में मैं अपनी बात बताऊंगा और सबसे बड़ी बात यह है कि एफ.आई.आर. कम्पल्सरी करने के बाद भी, मैं सदन के माननीय सदस्यों का यह ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसके बावजूद भी, पंजीकरण नीति के बावजूद भी वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में करीब 5 परसेंट अपराध कम दर्ज हुए हैं जबकि एम.पी., हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हो रहे हैं। तब भी, इसका मतलब क्या हुआ? कम्पल्सरी की, तब भी कम हो गये।

गुजरात में 69 परसेंट बढ़े हैं, हरियाणा के अंदर 24 परसेंट, मध्यप्रदेश में 20 परसेंट बढ़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या, महिलाओं के विरुद्ध अपराध व अपहरण में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। सबसे अधिक कस्टोडियल डैथ गुजरात में हुई है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉक्सो एक्ट के मामले में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। एस.सी., एस.टी. से जुड़े हुए अपराधों में यूपी. व एम.पी. देश में सबसे आगे हैं।

अनिवार्य पंजीकरण नीति के ये परिणाम हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता, प्रतिपक्ष का और तमाम साथियों का यह ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अनिवार्य पंजीकरण नीति के ये परिणाम हैं कि वर्ष 2017-18 में 33 परसेंट एफ.आई.आर. कोर्ट के माध्यम से सीआर.पी.सी. 156 (3) के तहत इस्तगासा द्वारा दर्ज होती थीं आपके वक्त में। अब कम्पल्सरी करने के बाद में विश्वास हो गया लोगों को कि हमारी सुनवाई होगी। अब यह संख्या सिर्फ 13 परसेंट ही रह गयी है। इसको तो मानेंगे, अचीवमेंट मानेंगे आप? इनमें से अधिकांश सीधे कोर्ट में जाने वाले मुकदमों की शिकायत यही होती थी।

हमारी सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का यही नतीजा है कि वर्ष 2017-18 में बलात्कार के मामले में अनुसंधान में 274 दिन लगते थे, अब सिर्फ 68 डेज ही लगते हैं। यह कितनी बड़ी उपलब्धि है, बताइये आप? कहां

(श्री अशोक गहलोत)

पर तो 274 दिन, लगभग एक साल और कहां पर 68 डेज में हो जाती है। पॉक्सो के अन्दर अनुसंधान का औसत वर्ष 2018 में, आपके वक्त में 232 दिन था, अब वह 66 दिन ही रह गया है, क्या कहेंगे इसको आप? क्या कहेंगे?

2015 में आपके वक्त में एस सी-एस टी एक्ट के करीब 51 परसेंट मामले अदालत के माध्यम से सीआर पी सी के 156 (3) में दर्ज होते थे, वह अब मात्र 10 परसेंट रह गये हैं। यह एफ आई आर की अनिवार्य पंजीकरण नीति की सफलता है। यह भी सही बात है और यह चिन्ता का विषय है कि कुछ लोगों ने हमारी सरकार की एफआईआर की अनिवार्य पंजीकरण की नीति का दुरुपयोग किया है। ये जो एफ आई आर दर्ज करवायी है उसी का नतीजा है कि प्रदेश में 2019 में महिला अपराधों में 45 परसेंट, 2020 में 44 परसेंट और 2021 में 45 परसेंट एफ आई आर असत्य साबित हुई हैं। आपकी शंका मिटा रहा हूं मैं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से इन सब बातों के साथ में इन चार सालों में 12 अपराधियों को फांसी की सज़ा, 450 से अधिक को आजीवन कारावास और 750 से अधिक को अन्य सजाएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट में फिर कहना चाहूंगा कि यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। ओ पी एस का मैं आपको तो क्या कहूं। देश के अन्दर अडाणी का जो शेयर डाउन हो रहा है, पूरे देश और दुनिया में तहलका मच गया है। हमने इस हाउस के अन्दर जो आर्ग्यूमेंट दिया था, हम एन पी एस के माध्यम से कर्मचारी बन्धुओं को, जो हमारे अपने भाई हैं, उनको मर्सी पर नहीं छोड़ सकते, यह मैंने कहा था। आज वही बात लागू हो गयी। पूरा देश हिल गया है। दुनिया के मुल्कों में चर्चा है। धड़ाम से सब शेयर नीचे आ गये हैं। एल आई सी के, एस बी आई के भी आ गये हैं। जिस-जिसने लोन दिया है, सबके धड़ाम से गिर गये हैं। वही बात मैंने पिछले वक्त में आपको कही थी। एनपीएस के माध्यम से पूरा पैसा जमा हो रहा है शेयर मार्केट के अन्दर, और धड़ाम से गिर जाएंगे तो क्या होगा उनका? भविष्य क्या होगा? प्रधान मंत्रीजी मोदी पहले देश को इसका जबाव दें। एन पी एस लागू क्यों रखना चाहते हो? मैंने उनसे भी बात की है। मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा वश चलता है, मैं पहुंच जाता हूं बात करता हूं। मुझे आप सबने यहां

(श्री अशोक गहलोत)

बिठाया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं खुल कर बात करूं। स्ट्रेट फार्वर्ड बात करूं। मैंने उनसे भी बात की है। मैं फिर कहना चाहूंगा पूरे सदन को कि एकजुट होकर बात करनी चाहिए। ओ पी एस लागू करना पड़ेगा, आज नहीं, तो कल करना पड़ेगा। यह मेरा मानना है। हमारा सबका पूरा पैसा जमा है। भारत सरकार दे नहीं रही है। ओ पी एस लागू करने के बाद भी नहीं दे रही है। हम कहना चाहेंगे कि नहीं देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पर हमारा पैसा लेकर रहेंगे।

हिमाचल प्रदेश में करारी मात हुई है। अब तो सबक ले लेगा आपका हाईकमान? अब भी नहीं लेगा क्या? हिमाचल में लोगों ने दिखा दिया। क्या हो गया, हमारा कर्मचारी है, आप क्या उसको इसके लायक नहीं रखेंगे ताकि वह कम से कम सिक्योर तो रह सके।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने ही उस पर साइन किए थे। साइन नहीं किए थे। नवम्बर में वाजपेयीजी की गवर्नमेंट के वक्त में डिक्लेयर हुआ था। हमारे वित्त मंत्रीजी ने रेफरेंस किया बजट के अन्दर। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट आ गयी। आपकी गवर्नमेंट के वक्त में लागू हुआ। हमारी गवर्नमेंट वहां फिर आ गयी तो जो नये नियम बने थे, उनको हमें मानना ही था। वह माने जिसका जिक्र आप कर रहे हो। पर समय बदलता है। आज ह्यूमन राइट कमीशन, सी एण्ड ए जी और जुडिशियरी कमीशन कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, मायने नहीं है। वह खुद इसकी आलोचना कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने 15-20 दिन पहले फैसला दिया है, अध्यक्ष महोदय। आर्मी में तो आप कह रहे हो ओ पी एस। बी एस एफ को दे रहे हो आप एन पी एस। पैरा-मिलिट्री को दे रहो आप एन पी एस। यह कैसी समझदारी है आपकी? उन्होंने फैसला दे दिया कि पैरा-मिलिट्री को भी आप ओ पी एस दो। सारे फैसले गवर्नमेंट के खिलाफ आ रहे हैं, फिर भी बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट से हमारे खिलाफ बुलवा रहे हो। हम चाहेंगे कि भारत सरकार को आगे आकर पुनर्विचार करना चाहिए और पूरे देश में ओ पी एस लागू होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि मौका मत चूको। दौसा बहुत नजदीक है। एक घंटे का ही रास्ता है। अगर दिल्ली नहीं तो यहां टाइम ले लीजिए। हम सब चलेंगे पक्ष और विपक्ष। वहां साइड में टेंट लगवा देंगे। वह तो कोई भी लगा देगा। वहां हमारी प्रधान मंत्रीजी से मीटिंग करवा दीजिए। ऐसा मौका कभी नहीं आयेगा। राजस्थान की जनता ने आपको 25

(श्री अशोक गहलोत)

एम पी दिए हैं, यह मत भूलो। यह मौका आपके लिए है, अगर आप राष्ट्रीय परियोजना को घोषित करवायेंगे। यह वादा किया था प्रधान मंत्रीजी ने। वसुन्धराजी के वक्त में आपने खुद ने देखभाल कर प्रपोजल भेजा था वहां पर। आपके मंत्रीजी 75/85 की बातें करते हैं, वह पूरे राजस्थान को गुमराह कर रहे हैं। उनसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं।

'संजीवनी' उनके पीछे पड़ी हुई है। गरीब मर रहा है बाड़मेर में, जोधपुर में। वह जगह-जगह मर रहा है। सभी कौम के लोग हैं। क्या उनको चिन्ता नहीं होनी चाहिए? लोगों की आंखों में आंसू आ गये। अध्यक्ष महोदय, मेरे सी एम हाउस में आये 70-75-80 साल के लोग। विश्वास नहीं होता है। 4 लाख, 5 लाख, 6-6 लाख, एक, दो, तीन लाख तो मामूली बात है, सबके डूब गये। कैसे दिलवाऊं अब मैं उनको? उनके लोग जेल में बैठे हुए हैं। वे खुद अभियुक्त बन गये हैं, उनके परिवार के लोग अभियुक्त बन गये हैं। चिन्ता नहीं है उनको। यहां पब्लिक को लेकर गुमराह कर रहे हैं। प्रधान मंत्रीजी ने ऐसे आदमी को इतना बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया।

मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे लिए मौका है। वहां चलें या यहां जाएं और जाकर समझाएं उनको कि देश के अन्दर 16 परियोजनाएं हैं, एक में क्या फर्क पड़ता है। अभी चुनाव आये यू पी के तो आपने 'केन बेतवा लिंक परियोजना' को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। कृपा करके पक्ष और विपक्ष हम सब मिलकर चलें।

अध्यक्ष महोदय, हमारी कई परम्पराएं अच्छी रही हैं। कुछ भी कह दें, फिर भी राजस्थान में पक्ष-विपक्ष का अपना एक ओरा रहा है, अलग शालीनता रही है, अलग ढंग से व्यवहार रहे हैं। व्यक्तिगत व्यवहार में तो कमी नहीं है। उनको निभाते हुए, राजस्थान के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं जवाब दे सकता हूं। मैं समझता हूं कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके कॉमन मुद्दों पर साथ मिलकर चलें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उसको पास करें। धन्यवाद।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर
धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री जितेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

जो पक्ष में हों, वह हां कहें।

जो विपक्ष में हों, वह ना कहें।

जो पक्ष में हों, वह हां कहें।

जो विपक्ष में हों, वह ना कहें।

जो पक्ष में हों, वह हां कहें।

जो विपक्ष में हों, वह ना कहें।

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.58 बजे शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2023 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

विद्युत निगमों का एकीकरण कर विद्युत मण्डल का गठन

98. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2000 में विद्युत मंडल को तोड़कर पांच विद्युत निगमों में विभक्त करने से विद्युत कम्पनियों का घाटा लगातार बढ़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निगमों का एकीकरण कर पुन: विद्युत मण्डल का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार एक विद्युत निगम से दूसरे विद्युत निगम में कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निगमों के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम व आरजीएचएस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के विघटन के उपरान्त अस्तित्व में आई विद्युत कम्पनियों का घाटा बढ़ा है यद्यपि 'उदय योजना' के उपरान्त डिस्कॉम्स के घाटे के बढ़ने की गति में कमी आई है।

वर्तमान में कार्यरत विद्युत निगमों का एकीकरण कर पुन: विद्युत मण्डल बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि विद्युत की बढ़ती हुई मांग, विद्युत तंत्र के निरन्तर फैलाव, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के मद्देनजर वर्तमान विकेन्द्रित व्यवस्था अपरिहार्य प्रतीत होती है।

(2) इस संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्ष 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का विघटन तथा पांच विद्युत निगमों का गठन, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 19.07.2000 को अधिसूचित "राजस्थान पावर सैक्टर सुधार अन्तरण स्कीम, 2000" के तहत किया गया था जिसके अनुसार कर्मचारियों का अन्य विद्युत निगमों में परस्पर स्थानान्तरण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अत: एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण सम्भव नहीं है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(3) विद्युत निगमों में दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारी जिन्होंने जीपीएफ पेंशन स्कीम का चयन किया था, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है तथा जीपीएफ नियमों के तहत 01.01.2004 से पूर्व के कर्मचारियों के लिए वर्तमान में चिकित्सा परिचर्या नियम (Medical Attendance Rules-2013) के तहत चिकित्सा पुर्नभरण सुविधा के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।

दिनांक 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी जो कि निगमों की सीपीएफ स्कीम के तहत आते हैं को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा उक्त स्कीम के अन्तर्गत आने वाले कार्मिकों को राज्य सरकार की आरजीएचएस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर

फसल चक्र के अनुरूप सिंचित क्षेत्र के वरीयता क्रम का निर्धारण

104. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना में फसल चक्र के अनुसार सिंचित क्षेत्र का वरीयता क्रम लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार फसल चक्र में वरीयता क्रम निर्धारित नहीं होने से किसानों को हो रहे नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में मुख्य अभियंता स्तर पर जन प्रतिनिधियों के सुझावों को दरकिनार किया जाता है? यदि हां, तो माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कौन-कौनसी बैठकों में दिये गये सुझाव को दरकिनार करते हुए निर्णय लिए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.05.2005 द्वारा स्थापित व्यवस्थानुसार खरीफ एवं रबी फसल के प्रारम्भ में बांधों में पानी की उपलब्धता के आधार पर जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में निर्णय उपरांत वरीयता क्रम तय किया जाता है।

(2) जी नहीं। रबी एवं खरीफ की फसल हेतु जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में निर्णय उपरांत ही पानी की उपलब्धता अनुसार ही वरीयता क्रम तय किया जाता है।

(3) जी नहीं। जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं माननीय प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों उपरांत लिये गये निर्णयों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मांडलगढ़ में किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी

105. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत सभी गांवों के किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो वंचित गांवों के किसानों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ के कौन-कौनसे गांव को उक्त योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तथा कितने किसानों को कितनी किश्तें मिल चुकी हैं व कितने किसान वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में सभी पात्र किसानों को सम्मान निधि समय पर प्राप्त हो, इस हेतु क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला भीलवाड़ा में समस्त ग्रामों के पात्र आवेदनकर्ताओं को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है।

(2) मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के समस्त गांवों में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। लाभार्थी कृषकों का विवरण निम्नानुसार है:-

किश्त	**लाभार्थी कृषकों की संख्या**
1	50,415
2	49,945
3	49,698
4	48,788
5	48,554
6	48,268
7	47,285
8	46,352
9	44,082
10	38,645
11	28,878
12	22,878

विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में 52,311 कृषकों द्वारा आवेदन किया गया एवं 50,415 किसानों को योजना का लाभ मिला है। 1,896 कृषकों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

(3) किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की योजना है। कृषकों को लाभान्वित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कृषकों के भूमि विवरण का

(सहकारिता मंत्री)

सत्यापन, E-KYC एवं बैंक खातों की आधार सीडिंग का कार्य जिला कलेक्टर के माध्यम से कराया जाता है एवं योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है।

प्रतिबंधित जिलों से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण से रोक हटाने की कार्ययोजना

106. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में समस्त कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का अन्तिम बार स्थानान्तरण कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में प्रतिबंधित जिलों एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के स्थानान्तरण से रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में समस्त कार्मिकों हेतु स्थानान्तरण नीति बनाने संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण अंतिम बार वर्ष 2018 में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.5(5)प्राशि/2018 के अनुसार स्थानान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न हुई थी। विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2018 में शासन द्वारा 19,340 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये।

(3) इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है।

गैर कृषि कार्यों में लिप्त ट्रैक्टर-ट्रोलियों का चालान

107. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत दो वर्षों में वाहन दुर्घटनाओं के कारण कुल कितनी मौतें हुई हैं तथा उक्त में से कितनी मौतें ट्रैक्टस्ट्रोलियों के कारण हुई हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में असंख्य ट्रैक्टर-ट्रोलियां गैर कृषि कार्य में बिना टैक्स जमा कराये उपयोग में ली जा रही हैं? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में कितने ट्रैक्टर-ट्रोली का अवैध उपयोग करने पर चालान किया गया? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(3) कोटा शहर में प्रतिदिन कितने ट्रैक्टर-ट्रोलियां अवैध रूप से पत्थर, बजरी व अन्य कार्य हेतु खुले आम संचालित हो रही हैं तथा विगत दो वर्ष में उक्त से कुल कितना जुर्माना वसूल किया गया तथा कितने ट्रैक्टर जब्त किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत 2 वर्षों में वाहन दुर्घटनाओं के कारण कुल 19,649 मौतें हुई हैं तथा इनमें से 1277 मौतें ट्रैक्टर-ट्रोलियों के कारण हुई हैं। पुलिस जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के प्रत्येक जिले में टैक्टर-ट्रोलियां गैर कृषि कार्य में (बिना व्यावसायिक रूप में पंजीकृत) बिना टैक्स जमा कर उपयोग में लिये जाने के प्रकरण सामने आये हैं। विगत दो वर्षों में गैर कृषि कार्य हेतु संचालित ट्रैक्टर-ट्रोलियों के विरुद्ध परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का परिवहन जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

पुलिस विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार विगत 2 वर्षों में गैर कृषि कार्यों में उपयोग में लिये जाने वाली ट्रैक्टर-ट्रोलियों के कुल 5,003 चालान किये गये। पुलिस जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा प्रतिदिन चल रहे वाहनों का रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है। कोटा शहर मे ट्रैक्टर-ट्रोलियों को अवैध रूप से पत्थर, बजरी व अन्य कार्यों में संचालित पाए जाने पर गत दो वर्षों में वसूल किया गया जुर्माना एवं जप्त की गई ट्रैक्टर-ट्रोलियों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सुजानगढ़ में नवीन खेल स्टेडियम की स्थापना

108. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार सुजानगढ़ शहर में नवीन स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान मे ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर स्टेडियम निर्माण का विचार किया जाता है।

छबड़ा में विद्युत आपूर्ति

109. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में किसानों को सिंचाई हेतु सुचारु रूप से बिजली दी जा रही है? यदि हां, तो दिन-रात में कितनी-कितनी बिजली दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन किसानों के विद्युत बिल बकाया हैं उक्त किसानों के विद्युत ट्रांसफार्मर उतार लिए गए हैं? यदि हां, तो कितनों के? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के तीनों उप खण्डों यथा छबड़ा, छीपाबड़ौद एवं हरनावदाशाहजी में विगत एक वर्ष में किसानों को सिंचाई हेतु बिजली की आपूर्ति सामान्यतया सुचारु रूप से की जा रही है। वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में सिचांई हेतु दिन व रात के साप्ताहिक बदलते ब्लाक में क्रमश 6:00 एवं 7:00 घंटे थ्री फेज विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के उप खण्डों के अन्तर्गत लम्बे समय से बकाया बिलों बाबत नोटिस देकर एवं बार-बार बकाया बिल राशि जमा कराने हेतु सूचित करने पर भी किसानों द्वारा बिलों की राशि जमा नहीं करवायी गयी। राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मजबूरन किसानों के ट्रांसफार्मर उतारे गये हैं, जिनकी पंचायतवार संख्यात्मक सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर में महाविद्यालयों के भवन एवं प्रवेश द्वारों के नामकरण में परिवर्तन

110. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला अजमेर में माह दिसंबर, 2018 के पश्चात् महाविद्यालयों के भवन तथा प्रवेश द्वारों के नाम में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो कब व क्या परिवर्तन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकारी भवनों के नाम परिवर्तन हेतु कौन अधिकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला अजमेर के किसी महाविद्यालय में नाम परिवर्तन हेतु राजकीय नियमों के अनुसार विधिवत प्रक्रिया अपनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह दिसम्बर, 2018 के पश्चात् सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर का नाम परिवर्तित नहीं किया गया है अपितु कालेज के आंतरिक कक्षा-कक्ष तथा ब्लाक की पहचान हेतु उनका नाम महापुरुषों/स्वतंत्रता सेनानियों/प्रेरणादायी व्यक्तित्वों के नाम पर रखा गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. कॉमर्स एवं मैनेजमेंट भवन - नेहरू भवन
2. पी.जी. ब्लाक - सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन
3. आर्ट्स ब्लाक - लाल बहादुर शास्त्री भवन
4. साइंस ब्लाक - डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आजाद भवन
5. साइंस एक्सटेंशन ब्लाक - सर सी.वी. रमन भवन
6. ज्योग्राफी ब्लाक - राजीव गांधी भवन
7. पुस्तकालय - स्वामी विवेकानन्द पुस्तकालय
8. पी.जी. छात्रा छात्रावास - कमला नेहरू छात्रावास
9. यू.जी. छात्रा छात्रावास - कस्तूरबा गांधी छात्रावास
10. शिशु गृह - इंदिरा गांधी शिशु गृह
11. सभागार- महात्मा गांधी सभागार
12. यू.जी.सी. ब्लाक - सुभाष चन्द्र बोस भवन
13. प्रवेश द्वार - डा. भीमराव अम्बेडकर द्वार
14. प्रवेश द्वार - महाराजा सूरजमल द्वार

(2) राजकीय महाविद्यालयों का नामकरण दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया है, जिसकी अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

महापुरुषों/प्रेरणादायक व्यक्तित्वों के नाम का प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर मंत्रिमण्डल के अनुमोदन पश्चात् नामकरण किया जाता है।

राजकीय महाविद्यालयों के आंतरिक ब्लाक/कक्ष/छात्रावास/सभागार एवं प्रवेश द्वारों की पहचान हेतु छात्र व शिक्षकों की सुविधा एवं आवश्यकतानुसार नाम महाविद्यालय स्तर पर रखा जाता है। इस संबंध में कोई नीति निर्धारित नहीं है।

(3) माह दिसम्बर, 2018 के पश्चात् अजमेर के किसी महाविद्यालय का नाम परिवर्तित नहीं किया गया है, अपितु सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर के आंतरिक कक्षा-कक्ष तथा ब्लाक की पहचान हेतु उनका नाम महापुरुषों/स्वतंत्रता सेनानियों/प्रेरणादायी व्यक्तित्वों के नाम पर रखा गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

साइबर अपराधियों के विरुद्ध चालान

61. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर (दक्षिण): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत चार वर्षों में प्रदेश में कितने साइबर अपराध दर्ज हुए? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से पुलिस द्वारा कितने प्रकरणों में चालान पेश कर दिये गये व कितने प्रकरण अन्वेषणीय हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में अपराधियों को सजा दिलाई गई व ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत चार वर्ष में प्रदेश में साइबर अपराध के 6,620 प्रकरण दर्ज हुए। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विगत चार वर्ष में पुलिस द्वारा साइबर अपराध के 1,901 प्रकरणों में चालान पेश किया गया तथा 760 प्रकरण अन्वेषणीय हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विगत चार वर्ष में साइबर अपराधों के पेशशुदा चालान के 10 प्रकरणों में अपराधियों को न्यायालयों से सजा हुई एवं 904 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें मुल्जिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

झालावाड़ में एम वी एक्ट के तहत जब्त वाहन

62. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला झालावाड़ में पुलिस द्वारा वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने वाहन बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल एवं अन्य वाहन एम वी एक्ट में जब्त किये गए हैं? उनमें से कितनों का निस्तारण किया जा चुका है तथा कितनों की नीलामी की गई है? थानेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

झालावाड़ जिले में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2022 तक पुलिस विभाग द्वारा एम.वी. एक्ट में 05 बस, 95 ट्रक, 458 कार, 11705 मोटरसाइकिल एवं अन्य वाहन 411 जप्त किये गये हैं तथा जप्तशुदा वाहनों में से 5 बस, 95 ट्रक, 451 कार 11,249 मोटरसाइकिल तथा अन्य वाहन 399 का निस्तारण किया जा चुका है। उक्त अवधि में किसी भी वाहन की नीलामी नहीं करवाई गई है। थानेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुफ्त स्मार्ट फोन का वितरण

63. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या?

(2) सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत महिला मुखियाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन कब तक दे दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार ने बजट 2022 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसमें लगभग एक करोड़ 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को इस योजना के तहत तीन साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ मुफ्त स्मार्टफोन दिये जाने हैं।

(2) इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन है।

देवली-उनियारा के उच्च माध्यमिक विद्यालय से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय

64. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ऐसे कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जिनमें अब तक उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा जिला टोंक में निम्नांकित दो ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राउमावि संचालित नहीं हैं:-

1. ग्राम पंचायत मुख्यालय, रिजोदा
2. ग्राम पंचायत मुख्यालय देवीखेडा

उक्त दोनों ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वर्तमान में प्राथमिक स्तर के विद्यालय संचालित हैं।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 28 के उपबिन्दु ।।। के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुसार एवं यथा आवश्यकता क्रमोन्नत किया जायेगा।

इसके साथ ही वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार 250 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

उक्त की पालना में मानदण्डानुकूल प्रस्तावों में उक्त क्षेत्र के प्रस्ताव भी प्राप्त होने पर समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन किया जाकर वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालयों की क्रमोन्नति की जा सकेगी।

बाड़मेर में ब्लाक शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण) का कार्यालय भवन

65. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ब्लाक शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण) एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्वयं के भवन में संचालित नहीं है?

(2) क्या सरकार ब्लाक शिक्षा अधिकारी ग्रामीण कार्यालय के भवन के लिए कोई बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, बाड़मेर ग्रामीण नव सृजित कार्यालय है।

उक्त कार्यालय का स्वयं का राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने से वर्तमान में मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर के भवन में संचालित हो रहा है।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बाड़मेर वर्तमान में डी.आर.डी.ए. कार्यालय, बाड़मेर के प्रथम तल पर संचालित हो रहा है।

(2) जी हां। मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर ग्रामीण कार्यालय द्वारा कार्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन के प्रस्ताव सचिव, नगर विकास न्यास, बाड़मेर को पत्र दिनांक 05.04.2022 को प्रेषित किये जा चुके हैं।

इसी प्रकार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, बाड़मेर द्वारा कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन के प्रस्ताव सचिव, नगर विकास न्यास, बाड़मेर को पत्र दिनांक 30.01.2023 द्वारा प्रेषित किये गये हैं।

भूमि आबंटित होने के उपरान्त भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभागीय मानदण्डानुसार वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

विद्यालयों में महिला स्टाफ हेतु पृथक् शौचालय का निर्माण

66. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के कितने विद्यालयों में महिला स्टाफ हेतु पृथक से शौचालय की व्यवस्था है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा महिला स्टाफ हेतु पृथक से शौचालय निर्माण हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिये निर्मित शौचालयों का उपयोग विद्यालय में कार्यरत महिला स्टाफ द्वारा भी किया जाता है। यू-डाइस वर्ष 2021-22 के अनुसार प्रदेश में संचालित स्वयं के भवन वाले 64,939 राजकीय विद्यालयों में से 64,700 विद्यालयों में बालिका/महिला शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है, जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। बालिका/महिला शौचालय सुविधा की आवश्यकता वाले विद्यालयों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2023-24 में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यों का सम्पादन किया जा सकेगा। साथ ही अन्य योजनाओं के माध्यम से भी उक्त कार्यों की स्वीकृति के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

बून्दी नगर परिषद् में आयुक्त के पद पर आर ए एस अधिकारी का पदस्थापन

67. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नगर परिषद्, बून्दी में अन्य नगर परिषदों की भांति आर ए एस अधिकारी को आयुक्त पद पर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर ए एस) के अधिकारियों का पदस्थापन कार्मिक विभाग द्वारा अपने स्तर पर किया जाता है। नगर परिषद्, बून्दी में आर ए एस अधिकारी को आयुक्त पद पर लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अलवर में हनुमान सर्किल तक नाले का निर्माण

68. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट 2021-22 में अलवर शहर में हीराबास काली मोरी से 200 फीट बाईपास एवं रूपबास आर ओ बी से हनुमान सर्किल तक नाला निर्माण कराने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त घोषणा के अनुरूप नाला निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। हीराबास कालीमोरी से 200 फीट बाईपास तक नाला निर्माण की निविदा आमंत्रित की हुई है एवं रूपबास आर ओ बी से हनुमान सर्किल तक नाला निर्माण कार्य में ग्राउण्ड लेवल उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण कार्य फिजिबल नहीं पाया गया।

(2) जी हां। उक्त घोषणा अनुरूप हीराबास कालीमोरी से 200 फीट बाईपास तक नाला निर्माण की निविदा आमंत्रित की हुई है एवं रूपबास आर ओ बी से हनुमान सर्किल तक नाला निर्माण कार्य में ग्राउण्ड लेवल उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण कार्य फिजिबल नहीं पाया गया।

जोधपुर में राज्य वृक्ष खेजड़ी के सूखने पर अनुसंधान

69. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ सूख रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच अथवा अनुसंधान करा कर उपचार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जोधपुर जिले में खेजडी के सूखने की कुछ घटनाएं पायी गई हैं, लेकिन इस संबंध में प्रमाणिक आंकड़े वन विभाग में उपलब्ध नहीं हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर द्वारा शोध उपरान्त यह पाया गया है कि खेजड़ी की जड़ों एवं सूखी डालों में शुष्क मौसम में दीमक लगने की प्रवृति रहती है। आफरी द्वारा इस समस्या के नियंत्रण हेतु समग्र तकनीक का विकास कर इसका प्रचार-प्रसार विवरणिका इत्यादि के माध्यम से करने के प्रयास किये गये हैं।

मेली बांध (बाड़मेर) का पुनर्भरण

70. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर का एक मात्र बांध मेली बांध है? यदि हां, तो उक्त के पुनर्भरण के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

(2) वर्तमान में उक्त बांध के लिए पुनर्भरण के लिए जो योजना बनी है उसमें अब तक कितना कार्य हो गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गुडा कैनाल योजना में अतिरिक्त बजट जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इसके पुनर्भरण हेतु पूर्व में वर्ष 2018 में राशि रुपये 149.55 लाख का कार्य करवाया गया। वर्तमान में इसके पुनर्भरण के लिए कार्य की आवश्यकता नहीं है।

(2) वर्तमान में मेली बांध के पुनर्भरण के लिए विभाग द्वारा योजना प्रस्तावित नहीं की गई है।

(3) गुडा डायवर्जन चैनल का पानी मेली बांध में जाता है। इस चैनल एवं बांध का पुनरुद्धार का कार्य वर्ष 2018 में राशि रुपये 149.55 लाख का करवाया गया। योजना के पूर्ण होने से अतिरिक्त बजट जारी कराने का कोई विचार प्रस्तावित नहीं है।

दलहन एवं तिलहन फसलों का समर्थन मूल्य पर खरीद

71. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत तीन वित्तीय वर्षों में राजफैड के माध्यम से प्रत्येक संभाग में दलहन एवं तिलहन की कौन-कौनसी फसलों की कितनी मात्रा में समर्थन मूल्य पर खरीद की गई एवं खरीद का समर्थन मूल्य क्या था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने दलहन एवं तिलहन की प्रतिवर्ष खरीद की अधिकतम मात्रा पूर्व में निश्चित की थी? यदि हां, तो उक्त अवधि में प्रत्येक संभाग में यह मात्रा कितनी थी?

(3) प्रदेश में उक्त अवधि में दलहन एवं तिलहन की कुल उत्पादन मात्रा कितनी थी एवं कितने प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत 3 वित्तीय वर्षों में राजफैड द्वारा की गई खरीद का विवरण निम्नानुसार है:-

(सहकारिता मंत्री)

वर्ष 2019-20

क्र. सं.	जिन्स	भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य (प्रति क्वि.)	मात्रा (मै.टन)	राशि (करोड़ों में)
1	सरसों	4200	608576.47	2556.02
2	चना	4620	120398.31	556.24
3	मूंग	7050	121669.07	857.77
4	उड़द	5700	26.50	0.15
5	मूंगफली	5090	193080.23	982.78
6	सोयाबीन	3710	0.00	0.00
	योग		**1043750.58**	**4952.96**

वर्ष 2020-21

क्र. सं.	जिन्स	भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य (प्रति क्वि.)	मात्रा (मै.टन)	राशि (करोड़ों में)
1	सरसों	4425	346891.86	1535.00
2	चना	4875	615716.88	3001.62
3	मूंग	7196	12004.86	86.39
4	उड़द	6000	0.00	0.00
5	मूंगफली	5275	73825.98	389.43
6	सोयाबीन	3880	0.00	0.00
	योग		**1048439.58**	**5012.44**

वर्ष 2021-22

क्र. सं.	जिन्स	भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य (प्रति क्वि.)	मात्रा (मै.टन)	राशि (करोड़ों में)
1	सरसों	4650	0.00	0.00
2	चना	5100	17464.47	89.07
3	मूंग	7275	5727.50	416.65
4	उड़द	6300	40.20	0.25
5	मूंगफली	5550	53226.06	295.41

(सहकारिता मंत्री)

क्र. सं.	जिन्स	भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य (प्रति क्वि.)	मात्रा (मै.टन)	राशि (करोड़ों में)
6	सोयाबीन	3950	0.00	0.00
	योग		**76458.23**	**801.38**

समर्थन मूल्य खरीद का संभागवार विवरण परिशिष्ट-1 से परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(2) समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन की खरीद हेतु लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों में स्वीकृत खरीद लक्ष्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जिन्स	स्वीकृत लक्ष्य (मै. टन)		
		वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22
1	सरसों	850275	1046500	1222775
2	चना	417575	615750	614900
3	मूंग	228350	357875	361282
4	उड़द	73800	71550	61807
5	मूंगफली	306875	374600	427000
6	सोयाबीन	354100	292295	293000

गत तीन वित्तीय वर्षों की समर्थन मूल्य खरीद के संभागवार लक्ष्यों की सूचना परिशिष्ट-1 से परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(3) गत तीन वित्तीय वर्षों में राज्य में दलहन/तिलहन के कुल उत्पादन एवं समर्थन मूल्य खरीद का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष 2019-20

क्र. सं.	जिन्स का प्रकार	उत्पादन (मात्रा लाख मै. टन)	समर्थन मूल्य खरीद (मात्रा लाख मै. टन)	खरीद का प्रतिशत
1	दलहन	44.94	2.42	5.38
2	तिलहन	73.20	8.02	10.95

(सहकारिता मंत्री)

वर्ष 2020-21

क्र. सं.	जिन्स का प्रकार	उत्पादन (मात्रा लाख मै. टन)	समर्थन मूल्य खरीद (मात्रा लाख मै. टन)	खरीद का प्रतिशत
1	दलहन	39.67	6.28	15.83
2	तिलहन	80.40	4.20	5.22

वर्ष 2021-22

क्र. सं.	जिन्स का प्रकार	उत्पादन (मात्रा लाख मै. टन)	समर्थन मूल्य खरीद (मात्रा लाख मै. टन)	खरीद का प्रतिशत
1	दलहन	40.52	0.23	0.56
2	तिलहन	102.68	0.53	0.51

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर में नवीन बसों का संचालन

72. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला नागौर में विगत तीन वर्षों में कितनी बसें बंद की गई व कितनी नवीन बसें प्रारम्भ की गईं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में नागौर जिले में बन्द की गई बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "1" पर तथा उक्त अवधि में नवीन संचालित की गई बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

परिवहन विभाग द्वारा निजी वाहनों के अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं। नागौर जिले में जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 331 परमिट जारी किये गये हैं तथा 376 परमिट सरेंडर किये गये। वर्तमान में नागौर जिले में 691 परमिट अस्तित्व में हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अवैध बसों के संचालन पर रोक

73. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती कल्पना देवी)

(1) क्या सरकार प्रदेश के विभिन्न शहरों में अवैध रूप से संचालित बसों को विशेष अभियान चलाकर रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त के संचालन से राजकोष को भारी नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घाटे को रोकने हेतु अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा अवैध वाहनों (भार वाहनों/यात्री वाहन/बसों) के संचालन को रोकने व सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सघन सड़क सुरक्षा जांच अभियान चलाए जाते हैं एवं विभागीय उड़नदस्तों द्वारा नियमित रूप से अवैध वाहनों के संचालन के विरुद्ध जांच कर प्रभावी कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

(2) जी नहीं। नियमानुसार प्रत्येक परिवहन यात्री वाहन (बस) के लिये परमिट प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में सभी यात्री वाहनों द्वारा देय कर का भुगतान किया जाता है। यदि परमिट शर्तों के उल्लंघन अथवा अपने निर्धारित मार्ग से हटकर अन्य मार्ग पर संचालित पाये जाने पर विभागीय अधिकारियों एवं उड़नदस्तों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जालौर में बंद बसों का पुन: संचालन

74. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कोरोना काल से पूर्व रोडवेज की बस जालौर से सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा वाया जसवंतपुरा से संचालित थी, जिसे कोरोना काल में बन्द कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस सेवा को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जालौर से सूरत

(राज्य मंत्री, परिवहन)

वाया जसवंतपुरा, अहमदाबाद, बड़ौदा बस सेवा कोरोना काल से पूर्व संचालित की जा रही थी। उक्त बस का संचालन कोरोना काल से बन्द कर दिया गया।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त बस सेवा का संचालन पुन: प्रारम्भ करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

वर्तमान में जालौर से अहमदाबाद वाया जसवंतपुरा होकर निगम द्वारा निम्नानुसार बसें संचालित की जा रही हैं:-

क्र.सं.	मार्ग	प्रस्थान समय
1	जालौर-अहमदाबाद-जालौर वाया जसवन्तपुरा	08.00
2	जालौर-अहमदाबाद-जालौर वाया जसवन्तपुरा	16.20

पंचायत समिति मुख्यालयों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

75. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा पंचायत समिति मुख्यालयों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला प्रतापगढ़ के पंचायत समिति मुख्यालय दलोट, सुहागपुरा एवं धमोतर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा पंचायत समिति मुख्यालयों पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता तथा गुणावगुणों के आधार पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन राजकीय आईटी.आई. खोले जाने का निर्णय लिया जाता है।

बून्दी में रोजगार मेले का आयोजन

76. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बून्दी में रोजगार मेले का आयोजन कर शिक्षित व प्रशिक्षण प्राप्त अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों से अनेक संस्थाओं द्वारा आवेदन प्राप्त किये गये थे? यदि हां, तो किस-किस वर्ग से, किस-किस संस्थान को, कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए व उक्त में से कितने-कितने बेरोजगारों को स्थाई रोजगार दिया गया? वर्गवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा जिला बून्दी में रोजगार मेले का आयोजन कर शिक्षित व प्रशिक्षण प्राप्त अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थियों से अनेक संस्थाओं द्वारा आवेदन प्राप्त किये गये थे। विभाग द्वारा लगाये जा रहे शिविरों में किसी भी प्रकार का स्थाई रोजगार नहीं प्रदान किया जाता अपितु रोजगार विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से नियोक्ताओं एवं बेरोजगार युवाओं को एक ही मंच उपलब्ध कराते हुए हर माह एक मासिक कौशल रोजगार शिविर अथवा कैम्पस शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा आशार्थियों की योग्यतानुसार प्राथमिक चयन किया जाता है।

बून्दी जिले में दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2022 तक विभाग द्वारा लगाये गये रोजगार शिविरों में कुल 30 कम्पनियों ने अपनी भागीदारी प्रदान करते हुए कुल 3,629 आशार्थियों में से लाभांवितों में 2,266 युवाओं का नियोजन हेतु प्राथमिक चयन किया गया।

उक्त लाभांवितों में 689 आशार्थी अनुसूचित जाति, 385 आशार्थी अनुसूचित जनजाति एवं 1,192 विछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के बेरोजगार आशार्थी शामिल हैं। संस्थावार, वर्गवार प्राथमिक चयन की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सहायक एवं अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोलने के प्रावधान

77. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सहायक व अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोलने के क्या प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आहोर में ए ईएन आफिस आहोर, उम्मेदपुर, बागरा के लिए अलग से अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोलने की शर्तें पूरी करता है? यदि हां, तो क्या सरकार आहोर में अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भाद्राजून सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की शर्तें पूरी करता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर उक्त कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार से प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत विद्युत वितरण निगमों में नवीन कार्यालय सृजित किये जाते हैं। प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों में नया सहायक अभियन्ता कार्यालय शहरी क्षेत्रों में 28,000 उपभोक्ताओं पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 22,000 उपभोक्ताओं पर एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 50 एम वी ए से 250 एम वी ए पर खोले जाने का प्रावधान है। नया अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय 90,000 उपभोक्ताओं पर खोलने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। सहायक अभियन्ता कार्यालय आहोर उम्मेदपुर व बागरा के उपभोक्ताओं के अनुसार यदि नया अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय आहोर में प्रस्तावित किया जाता है तो पहले से स्थापित अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय जालौर में एक ही सहायक अभियन्ता कार्यालय रह जायेगा। अत: वर्तमान में आहोर में नया अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय खोलना मापदण्डों के अनुरूप नहीं है।

(3) जालौर जिले के भाद्राजून में नवीन सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है जो कि मापदंडों के अनुरूप पाये जाने पर स्वीकृति संबंधित कार्यवाही के उपरान्त उक्त सहायक अभियंता कार्यालय का सृजन किया जाना प्रस्तावित है।

कोटा में संचालित कन्या महाविद्यालय

78. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2022-23 में बालिकाओं की बेहतर शिक्षा के लिये जिलेवार कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किन-किन जिलों में किस-किस स्थान पर उक्त कन्या महाविद्यालय संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोटा में कन्या महाविद्यालय कहां-कहां संचालित हैं तथा उक्त के लिये कितना बजट आबंटित किया गया? उक्त कालेज के कार्य की प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की अनुपालना में 24 जिलों में 61 राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) कोटा जिले में 04 राजकीय कन्या महाविद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा।
2. राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा।
3. राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, कोटा।
4. राजकीय कन्या महाविद्यालय, रामपुरा।

जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा, स्वयं के भवन में संचालित है तथा 03 महाविद्यालयों हेतु आबंटित बजट तथा भवन निर्माण कार्य की प्रगति का विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)